रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33001/97

REGISTERED NO. D. L.—33001/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 23, 1997/ भाद्र 1, 1919

No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 23, 1997/BHADRA 1, 1919

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 1997

का.आ. 2062.—सरकारी भवन (अनाधिकृत कब्जे की बेदखली) अधिनियम, 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा नीचे सारणी के कालम (1) में उल्लिखित अधिकारी को, भारत सरकार का राजपत्रित अधिकारी होने के कारण, उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम्पदा अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है और एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि उपर्युक्त अधिकारी उक्त सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट सरकारी भवनों की श्रेणियों के संबंध में उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिए गए कार्यों का निर्वहन करेगा—

सारणी

नाम तथा रैंक	सरकारी भवनों की श्रेणियां
श्री बेल प्रसाद गुरुंग, उप समादेष्टा, महानिदेशालय, असम राइफल्स, शिलांग-793 011	भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 2507 दिनांक 20 अगस्त, 1996 द्वारा अधिसूचित किए जा चुके भवनों के अतिरिक्त त्रिपुरा राज्य में असम राइफल्स के नियंत्रणाधीन सभी सरकारी भवन।

[फा. सं. II/27013/32/96-पी.एफ-V]

निर्मला देव, डैस्क अधिकारी (पी. एफ.-V)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 30th July, 1997

S.O. 2062.—In exercise of powers conferred by Section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupation) Act-1971 (40 of 1971) the Central Government hereby appoints the officer mentioned in the Column (1) of the table below, being a gazetted Officer of the Government of India, to be Estate Officer for the purpose of the said Act and hereby directs that the said officer shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed, on Estate Officers under the said Act in respect of the Categories of Public Premises specified in column (2) of the said table:—

TABLE

Name and rank	Categories of public premises
Shri Bel Prasad Gurung Deputy Commandant Directorate General Assam Rifles Shillong-793011	All public premises held on charge of Assam Rifles in the State of Tripura in addition to premises already notified in Gazette of India Part-II Section 3 Sub Section (ii) S.O. 2507 dated 20 August, 1996.

[F. No. II/27013/32/96 PF-V]

NIRMALA DEV, Desk Officer (PF-V)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1997

स्टाम्प

का०आ० 2063.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो पंजाब नैशनल बैंक, नई दिल्ली द्वारा 15 जनवरी, 1997 को आबंटित किए गए मात्र एक सौ नवासी करोड़, अट्ठानवे लाख और बीस हजार रुपए के कुल मूल्य के दस-दस हजार रुपए मूल्य के 199927 से 389908 तक की विशिष्ट संख्या वाले अप्रतिभूत गौण विमोच्य बंध-पत्रों (निश्चित दर वाले) के रूप में वर्णित प्रोमिसरी नोटों के स्वरूप वाले बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के तहत प्रभार्य है।

[सं०-21/97-स्टाम्प/फा०सं०-14/2/97-वि क]

एस० कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 29th July, 1997

STAMPS

S.O. 2063.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of promissory notes described as Unsecured Subordinated Redeemable Bonds (Fixed Rate) of the value of Rupees ten thousand each bearing distinctive numbers 199927 to 389908 aggregating to Rupees One hundred eighty nine crores, ninety eight lakhs and twenty thousand only allotted on 15th January, 1997 by the Punjab National Bank, New Delhi are chargeable under the said Act.

[No. 21/97-Stamps/F. No. 14/2/97-ST]

S. KUMAR, Under Secy.

कार्यालय आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क,

इन्दौर, 31 जुलाई, 1997

का०आ० 2064.—श्री वी०के० वेखन्डे, अधीक्षक, समूह "ख", केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, इन्दौर स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति पर दिनांक 01-06-97 को पूर्वान्ह में शासकीय सेवा से निवृत्त हुए।

[का०सं० II (3) 9-गोप/93/3466]

अशोक कुमार गुप्ता, उप आयुक्त (कार्मिक एवं सतर्कता

OFFICE OF THE COMMISSIONER, CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE

Indore, the 31st July, 1997

S.O. 2064.—Shri V. K. Wekhande, Supdt. Central Excise Group 'B' of Indore Commissionerate, on voluntary retirement, retired from Government Service on 01-06-97 in the forenoon.

[F. No. II(3)9-Con/93/3466]

ASHOK KUMAR GUPTA, Dy. Commissioner (P&V)

इन्दौर, 31 जुलाई, 1997

का०आ० 2065—श्री आर०बी० गुप्ता, अधीक्षक, समूह "ख" केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, इन्दौर निर्वतन आयु प्राप्त करने पर दिनांक 30-06-97 को अपरान्ह में शासकीय सेवा से निवृत्त हुए।

[फा० सं० II (3) 9-गोप/93/3465]

अशोक कुमार गुप्ता, उप आयुक्त (कार्मिक एवं सतर्कता)

Indore, the 31st July, 1997

S.O. 2065.—Shri R. B. Gupta, Supdt. Central Excise Group 'B' of Indore Commissionerate, having attained the age of Superannuation retired from Government Service on 30-06-97 in the afternoon.

[F. No. II(3)9-Con/93/3465]

ASHOK KUMAR GUPTA, Dy. Commissioner (P&V)

अधिसूचना संख्या 01/1997

नागपुर, 4 अगस्त, 1997

का०आ० 2066.—श्री जे०डी० अपराजित अधीक्षक, (निवारक), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समूह "ख" आयुक्तालय नागपुर का दिनांक 25 जून, 1997 को देहान्त हो गया है।

[फा० सं० II (3) 3/95/स्था०-I]

आर०जे० बेले, अपर आयुक्त (कार्मिक एवं सतर्कता)

NOTIFICATION NO. 01/1997

Nagpur, the 4th August, 1997

S.O. 2066.—Shri J. D Aparajit, Superintendent (Preven-Group 'B' Central Excise Commissionerate, Nagpur expired on 25-6-1997.

[C. No. II(3)3/95/Estt.I]

R. J. BELEY, Addl. Commissioner (P&V)

आदेश

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1997

स्टाम्प

का०आ० 1067.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली द्वारा प्रोमिसरी नोटों के रूप में निम्नोक्त प्रकार के वर्णित बांडों पर उक्त अधिनियम के तहत प्रभार्य है,—

(क) 29-3-96 को आबंटित किए गए मात्र तीस हजार रुपये के समग्र मूल्य के प्रत्येक दस-दस हजार रु० के 400001 से 400003 तक की विशिष्ट संख्या वाले 10.50% कर-मुक्त आर. ई. सी. बांड-2004;

(ख) 29-3-96 को आबंटित किए गए मात्र इक्यावन लाख रुपये के समग्र मूल्य के प्रत्येक एक-एक लाख रु० के 500001 से 500051 तक की विशिष्ट संख्या वाले 10.50% कर मुक्त आर०ई०सी० बांड-2004;

(ग) 29-6-96 को आबंटित किए गए मात्र अड़सठ करोड़ पचास लाख रुपए के समग्र मूल्य के प्रत्येक पचास-पचास लाख रु० के 600001 से 600137 तक की विशिष्ट संख्या वाले 10.50% कर-मुक्त आर०ई०सी० बांड-2004;

(घ) 13-9-96 को आबंटित किए गए मात्र पैंतीस करोड़ रुपए के समग्र मूल्य के प्रत्येक एक-एक हजार रुपए के 1001 से 1300 तक, प्रत्येक एक-एक लाख रुपए के 2001 से 2197 तक, प्रत्येक पचास-पचास लाख रुपए के 5001 से 5066 तक की विशिष्ट संख्या वाले 13.85% आर०ई०सी० बांड-2006 (***[-श्रृंखला)

(ङ) मार्च, 1996 को आबंटित किए गए मात्र छह लाख बानवे हजार रुपए के समग्र मूल्य के प्रत्येक एक-एक हजार रु० के 1001 से 1692 तक की विशिष्ट संख्या वाले 14% आर०ई०सी० बांड-2006,

(च) मार्च, 1996 को आबंटित किए गए मात्र छह करोड़ इक्यासी लाख रुपए के समग्र मूल्य के प्रत्येक एक-एक लाख रुपए के 2001 से 2681 तक की विशिष्ट संख्या वाले 14% आर०ई०सी० बांड-2006;

(छ) मार्च, 1996 को आवंटित किए गए मात्र सैंतीस करोड़ रुपए के समग्र मूल्य के प्रत्येक पचास-पचास लाख रु. के 5001 से 5074 तक की विशिष्ट संख्या वाले 14% आर.ई.सी. बांड-2006,

(ज) 27-3-97 को आवंटित किए गए मात्र एक सौ पचास करोड़ रुपए के समग्र मूल्य के प्रत्येक एक-एक लाख रुपये के 400001 से 400150 तक तथा प्रत्येक पचास-पचास लाख रुपए के 500001 से 500297 तक विशिष्ट संख्या वाले 9.15% कर मुक्त आर.ई.सी. बांड-2004 (XXXII-श्रृंखला)।

[सं. 32/97 स्टा. फा. सं. 14/22, 29, 40/96-वि. क./फा. सं. 14/10/97-वि.क.]

एस. कुमार, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 31st July, 1997

STAMPS

S.O. 2067.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of promissory notes described as :—

(a) 10.50 per cent Tax-free REC Bonds-2004 bearing distinctive numbers 400001 to 400003 of Rupees ten thousand each aggregating to Rupees thirty thousand only allotted on 29-3-96 ;

(b) 10.50 per cent Tax-free REC Bonds-2004 bearing distinctive numbers 500001 to 500051 of Rupees one lakh each aggregating to Rupees fifty one lakhs only allotted on 29-3-96 ;

(c) 10.50 per cent Tax-free REC Bonds-2004 bearing distinctive numbers 600001 to 600137 of Rupees fifty lakhs each aggregating to Rupees sixty eight crores fifty lakhs only allotted on 29-6-96 ;

(d) 13.85 per cent REC Bonds-2006 (XXXI Series) bearing distinctive numbers from 1001 to 1300 of rupees one thousand each from 2001 to 1297 of rupees one lakh each, from 5001 to 5066 of Rupees fifty lakh each aggregating to Rupees thirty five crores only allotted on 13-9-96 ;

(e) 14 per cent REC Bonds-2006 bearing distinctive numbers 1001 to 1692 of Rupees one thousand each aggregating to Rupees six lakhs ninety two thousands only allotted in March, 1996 ;

(f) 14 per cent REC Bonds-2006 bearing distinctive numbers 2001 to 2681 of Rupees one lakh each aggregating to Rupees six crore eighty one lakhs only allotted in March 1996 ;

(g) 14 per cent REC Bonds-2006 bearing distinctive numbers 5001 to 5074 of Rupees fifty lakh each aggregating of Rupees thirty seven crores only allotted in March, 1996 ; and

(h) 9.25 per cent Tax-free REC Bonds-2004 (XXXII-Series) bearing distinctive numbers from 400001 to 400150 of Rupees one lakh each and from 500001 to 500297 of Rupees fifty lakh each aggregating to Rupees one hundred fifty crores only allotted on 27-3-97.

by the Rural Electrification Corporation Limited, New Delhi, are chargeable under the said Act.

[No. 32/97-Stamps-F. No. 14/22, 29, 40/96-ST &
F. No. 14/10/97-ST]
S. KUMAR, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1997

स्टाम्प

का.आ. 2068.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो कि एच एम टी लिमिटेड, बंगलौर द्वारा जारी मात्र तीन करोड़ चौसठ लाख रु० के कुल मूल्य के निम्नांकित प्रकार से वर्णित प्रत्येक एक-एक लाख रु० के प्रोमिसरी नोटों के स्वरूप वाले बांडों पर उक्त अधिनियम के तहत प्रभार्य है

(1) 5 फरवरी, 1996 को आवंटित 56058 से 56072 तक की विशिष्ट संख्या वाले एच एम टी (कर-योग्य) बांड-श्रृंखला बी 1(एफ) ; और

(2) 5 फरवरी, 1996 को आवंटित 56371 से 56620 तक की विशिष्ट संख्या वाले एच एम टी (कर-योग्य) बांड-श्रृंखला बी 1(जी) ; और

(3) 5 फरवरी, 1996 को आवंटित 54005 से 54103 तक की विशिष्ट संख्या वाले एच एम टी (कर-योग्य) बांड-श्रृंखला बी 1(बी)।

[सं. 22/97-स्टाम्प/फा. सं. 11/18/96-वि.क.प्र.]

एस. कुमार, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 31st July, 1997

STAMPS

S.O. 2068.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of Promissory Notes of rupees one lakh each, described as.—

(a) HMT (Taxable) Bonds—Series B1(F) bearing distinctive numbers 56058 to 56072 allotted on 5th February, 1996 ; and

(b) HMT (Taxable) Bonds—Series B1(G) bearing distinctive numbers 56371 to 56620 allotted on 5th February, 1996 ; and

(c) HMT (Taxable) Bonds—Series B1(B) bearing distinctive numbers 54005 to 54103 allotted on 5th February, 1996.

Aggregating to rupees three crores sixty four lakhs only issued by HMT Limited, Bangalore are chargeable under the said Act.

[No. 22/97-Stamps/F. No. 14/18/96-ST]
S. KUMAR, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1997

स्टाम्प

का.आ. 2069.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम, चण्डीगढ़ द्वारा जारी किए गए निम्न प्रकार वर्णित प्रोमिजरी स्वरूप वाले बांडों पर उक्त अधिनियम के तहत प्रभार्य है :—

(क) 1 से 2540 तक की विशिष्ट संख्या वाले 1-1 लाख रु. मूल्य के मात्र पच्चीस करोड़ चालीस लाख रु. के समग्र मूल्य के 16 प्रतिशत करार्धेय पं.रा.औ.वि.नि.—बांड-2001 (1996—पहली श्रृंखला) ;

(ख) 2541 से 5000 तक की विशिष्ट संख्या वाले 1–1 लाख रु. मूल्य के मात्र चौबीस करोड़ साठ लाख रु. के समग्र मूल्य के 16 प्रतिशत कराधेय पं.रा.औ. वि.नि. बांड-2001 (1996—दूसरी श्रृंखला) ;

(ग) 5001 से 10000 तक की विशिष्ट संख्या वाले 1–1 लाख रु. मूल्य के मात्र पचास करोड़ रु. के समग्र मूल्य वाले 16 प्रतिशत कराधेय पं.रा.औ.वि.नि. बांड-2001 (1996—तीसरी श्रृंखला);

(घ) 0001 से 4390 तक की विशिष्ट संख्या वाले 1–1 लाख रु. मूल्य के मात्र तितालीस करोड़ नब्बे लाख रु. के समग्र मूल्य के 13.5 प्रतिशत कराधेय प.रा.औ. वि.नि. बांड - 2001 (7 वर्षीय) (1994—पहली तथा तीसरी श्रृंखला); और

(ङ) 4391 से 6890 तक की विशिष्ट संख्या वाले 1–1 लाख रु. मूल्य के मात्र पच्चीस करोड़ रु. मूल्य के समग्र मूल्य वाले 13 प्रतिशत कराधेय पं. रा. औ. वि. नि. बांड 2001 (7 वर्षीय) (1994–तीसरी श्रृंखला)।

[सं० 23/97–स्टाम्प/फा.सं. 14/26/96–वि.क.]
एस. कुमार, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 31st July, 1997

STAMPS

S.O. 2069.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1999), the (2 of 1899), Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of promissory note described as :—

(a) 16% Taxable PSIDC Bonds-2001 (1996-1st Series bearing distinctive numbers from 1 to 2540 of rupees one lakh each aggregating to rupees twenty five crore forty lakhs only;

(b) 16% Taxable PSIDC Bonds—2001 (1996-IInd Series) bearing distinctive numbers from 2541 to 5000 of rupees one lakh each aggregating to rupees twenty four crore sixty lakhs only;

(c) 16% Taxable PSIDC Bonds-2001 (1996-IIIrd Series) bearing distinctive numbers from 5001 to 10000 of rupees one lakh each aggregating to rupees fifty crores only;

(d) 13.5% Taxable PSIDC Bonds-2001 (7 years) (1994-Ist & IInd Series) bearing distinctive numbers from 0001 to 4390 of rupees one lakh each aggregating to rupees forty three crore ninety lakhs only; and

(e) 13% Taxable PSIDC Bonds-2001 (7 years) (1994-IIIrd Series) bearing distinctive numbers from 4391 to 6890 of rupees one lakh each aggregating to rupees twenty five crore only.

issued by the Punjab State Industrial Development Corporation Limited, Chandigarh are chargeable under the said Act.

[No. 23/97-Stamps/F. No. 14/26/96-ST]
S. KUMAR, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1997

स्टाम्प

का.आ. 2070.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो प्रोमिसरी नोटों के स्वरूप के निम्नानुसार वर्णित :—

(i) 00001 से 25000 तक की विशिष्ट संख्या वाले एक-एक लाख रु. मूल्य के केवल दो सौ पचास करोड़ रु. के समग्र मूल्य के 10.5 प्रतिशत कर-मुक्त सुरक्षित विमोच्य पीएफसी बांड; और

(ii) 1000001 से 152500 तक की विशिष्ट संख्या वाले मात्र तीन सौ पांच करोड़ रु. मूल्य के 10.5 प्रतिशत कर-मुक्त विमोच्य बांड—2004-श्रृंखला VII विद्युत वित्त निगम लि., नई दिल्ली द्वारा आवंटित किए गए बांडों पर उक्त अधिनियम के तहत प्रभार्य है।

[सं. 30/97–स्टाम्प/फा.स. 14/31/96–वि.क./14/16/97–वि.क.]
एस. कुमार, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 31st July, 1997

STAMPS

S.O. 2070.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of promissory notes described as,—

(a) 10.5% Tax-free Secured Redeemable PFC Bonds bearing distinctive numbers from 00001 to 25000 of rupees one lakh each of the aggregate value of rupees two hundred fifty crores only; and

(b) 10.5% Tax-free Secured Redeemable Bonds-2004-(Series-VII) bearing distinctive numbers from 1000001 to 152500 aggregating to rupees three hundred five crores only.

allotted by the Power Finance Corporation Limited, New Delhi are chargeable under the said Act.

[No. 30/97-Stamps/F. No. 14/31/96-ST & 14/16/97-ST]
S. KUMAR, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1997

स्टाम्प

का.आ. 2071.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उस शुल्क को माफ करती है जो भारतीय पर्यटन वित्त निगम लि., नई दिल्ली द्वारा निम्नलिखित के रूप में वर्णित प्रोमिसरी नोटों के रूप में बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य है :—

(क) दिनांक 1-6-1995 को आवंटित किए गए 21 करोड़ 28 लाख रुपए के कुल मूल्य के 01 से 212800 तक की विशिष्ट संख्या वाले 14.5/15 प्रतिशत असुरक्षित कर-योग्य बंधपत्र (एमवी श्रृंखला-VI);

(ख) दिनांक 7-8-1995 को आवंटित किए गए 23 करोड़ 39 लाख रु. के कुल मूल्य के 01 से 233900 तक की विशिष्ट संख्या वाले 15.5 प्रतिशत असुरक्षित कर-योग्य बंधपत्र (एमवी श्रृंखला-VII);

(ग) दिनांक 5-9-95 को आवंटित किए गए 38 करोड़ 39 लाख रु. के कुल मूल्य के 000001 से 383900 तक की विशिष्ट संख्या वाले 15.75 प्रतिशत असुरक्षित कर-योग्य बंधपत्र (एमवी श्रृंखला-VIII);

(घ) दिनांक 16-11-95 को आवंटित किए गए 17 करोड़ 52 लाख रु. के कुल मूल्य के 0000 से 175200 तक की विशिष्ट संख्या वाले 16 प्रतिशत असुरक्षित कर-योग्य बंधपत्र (एमबी श्रृंखला-IV);

(ङ) दिनांक 25-3-96 को आवंटित किए गए 21 करोड़ 65 लाख 62 हजार रु. के कुल मूल्य के 0 से 216562 तक की विशिष्ट संख्या वाले 16.5 प्रतिशत असुरक्षित कर-योग्य बंधपत्र (एमबी श्रृंखला-X);

(च) दिनांक 4-6-96 को आवंटित किए गए 82 करोड़ 84 लाख 50 हजार रु. के कुल मूल्य के 1 से 828450 तक की विशिष्ट संख्या वाले 18 प्रतिशत असुरक्षित कर-योग्य बंधपत्र (एमबी श्रृंखला-XI); और

(छ) दिनांक 18-2-97 को आवंटित किए गए 78 करोड़ 59 लाख रु. के कुल मूल्य के 1 से 7859 तक की विशिष्ट संख्या वाले 16 प्रतिशत असुरक्षित कर योग्य बंधपत्र (एमबी श्रृंखला-XIII)

[सं. 31/97-स्टा./फा.सं. 33/47/95-वि.क.]

एस कुमार, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 31st July, 1997

STAMPS

S.O. 2071.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of promissory notes described as,—

(a) 14.5%/15% Unsecured Taxable Bonds (MB Series-VI) bearing distinctive numbers from 01 to 212800 aggregating to rupees twenty one crore twenty eight lakhs only allotted on 1-6-1995;

(b) 15.5% Unsecured Taxable Bonds (MB Series-VII) bearing distinctive numbers from 01 to 233900 aggregating to rupees twenty three crore thirty nine lakhs only allotted on 7-8-1995;

(i) 15.75% Unsecured Taxable Bonds (MB Series-VIII) bearing distinctive numbers from 000001 to 383900 aggregating to rupees thirty eight crore thirty nine lakhs only allotted on 5-9-1995;

(d) 16% Unsecured Taxable Bonds (MB Series-IX) bearing distinctive numbers from 00000 to 175200 aggregating to rupees seventeen crore fifty two lakhs only allotted on 16-11-1995;

(e) 16.5% Unsecured Taxable Bonds (MB Series-X) bearing distinctive numbers from 0 to 216562 aggregating to rupees twenty one crore sixty five lakh sixty two thousand only allotted on 25-3-1996;

(f) 18% Unsecured Taxable Bonds (MB Series-XI) bearing distinctive numbers from 1 to 828450 aggregatting to rupees eighty two crore eighty four lakh fifty thousand only allotted on 4-6-1996; and

(g) 16% Unsecured Taxable Bonds (MB Series-XIII) bearing distinctive numbers from 1 to 7859 aggregating to rupees seventy eight crore fifty nine lakhs allotted on 18-2-1997.

by Tourism Finance Corporation of India Limited, New Delhi are chargeable under the said Act.

[No 31/97-Stamps/F No. 33/47/95-ST]

S. KUMAR, Under Secy.

अधिसूचना संख्या: 02/1997

नागपुर, 4 अगस्त, 1997

का० आ० 2072.—श्री बी० के० घाडखन्दे, अधीक्षक, एवं श्री एम० जे० चंदने, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद, शुल्क आयुक्तालय, नागपुर निदर्तन की आयु प्राप्त करने दिनांक 31-07-97 को अपराह्न में शासकीय सेवा से निवृत्त हुए हैं।

[फा.सं० 11(3)3/95/स्था०]

आर०जे० बेले, अवर आयुक्त (कार्मिक एवं सतर्कता)

NOTIFICATION NO. 02/1997

Nagpur, the 4th August, 1997

S.O. 2072.—Shri B. K. Ghodkhande, Superintendent and Shri M. J. Chandane, Superintendent, Central Excise, Nagpur Commissionerate having attained the age of superannuation retired from Government service on 31-07-1997 in the afternoon.

[C. No. II(3)3/95/Estt.I]

R. J. BELEY, Addl. Commissioner (P&V)

आदेश

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1997

का.आ. 2073.—अतः संयुक्त सचिव, भारत सरकार जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत विशेष रूप से शक्ति प्रदान की गई है, ने उक्त उप-धारा के अधीन आदेश फाइल सं. 673/50/96-सी-यू-एस-VIII दिनांक 23/8/96 को जारी किया और यह निर्देश दिया कि श्री रविन्द्र रस्तोगी पता 59-उदय पार्क, न्यू देहली को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, तिहाड़, नई दिल्ली, में अभिरक्षा में रखा जाए जिससे कि उन्हें भविष्य में माल की तस्करी करने से रोका जा सके।

2. अतः केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या स्वयं को छिपा रखा है जिससे कि यह आदेश निष्पादित नहीं किया जा सकता।

3. अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को यह निर्देश देती है कि वह शासकीय राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशित होने के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त नई दिल्ली के सम्मुख उपस्थित हो।

[फा. सं. 673/50/96/सी.यू.एस.VIII]

जमना दास, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 7th August, 1997

S.O. 2073.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of section 3 of the Conservation of Foreign Exchange & Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974), issued Order F. No. 673/50/96-Cus. VIII dated 23-8-96 under the said sub-section directing that Shri Ravindra Rastogi, 59, Pday Park, New Delhi be detained and kept in custody in the Central Prison, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from Smuggling goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, New Delhi within 7 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 673/50/96 Cus. VIII]
JAMNA DASS, Under Secy.

सेन्ट्रल इकॉनॉमिक इन्टेलीजेंस ब्यूरो

आदेश

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1997

का.आ. 2074—अतः संयुक्त सचिव, भारत सरकार जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विशेष रूप से शक्ति प्रदान की गई है, ने उक्त उप-धारा के अधीन आदेश फाइल सं. 673/96-सीयूएस-VIII दिनांक 12-2-96 को जारी किया और यह निर्देश दिया कि श्री विनोद कुमार चावला सुपुत्र मनोहर लाल चावला, पता: ई-526, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, तिहाड़, नई दिल्ली में अभिरक्षा में रखा जाए जिससे कि उन्हें भविष्य में माल की तस्करी करने से रोका जा सके।

2. अतः केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या स्वयं को छिपा रखा है जिससे कि यह आदेश निष्पादित नहीं किया जा सकता।

3. अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को यह निदेश देती है कि वह शासकीय राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशित होने के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली के सम्मुख उपस्थित हो।

[फा. सं. 673/19/96/सी.यू एस.-VIII]
जमना दास, अवर सचिव

CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU

ORDER

New Delhi, the 11th August 1997

S.O. 2074.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/19/96-Cus. VIII dated 12-2-96 under the said sub-section directing that Shri Vinod Kumar Chawla S/o Late Shri Moolchand Chawla R/o E-526, Greater Kailash-II, New Delhi be detained and kept in custody in the Central Prison, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from Smuggling of goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, New Delhi within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/19/96-Cus. VIII]
JAMNA DASS, Under Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1997

का०आ० 2075.—अतः संयुक्त सचिव, भारत सरकार जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विशेष रूप से शक्ति प्रदान की गई है, ने उक्त उप-धारा के अधीन आदेश फाइल सं० 673/96-सी-यू-एस० — दिनांक 12-8-96 को जारी किया और यह निर्देश दिया कि श्री मोहम्मद रफीक @रफीक मौलाना पता-2330 (तीसरा तल) साहनी भवन, कुच्चा चालान, दरियागंज-नई दिल्ली को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, तिहाड़, नई दिल्ली में अभिरक्षा में रखा जाए जिससे कि उन्हें भविष्य में माल की तस्करी का दुष्प्रेरण करने से रोका जा सके।

2. अतः केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या स्वयं को छिपा रखा है जिससे कि यह आदेश निष्पादित नहीं किया जा सकता।

3. अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को यह निदेश देती है कि वह शासकीय राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशित होने के 7 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली के सम्मुख उपस्थित हो।

[फा०सं० 673/73/96/सी-यू-एस० VIII]
जमना दास, अवर सचिव

ORDER

New Delhi, the 11th August, 1997

S.O. 2075.—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued order F. No. 673/73/96-Cus. VIII dated 12-8-96 under the said sub-section directing that Shri Mohd. Rafiq q@ Raff @ Maulana R/o 2330 (IIIrd Floor), Sahni Bhavan, Kucha Chalan, Darya Ganj, New Delhi be detained and kept in custody in the Central Prison, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from abetting the smuggling of goods.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, New Delhi within 7 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 673/73/96-Cus.VIII]
JAMNA DASS, Under Secy.

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1997

का०आ० 2076.—भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम (सं० 57) 1959 की धारा 8, उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1998-99 के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति का गठन करती है :—

1. प्रो० जी० एस० भल्ला, अध्यक्ष
प्रोफेसर, अवकाश प्राप्त
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई दिल्ली-110067.

2. डॉ० एस०जी०के० पिल्लई, चार्टर्ड इंजीनियर एवं प्रबंध परामर्शदाता, 16-IV एवेन्यू, इन्दिरा नगर, मद्रास-600020.	सदस्य
3. प्रो० एस०के० चटर्जी, प्रोफेसर, सांख्यिकी, कलकत्ता विश्वविद्यालय, न्यू साइंस बिल्डिंग, 35, बेलीगंज, सर्कुलर रोड, कलकत्ता-19.	सदस्य
4. प्रो० के०एल० कृष्ण, प्रोफेसर, दिल्ली स्कूल आफ इकनामिक्स दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली.	सदस्य
5. प्रो० एस०बी० राव, निदेशक, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता. (भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के मनोनीत)	सदस्य
6. महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी विभाग, नई दिल्ली.	सदस्य
7. वित्तीय सलाहकार, सांख्यिकी विभाग, नई दिल्ली.	सदस्य
8. उप वित्तीय सलाहकार तथा उप सचिव, सांख्यिकी विभाग, नई दिल्ली.	सदस्य सचिव

और उक्त समिति को निम्नलिखित कार्य निर्धारित करती है :—

(1) कार्य के सम्मत कार्यक्रम (योजनागत तथा योजनेतर दोनों) की समीक्षा करना तथा संशोधन प्राक्कलन 1997-98 में प्रदान की जाने वाली राशि के संबंध में सिफारिशें करना तथा भारतीय सांख्यिकीय संस्थान को सहायता अनुदान अदा करने के लिए 1998-99 के लिए वित्तीय प्राक्कलनों के संबंध में भी सिफारिशें करना।

(2) (क) वर्ष 1998-99 के दौरान भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कलकत्ता, द्वारा किए जाने वाले कार्य का कार्यक्रम (योजनागत तथा योजनेतर दोनों) दर्शाने वाले विवरण तथा इस प्रकार के कार्य के लिए सामान्य वित्तीय अनुमान तैयार करना और उसे केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार निधि की व्यवस्था करती है।

(ख) कार्यक्रम से संबंधित विस्तृत रूप-रेखा निश्चित करना।

2. समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को 31 मार्च 1998, को या इससे पहले प्रस्तुत करेगी।

3. सांख्यिकी विभाग, समिति को जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, सचिवालय सहायता प्रदान करेगा।

[सं० एम०-12011/7/96-समन्वय
एन०के० शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(Department of Statistics)

New Delhi, the 7th August, 1997

S.O. 2076.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Indian Statistical Institute Act (No. 57 of 1959), the Central Government hereby constitutes a Committee for 1998-99 consisting of :—

1. Prof. G. S. Bhalla, Professor, Emeritus, Jawaharlal Nehru University, New Delhi-67.	Chairman
2. Dr. S. G. K. Pillai, Chartered Engineer & Management Consultant, 16-IV Avenue, Indira Nagar, Madras-600020.	Member
3. Prof. S. K. Chatterjee, Professor of Statistics, Calcutta University, New Science Building, 35, Ballygunge, Circular Road, Calcutta-19.	Member
4. Prof. K. L. Krishna, Professor, Delhi School of Economics, University of Delhi, Delhi.	Member
5. Prof. S. B. Rao, Director, Indian Statistical Institute, Calcutta, (Nominee of the ISI).	Member
6. Director General, CSO, Department of Statistics, New Delhi.	Member
7. Financial Adviser, Department of Statistics, New Delhi.	Member
8. Deputy Financial Adviser and Deputy Secretary, Department of Statistics, New Delhi.	Member- Secretary

and assigns the following duties to the said Committee, namely :—

(1) Review of the agreed programme of work (both Plan and Non-Plan) and make recommendations regarding the amount to be provided in the RE 1997-98 and also make recommendations regarding the financial estimates for 1998-99 for paying 'grant-in-aid' to the ISI.

(2)(a) Preparation and submission to the Central Government of statement showing programmes of work (both Plan and Non-Plan) agreed to be undertaken by the Indian Statistical Institute, Calcutta, during the year 1998-99 for which the Central Government may provide funds, as well as general financial estimates of such work.

(b) The settlement on broad lines of the programme of work.

2. The Committee shall submit its Report to the Government on or before 31st March, 1998.

3. The Department of Statistics shall render secretariat assistance to the Committee, the headquarters of which will be at New Delhi.

[No. M. 12011/7/96-Coord.]
N. K. SHARMA, Under Secy.

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1997

का.आ. 2077.—केन्द्रीय सरकार ने भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए निर्यात से पूर्व अंडा उत्पादों का क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण करने के लिए कतिपय प्रस्ताव, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं. का.आ. 130(अ), तारीख 20 फरवरी, 1997 को राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 20 फरवरी, 1997 में प्रकाशित किए गए थे,

2. और इससे प्रभावित होने वाले उन सभी व्यक्तियों से उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे,

3 और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 20 फरवरी, 1997 को उपलब्ध करा दी गयी थीं,

4. और उक्त मसौदा पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है,

5. और यह आवश्यक है कि क्वालिटी नियंत्रण के उच्च मापदंड और स्वास्थ्य स्तरों को यूरोपियन आर्थिक समुदाय (ईईसी) 89/437/ईईसी, तारीख 20-6-1989 और संयुक्त राष्ट्र के कृषि विभाग (यूएसडीए) के विनियमों में विहित निर्देशों का अनुपालन करते हुए सुनिश्चित किया जाए,

6. अंडा उत्पादों के उत्पादन, भंडारण और परिवहन की बाबत स्वास्थ्य संबंधी अपेक्षाएं अधिकथित की जानी चाहिए और विशिष्टतया यह महत्वपूर्ण है कि इस संबंध में स्थापनों को अनुमोदन को शासित करने वाले नियम अधिकथित किए जाएं।

7. यह भी महत्वपूर्ण है कि अंडा उत्पादों के लिए स्वास्थ्य संबंधी अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए नियम अधिकथित किए जाएं।

8. प्रसंस्करणकर्ताओं का, प्रमुखतया, यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि इस आदेश में अंडा उत्पाद के लिए अधिकथित स्वास्थ्य संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और सक्षम प्राधिकारी यह देखेगा कि इस संबंध में क्वालिटी नियंत्रण निरीक्षण और मानीटरिंग की उपरिवर्णित अपेक्षाओं को पूरा करता है। क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग को शासित करने वाले ये नियम अंतरराष्ट्रीय बाजार की मांग को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं।

9. पदार्थों में ऐसे अपशिष्टों का जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पता लगाने के लिए यदाकदा ऐसी जांच करना आवश्यक है।

10. और आयातित देशों की अपेक्षाओं के प्रति निर्देश करते हुए मानीटर करने की प्रक्रिया की बाबत ऐसे उपबंध किए जाएं जो उपरोक्त स्थितियों की समानता सुनिश्चित हो जाए।

11. अतः, केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी देश में क्वालिटी मानकों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करें।

12. अतः, अब, केन्द्रीय सरकार के निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 6 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद से परामर्श करने के पश्चात् उसकी यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है :—

क. यह अधिसूचित करती है कि निर्यात से पूर्व अंडा उत्पाद क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के अध्यधीन रहते हुए होंगे।

ख. अंडा उत्पादों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 1997 के अनुसार क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण के प्रकार को ऐसे क्वालिटी नियंत्रण, निरीक्षण और मानीटरिंग के रूप में विनिर्दिष्ट करना जो ऐसे अंडा उत्पादों पर, अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट देशों को, निर्यात से पूर्व लागू होंगे।

ग. विनिर्देशों को मान्यता देना :—

(i) निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य निकायों के मानक तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मानक।

(ii) निर्यातक द्वारा घोषित ऐसे विनिर्देश जो क्रेता और निर्यातकर्ता के मध्य हुए निर्यात करार में तय पाए गए विनिर्देश है परन्तु यह तब जब कि वे उपरोक्त खंड (i) में विनिर्दिष्ट मानकों से निम्न मानकों के न हों;

घ किसी यूनिट द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुक्रम में, जिसके अन्तर्गत यूरोपियन संघ (ई.यू.) और संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.) भी सम्मिलित है, अंडा उत्पाद का निर्यात तब तक प्रतिषिद्ध होगा जब तक कि वह निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 7(1) के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों द्वारा अनुमोदित और मानिटर की गयी ऐसी यूनिट द्वारा यह कथन करते हुए एक प्रमाणपत्र के साथ कि अंडा उत्पाद लागू मानकों के अनुरूप है।

13. इस आदेश की कोई भी बात भावी क्रेताओं को अंडा उत्पाद के ऐसे वास्तविक नमूनों के भूमि या समुद्र या वायु मार्ग द्वारा निर्यात पर लागू नहीं होगी जिनका मूल्य समय-समय पर आयात-निर्यात नीति में यथा अधिकथित अनुज्ञेय सीमाओं से अधिक नहीं होगा और जहां ऐसा कोई उपबंध नहीं है वहां निःशुल्क नमूनों की मूल्य सीमा 10,000/- रुपए से अधिक नहीं होगी।

14. इस आदेश में, अंडा उत्पादों से अभिप्रेत है :—

अंडों से प्राप्त किया गया वह उत्पाद, जो उसके आवरण और छिल्ली को पृथक करने से, विभिन्न संघटक और मिश्रण से प्राप्त होता है तथा जो मानव उपयोग के लिए आशयित है। वह आंशिक रूप में अन्य खाद्य पदार्थों या संयोजनों द्वारा अनुपूरित हो सकता है, जो सांद्रित, सूखा, क्रिस्टलित, प्रशीतित, द्रुतशीतित या जमे हुए रूप में हो सकता है, बढ़ाया जा सकता है।

[फा. स. 6(1)95-ईआई एण्ड ईपी]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 4th August, 1997

S.O. 2077.—Whereas, for the development of the export trade of India, certain proposals for subjecting Egg Products to quality control and Inspection prior to export, were published as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 in the Extraordinary Gazette of Part II, Section, 3 Sub-section (ii) dated 20th February, 1997 under the order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 130(E) dated 20th February 1997;

2. And, whereas, the objections and suggestions were invited from all persons likely to be affected thereby, within a period of forty five days of the date of publication of the said order in the official Gazette;

3. And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on 20th day of February, 1997;

4. Whereas, the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government;

5 And whereas, it is necessary to maintain the highest quality standards and stipulate health requirements that would encompass the standards prescribed in European Economic Community (EEC) Directives 89/437/EEC dt. 20-6-1989, the United States Department of Agriculture (USDA) regulations etc.;

6. Whereas, health requirements should be laid down for the production, storage and transport of egg products; whereas, in particular, it is important that rules be laid down governing the approval of establishments;

7. Whereas, it is important also that the health requirements to be met by egg products be laid down;

8. Whereas, it is the responsibility primarily of the processors to ensure that egg products meet the health requirements laid down in this order; whereas, the competent authority must by carrying out quality control, inspection and monitoring see to it that processors comply with the above mentioned requirements; whereas, the rules governing these quality control, inspections and monitoring must take account of the demands of the international market;

9. Whereas, a random check must be made to detect the presence of residues of substances liable to be harmful to human health;

10. And, whereas, provisions should, therefore, be made for procedure for monitoring to ensure the above conditions of equivalence with reference to the requirements of the importing countries;

11. And, whereas, Central Government nominated Competent Authority should ensure the effective compliance of the quality standards in the Country;

12. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the Export (Quality Control and Inspection) Act 1963 (22 of 1963), Central Government after consulting the Export Inspection Council being of the opinion that it is necessary and expedient to do so for the development of the export trade of India, hereby;

(a) notifies that Egg products shall be subjected to quality control, inspection and monitoring prior to export.

(b) specifies the type of quality control, inspection and monitoring shall be in accordance with the Export of Egg products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1997 as the type of Quality Control, Inspection and Monitoring which shall be applied to such egg products prior to export, to the countries as specified, in the notification.

(c) recognises the specifications :

(i) National and International Standards and standards of other bodies recognised by the Export Inspection Council;

(ii) The specifications declared by the exporter to be the agreed specifications of the export contract between buyer and the exporter, provided that the same are not below the standard specified in clause (i) above.

(d) prohibits the export of Egg products by a unit in the course of International trade which includes European Union (EU) and United States of America (USA) unless it conforms to the standards applicable to it and is accompanied by a certificate stating that such unit is approved and monitored by the Export Inspection Agencies established under Section 7 (i) of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963).

13. Nothing in this order shall apply to the export by land or sea or air of bonafide samples of egg products to prospective buyers, the value of which shall not exceed permissible limits as laid down in Exim Policy from time to time where no such provisions exist the value limit of free sample(s) shall not exceed Rs. 10,000/-.

14. In this order, Egg Products means :—products obtained from eggs, their various components or mixtures thereof man cossumption; they may be partially supplemented by after removal of the shell and membranes, intended for huother foodstuffs or addicts; they may be liquid, concentrated, dried, crystallized, frozen, quick-frozen or coagulated;

[F. No. 6/1/95-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1997

का.आ. 2078.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अंडा उत्पादों का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण तथा मानीटरिंग) नियम, 1997 होगा।

(ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

भाग-1 (यूरोपियन संघ (ईयू) को किए गए निर्यात पर लागू)

2. परिभाषाएं.—इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी :

(क) "अधिनियम" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है,

(ख) "अभिकरण" से क्वालिटी नियंत्रण या निरीक्षण अथवा दोनों के लिए धारा 7 के अधीन स्थापित या मान्यता प्राप्त कोई अभिकरण अभिप्रेत है,

(ग) "बैच" में अंडा उत्पाद की वह मात्रा अभिप्रेत है जो समान अवस्थाओं के अन्तर्गत संसाधित की गई हो और जिसे विशेष रूप से माल एक ही सतत से क्रिया में रखा गया हो,

(घ) "प्रमाण-पत्र" से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन जारी किया गया ऐसा प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है जिसमें यह कथित किया गया है कि वस्तु क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण की शर्तों के अनुरूप है,

(ङ) "सक्षम प्राधिकारी" से कोई भी निर्यात निरीक्षण अभिकरण जो मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली तथा चेन्नई में स्थापित है या कोई भी मान्यता प्राप्त अभिकरण, जो निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अधीन मान्यता प्राप्त है अभिप्रेत है,

(च) "परेषण" से अंडा उत्पाद की ऐसी मात्रा अभिप्रेत है जो खाद्य उद्योग को अग्रिम-प्रसंस्करण के लिए एक ही गंतव्य पर पहुंचाए गए एकल परिदान के रूप में है या वह सीधे मानव उपभोग के लिए आशयित है,

(छ) "परिषद" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद अभिप्रेत है,

(ज) "गंतव्य देश" से वह देश अभिप्रेत है जिसे भारत से प्रेषित किया जाता है,

(झ) "अंडा उत्पाद" से मानव उपभोग के आशय से अंडे की झिल्ली तथा उसके आवरण को पृथक करने के उपरान्त उससे प्राप्त विभिन्न संघटक या मिश्रण अभिप्रेत है। यह अंशतः अन्य खाद्य पदार्थों या अन्य संयोजनों द्वारा बढ़ाया जा सकता है जो तरल संघटित, सूखा, कणिय, प्रशीतित, तुरन्त प्रशीतित या जमा हो सकता है,

(ञ) "प्रेषक देश" से भारत अभिप्रेत है,

(ट) "संभरणकर्ता निर्यातक" से इस नियम के अधीन निर्यात हेतु अनुमोदित अंडा प्रसंस्करण प्लांट से अंडों की खरीद करने वाला निर्यातक अभिप्रेत है,

(ठ) "उत्पादन फार्म" से अंडा उत्पाद के लिए आशयित अंडे की आपूर्ति करने वाला फार्म अभिप्रेत है,

(ड) "पैकिंग" से अंडा उत्पाद को किसी भी प्रकार के पैकिंग में रखा जाना अभिप्रेत है,

(ढ) "प्लांट" से ऐसा परिसर अभिप्रेत है जहां अंडा उत्पाद प्रसंस्कृत किया जाता है,

(ण) "पेयजल" से ऐसा जल अभिप्रेत है जिसे राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारी या अन्य अभिकरण या प्रयोगशाला द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा पीने और खाद्य प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त होने के रूप में स्वीकार किया है।

3. अनुसरणीय आधार :— प्रसंस्करणकर्ताओं का यह सुनिश्चित करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व होगा कि निर्यात के लिए अंडा उत्पाद को उत्पादन, भण्डारण और परिवहन के समीचरणों में उचित स्वास्थ्यकर अवस्थाओं के अधीन देखरेख व प्रसंस्करित किया गया है जिससे वे इन नियमों के अधीन अधिकथित स्वास्थ्य अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और यह कि उत्पाद इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा पारित आदेश में दिए गए विनिदेशों के अनुरूप हैं।

सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि इस खंड के पैरा 4.18 में विहित नियंत्रण उपायों के अनुसार प्लांट की नियमित मानिटरिंग द्वारा सभी प्रसंस्करणकर्ता अपेक्षाओं का अनुपालन करें। इस योजना की प्रभावी मानिटरिंग के लिए इस संबंध में समय समय पर परिषद द्वारा आवश्यक अनुदेश जारी किए जायेंगे।

4. निर्यात के लिए अंडा उत्पाद निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :

4.1 किसी राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा वाणिज्यिक/पर्यावरणीय संरक्षण उपायों के संबंध में जो समय समय पर बताए गए उपायों के सबध में अधिरोपित किसी कानूनी निर्बंधन का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

4.2 वे मुर्गी, बत्तख गुर्गाबी, टर्की, नायना फाउल या बटेर के अंडों से प्राप्त किए गए होने चाहिए, परन्तु यह विभिन्न प्रकार के अंडों का मिश्रण होना चाहिए।

4.3 उनके ऊपर या उनमें स्वतः दूसरे खाद्य पदार्थों के साथ मिलाया जाता है, अंडा अवयवों की प्रतिशतता जो उनमें से, उनके ऊपर अंकित होनी चाहिए।

4.4 उन्हें ऐसे अनुमोदित सयंत्र में संसाधित और तैयार किया गया होना चाहिए जो उपाबन्ध के अध्याय 1 और 2 का अनुपालन करता है तथा इन नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

4.5 उन्हें उपाबन्ध के अध्याय 3 और 4 में स्वास्थ्यकर परिस्थितियों के अधीन ऐसे अंडों से तैयार किया गया होना चाहिए जो उपाबन्ध के अध्याय 4 में अधिकथित अपेक्षाओं को पूरा करते हैं ।

4.6. उन्हें संसाधन प्रसंस्करण द्वारा तैयार किया गया होना चाहिए जिससे कि वे अन्य बातों के साथ उपबन्ध के अध्याय 6 में अधिकथित विश्लेषण विनिर्देशों को पूरा करें ।

4.7 उनकी उपाबन्ध के अध्याय 8 के अनुसरण में स्वास्थ्य जांच की गई होनी चाहिए ।

4.8 उन्हें उपाबन्ध के अध्याय 7 के अनुसार पैक किया गया होना चाहिए ।

4.9 उनका उपाबन्ध के अध्याय 9 और 10 के अनुसार भंडारकरण और परिवहन किया गया होना चाहिए ।

4.10 उन पर उपाबन्ध के अध्याय 9 के अनुसरण में स्वास्थ्य-प्रदत्ता का चिह्न लगा होना चाहिए और जहां उनका सीधे मानव उपयोग किया जाना है, खाद्य पदार्थों को लेबल लगाने, उनके प्रस्तुतीकरण और विज्ञापन के संबंध में जैसाकि अन्तिम बार उन्हें निदेश 86/197/ईईसी द्वारा संशोधित किया गया है, अन्तिम उपभोक्ता को विक्रय के संबंध में परिषद के निदेश 79/112/ईईसी तारीख 18 दिसम्बर, 1978 की अपेक्षाओं को पूरा करना चाहिए ।

4.11 उपाबन्ध के अध्याय 6 में उपवर्णित विश्लेषण विनिर्देशन के अनुसार नमूनों को प्रयोगशाला जांच हेतु ले जाया जाएगा ।

4.12 उपाबन्ध के परिशिष्ट 9 व 10 में उल्लिखित अंडा उत्पाद जो परिवेशी तापमान पर नहीं रखा गया है उसका भण्डारण और परिवहन नियत तापमान पर किया जाएगा ।

4.13 जिसके लिए अंडा उत्पाद संरक्षित किया जाएगा, प्रसंस्करणकर्ता द्वारा उस अवधि का बीमा कराया जाएगा ।

4.14 विभिन्न जांच और परीक्षण के परिणाम अभिलिखित किए जायेंगे और सक्षम प्राधिकारी को, प्रस्तुतिकरण के के लिए 2 वर्ष तक रखे जाएंगे ।

4.15 ऐसे पदार्थों के अवशेषों का पता लगाया जाएगा भेषजीय या हार्मोनीय तथा एंटीबायोटिक, कीटनाशी, अपमार्जक तथा ऐसे अन्य पदार्थ हैं जो हानिकारक हैं या जो अंडा उत्पाद के जैवीय गुणों को बदल सकते हैं और उनके उपभोग को मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक या हानिकारक बना सकते हैं ।

4.16 यदि अंडा उत्पादन के परीक्षण से यह पाया गया है कि अनुज्ञेय नियत स्तर से अधिक अवशेष हैं तो उनका प्रयोग खाद्य पदार्थों के विनिर्माण या सीधे तौर पर मानव उपभोग में अनुज्ञेय नहीं होना चाहिए ।

4.17 अवशेषों की जांच सिद्ध और वैज्ञानिक तौर पर मान्यता प्राप्त रीतियों के अनुसार होनी चाहिए ।

4.18 इसका समाधान होने पर कि प्लांट क्रिया कलापों यदि किए जाते उनकी प्रकृति से संबंधित अपेक्षाओं की पूर्ति करता है, सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्लांट को अनुमोदन प्रदान करेगा ।

4.19 सक्षम प्राधिकारी प्रसंस्करण प्लाटों के अनुमोदन के मामले में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) और विपणन और निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) तथा उद्योगों में से एक एक प्रतिनिधि से सहायता ले सकेगा ।

4.20 सक्षम प्राधिकारी अनुमोदित प्लाटों की सूची तैयार करेगा जिसमें प्रत्येक में एक शासकीय संख्यांक होगी और सक्षम प्राधिकारी अनुमोदित प्लाटों की एक सूची तथा उसमें फेरबदल भी समुचित प्राधिकारियों को भेजेगा ।

4.21 निरीक्षण तथा प्लाट और पैकिंग केन्द्रों के मानीटरिंग सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमित रूप से किया जाएगा । जो प्लाटों के सभी भागों में निर्बाध रूप से जा सकेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि नियमों का पालन किया जा रहा है ।

भाग II—संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) पर लागू

1. परिभाषा : इस आदेश के प्रयोजन के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होंगी :—

(क) 'अधिनियम' से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है ।

(ख) 'स्वीकार्य' से सक्षम प्राधिकारी द्वारा आशयित प्रयोजन के लिए उचित और स्वीकार्य अभिप्रेत है ।

(ग) 'अभिकरण' से धारा 7 के अधीन स्थापित या मान्यता प्राप्त क्वालिटी नियंत्रण या निरीक्षण या दोनों के लिए कोई अभिकरण अभिप्रेत है ।

(घ) आवेदक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इन नियमों के अधीन या इस भाग के विनियमों के अधीन निरीक्षण, सेवा के लिए निवेदन करता है ।

(ङ) 'मानव खाद्य के रूप में उपयोग किए जाने योग्य' में कोई भी अंडा उत्पाद अभिप्रेत है जब तक कि वह विकृत न हो या अन्यथा मानव खाद्य के रूप में इसके उपयोग के लिए अन्य रूप में परिवर्तित या बिगड न गया हो ।

(च) 'प्रमाण पत्र' से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन जारी प्रमाण पत्र अभिप्रेत है जिसमें यह उल्लिखित हो कि पदार्थ क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण की शर्तों के अनुरूप है ।

(छ) 'सक्षम प्राधिकारी' से मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली और मद्रास में स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई एक या कोई भी

अभिकरण जो निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अधीन मान्यता प्राप्त कोई एक अभिकरण अभिप्रेत है ।

(ज) 'अवस्था' से किसी भी उत्पाद की कोई भी अवस्था जिसमें परिरक्षण की स्थिति सफाई स्वास्थ्यगत प्रदत्ता या मानव उपभोग के लिए उचित होना सम्मिलित है किन्तु उसी तक सीमित नहीं है अभिप्रेत है जो इसकी व्यापारिकता या किसी अन्य अवस्था जिसमें ऐसे उत्पाद के प्रसंस्करण, संभालने और पैकिंग सम्मिलित है किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं है, को प्रभावित करेगी ।

(झ) 'कंटेनर या पैकेज' में कोई भी डिब्बा, केन, टिन, प्लास्टिक या अन्य संबंधित आधान रैपर या ढक्कन सम्मिलित है ।

(ञ) 'परिषद' से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद अभिप्रेत है ।

(ट) 'संभरणकर्ता निर्यातक' से इस नियम के अधीन निर्यात हेतु अनुमोदित अंडा प्रसंस्करण प्लांट से अंडों की खरीद करने वाला निर्यातक अभिप्रेत है ।

(ठ) 'अंडा उत्पाद' से मानव उपयोग के आशय से अंडे की झिल्ली तथा उसके जो अंडों के उत्पाद से प्राप्त किए जाते हैं के आवरण को पृथक करने के उपरान्त उससे प्राप्त विभिन्न संघटक या मिश्रण अभिप्रेत हैं, यह अंशतः अन्य खाद्य पदार्थों या अन्य संयोजनों द्वारा बढ़ाया जा सकता है जो तरल संघटित, सूखा कणिय, प्रशीतित, तुरन्त प्रशीतित या जमा हुआ हो सकता है ।

स्पष्टीकरण : उपरोक्त अंडा उत्पाद की परिभाषा में प्रशीतित सूखे उत्पाद, कृत्रिम अंडा उत्पाद, अंडा अनुकल्प, पोष्टिक खाद्य, सूखे बिना पकाए हुए कस्टर्ड मिश्रण, अंडा चिप्पड मिश्रण, आमलीय मसाला, नूडल, दूध और अंडा मिश्रण, केक मिश्रण, फ्रेंच टोस्ट और अंडों या अंडा उत्पाद के सैंडविच सम्मिलित नहीं होंगे । बुलट और इससे मिलते जुलते अन्य प्रमाणित स्वाद भी इसमें सम्मिलित नहीं होंगे ।

(ड) 'उष्मामापक अस्वीकृत' से ऐसा अंडा अभिप्रेत है जिसे उष्मायक में रखा गया है किन्तु उसे अंडा सेने की प्रक्रिया के दौरान असंचित अंडे या अधूरे अंडों के रूप में सेने की प्रक्रिया से निकाल दिया गया है ।

(ढ) 'लेबल' से पोत कंटेनर या अध्यहित कंटेनर पर, यदि कोई है पहचान के रूप में कोई छपा हुआ, ग्राफिक या अन्य कोई प्रणाली का प्रदर्शन अभिप्रेत है ।

(ण) 'पेस्टोराइज्ड' से अंडा उत्पाद के प्रत्येक कण को ऊष्म करना या उसके सूक्ष्म जीवन समरूप से हानिकारक पदार्थ को ऐसी किन्हीं अन्य प्रणालियों द्वारा नष्ट करना जो इन विनियमों में निहित है अभिप्रेत है ।

(त) 'प्लांट' से कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है जहां अंडा उत्पाद को प्रसंस्कृत किया जाता है ।

(थ) 'पेय जल' से ऐसा जल अभिप्रेत है जिसे राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण या अन्य अभिकरण या किसी ऐसी प्रयोगशाला द्वारा अनुमोदित किया है और वह सक्षम प्राधिकारी को सुरक्षित पेय और उपयुक्त खाद्य संसाधन के रूप में स्वीकार्य है ।

(द) 'संसाधन' से अंडा उत्पाद का विनिर्माण अभिप्रेत है इसमें टूटे अंडे या फिल्टरिंग (छानन) मिश्रण, छीलन, पैस्टोराइजिंग, स्थिरता प्रशीतित, हिम शीतित या सुखाए या पैकेजिंग अंडा उत्पाद प्लांट जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है सम्मिलित है ।

(ध) 'नमूना' से किसी उत्पाद का निरीक्षण या विश्लेषण के लिए नमूना लिया जाना अभिप्रेत है ।

(न) 'स्वच्छ करना' से कोई जीवाणुनाशी उपचार अभिप्रेत है जो सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रभावी रूप में अनुमोदित है, जिनमें रोगाणु सम्मिलित हैं ।

(प) 'नोवहन आधान' से ऐसा आधान अभिप्रेत है जो किसी उत्पाद के पैकिंग के उपयोग में आता है ।

(फ) 'स्थिरीकरण' से किसी अंडा उत्पाद का शर्करारहित संसाधन अभिप्रेत है ।

(ब) 'श्वेत या श्वेतक' से इस भाग के प्रयोजन के लिए ऐसा उत्पाद अभिप्रेत है जो किसी अंडे के आवरण को तोडकर और उसे जरदी से अलग करके प्राप्त किया जाता है ।

2. अनुपालन का आधार

प्रसंस्करणकर्ता का यह प्रारंभिक दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि निर्यात के आशय से अंडा उत्पाद की संभाल और प्रसंस्करण, उत्पादन, भण्डारण और परिवहन के प्रत्येक स्तर पर उचित स्वास्थ्यकर अवस्थाओं में किया गया है और यह इन नियमों में अधिकथित स्वास्थ्य संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है तथा यह कि उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश में किए गए विनिर्देशों के अनुरूप है ।

सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि इस भाग के पैरा 3.4 में विहित नियंत्रण उपायों के अनुसार सभी प्रसंस्करणकर्ता प्लांट की नियमित मानीटरिंग करके अपेक्षाओं की पूर्ति करते है । इस योजना की प्रभावी मानीटरिंग के लिए, इस विषय में परिषद आवश्यक अनुदेश जारी करेगी ।

3. निर्यात के लिए अंडा उत्पाद निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :

3.1 किसी भी राज्य केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी वाणिज्य पर्यावरणीय संरक्षण उपायों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।

3.2 उन्हें इस भाग के अध्याय 12 में अधिकथित सफाई, संसाधन और सुविधा अपेक्षाओं का पालन करना चाहिए।

3.3 उन्हें इस भाग के अध्याय 13 में अधिकथित अंडा उत्पाद के लिए पहचान और चिह्नन का पालन करना चाहिए।

3.4 सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान होने पर कि प्लांट उसमें की जाने वाली गतिविधियों की प्रकृति को संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करता है, वह ऐसे प्लांट को अनुमोदित करेगा।

3.5 सक्षम प्राधिकारी प्रसंस्करण प्लांटों के अनुमोदन के मामले में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकारी (एपीडा) और विपणन और निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) तथा उद्योग में से एक-एक प्रतिनिधि से सहायता ले सकेगा।

3.6 सक्षम प्राधिकारी अनुमोदित प्लांटों की एक सूची तैयार करेगा जिसमें से प्रत्येक को शासकीय संख्यांक दिया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी अनुमोदित प्लांटों की अपनी सूची और उसमें पश्चातवर्ती परिवर्तन को समुचित प्राधिकारियों को अधिसूचित करेगा।

प्लांट की नियमित निरीक्षण व मानीटरिंग और पैकिंग सैंटर्स का नियमित रूप से सक्षम प्राधिकारी निरीक्षण करेंगे जो यह सुनिश्चित करने के लिए नियमों का पालन किया गया है कि वह हर समय प्लांट के सभी भागों का मूल्यांकन करेंगे।

3.7 प्लांट और पैकिंग केन्द्रों का निरीक्षण और मानीटरिंग सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमित रूप से किया जाएगा। वह प्लांटों के सभी भागों में निर्बाध रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए जा सकेगा कि इन नियमों का पालन किया जा रहा है।

4. प्रमाणीकरण : प्लांट एकक के अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी अपना यह समाधान हो जाने पर कि सुसंगत अपेक्षाओं की पूर्ति करने के उपरान्त प्लांटों को विधिमान्य अनुमोदन संख्यांक प्राप्त है, विहित रूप में पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करेगा।

4.1 सक्षम प्राधिकारी संसाधनकर्ता या निर्यातिकर्ता के अनुरोध पर अपना यह समाधान हो जाने पर कि सुसंगत मानकों की अपेक्षाएं पूरी कर दी गयी हैं, कोई अन्य प्रमाण पत्र भी जारी करेगा।

5. फीस :

5.1 अंडा संसाधन प्लांट के अनुमोदन के लिए इन नियमों के खंड 4.18 और 4.4 के अनुसार आवेदन के साथ संसाधनकर्ता द्वारा रु. 2000/- का संदाय फीस के रूप में किया जाएगा।

5.2 निर्यातित अथवा निर्यात संभरणकर्ता अंडा प्रसंस्करण प्लांट के उपरोक्त अनुमोदित नियम 5.1 के अनुसार सक्षम प्राधिकरण को प्रसंस्करणकर्ता द्वारा 0.2 प्रतिशत की दर से एफ.ओ.बी. मूल्य की दर से शुल्क सदत्त किया जाएगा।

टिप्पण : संभरणकर्ता/निर्यातिकर्ता द्वारा सुदेय प्रत्येक परेषण के लिए फीस की राशि के रुपए के निकटतम तक पूर्णांकित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए जहां ऐसी राशि में रुपए का भाग सम्मिलित है वहां, यदि ऐसा भाग 50 पैसे या अधिक है, इसमें एक रुपए की वृद्धि कर दी जाएगी और यदि ऐसा भाग 50 पैसे से कम है तो इसे छोड़ दिया जाएगा।

7. अपेक्षा पूरी नहीं किए जाने की दशा में सक्षम प्राधिकारी उपाय करेगा।

7. अपील .

7.1 कोई भी व्यथित व्यक्ति,

(i) नियम 4.18 (भाग-I) और नियम 3.4 (भाग-II) के अनुसार अनुमोदन के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी का विनिश्चय नहीं होने की दशा में,

(ii) इस अधिसूचना के नियम 4 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार करने पर,

(iii) इस अधिसूचना के नियम 7 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन को वापिस लेने के लिए विनिश्चय की दशा में,

7.2 अपीली प्राधिकारी में कथित कोई भी व्यक्ति ऐसे विनिश्चय की प्राप्ति के 10 दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अपीली प्राधिकारी को अपील कर सकेगा।

7.3 इस प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा अपीली प्राधिकरण में पांच सदस्य नियुक्त होंगे।

7.4 अपीली प्राधिकरण की कुल सदस्यता का कम से कम दो तिहाई गैर-सरकारी सदस्य होंगे।

7.5 अपील प्राधिकरण की किसी भी बैठक की गणपूर्ति तीन से होगी।

7.6 अपील का निपटारा उसकी प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा।

अध्याय I

अनुमोदन और प्रचालन की सामान्य शर्तें

1. प्रतिस्थापन के पास कम से कम निम्नलिखित होना आवश्यक है :

1. अब क्षेत्रों में जहां अंडों का भंडारण और अंडा उत्पाद का विनिर्माण या भंडारण किया जाता है :—

1.1 जल सहय पर्ण जो आसानी से साफ और संदूषित किया जा सके व सडन रहित हो तथा इस प्रकार का होना चाहिए कि उसकी नाली में पानी की निकासी की सुविधा हो, पानी की

निकासी के मार्ग में नाली की ओर होना चाहिए जिसमें ग्रेटिंग तथा ट्रैप लगे हों जो बदबू को दूर कर सके।

1.2 दीवारें चिकनी, टिकाऊ, अभेद्य और हल्के रंग वाली दो मीटर तक धोयी जा सकने वाली परत चढ़ी हुई और भंडारण के लिए ठंडा या प्रशीतित करने के कक्ष कम से कम भंडारण की ऊंचाई तक धोने वाली परतदार दीवारें होनी चाहिए, दीवारें व फर्श जहां मिलते हों वह गोलाई लिए हुए या इस प्रकार बनी होनी चाहिए जिससे उन्हें साफ करने में आसानी हो।

1.3 दरवाजों की सामग्री इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिसका कोई भाग विकृत न हो और यदि लकड़ी की हो तो उसके दोनों तरफ चिकनी व अभेद्य आवरण होना चाहिए।

1.4 छत ऐसी होनी चाहिए जो कि आसानी से साफ की जा सके और जिसका निर्माण इस प्रकार का होना चाहिए कि धूल मिट्टी को इकट्ठा होने से रोक सके व टीलों का बनना, रंग रोगन का उतरना रोका जा सके और वहां पर भाप का जमाव न हो।

1. 1.5 पर्याप्त वायु संचालन हो, और यदि आवश्यक हो, तो अच्छे प्रतिपारिक निष्कर्षण लगे हों;

1.6 पर्याप्त प्राकृतिक या कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था।

1.7 जहां तक संभव हो कार्यस्थल के पास पर्याप्त संख्या में गर्म पानी से उपकरण हों, हाथों को साफ व रोगाणुमुक्त करने की सुविधाएं होनी चाहिये। नल हाथों से या बाहों से संबंधित नहीं होने चाहिये, हाथों को साफ करने के लिये चलते हुए गर्म पानी/ठंडे पानी की सुविधा होनी चाहिये या पहले से उपयुक्त तापमान पर मिश्रित पानी उपलब्ध हो, जो उत्पादों को रोगाणुमुक्त और साफ करने के लिये हों और हाथ साफ करने वाले तौलिये एक बार प्रयोग किए जाने चाहिये। औजारों को रोगाणुमुक्त करने की सुविधायें होनी चाहिये।

2. परिवर्तनशील कमरे की समुचित संख्या हो जिसमें चिकने, अभेद्य और धोई जा सकने वाली दीवारें और फर्श, धावन पात्र, स्वक्षालन शौचालय होने चाहिये। इनका बहाव सीधे कार्यस्थल की ओर नहीं होना चाहिये। धावन पात्रों में बहता हुआ गर्म और ठंडा पानी या उपयुक्त तापमान पर पहले से मिलाया हुआ पानी होना चाहिये, हाथों को साफ करने के लिये व रोगाणुमुक्त करने के लिये सामग्री होनी चाहिये, छोटे तौलिये केवल एक बार उपयोग किये जाने के लिये होने चाहिये। धावन पात्र के नल हाथों से प्रचालित किये जाने वाले नहीं होने चाहिये। शौचालयों के निकट पर्याप्त संख्या में धावन पात्र होने चाहिये।

3. स्थिर और गतिशील आधानों और टंकियों को साफ करने और रोगाणुमुक्त करने के लिये एक अलग क्षेत्र और पर्याप्त सुविधायें होना चाहिये। तथापि यह क्षेत्र और यह सुविधायें उस दशा में आवश्यक नहीं होगी यदि उन आधानों और टंकियों को साफ करने और रोगाणुमुक्त करने की व्यवस्था किन्हीं अन्य केन्द्रों पर की गई है।

4. पेयजल प्रदाय करने की सुविधायें, कच्चे पानी की पूर्ति, वाष्प उत्पादन अग्निशयन और रेफ्रिजरेशन उपकरणों को ठंडा करने के लिये प्राधिकृत है, परन्तु इस प्रयोजन से लगाये गये पाइपों से अन्य प्रयोजनों के लिये जल का प्रयोग वर्जित होगा और अंडा उत्पाद को संक्रमण का कोई जोखिम नहीं होगा, ऐसी भाप और संबद्ध जल अंडे के संपर्क में नहीं आयेंगे या साफ किये जाने के लिये या रोगाणुमुक्त डिब्बे प्लांट या उपकरण जो अंडा उत्पाद के संपर्क में है उनके संपर्क में नहीं आयेंगे, कच्चे पानी को ले जाने वाले पाइपों को पीने योग्य जल से अलग रखा जायेगा।

5. किटाणुओं जैसे कीड़े और मकोड़े से सुरक्षित रखने के लिये समुचित उपकरण होंगे।

6 उपकरण, कर्पालग और उपस्कर या उनकी सतह, जो अंडा उत्पाद के संपर्क में आयेगी वह चिकनी सामग्री की बनी होनी चाहिये जिसको आसानी से साफ किया जा सके और धुलाई तथा रोगाणुमुक्त किया जा सके जंग के प्रभाव से मुक्त तथा अंडा उत्पाद को ऐसे पदार्थ, इतनी मात्रा में अंतरित न करने वाला हो, जो मानव स्वास्थ्य को खतरा पैदा न करे, अंडा उत्पाद की संरचना में हानि पहुंचाये या उनके जोखिम गुणों को विपरीत रीति में प्रभावित करे।

अध्याय—II

प्लांट के अनुमोदन के लिये विशेष शर्तें

अध्याय–1 में उल्लिखित सामान्य शर्तों के अतिरिक्त प्रति स्थापना में निम्नलिखित होना चाहिये।

1. अंडों और परिष्कृत अंडा उत्पाद के लिये उचित और अलग भंडारण कक्ष जहां अंडा उत्पाद की रेफ्रिजरेशन में उचित तापमान पर रखा जा सके। प्रशीतित गृह में थर्मामीटर लगा होना चाहिये या रिमोट रिकार्डिंग थर्मामीटर होना चाहिए।

2. जहां प्रदूषित अंडों का प्रयोग होता है, वहां उन्हें धोने और रोगाणुमुक्त करने की सुविधायें होनी चाहिये, उत्पादों की सूची जो इन्हें रोगाणुमुक्त करने के लिये प्राधिकृत है, बनाई जानी चाहिये।

i. अंडों को तोड़ने के लिये उनके अंतर्वस्तुओं को प्राप्त करने के लिये तथा उनके भाग और छिल्ली को प्रकार करने के लिये एक विशेष कक्ष उपयुक्त सुविधाओं के साथ होना चाहिये।

ii. उपरोक्त रंग में निर्दिष्ट के अलावा अन्य संचालन के लिये एक पृथक कक्ष होना चाहिये, जहां अंडा उत्पाद पेस्चुराइज्ड है, पेस्चुराइजेशन जैसा कि पूर्वत रंग में निर्दिष्ट है, कक्ष होना चाहिये यदि प्रतिस्थापना के पास बंद

पंस्कूराइजेशन पद्धति है और अन्य मामलों में पेस्चुराइजेशन प्रक्रिया को पृथक रूप में पृथक कक्ष में (जैसाकि रंग में निर्दिष्ट है) किया जाना चाहिये, अन्य मामलों में अंडे उत्पाद को प्रदूषित होने से बचाने के लिये पेस्चुराइजेशन के उपरान्त प्रत्येक सावधानी बरती जानी चाहिये ।

4. अंडा अंश को संयंत्रों में ले जाने के लिये उपयुक्त सुविधायें हों ।

5. इन नियमों में उपबंधित के अनुरूप, अंडा उत्पाद के संसाधन के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित उपस्कर हो, जो कम से कम निम्नलिखित के साथ होने चाहिये ।

(i) पेस्चुराइजेशन से संबंधित मामलों में :
—स्वचालित तापमान नियंत्रण
—रिकार्डिंग तापमापक
—स्वचालित सुरक्षात्मक उपकरण जो अपर्याप्त ऊष्मा का प्रतिरोधक हो

(ii) निरंतर पैस्चुराइजेशन प्रणाली के मामले में उपस्कर में निम्नलिखित उपकरण भी लगाये जायेंगे

—पर्याप्त सुरक्षात्मक प्रणाली जो अपूर्ण पेस्चुराइज्ड उत्पाद के साथ पस्चुराइजेशन अंडा उत्पाद का मिश्रण होने से बचायेगा
—स्वचालित सुरक्षात्मक रिकार्डिंग उपकरण जो उपरोक्त का मिश्रण होने से रोक सके।

6. खाद्य पदार्थ और उसके संयोजक के भंडारण के मिश्रण के लिये पृथक कक्ष ।

7. जहां उत्पाद प्रयोजन आधानों में पैक किया जाता है यदि आवश्यक हो ऐसे आधानों और उनके विनिर्माण में आने वाली कच्ची सामग्री के भंडारण के लिए एक समुचित एवं पृथक क्षेत्र होना चाहिए।

8. अंडा छिलकों का तात्कालिक रूप से हटाने के लिए सुविधायें होनी चाहिए तथा अंडे और अंडा उत्पाद जो मानव उपभोग के लिये उन्हें तुरन्त हटाने और उन्हें पृथक रखने की सुविधायें होनी चाहिए।

9. अंडा उत्पाद की स्वास्थ्यकर पैकिंग के लिये उपयुक्त उपस्कर होने चाहिये ।

10. इन नियमों की अपेक्षानुसार कच्ची सामग्री और अंडा उत्पाद का विश्लेषण और उसकी जांच की जानी चाहिए, प्लांट में उपयुक्त प्रयोगशाला होनी चाहिए, यदि नहीं है, तो इन अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाली प्रयोगशाला की सेवायें ली जानी चाहिए, पश्चात् वर्ती के मामले में वह तदनुसार सक्षम प्राधिकारी को सूचित करें ।

11. जहां अपेक्षित हो, प्रशीतित अंडा उत्पाद को गलाने के लिये उचित उपस्कर होने चाहिये और अनुमोदित प्लांट में उसको संसाधन तथा आगे संभाल होनी चाहिए।

12. साफ और रोगाणुमुक्त उत्पाद के भंडारण के लिये पृथक कक्ष होना चाहिए।

अध्याय—3

परिसर उपकरण और प्लांट के कर्मचारियों से संबंधित स्वास्थ्यकर अपेक्षायें

कर्मचारी परिसर और उपस्करों की सफाई के लिये उच्चतम स्तर अपेक्षित हैं :—

1. जो कर्मचारी अंडा उत्पाद की संभाल और उसे संसाधित करेंगे व विशेष रूप से स्वच्छ कार्य करते समय पहनने वाले वस्त्र पहनेंगे और सिर पर टोपी लगायेंगे। इन को कार्य आरम्भ करने समय और कार्य के विशेष सत्र में हाथों को कीटाणुमुक्त करने के लिए बार-बार हस्त प्रक्षालन करना होगा । जहां अंडा उत्पाद का संसाधन और भंडारण किया जाता है वहां पर धूम्रपान, खाना, थूकना और चबाना निषेध होगा।

2. कोई भी पशु प्लांट के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, कोई भी कीड़े मकौड़े और कोई अन्य कीटाणु यदि पाये जायेंगे तो उनको अच्छी प्रकार से नष्ट कर दिया जायेगा।

3. अंडा उत्पाद से संबंधित कार्य में प्रयोग होने वाले परिसर, उपकरण और उपस्कर हैं स्वच्छ और अच्छी अवस्था में रखे जाने चाहिये। उपकरण और उपस्कर, यदि आवश्यक हों कार्य दिवस के दौरान दिन का कार्य समाप्त होने पर और यदि वे मिट्टी पर पड़े हैं तो दुबारा प्रयोग करने से पहले सावधानी से अनेक बार साफ और कीटाणुमुक्त किये जाने चाहिये। अंडा उत्पाद को ले जाने के लिये ढकी हुई पाइप लाईन प्रणाली की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे ऐसी समुचित सफाई प्रणाली हो जो यह सुनिश्चित करेगी कि उसके सभी भाग सफाई और रोगाणुमुक्त हैं। पाइपों को सफाई और रोगाणुमुक्त करने के पश्चात् साफ पानी से खंगालना चाहिये।

4. सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा लेने के पश्चात् अन्य खाद्य पदार्थों को प्रसंस्करण के सिवाय, चाहे यह साथ न हो या भिन्न समय पर, परिसर, उपकरण और उपस्कर अंडा उत्पाद को संसाधन करने के अतिरिक्त और किसी भी प्रयोग में नहीं लाना चाहिये। परन्तु प्रदूषित होने से रोकने के लिये सभी उपयुक्त उपाय अपनाये जाने चाहिये या इन नियमों के अन्तर्गत उत्पन्न में विपरीत बदलावों से संबंधित उपाय करने चाहिये।

5. पेय जल सभी उद्देश्यों के लिये प्रयोग किया जाना चाहिये तथापि अपेयजल अपवाद स्वरूपमामलों में भाप उत्पादन के लिये प्रयोग किया जाना चाहिये बशर्ते कि

इसके लिये लगाये गये पाइप अन्य उद्देश्यों के लिये इनमें जल का प्रयोग नहीं होने देते और इसमें अंडों या अंडा उत्पाद को किसी प्रकार का संदूषण नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अपेय जल का प्रयोग, रेफ्रिजरेशन उपस्कर को ठंडा करने के अपवादात्मक मामलों में किया जा सकता है। अपेय जल पाइप पेय जल पाइपों से स्पष्ट तथा अलग होनी चाहिये।

6. साफ करने वाले पदार्थ, रोगाणुमुक्त करने वाले पदार्थ और दूसरे पदार्थों का प्रयोग और भंडारण इस प्रकार से होना चाहिये कि उपस्कर, उपकरण और अंडा उत्पादों पर उनका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उपकरणों और उपस्करों पर इनके प्रयोग के बाद उनको पेय जल से अच्छी प्रकार से खंगालना चाहिये।

7. ऐसे व्यक्ति जो संदूषितकरण के संभव स्रोत हो सकते हैं, उनको अंडों या अंडा उत्पादों या उनके रख रखाव से संबंधित कार्य करने की अनुमति नहीं होनी चाहिये।

8. कोई भी व्यक्ति जिसको अंडों या अंडा उत्पादों के कार्य में लगाया गया है उसको स्वास्थ्य प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। स्वास्थ्य प्रमाणपत्र का प्रति वर्ष नवीनीकरण कराना चाहिये जब तक कि उसी प्रकार की गारंटी देने वाली दूसरी कर्मचारी चिकित्सा जांच योजना को सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता न दे दी गई हो।

अध्याय—4

अंडा उत्पाद के विनिर्माण के लिये अंडों से संबंधित अपेक्षायें

1. अंडा उत्पाद के विनिर्माण के लिये प्रयोग किये गये अंडों को उचित पैकिंग में रखना चाहिये।

2. (i) अंडा उत्पाद के विनिर्माण के लिये केवल उष्मायित्र में रखे बिना ऐसे अंडे प्रयोग किये जाने चाहिये जो मानव उपभोग के लिये उचित हो। उनको पूर्णतः विकसित और बिना तोड़-फोड़ के होना चाहिये।

(ii) उपरोक्त (i) के अल्पीकरण के द्वारा अंडा उत्पाद के विनिर्माण के लिये टूटे हुए अंडे प्रयोग में लाये जा सकते हैं बशर्ते वे अनुमोदित प्लांट को जहां उन्हें जल्दी से जल्दी तोड़ा जायेगा, उत्पादन फार्म द्वारा सीधे भेजे गये हों।

3. अंडा और अंडा उत्पाद, जो मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त है, उनको हटा लेना चाहिये और उनको ऐसी रीति से विकृत किया जाना चाहिये ताकि वे मानव उपभोग के लिये पुनः प्रयोग न हो सके। उन्हें अध्याय–2 के बिन्दु 8 की व्यवस्थानुसार तुरन्त कमरे में रखा होना चाहिये।

अध्याय–5

अंडा उत्पाद के विनिर्माण के लिये विशेष स्वास्थ्यकर अपेक्षायें

सभी प्रक्रियायें इस प्रकार से की जानी चाहियें ताकि अंडा उत्पाद के उत्पादन संभाल और भंडारण के दौरान किसी प्रकार के संदूषण से बचा जा सके और विशेष रूप से निम्नलिखित किया जाना चाहिये।

1. अंडा और अंडा उत्पाद का अनुमोदित प्लांट में आगे के संसाधन के लिये अध्याय 2 के बिन्दु 1 में बताये गये कमरों में पहुंचते ही उनका संसाधन होने तक तुरन्त भंडारण किया जाना चाहिये। इन कक्षों का तापमान इतना होना चाहिये जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे संदूषित नहीं है। अंडे के छिलकों को सीधे रूप में फर्श पर नहीं रखनी रखनी चाहिये।

2. अंडों को पैक नहीं किया जाना चाहिये और यदि आवश्यक हो, तो उनको उस कमरे में धोना चाहिये और रोगाणुमुक्त कर लेना चाहिये जो अंडा तोड़ने वाले कक्ष से पृथक होगा। पैकिंग सामग्री को अंडा तोड़ने वाले कक्ष में नहीं ले जाना चाहिये।

3. अंडों को अध्याय 2 के बिन्दु 3(i) में बताये गये कमरे में ही तोड़ना चाहिये। अध्याय 4 के बिन्दु 2(ii) में उल्लिखित अनुसार टूटे अंडों का संसाधन बिना किसी देरी के करना चाहिये।

4. गंदे अंडों को तोड़ने से पूर्व साफ कर लेना चाहिये। यह कक्ष अंडे तोड़ने वाले कक्ष से या किसी ऐसे कक्ष से जहां खुले अंडों की अर्न्तवस्तु रखी जाती है, पृथक होगा। सफाई प्रक्रिया इस प्रकार की होनी चाहिये ताकि अंडे की अर्न्तवस्तुओं को संदूषण और मिलावट से बचाया जा सके। अंडों के छिलके तोड़ने समय पर्याप्त सूखे होने चाहिये जिससे अंडे की अर्न्तवस्तुओं को साफ करने वाले जल की गन्दगी से होने वाली मिलावट से बचाया जा सके।

5. मुर्गी या टर्की या गोइना फालके अंडों से भिन्न अंडों की संभाल और संसाधन पृथक रूप से करनी चाहिये। जब मुर्गी, टर्की, गोइना, फालके के अंडों का संसाधन करना हो तो सभी उपस्कर साफ और कीटाणुरहित होने चाहिए।

6. अंडों को तोड़ने की प्रक्रिया, चाहे किसी भी प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गयी हो, इस प्रकार की होनी चाहिये जिससे कि अंडों के तत्वों को संभावित संदूषण से बचाया जा सके। इसके लिये अंडों के तत्व को सेंट्रीफ्यूगेशन या उन्हें तोड़कर प्राप्त नहीं करना चाहिए और या खाली खोलों से अंडे की सफेदी के अवशेषों को सेन्ट्रीफ्यूगेशन से भी प्राप्त नहीं करना चाहिए जहां तक संभव हो सके खोलों के अवशेषों

या झिल्लियों को अंडे उत्पाद से अलग रखना चाहिए और अध्याय–6 के बिन्दु 2(ii) में विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

7. अंडे उत्पाद को, तोड़ने के उपरान्त जहां तक संभव हो सके शीघ्रातिशीघ्र प्रत्येक अंश का संसाधित किया जाना चाहिए। ताप संसाधन, जिसमें अंडा उत्पाद को किसी विद्यमान पैथोजनिक ओरगेनिज्म को हटाने के लिए समुचित अवधि तक, समुचित ताप दिया जाना सम्मिलित है, दिया जाना चाहिए। ताप संसाधन के दौरान तापमान सतत रूप से रजिस्टर किया जाना चाहिए। प्रत्येक बैच के साथ किए गए संसाधन का अभिलेख दो वर्ष के लिए सक्षम प्राधिकारी के निपटान हेतु रखा जाना चाहिए। प्रत्येक अपर्याप्त रूप से संसाधित किए गए बैच को तुरन्त उसी प्लांट में पुनः संसाधित अंडा उत्पाद मानव उपभोग के लिये उचित हो। यदि यह मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाया जाए तो उसे अध्याय–4 के बिन्दु 3 के अनुसार नष्ट कर देना चाहिए।

8. यदि तोड़ने के उपरान्त तुरन्त उनका संसाधन नहीं किया जाता है तो अंडे के तत्वों को संतोषप्रद स्वास्थ्यकर परिस्थितियों में भंडारण कर देना चाहिए या तो उनको प्रशीतित या चार डिग्री सेल्सियस से अनधिक तापमान पर रखा जाना चाहिए। शर्करा रहित अवयवों के मामले को छोड़कर, चार डिग्री सेल्सियस पर भंडारण 48 घंटों से अधिक नहीं होना चाहिए।

9. निम्नलिखित सामान्य शर्तों का पालन किया जाना चाहिए :—

(i) उनकी पैकिंग, जांच, परिवहन और संभाल इन नियमों की अपेक्षानुसार की जायेगी।

(ii) उनको अध्याय 2 में अधिकथित अपेक्षाओं के अनुसार लेबल किया जाएगा माल की प्रकृति निम्नांकित रूप में उपदर्शित की जाएगी — अप्राश्च्यूराइड अंडा उत्पाद गन्तव्य स्थान पर संसाधित किया जायगा तथा तोड़ने का समय व तारीख,

10. संसाधन के उपरान्त आगामी संसाधित प्रक्रियायें यह सुनिश्चित करेंगी कि अंडा उत्पाद में पुनः कोई संदूषण नहीं होगा। तरल उत्पाद या ठोस उत्पाद जिन्हें कक्ष तापमान पर नहीं रखा गया है, या तो सूखा हो या ठंडा हो जो 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। तरन्त या ख़मीरीकरण प्रक्रिया के उपरान्त उत्पाद को संसाधित करने के बाद तुरन्त प्रशीतित करने के लिए रखना चाहिए।

11. जब तक कि उन्हें अन्य खाद्यों के विनिर्माण के प्रयोग में न लाया गया हो अंडे उत्पाद को इन नियमों में अपेक्षित तापमान पर रखना चाहिए।

12. अनुमोदित प्लांट में, ऐसी कच्ची सामग्री से जो खाद्य पदार्थों के विनिर्माण के लिए उपयुक्त नहीं है, अंडा उत्पाद कर प्रतिषिद्ध है भले ही वह अखाद्य प्रयोजनों के लिए हों।

अध्याय–6

विश्लेषणात्मक विनिर्देश

1. सूक्ष्मजैविकी मापदंड

संसाधन के बाद अंडा उत्पादों के सभी बैचों की यह गारंटी देने के लिए कि वे निम्नलिखित माप दण्डों को पूरा करते हैं, संसाधन प्लांटों में नमूनों के आधार पर सूक्ष्मजैविकी जांच की जानी चाहिए :—

(i) सालमोनेल्ला—अंडा उत्पाद में 25 ग्राम या मिली ली. का अभाव,

(ii) अन्य मापदंड :

—वर्णमध्यक वायुजीवी जीवाणु : एम. = 10^5 / ग्राम या 1 मि.ली. में

—प्रवेश या आहार नाल जीवाणु—एम. = 10^2 / ग्राम या 1 मिली लीटर में

—गुच्छाणु — अंडा उत्पादन में 1 ग्राम का अभाव

एम = जीवाणु की संख्या का मान, यदि एक या अधिक नमूना एक को में जीवाणु की संख्या एम या अधिक है तो यह परिणाम असंतोषजनक माना जाता है।

2. अन्य मापदंड

अंडा उत्पादों के सभी बैचों की, यह गारंटी देने के लिए कि वे निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं, संसाधन परस्थापनाओं में नमूने के आधार पर जांच की जानी चाहिए :—

(i) 3 ओ एच—ब्यूटिरिक अम्ल की सान्द्रता अपरिष्कृत अंडा उत्पाद के सूखे पदार्थ में प्रति किलो ग्राम, 10 मिलीग्राम से अधिक न हो।

(ii) संसाधन से पहले अंडे व अंडा उत्पादों को स्वास्थ्यप्रद रूप में सचालन को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित मापकों का प्रयोग किया जाएगा। अंडा उत्पादों के सूखे पदार्थों में दुग्धाम्ल की मात्रा प्रति किलोग्राम में 1000 मिलीग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। केवल असंसाधित उत्पादों पर लागू है।

—एकसीनिक अम्ल की मात्रा अंडा उत्पाद के सूखे पदार्थ में प्रति किलोग्राम में 25 मिलीग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि किण्वणित उत्पादों के मामलों में वह मान वह होगा जो किण्वन प्रक्रिया से पहले अभिलिखित किया गया है।

(iii) बचे हुए अंडों के छिलकों की मात्रा, अंडों की झिल्ली और अंडा उत्पाद में अन्य दूसरे कण, अंडा उत्पाद में प्रति किलोग्राम में 100 मिली ग्राम से अधिक नहीं होने चाहिए।

(iv) पदार्थ की अपशिष्ट मात्रा सह्य सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अध्याय–7

स्वास्थ्य नियंत्रण और उत्पादन का पर्यवेक्षण

1. प्लांटों का पर्यवेक्षण सक्षम प्राधिकारी के अधीन होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण में ऐसे पर्यवेक्षण उपाय सम्मिलित होंगे जो यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझे जायेंगे कि अंडा उत्पाद के विनिर्माताओं ने इन नियमों की अपेक्षाओं को पूरा कर दिया है और इनमें विशेष रूप से निम्नलिखित होगी :—

—अंडों के उद्गम तथा अंडा उत्पाद के गन्तव्य तथा अभिलेख की जांच।

—अंडा उत्पादों के विनिर्माण के उद्देश्य से अंडों का निरीक्षण।

—प्लांटों से प्रेषण पर अंडा उत्पादों का निरीक्षण।

—परिसर की स्वच्छता, सुविधाओं और उपस्करों तथा कर्मचारियों के स्वास्थ्य का सत्यापन।

—प्रयोगशाला परख के लिये अपेक्षित कोई नमूना यह सुनिश्चित करने के लिये लेना कि अंडे व अंडा उत्पाद इन नियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप है। ऐसी जांच के परिणामों को रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिये और उसे अंडा उत्पाद विनिर्माता को अधिसूचित करना चाहिये।

2. सक्षम प्राधिकारी की प्रार्थना पर, अंडा उत्पाद की विनिर्माताओं को, जहां यह अंडा उत्पाद के स्वास्थ्यप्रद उत्पादन के सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक प्रतीत होता है, प्रयोगशाला परीक्षणों की पारम्परता बढ़ायी जानी चाहिये।

अध्याय–8

अंडा उत्पाद की पैकिंग

1. अंडा उत्पादों को संतोषजनक स्वास्थ्यजनक परिस्थितियों में पैक करना चाहिये जिससे कि ये सुनिश्चित हो जाए संदूषित नहीं है।

आद्यानों के मामलों में निम्नलिखित सहित स्वास्थ्य संबंधी सभी नियमों का पालन करना चाहिए :—

—ये ऐसे नहीं होना चाहिए जो अंडा उत्पादों के जैविक गुणों का ह्रास करते हों।

—ये अंडा उत्पादों में ऐसे पदार्थों को अन्तरित करने वाले नहीं होने चाहिये जो मानव स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हों।

—ये अंडा उत्पादों को पर्याप्त रूप से संरक्षण देने वाले और मजबूत होने चाहिये।

2. जिस कक्ष में आद्यान रखे जाएं वह धूल व कीड़े मकोड़ों से रहित होना चाहिए। प्रयोज्य आद्यानों को बनाने वाली सामग्री का भंडारण जमीन पर नहीं करना चाहिए।

3. अंडा उत्पाद के लिये प्रयोग किये गये आद्यानों को प्रयोग करने से पहले साफ करने चाहिए। पुनः प्रयोज्य आद्यान भरने से पहले साफ होना चाहिए, उसे रोगाणुमुक्त करके खंगाल लेना चाहिए।

4. आद्यानों को स्वास्थ्यजनक ढंग से कार्य करने वाले कक्ष में लाना चाहिए तथा अनावश्यक देरी किए बिना इनका प्रयोग होना चाहिए।

5. पैकिंग के तुरन्त बंद, आद्यानों को बंद करना और उन्हें अध्याय—II के बिन्दु 1 में निर्दिष्ट भंडारकक्ष में ले जाना चाहिए।

6. अंडा उत्पाद के लिए आद्यानों का प्रयोग, यदि अपेक्षित हो, अन्य खाद्य सामग्री के लिए किया जा सकता है, परन्तु ये साफ और रोगाणुमुक्त हों जिससे अंडा उत्पाद संदूषित न हो।

7. बड़ी मात्रा में, अंडा उत्पाद के परिवहन के लिए प्रयोग किए जाने वाले, आद्यानों को स्वास्थ्य संबंधी सभी नियमों का पालन करना चाहिए। इनमें विशेष रूप से निम्नलिखित हैं :—

—आद्यानों को भरत्रों/भीतरी सतह और कोई अन्य भाग जो अंडा उत्पाद के संस्पर्श में आएगा, ऐसे चिकने पदार्थों से निर्मित हो जो खाने में सहज हों, साफ और रोगाणुमुक्त हो, जंग प्रतिरोधक हो और पदार्थों को अंडा उत्पाद में ऐसी मात्रा में स्थानान्तरित न करें जो मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करें या अंडा उत्पाद के संयोजन में गिरावट लाए अथवा इसके जैविक गुणों पर विपरीत प्रभाव डाले।

—आद्यानों की बनावट इस प्रकार की होनी चाहिए कि अंडा उत्पाद आसानी से पूर्ण रूप से हटाया जा सके। यदि वह टेप से बंद किया गया है तो उन्हें हटाना, खोलना, धोना, साफ करना व रोगाणुमुक्त करना आसान होना चाहिए।

—पुनः प्रयोग से पूर्व यदि आवश्यक हो प्रत्येक के तुरन्त बाद ही इन्हें धोना, साफ करना, रोगाणुमुक्त करना और खंगालना चाहिए।

—इनको भराई के बाद उचित सील लगाई जानी चाहिए और इन्हें परिवहन के दौरान तथा उपयोग किए जाने तक सील रहना चाहिए ।

—इन्हें अंडा उत्पादों के परिवहन के लिए सुरक्षित रखना चाहिए ।

अध्याय—9

भंडारण

1. अंडा उत्पादों को अध्याय 2 के बिन्दु 1 में निर्दिष्ट भंडारकक्ष में रखना चाहिए ।

2. अंडा उत्पादों को जिनके भंडार के लिए कतिपय तापमान अपेक्षित है; उन्हें उसी तापमान पर रखना चाहिए। भंडार कक्ष के तापमान को लगातार अभिलिखित किया जाए । प्रशीतन दर ऐसी होनी चाहिए कि उत्पाद शीघ्रतातिशीघ्र अपेक्षित तापमान पर पहुंच जाए; आद्यानों को ऐसी रीति से भंडार करना चाहिए कि उनके चारों ओर वायु आसानी से आ जा सके।

3. भंडार कक्ष में तापमान निम्नलिखित मान से अधिक न हो —

—अधिक जमा हुआ उत्पाद	18 डिग्री सेल्सियस
—जमा हुआ उत्पाद	12 डिग्री सेल्सियस
—ठंडा उत्पाद	+ 4 डिग्री सेल्सियस

निर्बल उत्पाद (अंडे की सफेदी के बिना) + 15 डिग्री सेल्सियस ।

अध्याय—10

परिवहन

1. अंडा उत्पादों के परिवहन के लिए वाहन और आद्यानों का ढांचा और सज्जा ऐसी होनी चाहिए कि इन निबंधों द्वारा अपेक्षित तापमान परिवहन की संपूर्ण अवधि में सतत रूप से बना रहे ।

2. अंडा उत्पादों को ऐसी रीति में प्रेषित किया जाना है चाहिए कि परिवहन के दौरान किसी भी ऐसी चीज से जो उनके लिए हानिकारक है, पर्याप्त रूप से सुरक्षित रहे ।

3. अध्याय 1 में बिन्दु 3 में विहित तापमान परिवहन के दौरान बने रहना चाहिए ।

अध्याय—11

अंडा उत्पादों का चिन्हांकन

1. प्लांट के अंडा उत्पादों के प्रत्येक परेषण पर निम्नलिखित विवरण वाला लेबल लगा होना चाहिए :—

(i) या तो :—ऊपरी भाग पर प्रेषिती देश के नाम के आरंभिक अक्षर/अक्षरों को साफ अक्षरों में लिखा जाए अर्थात् — बी/डी/डी के/के एल/ई एस पी/एफ/ आई आर एल/आई/एल/ एन एल/ पी/ यू के, जिसके पश्चात् प्लांट का अनुमोदन संख्यांक दर्शित हो। नीचे के भाग पर निम्नलिखित सेटों में से एक के आद्याक्षर लिखे जाए : सीईई—ईईसी—ईईजी—ईओके—ईडब्ल्यूजी—ईओएफ ।

(ii) या :—ऊपरी भाग पर प्रेषिती देश का नाम साफ अक्षरों में। मध्य में प्लांट का अनुमोदन संख्यांक होना चाहिए ; नीचे के भाग पर निम्नलिखित सैटों में से एक के आद्याक्षर लिखे जाएं : सीईई—ईईसी—ईईजी —ईओके—ईडब्ल्यूजी—ईओएफ ।

(iii) वह तापमान जिस पर अंडा उत्पाद को रखना है तथा वह अवधि जिसके दौरान उनका संरक्षण सुनिश्चित किया गया है । लेबल सुपाठ्य अमिट और आसानी से अर्थ निकाला जा सकने वाली प्रकृति का होना चाहिए।

2. परिवहन दस्तावेजों में विशेष रूप से निम्नलिखित सम्मिलित होने चाहिए :—

(i) उत्पादों की प्रकृति उद्गम के वर्ग सहित इंगित होनी चाहिए;

(ii) बैच संख्यांक;

(iii) गन्तव्य स्थान और पहले पाने वाले का नाम व पता;

(iv) यह जानकारी और पौष्टिकता का चिन्ह राजभाषा में या गन्तव्य देश की भाषा में होना चाहिए।

अध्याय—12

[यू एस ए (संयुक्त राज्य अमरीका) को किए गए निर्यात पर लागू]

1. सफाई, संसाधन और सुविधा की अपेक्षाएं

1. प्लांट की अपेक्षाएं

1.1 प्लांट आपत्तिजनक गंध, धूल और धुएं वाली वायु से पूर्णतया मुक्त होना चाहिए ।

1.2 परिसर कूड़ा करकट, कबाड़, रद्दी और अन्य दूसरे तत्वों से पूर्णतया मुक्त होना चाहिए और ऐसी अवस्थाएं जो गंध के साधनों का सृजन करती है या कीट, कृन्तकों तथा अन्य कीड़े मकौड़ों के स्रोत बनती है, से मुक्त होना चाहिए ।

1.3 भवन का मजबूती से निर्मित होना चाहिए और अच्छी मरम्मत करके रखा गया हो जिससे उसमें कीड़े मकौड़ों के शरण लेने या प्रवेश की गुंजाइश न हो ।

1.4 कक्ष कूड़ा करकट, कचड़े, रद्दी तत्वों, दुर्गंध, कीटों, कृन्तकों से मुक्त रखा जाएगा और ऐसी अवस्थाएं जो गंद के साधनों का सृजन करती है या कीट कृन्तकों तथा अन्य कीड़े मकोड़ों के स्त्रोत बनती है, से मुक्त होना चाहिए। ऐसी सामग्री और उपस्कर को, जो वर्तमान में प्रयोज्य नहीं है, संभाल और भंडारकरण ऐसी रीति में किया जाएगा जिससे कि वह स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा न करे।

1.5 दरवाजे और खिड़कियां जो बाहर को खुलती है, कृन्तकों व अन्य कीड़ों आदि के प्रवेश को रोकने वाले होंगे। दरवाजे, खिड़कियों व सेविका कक्ष, जहां खाद्य पदार्थ रखा गया हो की, संरचना व बनावट इस प्रकार होनी चाहिए कि वे धूल व गंदगी को रोक सकें। उन दरवाजों का निर्माण, जो उन कमरों में खुलते है जहां खाद्य उत्पाद का प्रसंस्करण होता है, मजबूती से होना चाहिए और ऐसे दरवाजे जो फ्रिज या कूलर के दरवाजों से भिन्न है, स्वयं बंद करने वाली युक्ति सहित होने चाहिए।

1.6 दरवाजे और ऐसे अन्य निकास जिनसे कृन्तक प्रवेश कर सकते है, का निर्माण कृन्तक प्रूफ होना चाहिए।

1.7 प्लांट और परिसर के लिए सुचारू पानी निकास और नलसाजी की व्यवस्था होनी चाहिए। नाली और मलवहन नाल अनुमोदित जाली और छिद्रों के साथ उचित रूप से लगायी जानी चाहिए। पर्याप्त ढलान के साथ शीघ्रता और निर्बाध रूप से गंदे पानी का निकालना और अन्य बहुत सी संसाधन की प्रक्रिया का संचालन होना चाहिए। फर्श की नाली का भाग निकास जाली के साथ इस प्रकार जुड़ा हुआ हो जो पानी के ठहराव को न होने दे। नयी या पूर्ण संशोधित रूप देकर बनाए गए शौच रोके पानी से निकास की नालियां प्लांट की अन्य निकास नालियों से नहीं जोड़ी जानी चाहिए।

1.8 पानी की आपूर्ति (गर्म और ठंडा दोनों) प्रचुर, साफ व पेय रूप में पर्याप्त दबाव के साथ होगी। तथा प्लांट या उसके किसी भाग को पानी की आपूर्ति की सुविधाएं दी जाएगी जो अंडा प्रसंस्करण और संचालन व्यवस्था तथा उन्हें संदूषित तथा प्रदूषित होने से बचाया जाना चाहिए।

1.9 फर्श, दीवारें, छत, पृथककरण, स्तंभ दरवाजे, सभी अन्य प्रकार के भागों का निर्माण ऐसे पदार्थों से होगा जो उनका त्वरित और सम्पूर्ण सफाई को सुकर बना सके। फर्श और मोड जलरोधी होने चाहिए।

1.10 प्रत्येक कमरा और कक्ष जिसमें झिल्ली अंडा या अंडा उत्पाद का रखरखाव या प्रसंस्करण होता है, उसका डिजाइन निर्माण और रखरखाव इस प्रकार किया जाएगा कि यह साफ और सुचारू प्रकृति जो आपत्तिजनक गंध और वाष्प से मुक्त हो, के संसाधन और संचालन शर्तों को सुनिश्चित करे। साथ ही सफाई और स्वास्थ्य जनक परिस्थिति को भी बनाए रखे।

1.11 प्लांट या उसके किसी भाग, जिसमें झिल्ली अंडा या अंडा उत्पाद का रखरखाव या भंडारण किया जा रहा है, से कुत्ते, बिल्लियों और कीड़े-मकोड़ों (जिसमें कीट, कृन्तक और जन्तु सम्मिलित है परन्तु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है) को बाहर रखने की प्रत्येक सावधानी बरती जाएगी।

1.12 (i) वहां पर्याप्त संख्या में शौचालय, ड्रेसिंग कक्ष, प्रसाधन कक्ष जिनका आकार विन्यास हो, और सुविधाजनक व कुशलता पूर्ण उपयोक्त स्थिर हो। जो सुविधाजनक स्थान पर स्थित हों तथा उन कमरों और कक्षों से पृथक हो जिनमें झिल्ली अंडा या अंडा उत्पाद का रखरखाव, संसाधन या भंडारण होता है। ड्रेसिंग कक्षों और प्रसाधन कक्षों में पृथक रूप से वायु संचार होना चाहिए, उन्हें स्वास्थ्य निर्माण व उपस्कर संबंधी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए।

(ii) निम्नलिखित सूत्र अपेक्षित प्रसाधन सुविधाओं के निर्धारण के लिए आधार है:—

एक ही लिंग भेद के व्यक्ति	अपेक्षित प्रसाधन पात्र	
01 से 15, दोनों सम्मिलित		1
16 से 35, दोनों सम्मिलित		2
36 से 55, दोनों सम्मिलित	*	3
56 से 80, दोनों सम्मिलित	*	4
80 से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त 30 व्यक्तियों के लिए	*	1

*प्रसाधन पात्र के स्थान पर मूत्रालय रखे जा सकते है परन्तु यह पात्रों की कुल संख्या के 1/3 भाग तक ही हो सकता है।

1.13 शौचालय ही जगह प्लांट में जिनमें, गर्म व ठंडा बहता हुआ पानी, एक बार प्रयोज्य तौलियों और साबुन जिसमें ऐसी गंध न हो जो उत्पाद के ठीक मूल्यांकन करने में हस्तक्षेप करे, सम्मिलित है परन्तु यह इन्हीं बातों तक सीमित नहीं है उस स्थान पर स्थित होगी जहां किसी झिल्ली अंडा या अंडा उत्पादों का रखरखाव करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सफाई सुनिश्चित हो सके। संसाधन क्षेत्रों में हाथ धोने की सुविधाएं संचालन नियंत्रण करने वाले व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा संचालित होगी। और निकास के लिए जाली होगी जो नल साज-व्यवस्था से जुड़ी होनी चाहिए।

1.14 प्लांट में सभी सुविधाजनक स्थानों पर उपकरणों व उपस्करों की सफाई और स्वच्छता के लिए उपयुक्त सुविधाओं की व्यवस्था होगी।

1.15 झिल्लियों, कचरा और दूसरे कूड़े को रखने और इकठठा करने के लिए कूड़ाघर की व्यवस्था होनी चाहिए। ये पूर्ण रूप से पृथक कक्ष होते है, जो अंडा तोड़ने वाले कक्षों या रखने वाले नहीं होंगें या वे उन कमरों में नहीं खुलेंगें जहां अंडा उत्पाद और बकिंग पदार्थों की संभाल की जाती है या भंडारण होता है और ये सफाई के लिए अनुमोदित नालियों सुविधाओं सहित होंगें तथा बाहर हवा फेंकने वाली अनुमोदित सहित बने होंगे। झिल्ली का रखरखाव तथा कचरे और अन्य कूड़े की वैकल्पिक व्यवस्था सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो सकती है बशर्ते इस व्यवस्था में कचरे को हटाने और उसकी व्यवस्था करने के लिए तुल्यमाप मान की सफाई की व्यवस्था की गई है

2 उपस्कर और उपकरण :—पोलीक लोरीनेटिड बाईपिनाइल्स (बी सी बी) रखने वाला उपस्कर

2.1 झिल्ली अंडा और अंडा उत्पाद के संसाधन में प्रयुक्त उपकरणों की बनावट, सामग्री और निर्माण तथा अपेक्षा निम्न प्रकार होगी :—

(i) जो ऐसे उत्पाद का परीक्षण, पृथककरण और संसाधन के सुचारू, साफ और संतोषजनक रूप में करने में सहायता करें।

(ii) वे पूर्ण सफाई और स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए सभी भागों में आसानी से पहुंच सकें। जहां तक व्यवहार्य होंगें सभी औजार धातु से या अन्य ऐसी अप्रभावित सामग्री से बने होंगे जो रसायनिक क्रिया या भौतिक सम्पर्क से उत्पाद को प्रभावित नहीं करें।

2.2 सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा प्राधिकृत नए और पुनः माडल किए उपस्कर और उसके स्थापित करने को छोड़कर स्थापित उपस्कर ऐसे उपस्कर के लिए अंगीकृत रीति से उसे लागू स्वच्छता के मानकों को अनुपालन करेगा।

2.3 नए या पुराने उपस्कर के बदले नए उपस्कर या मशीन (जिसमें बदला गया कोई भाग सम्मिलित है) जो किसी अनुमोदित प्लांट के परिसर में लाई गयी है उसमें द्रव्य माध्यम के 50 पीपी एम भार से अधिक सांद्रता वाली द्रव्य पोलीक्लोरीनेटिड बाईफिनाइल नहीं होगी। व्यवस्था दोनों खाद्य संसाधन और अखाद्य संसाधन उपस्कर और मशीनरी तथा ऐसे उपस्कर मशीनरी के बदले में आए किसी भाग पर लागू होगी। पूर्ण रूप से घिरे हुए ऐसे संधारित्र जिनमें 3 पौण्ड पीसीबी से कम हो इस प्रतिषेध से मुक्त होंगे।

3. सामान्य संचालन प्रक्रिया

3.1 संचालन, जिसमें संसाधन, भंडारण और अंडा झिल्ली अवयवों तथा अंडा उत्पादों की व्यवस्था अर्न्तविष्ट है, पूर्णतया सफाई व स्वच्छता के तरीकों का कड़ाई से पालन करते हुए किया जाएगा। अभिक्रिया, स्थरीकरण और अन्य संसाधन इस भाग के अनुसार होनी चाहिए तथा वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो सभी संचालनों में संसाधन के तरीके और तापमान इस प्रकार होंगे कि वे अंडा उत्पाद के विनाश को रोके।

3.2 अनुमोदित प्लांटों मे संसाधित झिल्ली अंडा और अंडा उत्पादों का प्रत्येक संसाधन संचालन के दौरान स्थायी और लगातार निरीक्षण होगा। कोई भी झिल्ली अंडा या अंडा उत्पाद जो उन विनियमों के अनुसार संसाधित न हो या जो मानवीय खाद्य के योग्य न हो उन्हें हटा कर अलग किया जाएगा।

3.3 सभी हानि और अखाद्य अंडे या अंडा उत्पाद को "अखाद्य" लेबल अंकित आधान में रखा जाएगा तथा जिसमें पर्याप्त मात्रा में अनुमोदित विकृतिकारक या लक्षणहीन कारक रखे हों, जैसे भूरा, नीला, काला या गहरा रंग मांस कम और पेषण उपोत्पादन या कोई अन्य उत्पाद जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो इस धारा का प्रयोजन पूरा करेगा।

झिल्ली अंडा को तोड़ा जाएगा और उसके अंग को उत्पाद में ऐसी पर्याप्त मात्रा में निखेर दिया जाएगा जो उत्पाद को एक भिन्न रूप या गंध दे सके। पूर्ववर्ती के होते हुए भी और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ओवेटक खाद्य उत्पाद को "अखाद्य" लेबल किए गए आधान में रख सकता है जिनमें विकृतिकारक नहीं रखा गया है यदि ऐसा अखाद्य उत्पाद को अनुमोदित प्लांट से नौमरण के पहले विकृत या लक्षनहीन कर दिया है परन्तु यह कि ऐसा उत्पाद उचित रूप से पैक लेबल और पृथक किए गए हैं और उनके संबंध में नियंत्रण सूची बनाई गई है। इसके अतिरिक्त अनुमोदित प्लांट से औद्योगिक प्रयोग के लिए या पशु खाद्य के लिए भेजे गए उत्पाद को विकृतिकारक या लक्षण विहीन करना जरूरी नहीं है बशर्ते यह सरकारी सील के अधीन नौभार किया गया है।

3.4 सक्षम प्राधिकारी सैगनेला के लिए प्रयोगशाला परिणाम की प्राप्ति से पूर्व या किसी आम कारण के जैसे कि ठोस वस्तुओं को लेबल करना, अनुमोदित प्लांट से अंडा उत्पादों को भेजने की अनुमति दे सकेगा, जब उनको यह संदेह नहीं हो कि इस भाग के किसी व्यवस्था का अपालन हो रहा है। तथापि ऐसा नौभार ऐसी परिस्थितियों के अधीन होगा जो प्लांट में उत्पाद की वापसी, पुनः संसाधन, पुनः लेबल करने को, आश्वस्त करें या ऐसी अन्य शर्तों के अधीन हो जो सक्षम प्राधिकारी इस भाग की अनुपालन कराने के लिए निर्धारित करे।

3.5 पेश्चुराइजिंग, स्थायीकरण या सुखा संचालन अंडा तोड़ने के पश्चात् यथा शीघ्र शुरू करना होगा जिससे उत्पाद का विनाश होने से रोका जा सके। यह अंडा उत्पाद के लिए, अंडा तोड़ने की मशीनों से भिन्न हो जिसे शर्करा रहित किया जाता है, के समय से अधिमानतः 72 घंटों के भीतर होना चाहिए ।

3.6 प्रत्येक व्यक्ति जो खुले या बिना पैक किए हुए अंडा उत्पाद या किसी औजार या ऐसे आधान को जो अंडा उत्पाद के संपर्क में आ सकता है संभाल करता है वह अपने हाथ धोएगा और उन्हें साफ रखेगा ।

3.7 कोई उत्पाद या सामग्री जो आपत्तिजनक स्थिति उत्पन्न करती है संसाधित नहीं की जाएगी या उन्हें ऐसे कक्ष, कमरे या स्थान पर नहीं रखा जाएगा जहां छिल्की अंडा या अंडा उत्पादन का संसाधन भंडारण या संभाल होती है ।

3.8 अनुमोदित प्लांट में केवल जीवाणु नाशी, कीट-नाशी साफ करने वाले या नमी नाशीकारक या दूसरे ऐसे समतुल्य यौगिक, जो अंडा व अंडा उत्पादों पर हानिकर प्रभाव नहीं डालते और जिन्हें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो, का प्रयोग हो सकेगा । ऐसे यौगिकों का प्रयोग सक्षम प्राधिकार के समाधान पर किया जाएगा ।

3.9 कोई औजार और उपस्कर जो अंडा झिल्ली या अंडा उत्पाद के संसाधन के दौरान संदूषित हो गए हों, उन्हें प्रयोग न करने के लिए तुरन्त ही हटा दिया जाना चाहिए और उनका जब तक प्रयोग नहीं किया जाए जब तक वे साफ व स्वच्छ दशा में न हों ।

3.10 अंडा उत्पाद के संसाधन के दौरान मिलाया गया कोई भी पदार्थ मानव खाद्य के लिए साफ व उचित होगा या अवयव ।

3.11 जब उन्हें अंडा उत्पादों से भरा जाए तब अंडा उत्पादों की पैकिंग या आधान के स्वच्छ डिजाइन के तथा साफ होंगे तथा भरते समय प्रत्येक प्रकार की सावधानी बरती जानी चाहिए जिससे कि किसी पैकिंग या आधान की सतह, जो ऐसे अंडा उत्पाद के सीधे संपर्क में हो आती है या आएगी, धूल या संदूषण से दूर रहे केवल नए आधान ही या प्रयोग किए गए ऐसे आधान जो साफ हो और अच्छी स्थिति में हो और भीतरी उपयुक्त सतह वाले आधान ही खाद्य उत्पाद की पैकिंग के लिए उपयोग किए जा सकते हैं । फाइबर आधान, जिनका प्रयोग बिना अन्तर की सतह के हुआ हो, समक्ष प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित है ।

3.12 परिष्कृत उत्पाद की स्वास्थ्य प्रदता निर्धारित करने के लिए अंडा उत्पादों का निरीक्षण किया जाएगा ।

3.13 अंडा उत्पाद का संसाधन ऐसी रीति में यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि उससे रक्त और गोश्त के धब्बे, झिल्ली के कण और बाहरी वस्तु तुरन्त दूर हो ।

3.14 घुमाने वाले एकक, पाउडर वाहक, छनना, मिथक, मशीनी पाउडर कूलरों के सिवाय संसाधन संचालनों के प्रारंभ में औजार और उपस्कर साफ और स्वच्छ होंगे । सभी संसाधन संचालनों के दौरान उपस्कर और औजार साफ और स्वच्छ ढंग से रखे जाएंगे ।

3.15 अंडा उत्पाद को उपभोक्ता के लिए भेजने से पहले इस अध्याय के पैरा 20 के अनुसार पेश्चुराइज किया जाएगा सिवाय इसके कि बिना पेश्चुराइज किए द्रव से तैयार सूखी सफेदी का इस अध्याय के पैरा 27 के अनुसार गरम किया जाएगा ।

(i) पर्याप्त पेश्चुराइजेशन निश्चित करने के लिए विश्वासपूर्वक हो कि रोग उत्पन्न उत्पादन जीवाणु की उपस्थिति के लिए अंडा उत्पाद का नमूने लेकर उसकी समोनेला की उपस्थिति के लिए जांच करायी जाएगी । सैमोनेला की उपस्थिति की जांच के लिए नमूना अध्याय II के अनुसार होगी और यदि उत्पाद में सेमोनेला पाजिटिव पाया जाता है तो इसे पुनः संसाधित, पेश्चुराइज किया जाएगा और सेमोनेला की विद्यमानता के लिए विश्लेषण किया जाएगा या इसे विकृत कर दिया जाएगा ।

(ii) बिना पेश्चुराइज या सैमोनेला पाजिटिव अंडा उत्पाद की अनुमोदित प्लांट में पश्चुराइज, पुनः पेश्चुराइज या ताप संसाधित किया जा सकता है बिना पेश्चुराइज या संमोनेला पाजिटिव उत्पाद वाले आधानों पर अध्याय XIII के चित्र 3 में दर्शित चिन्ह से पहचान बनायी जाएगी ।

3.16 उत्पाद या उत्पाद संपर्क सतहों में आने वाले वायु बाहरी वायु स्रोतों के अनुमोदित फिल्टर से आएगी ।

3.17 अनुमोदित प्लांट में सभी द्रव और ठोस अपशिष्ट सामग्री उत्पाद को संदूषण से बचाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति में हटायी जाएगी और यह स्वीकार्य पर्यावरणीय संरक्षण पद्धतियों के अनुसार होगी ।

4 कृत्रिम प्रकाश और अन्तरण कक्ष सुविधाएं तथा उपस्कर

4.1 कमरे की संरचना इस प्रकार होनी चाहिए जिसमें पर्याप्त रूप में अन्धेरा किया जा सके और कृत्रिम प्रकाश के द्वारा होने वाली असाव या अंडों की हानि को हटाने में निश्चितता हो । उपस्करों की व्यवस्था सफाईजनक हो और कचरे को तथा पैकिंग सामग्री को हटाने में सहायक हो ।

4.2 फर्श का निर्माण पूर्णतया सफाई करने में सहायक हो और फर्श पानी का प्रतिरोधी बनावट वाला हो तथा इसमें उचित निकास भी हो ।

4.3 अनुमोदित निकास व्यवस्था लगातार सीधे रूप में भाप, धुआं, गंध व धूल को कमरे से बाहर फेंकने वाली

हो। संचालन के दौरान कमरे का ताप यथोचित रूप से कार्य करने योग्य तापमान पर रखा जाना चाहिए।

4.4 अनुमोदित प्रकार की कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था हो जो प्रकाश रखने वाले को हानि पहुंचाए, गन्दगी या ऐक अंडे तथा मुर्गी के अंडों से भिन्न अंडों का पता लगाने में सहायक हो।

4.5 लोकर ट्रे ऐसी सामग्री और ऐसे डिजाइन की बनी होनी चाहिए जिससे सफाई व स्वच्छता आसान हो सके।

4.6 खाद्य अंडों के लिए ऐसे आधानों को दिया जाना चाहिए जो ऐसी सामग्री और ऐसे डिजाइनों से बने हों कि उनकी सफाई सरलता से की जा सके। सभी ऐसे आधानों पर स्पष्ट रूप से चिन्हांकन किया जाए।

4.7 कमरे के लिए ऐसे आधानों को दिया जाना चाहिए जो ऐसी सामग्री और ऐसे डिजाइन से बने हों कि उनकी सफाई सरलता से की जा सके जब तक कि प्रतिदिन प्रयोजक साफ आधान न दिए जाएं।

4.8 झिल्ली अंडा वाहक का निर्माण इस प्रकार होना चाहिए कि उन्हें पूर्ण रूप में साफ किया जा सके।

5. प्रकाशीय और स्थानांतरण कक्ष का संचालन

5.1 प्रकाशीय और स्थानांतरण कक्षों और उपकरणों को स्वच्छ मकड़ी के जालों, धूल आपत्तिजनक दुर्गंधों और अत्यधिक पैकिंग सामग्री से मुक्त रखा जाएगा।

5.2 अखाद्य अंडों के डिब्बों को प्रकाशय कक्षों से दूर रखा जाएगा यदि प्रायः आवश्यकता समझी जाए तो प्रतिदिन प्लांट को स्वच्छता से साफ किया जाएगा। प्लांट को आपत्तिजनक दुर्गंधों से मुक्त रखा जाएं।

5.3 अंडों के छिलकों को तोड़ने से पूर्व प्रेस्वेदन क्रिया को कम करने की किन्हीं रीति का प्रबंध किया जाएगा.

5.4 जब तक इस अध्याय के 6.4 के अधीन प्रतिषिद्ध न किया गया हो व्यापक रूप से क्षतिग्रस्त छिलकों सहित अंडों के छिलकों को छिद्र-ट्रे में स्थानांतरित किया जाएगा और तत्काल तोड़ा जाएगा।

6. अंडा उत्पाद प्रक्रिया में प्रयुक्त अंडों के छिलकों का वर्गीकरण

6.1 अंडे छिलकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति से निम्नलिखित प्रवर्गों में छटाई और वर्गीकृत किया जाएगा :

(i) इस अध्याय के पैरा 6.4 में सूचीबद्ध अंडे।

(ii) गंदे।

(iii) छिद्र जैसाकि इस अध्याय के पैरा 6.3 (ii) में वर्णित है।

(iv) मुर्गी का चूजा बतख, पीरू (पक्षी) गिनी, कुकुमट और हंसनी के अंडों से भिन्न अन्य अंडे से।

(v) तोड़न स्टॉक के रूप में प्रयोग के लिए अन्य समाधानप्रद अंडे।

6.2 अंडे छिलकों में यदि अधिक दुर्गंध पाई जाए या अधिक दुर्गंध युक्त अंडे के प्राप्त किए जाने के मामले में स्वीकार्यता से निश्चित करने के लिए पृथक रूप से प्रकाशित और तोड़ा जाएगा।

6.3 जब अंडों के छिलकों को तोड़ने के लिए प्रस्तुत किया जाए तब खाद्य अंतरीय गुणवता को सुरक्षित रखा जाएगा और (छिलके ठीक रखे जाएंगे) और धूल और उसके अतिरिक्त बाह्य सामग्री से मुक्त होंगे।

(i) यदि अंडों के साथ अंडों के छिलकों के हिस्सों में मिल जाए उसकी जांच की जाए कि दुर्गंध धूल और बाह्य सामग्री से मुक्त है और छिलकों की झिल्ली न फटी हो।

(ii) साफ छिलकों वाले अंडे जो प्रकाशन और/या स्थानांतरण में क्षतिग्रस्त हो गए हैं और छिलके के हिस्से (छिलके) झिल्ली में अप्राप्त मिल जाए तो उन्हें केवल तभी उपयोग में लाया जाएगा जब जर्दी खंडित नहीं हुई हो और अंडों के पदार्थ छिलकों के बाहरी भाग में से नहीं रिसते है। इस प्रकार के अंडों को छिद्र ट्रे में स्थानांतरित किया जाएगा और तत्काल तोड़ा जाएगा।

(iii) अंडों के साथ मांस और खून के धब्बे लग जाएं तो यदि धब्बों को स्वीकार्य रीति से मिटा दिया जाता है तो प्रयोग में लाए जा सकते है।

6.4 सभी घटित और अखाद्य (अभोज्य) अंडों का नाम निर्दिष्ट आधानों में स्थानांतरित किया जाएगा और इस अध्याय के 3.3 में, की अपेक्षानुसार प्रबंध किया जाएगा। अखाद्य और घटित अंडों के इस अध्याय और इन आधानों के 9.9 के प्रयोजन के लिए परिभाषित जैसे काले, रोप्स सहित, सफेद रोटस, मिश्रित रोटस, हरा सफेद एवं ब्यूम या पीला भाग (जरदी) कुचला पीला भाग (जरदी) गजकारी पीला भाग भ्रूण विकसित, फफूंदीदार अंडे, खट्टे अंडे और अंडों का अपमिश्रण के इस प्रकार की शर्तों द्वारा उस भाग में परिभाषित है और कोई अन्य गले सड़े और विघटित अंडे जिसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित है :—

(i) अंडों में से मांस और खून के हटाने योग्य धब्बों से भिन्न दृश्य बाह्य पदार्थों वाला कोई अंडा।

(ii) छिलके के किसी भाग वाला और अखाद्य झिल्ली वाला अंडा और छिलके के बाह्य हिस्से के साथ चिपका हुआ या छिलकों के बाह्य हिस्सों से अंडा मांस से स्पर्श होने वाला कोई अंडा।

(iii) छिलके में चिपकी हुई धूल या बाह्य पदार्थ वाला और छिलके और छिलके की झिल्ली में दरार वाला कोई अंडा ।

(iv) अंडों के छिलकों के पात्रों (डिब्बों) और छिद्र ट्रे से पुनराप्त तरल अंडा ।

(v) स्वच्छता प्रचालन में बनाए गए खुले छिद्र ।

(vi) ऐसा कोई अंडा जो यह साक्ष्य प्रदर्शित करता हो कि फेस से स्थानांतरण के पूर्व अंतर्वस्तु रिसती है या रिस रही है ।

6.5 उष्मायित अस्वीकृत अंडों को अनुमोदित प्लांट में नहीं लाया जाएगा ।

7. अंडों में स्वच्छता संचालन ।

7.1 जब धूले अंडों के छिलकों को तोडने के लिए पेश किया जाए तो निम्नलिखित अपेक्षाओं की पूर्ति की जाएगी ।

(i) अंडों के छिलकों को साफ करने के औजारों (उपकरणों) को पूर्ण रूप से व्यवस्थिति स्थिति में रखा जाए । यदि आवश्यक समझा जाए तो प्रत्येक दिन प्रयोग करने के बाद उनकी स्वच्छता से सफाई की जाए ।

(ii) साफ करने वाले पानी के ताप को 32 डिग्री सेल्सियम पर या अधिक पर सुनिश्चित किया जाए और जब अंडों को धोया जाए तो तापमान को कम से कम 11 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए । ये तापमान पूर्णरूप से सफाई के आवर्तन में सुनिश्चित रखा जाएगा ।

(iii) घुले पानी के लिए एक स्वच्छतापूर्ण अनुमोदित कंपाउंड का प्रयोग किया जाए । विक्रय में कंपाउंड डिस्पैनसिंग के लिए भाप मापीय उपकरणों के प्रयोग और सिफारिशें की गई हैं ।

(iv) घुले पानी को लगभग प्रत्येक 4 घंटों के अन्तराल पर बदल दिया जाएगा यदि प्रायः आवश्यकता समझी जाए तो प्रत्येक आखिरी शिफ्ट पर इसे स्वच्छता की स्थिति में रखा जाए । अंडे की धुलाई प्रचालन (संचालन) के दौरान उपचारात्मक मापकों से अतिमात्रा में फेल करने से रोका जाएगा ।

(v) प्रशीतित पानी को क्रमशः निरन्तर प्रतिस्थापन कर दिया जाए और वासर्श को लगातार प्रवाहित किया जाएगा । प्रक्षालन पानी और रसायनिक स्वच्छ प्रक्षालन प्रतिस्थापन बदलने का प्रयोग होना चाहिए । आयोडिन शुद्धता प्रक्षालन का प्रयोग पानी के प्रतिस्थापन में नहीं किया जाना चाहिए ।

(vi) अंडे की धुलाई (प्रक्षालन) संचालन से निकलने वाले पानी को सीधे निकासी से निकाला जाएगा ।

(7) धुलाई संचालन को निरंतर किया जाएगा और जहां तक संभव हो संचालन को शीघ्रता से पूर्ण किया जाएगा। अंडों को खड़ा करना या पानी में भिगोना स्वीकार्य नहीं होगा। निमज्जन किस्म के वाशर्त का प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

(8) अंडे के छिलकों को धुलाई करने के पूर्व उनको गीला करने से पहले अंडों के ऊपर गण सम्पन्न पानी के लगातार बहाव द्वारा ऐसी रीति से छिड़काव किया जाए जो पानी को बाहर निकलने की अनुमति देती है या ऐसे संयत्रों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाए । पानी का तापमान वही होगा जो इस अध्याय में निहित है ।

(9) धुले अंडों का प्रक्षालन छिकाव अनुमानित स्वच्छतापूर्ण स्थिति के साथ 100 पीपीएम से कम न किया जाए और ना ही 200 पीपीएम के अधिक रसायनिक का, अथवा इसके समतुल्य;

7.2 अंडों को तोड़ने वाले कक्ष में न धोया जाएगा या किसी कक्ष में जहां खाद्य उत्पाद की प्रक्रिया की जाए।

7.3 अंडे तोड़ते समय छिलकों को पर्याप्त रूप में सुखाया जाए और संदूषण से रोकने के लिए या तरल अंडे उत्पाद के अपमिश्रण से छिलके की नमी से मुक्त (दूर) रखने के लिए।

8. तोड़ने वाली कक्ष (कमरों) की सुविधाए

8.1 तोड़ने वाले सभी कक्ष के कार्य सतह से प्रकाश को लगभग 30 फुट से बराबर रखा जाएगा इसके सिवाय यह प्रकाश तीव्र या तोड़ने वाले और निरीक्षण स्थान से कम से कम 50 फुट की दूरीपर रखा जाए। प्रकाश समुचित सुरक्षा जिस दूरी से संरक्षित होगी।

8.2 छतों और दीवारों की सतह को चिकनी और पानी रोधक सामग्री से बनाया जाएगा।

8.3 सतह की संरचना जलरोधक से की जाएगी और सतह की टूटी हुई और खरदरी से रहित होगी। दीवार के अंतरीय भाग की जगह से गंदे पानी की पर्याप्त निकासी के लिए नाली बनाई जानी चाहिए।

8.4 वायु आगमन के लिए व्यवस्था करना ।

(1) पूर्णकक्ष में बाहय वायु आने के लिए उपयुक्त छिद्रों की व्यवस्था ।

(2) संचालन प्रक्रिया के समय हवा का उचित तापमान ।

8.5 व्यक्तिगत तौर पर सभी अंडों को तोड़ने वाले कर्मियों के लिए पर्याप्त मात्रा में हाथ धोने के लिए आसान व सुगम सुविधाएं होंगी। गर्म पानी की पर्याप्त व्यवस्था, स्वच्छ तौलिए या हाथ सुखाने के लिए अन्य सुविधाएं, दुर्गन्ध रहित साबुन, काम में आने वाले तौलिए, डिब्बों की व्यवस्था होगी। हाथ धोने के लिए हस्तांतरित नियंत्रण से भिन्न द्वारा स्वचालित सुविधा होगी।

8.6 अंडे उत्पाद पैकिंग के लिए डिब्बे तरल अंडे ट्रान्टियों के रूप में स्वीकार्य नहीं है।

8.7 डिब्बों में से एक उचित पहचान प्रदत्त की जाए कि अस्वीकार्य तरल व्यंजन के लिए है।

8.8 छिलकों के हिस्सों और बाह्य सामग्री को प्रभावी तौर से हटाने के लिए अनुमोदित संरचना की छलनी, फिल्टर अथवा अपकेन्द्रीय निर्मल कर्मियों की व्यवस्था की जाएगी जब तक कि अन्य यांत्रिक डिवाइसेंस के लिए सक्षम प्राधिकारी से विशेष अनुमोदित प्राप्त नहीं कर लिया जाता है।

8.9 तरल अंडे उत्पाद पैकिंग के लिए, सिवाय स्वतः बंद पैकिंग प्रणाली के छलनी, कृत और पूर्ण हवादार किस्म के पृथक कक्ष की व्यवस्था की जाएगी।

9. तोड़ने वाले कक्ष का संचालन

9.1 तोड़ने वाले कक्ष को धूल से मुक्त स्वच्छता की दशा में और मक्खियों कीट और कृतकों से मुक्त रखा जाएगा। तोड़ने वाले कक्ष की फर्श के संचालन को समय पूर्णतया स्वच्छता से साफ और सुखाया जाएगा। तथा अंडा, मांस और छिलकों से रहित रखा जाएगा।

9.2 सभी तोड़ने वाले कक्ष के कर्मियों को अपने हाथों को दुर्गंध मुक्त साबुन से प्रत्येक समय तोड़ने वाले कक्ष में प्रवेश से पूर्व अच्छी तरह से साफ करेंगे और अखाद्य अंडों को तोड़ने के बाद साफ उपकरणों को प्रयोग में लाने से पूर्व साफ करेंगे।

9.3 कागज तौलिया अथवा टिसूज को तोड़ने वाली मेज पर प्रयोग किया जाएगा और इन्हें दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। कपड़े के तौलिए की अनुमति नहीं दी गई है।

9.4 तोड़ने वाले जब भी कार्य प्रारंभ किया जाए और भोजनावकाश के बाद स्वच्छ उपकरण औजार पूर्ण सेट का प्रयोग करेंगे। सभी मेजों के उपकरणों को प्रत्येक 2.5 घंटों में स्वच्छकर बारी-बारी से प्रयोग किया जाएगा।

9.5 प्यालों को अत्यधिक मात्रा में नहीं भरा जाएगा।

9.6 प्रत्येक अंडे के छिलकों को संतोषजनक ढंग से और स्वच्छता के माध्यमों से और दुर्गन्ध का निरीक्षण करके अंडे मास का परीक्षण कर समयबद्ध दशा में तोड़ा जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा अनुमोदित के अलावा सभी अंडा मांस का, टैंक या चूर्ण में खाली किए जाने के पूर्व इस प्रकार के कार्यों को साफ करने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति द्वारा पुनः निरीक्षण किया जाएगा।

9.7 अंडों के छिलकों में मांस और खून के धब्बों और अन्य बाह्य सामग्री कप, ट्रे में लग जाए तो उन्हें चम्मच से हटाया जायेगा या अन्य अनुमोदित उपकरणों से हटाया जाएगा।

9.8 जब भी अखाद्य अंडे तोड़े जाएं प्रभावित तोड़ने वाले उपकरणों को स्वच्छता के साथ साफ किया जाएगा।

9.9 अखाद्य और घटित अंडों को इस अध्याय के 6 से परिभाषा दी गई है, लागू होगी।

9.10 किसी भी प्याले के पदार्थ या अन्य तरल अंडों के पात्र जिसमें एक या अत्यधिक अखाद्य या घटित अंडे हों, को निकाल दिया जाएगा।

9.11 अंतर्वस्तु को जब भी ब्रिप, ट्रे में खाली किया जाए तो उसे सावधानीपूर्वक तरल रूप में दुर्गन्ध रहित कर प्रवाहित किया जाए। ब्रिप ट्रे प्रत्येक 15 दर्जन अंडों के लिए कम से कम एक बार प्रत्येक 15 मिनट में खाली किया जायेगा।

9.12 जैसाकि खाद्य अंडों (छिद्रों के संबंध इस अध्याय के (2) 6.3 परिभाषा दी गई है तथा तोड़ने वाली मशीन का संचालन विशेष रूप से प्रशिक्षित कार्मिक द्वारा किसी पृथक स्थान पर किया जायगा।

9.13 अंडे उत्पाद प्रक्रिया में अवशेष और अवशेषों का प्रयोग स्वच्छता के तरीके से संचालित किया जायेगा।

9.14 तरल अंडों के डिब्बों को प्रकाशमय कमरे से नहीं गुजारा जाना चाहिए।

9.15 परीक्षण उपकरणों के किए की व्यवस्था की जायेगी और उसका प्रयोग स्वच्छता घोल की शक्ति निर्धारण करने के लिये किया जायेगा।

9.16 छिद्र ट्रे को प्रत्येक आखिरी शिफ्ट के बाद स्वच्छता से साफ किया जाय जब कभी भी छिद्र ट्रे गंदी हो।

9.17 अंडों के छिलकों के डिब्बों में जब भी गंदगी हो तो उन्हें सुखाकर एवं स्वच्छता के साथ साफ किया जाये तथा प्रत्यक आखिरी पारी के बाद स्वच्छता से साफ किया जायेगा।

9.18 बेल्ट किस्म अंडों का वाह पट्टा जब भी गंदा हो तो उसे लगभग 4 घंटों के दौरान स्वच्छता से साफ किया जायेगा तथा प्रचालन के समय पूर्ण रूप से साफ किया जायेगा जब वाहक पट्टा प्रयोग में लाया न जाये तो उसे उंचाकर हवा में सुखाया जायेगा।

9.19 कप, ट्रे, चाक्, रेकों, विभागीय ट्रे, चम्मचों तरल अंडों, ग्लास एवं अन्य तोड़ने वाले उपकरण यांत्रिक, अंडे तोड़ने वाले उपकरण के अलावा सभी उपकरणों को प्रत्येक 2.5 घंटे में स्वच्छता से साफ, किया जायेगा, यह उपकरण प्रत्येक आखिरी पारी के बाद स्वच्छता के साथ साफ, करने के बाद ही प्रयोग में लाया जायेगा।

9.20 पात्र (बर्तनों) और खंडित उपकरणों को जलोत्सारित किया जायेगा और अनुमोदित स्वतः जल बहाने वाली धातु की रेकों पर हवा में सुखाया जायेगा और पीड़ित रूप में नहीं रखा जाएगा।

9.21 डम्प टैंकों, टेकों और मंथन ढोल को लगभग प्रत्येक 84 घंटों में साफ, किया जायेगा, सभी इस प्रकार के उपकरणों और सभी अन्य तरल उपकरणों की व्यवस्था एवं स्वच्छता नियमिता से की जायेगी तथा पृथकीकरण उपकरणों को प्रत्येक आखिरी पारी के बाद साफ, किया जायेगा। पसराइजेशन उपकरण प्रत्येक दिन आखिरी पारी के बाद साफ, किया जाएंगे इस प्रकार के सभी उपकरणों प्रथमतः स्वच्छता से साफ, करने के पश्चात ही प्रयोग में लाया जाएगा।

9.22 छलनी, निर्गलीकरण, छलना और छिलका के हिस्सों और अन्य बाह्य सामग्री के हटाने के लिये प्रत्येक में लाये गये अन्य उपायों को प्रत्येक समय स्वच्छता से साफ, किया जायगा। यदि इस प्रकार के अपकरणों को बदलना आवश्यक समझा जाये तो परीक्षण के 4 घंटों के अंतराल के दौरान बदला जाये।

9.23 तोड़ने वाले कक्ष के प्रक्रियात्मिक उपकरणों का भंडारण फर्श पर नहीं किया जायेगा।

9.24 धातु के डिब्बों और शुष्क उत्पादों ढक्कनों को, से भिन्न के लिये पूर्णतः साफ, किया जायेगा और स्वच्छता से प्रदूषण मुक्त किया जायेगा तथा भरने से पूर्व शीघ्रता से जलोत्सारित किया जायगा। यदि लिखित में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित समान प्रभावकारी उपायों का पालन यह आश्वस्त करने के लिये किया जाता है कि भरने के समय डिब्बे स्वच्छता से साफ, किये जाते है तो उपरोक्त अनुक्रम की आवश्यकता नहीं होगी।

9.25 तरल अंडो का भंडारण, डिब्बों (टैंक और ट्रकों सहित) सफाई से मुक्त करके परिवहन के काम में लाया जायेगा, इस प्रकार के उपकरण को प्रयोग में लाये जाने के पूर्व तत्काल साफ किया जायेगा तथा स्वास्थ्यप्रद किया जायेगा।

9.26 प्रत्येक आखिरी पारी के बाद मेज, छिलका वाहक और अखाद्य अंडे उत्पाद के डिब्बों को साफ किया जायेगा।

9.27 यांत्रिक अंडे तोड़ने वाली मशीन का संचालन पूर्णतया नियंत्रण और उचित निरीक्षण के हिसाब से चलाया जायेगा और अखाद्य अंडों का और सभी घाटे से विश्वास दिलाया जाये के लिये प्रत्येक अंडे का प्रथकरण किया जायेगा। मशीन का संचालन स्वच्छता पूर्ण ढंग से किया जायेगा।

(1) जब अखाद्य अंडे यांत्रिक अंडों से मिल जाये तब पृथक करने वाले उपकरणों से अखाद्य अंडों और संक्रवित तत्व को हटा दिया जायेगा, मशीन को दोषमुक्त करने अथवा स्वच्छता से साफ किया जायेगा, अथवा सभी मशीनों के हिस्सों को साफ कर अखाद्य अंडों को तोड़ने वाली मशीन से उचित माध्यम से हटा दिया जाये।

(2) तरल अंडों के पंप चालन की प्रणाली सीधे तोलने वाली मशीन से अनुमोदित स्वच्छता डिजाइन से बनाई जाये जब अखाद्य अंडों में मिल जाये तब नमूने द्वारा बनी नाली को बंद कर देना चाहिये तथा पंप चालन प्रणाली प्रत्येक आखिरी पारी के बाद स्वच्छता से साफ किया जाये तथा अन्य पंप चालन प्रणाली के उपकरणों को स्वच्छता की दृष्टि से 4 घंटों के अंतराल पर स्वच्छता से साफ किया जायेगा, सभी तरल अंडों को तोड़ने वाली मशीन का पुनः निरीक्षण किया जायेगा। सिवाय इसके जो अन्यथा सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित और अनुमोदित किये जायें।

(3) यांत्रिक अंडों को तोड़ने वाले उपकरण को प्रयोग करने से पूर्व स्वच्छता से साफ किया जायेगा और संचालन के दौरान उपकरण को लगभग प्रत्येक 4 घंटों के अंतराल उनकी स्वास्थ्यप्रद दशा बनाये रखने के लिये स्वच्छता से साफ किया जायेगा, और यह यंत्र (उपकरण) प्रत्येक आखिरी पारी के बाद साफ किया जायेगा।

10. तरल अंडों का प्रशीतन

10.1 तरल अंडों का भंडारण कक्षों, कूलरों की सतह सहित और भंडारण टैंक कक्षों को आपत्तिजनक दुर्गन्धों एवं घरीभूत करने से मुक्त एव साफ रखा जायेगा। जब भी कूलरों की सतह को तरल भंडारण के प्रयोग में लाया जाये तो तरल उत्पाद ढका होगा, तरलता प्रशीतन इकाइयां अनुमोदित संरचना की होगी और इस अध्याय में निर्दिष्ट सभी तरल अंडों को तापीय अपेक्षाओं से बचाने के लिये प्रशीतित सामग्री पर्याप्त क्षमता रखेगी।

10.2 तरल अंडों को लागू होने वाली तापीय अपेक्षाओं का अनुपालन एवं केवल सभी समाधान के रूप में समझा जायेगा, यदि तरल अंडे पूर्ण जनसाधारण की आवश्यकता को पूरा करते हैं।

10.3 तरल अंडा उत्पाद के लिये प्रशीतन और तापीय अपेक्षाएं वे होंगी जो इस अध्याय की सारणी–1 में विनिर्दिष्ट है।

10.4 लिखित आवेदन पर और ऐसी शर्तों के अधीन जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित अन्यथा ऐसी तरल प्रशीतन और तापीय भंडारण की इस अध्याय में अन्यथा व्यवस्था नहीं की गई है, अनुमोदित की जायेगी।

10.5 द्रव्यों (पदार्थों) को मिलाने वाले यंत्र का संचालन ऐसी रीति से किया जायेगा जिससे फेन कम हो।

10.6 जब बर्फ का प्रयोग किसी असामान्य परिस्थितियों में प्रशीतन के लिये किया जाये तो सीधे संपर्क के स्थान में किया जाये तथा बर्फ का स्रोत जो खाद्य प्रसंस्कार्य के लिये सुरक्षित तथा यथोचित के लिये सक्षम प्राधिकारी के स्वीकार्य राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारी या अन्य अभिकरण या प्रयोगशाला द्वारा अनुमोदित स्थानीय या राज्य स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

11. तरल अंडों का रख-रखाव

11.1 तरल अंडों के लिये रख-रखाव के लिये प्रयोग की रूपरेखा टेंकों और नालों की संरचना अनुमोदित होगी और ढक्कनों से फिट और स्वच्छता की स्थिति के कमरों में उपलब्ध होगी, जो पूर्ववर्ती के होते हुए अंकों के आकार के लिये व्यवस्थापन कक्ष या भवन के बाहर की तरफ इसके लिये स्वीकार्य है, और टेंकों की परीक्षण कक्ष से हटाकर खोला जाये।

11.2 तरल अंडे का रख रखाव टेंकों या नादों की यथोचित थर्मामीटरों और हिलाने के यंत्रों से सज्जित रखा जायेगा।

11.3 रख-रखाव के टेंकों या बर्तनों की अतिमात्रा में फेनन से रोका जायेगा।

11.4 यदि गैस केप्स को प्रयोग में लाया जाये तो वह पूर्ण से स्वच्छता युक्त हो।

12 प्रशीतन युक्त सुविधायें

12.1 प्रशीतन युक्त कक्ष या तो चालू या बंद के के परिसर सभी तरह के अंडों के उत्पाद के लिये हिमशीतन क्षमता जो इस अध्याय के 13 में दी गई है। अपेक्षाओं के अनुसार होगी, बंद परिसर प्रशीतन सविधाएं केवल तभी अनुज्ञात है जब सुक्षम प्राधिकारी से लिखित में पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया है।

12.2 सभी हिमशीतन कक्षों में यथोचित हवा की व्यवस्था की जाएगी।

13. प्रशीतन संचालन

13.1 प्रशीतन कक्षों को साफ, और आपत्तिजनक दुर्गन्धों से मुक्त रखा जायगा।

13.2 अपेक्षाएं

(1) अब पेस्चुराइज्ड अंडे उत्पाद जिसे जमाया जाता हो उसे टोस रूप में जमाया जायेगा और तोड़ने के समय से 60 घंटों के अंदर ताप–12 डिग्री सेल्यिस या उससे कम किया जायेगा।

(2) पेस्चुराइज्ड अंडे के उत्पाद जिसे जमाया जाता हो उसे टोस रूप में जमाया जायगा या पेस्चुराइजेशन के समय से 60 घंटों के भीतर ताप 12 डिग्री सेल्यिस या उससे कम किया जायेगा।

(3) जिस उत्पाद का ताप टोस प्रशीतन में न हो उसे इस अध्याय की अनुपालनता के निर्धारण करने के लिये डिब्बों में केन्द्र पर ले जाया जायेगा।

13.3 डिब्बों को ढेर में रखा जायेगा ताकि वे चारों तरफ, की हवा के प्रवाह को सहन कर सके।

13.4 तरल अंडे के डिब्बे के बाहर की तरफ, से साफ, और तरल अंडे के साक्ष्य से मुक्त होंगे।

13.5 प्रशीतित अंडे के उत्पाद की प्रशीतन के बाद यह निर्धारित करने के लिये कि ये अंडे मानव खाद्य योग्य है आरगनोलेप्टिक परीक्षण द्वारा जांच की जायेगी, यदि इस प्रकार का उत्पाद जाम मानव खाद्य है योग्य न हो तो अप्राकृतिक होगा और इस पर औपचारिक पहचान चिन्ह जोकि किसी डिब्बे पर लगा हो, ऐसे डिब्बों को हटाया जायेगा या पूर्णतः हटाया जायेगा या पूर्णतः नष्ट कर दिया जायेगा।

14. अप्रशीतन सुविधायें

14.1 अब रीतप टेंकों एवं बर्तनों की संरचना अनुमोदित धातु से की जायेगी ताकि पूर्णतः स्वच्छता का प्रबंध सुनिश्चित किया जा सके।

14.2 प्रशीतन अंडे तोड़ने वाला यंत्र जब प्रयोग में लाया जाये तो यह अनुमोदित धात्विक संरचना का होगा जो तोड़ने वाला यंत्र पूर्णतः स्वच्छ होगा और जब धारक और द्रव्य बनाई जाये तो उन्हे उचित माध्यम से संदूषित होने से रोका जायेगा।

14.3 काम करने वाली मेजों को अनुमोदित धात्विक संरचना से बनाया जायेगा तथा इनकी सतह को मुलायम एवं पूर्णतः स्वच्छ की जाने योग्य होगी।

15. प्रशीतन प्रचालन

15.1 प्रशीतन अंडे उत्पाद जिन्हे अप्रशीतन किया जाता हो उन्हें किसी स्वास्थ्यप्रद तरीके से अप्रशीतन किया जायेगा।

15.2 अप्रशीतन अंडे के प्रत्येक डिब्बे की प्रवेश टैंक में खाली करने से पूर्व जांच की जाएगी कि डिब्बे दुर्गन्धित न हो, अप्रशीतन अंडे जो आपत्तिजनक दुर्गन्धों से मुक्त और मानव उपयोग के योग्य न हो तो इन्हें अप्राकृतिक (भ्रष्ट) किया जाए, जैसे खट्टे, दुर्गन्धता पूर्ण, फफूंदीदार या सड़ने की दुर्गन्ध आदि।

15.3 सूखी के उत्पाद के प्रयोग किये जाने वाली जमी हुई सफेदी को कमरे के तापमान में पिघलाया जा सकता है, अन्य सभी सफेदी इस अध्याय के पैरा 15.4 के अनुसार पिघलाई जा सकेगी।

15.4 जमे हुए संपकर्ण अंडे की सफेदी और पिघला हुआ भाग और पीला भाग नष्ट कर दिया जाए या कुछ पिघलाया जाए जो कि कमरे के तापमान में 48 घंटे से अधिक न रखा गया हो इसका कक्ष का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो परन्तु यह कि पिघले हुए तरल का कोई भी भाग बर्तन में या इसके बाहर 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होगा।

(i) धातु के बर्तन में पैक किए गए जमे हुए अंडों को बिना निमज्जन के ठंडे नल के चलते पानी में रखा जा सकेगा।

15.5 बर्तनों के उठाने और अंडे उत्पाद को हटाने के लिये स्वच्छता के तरीकों का प्रयोग किया जायगा।

15.6 पिघलाने की प्रक्रिया में प्रयोग किए गए दलित और अन्य यंत्र प्रत्येक पारी के बाद खंडित कर दिए जाएंगें और स्वच्छता से साफ किए जाएंगें;

(1) जहां दलित कुछ अंतराल पर प्रयोग में लाए जाते हैं ये हमेशा प्रत्येक प्रयोग के उपरांत और पुनः प्रयोग के लिए आने के पूर्व साफ किए जाएंगें;

(2) फर्श और काम करने वाला मेज साफ रखा जाएगा।

16. छिड़काव की क्रिया सुखाने की सुविधाएं

16.1 सुखाने वाले यंत्र निरंतर छिड़काव वाले होंगें और इसकी संरचना ऐसी होनी चाहिए कि इसमें ज्यादा पाउडर जमा न हो सके।

16.2 सुखाने वाले यंत्रों की संरचना अनुमोदित सामग्री से बनी होनी चाहिए, इसके ब्लेड तेज हों और इसका सतह समानांतर और सफाई युक्त हो।

16.3 सुखाने वाले यंत्र हवादार अनुमोदित फिल्टर से सज्जित होंगें;

16.4 सुखाने वाले यंत्रों में हवा के स्रोत गंदी, गध, धूल और गंदगी से मुक्त स्रोतों की होगी;

16.5 अप्रत्यक्ष गर्मी या किसी अनुमोदित मिलावट के साधन का प्रयोग या प्रत्यक्ष आग की इकाइयों के पूर्व दहनशील अन्य अनुमोदित साधनों के लिए आवश्यक यदि किसी पूर्व मिश्रण प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाए तो यह ब्लोवर की ओर से स्वीकृत हवा की छलनी से युक्त होनी चाहिए।

16.6 उच्च तापमान के पंप हुड और लाइन लैस स्टील के होने चाहिए इसकी संरचना स्टैनलैस स्टील की या इसके समकक्ष होनी चाहिए, जिससे कि सफाई उचित प्रकार हो सके।

16.7 यदि प्रीहिटिंग इकाई को प्रयोग में लाया जाए तो उसकी संरचना स्टैनलैस स्टील या समतुल्य से की जाए जिसे पूर्ण रूप से साफ होना चाहिए।

16.8 पाउडर फेंकने वाले यन्त्रों की संरचना ऐसी होनी चाहिए जिसे कि पूर्ण रूप से साफ किया जा सके।

16.9 छलनी अनुमोदित धातु की बनी हो या धातु की मोल्डिंग की, छलनी का पर्दा तथा फ्रेम की संरचना अनुमोदित धातु की हो, जिससे कि सूखे हुए अण्डों का बहुत सा भाग या ढेर जब छलनी का कार्य कर रही हो तो लगातार हटाया जा सके।

17. छिड़काव प्रक्रिया सुखाने की क्रिया

17.1 सुखाने का कमरा स्वच्छतापूर्ण स्थितियों में रखा जाना चाहिए और मक्खी कीटों और कृन्तकों से मुक्त होगा।

17.2 (1) छिड़काव की तुती, हिंद कोर या ड्राइ-अरज, सुखाने की प्रक्रिया की समाप्ति के तत्काल बाद साफ कर दिए जाएंगें;

कम दाब लाइन, उच्च दाब लाइन, उच्च और कम दाब लाइन, उच्च और कम दाब के पम्पों, होमोजनाइजरों और पेस्चुराइजरों को, जब उनका संचालन बन्द कर दिया जाता है, जैसा आवश्यक हो स्वीकार्य इनसेट सफाई के तरीकों से साफ किया जाएगा या प्रयोग के पश्चात खंण्डित कर दिया जाएगा या साफ कर दिया जाएगा।

(2) दोबारा संचालन के पूर्व यन्त्रे 2 घण्टे के अन्तराल पर साफ किए जाएं।

17.3 सुखाने वाली इकाइयां वाहक छलनी और पैकिंग प्रणाली, तभी साफ की जानी चाहिए जब गीला पाउडर डाला जाए या जब ऐसे अन्य हालात हों जो उत्पाद पर विपरीत प्रभाव डाले पूर्ण सुखाने वाले इकाई छलनी जिसमें छलनी वाहक और पाउडर कूलर भी है, को या तो गीला ही साफ किया जाएगा या सूखा साफ किया जाएगा, पूर्ण सुखाने वाली इकाई की गीली धुलाई और सूखी सफाई करना दोनों का मिश्रण तब तक अनुज्ञात नहीं होगा जब तक कि वह साफ किए जाने वाली इकाई से बिल्कुल अलग न हो गया हो।

(1) सूखे हुए सफेद से भिन्न के लिए प्रयोग में लाई गयी छलनी तथा वाहक को पाउडर से साफ किया जाना चाहिए जब यह यन्त्र 24 घण्टे से अधिक अवधि तक प्रयोग में नहीं लाया जाता हो।

(2) क्लेक्टर बैगज जब भी आवश्यक हों साफ किए जाने चाहिएं, जिससे कि उनको स्वीकार्य साफ स्थिति में रखा जा सके।

17.4 पाउडर को छाना जाएगा और स्क्रीन को, जब यह फट गयी हो तो उसे बदल दिया जाएगा।

17.5 सूखे अण्डे के जमा हुए भाग या सूखे अण्डों की डलियां छलनी की स्क्रीन से निरन्तर साफ की जाएंगी।

17.6 पतन, बरमा, उच्च दाब लाइन आदि आसपास सुखाने वाले स्थान के सभी फैले भाग, सुखाने की प्रक्रियाओं के समय जहां तक सम्भव हो बन्द कर दिए जाएंगे जिससे कि बिना छनी हुई हवा अन्दर प्रवेश न कर सके।

17.7 सुखाने वाली इकाइयों का खुला भाग सिवाय जब सुखाने वाली इकाई पाउडर धुलाई और गीली धुलाई से पूर्णतः खाली हो जाने पर सुखाने वाले यन्त्र प्रयोग में न हों तो यह बन्द कर दिया जाएगा। यह खुले भाग तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि हवा का आगमन और निकासी तूती के खुलने, पतन, बरमा आदि भी इसमें सम्मिलित हैं।

18. पाउडर के छिड़काव की प्रक्रिया, परिभाषा और आवश्यकताएं

18.1 उत्पाद की परिभाषा

(1) "प्राथमिक पाउडर" वह पाउडर है जो कि सुखाने की इकाई की प्रक्रिया के समय प्राथमिक या मुख्य सुखाने वाले चैम्बर से निरन्तर हटाया जाए।

(2) सैकेण्डर पाउडर, वह पाउडर है जो कि सुखाने की इकाई की प्रक्रिया के समय सैकेण्डरी चैम्बर/या बैग कलेक्टर चैम्बर से मन्त्रवत और निरन्तर हटाए जाएं।

(3) "झाड़ने वाला पाउडर" वह पाउडर है जो कि ब्रुश-डाउन प्रक्रिया के समय प्राथमिक या सैकेण्डरी चैम्बर और वाहन में पाया जाता है।

(4) "ब्रुश बैग पाउडर" वह पाउडर है जो कि क्लेक्टर बैग से ब्रुश किया जाए।

18.2 सकेण्डरी पाउडर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रणाली से निरन्तर फेंका जाएगा और प्राथमिक पाउडर के साथ एजेंसियों में मिलाया जाएगा।

18.3 खाद्य अण्डों के सूखे उत्पाद सूखे अंशों सहित जो कि ऐसे सूखे उत्पादों में मिलाया जाए परन्तु यह तब जब यह मिलावट ऐसे किसी कक्ष में की जाती है जो इस अध्याय के 21 में दिया गया है या एक बन्द मिश्रण प्रणाली द्वारा और साफ एवम स्वच्छ कार्य प्रणाली से और ऐसी प्रक्रिया से जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित की जाए।

18.4 किसी भी खाद्य सूखे अण्डों का पाउडर पुनः गठित, पुनः निर्जीवीकरण और पुनः सुखाकर साफ किया जा सकेगा, जब वह किसी साफ स्वच्छ रीति से सम्पन्न की जाती है और ऐसी प्रक्रियाओं के अनुसार जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित की जाए।

18.5 झाड़न पदों और ब्रुश बैग सूखी सफेदी में ब्रुश बैग के लिए के सिवाए और अनुचित रूप से सूखे या दुग्ध पाउडर से प्राप्त किया गया खाद्य सूखे अण्डों के पाउडर का पुनः गठन, पुनः निर्जीवीकरण और पुनः सुखाकरन किया जा सकेगा।

18.6 प्रत्येक अन्तराल के समय लगभग पहला और अन्तिम सुखाने वाली इकाइयों से अनुचित रूप से सुखाने या दग्ध पाउडर की जांच की जाएगी।

19. सफेदी सुखाने की सुविधाओं की प्रक्रिया

19.1 सुखाने की सुविधाएं इस प्रकार की हों कि जिससे पूर्ण सफाई हो सके और यह अनुमोदित फिल्टरों के यन्त्र से युक्त होंगी।

19.2 अन्दर जाने वाली हवा के स्त्रोत, धूल और गन्दगी से मुक्त होंगें।

19.3 यदि पूर्व मिश्रित प्रकार की भट्टियां प्रयोग की जाती हों तो यह अनुमोदित हवा के फिल्टरों से युक्त होंगी।

19.4 किण्वन टैंकों, सुखाने के बर्तनों या बेल्टस छीलने वाला क्यूरिंग रैकों और सूखी सफेदी के चूर्ण करने से तसले के लिए प्रयोग किए गए उपकरण किसी ऐसे तरीके की अनुमोदित सामग्री के बने होंगे जो सफाई के लिए योग्य होगी।

19.5 बदलने वाले मशीनों की संरचना अनुमोदित सामग्री द्वारा की जाएगी तथा इस प्रकार के उपकरण पूर्णतः स्वच्छ होंगे और एल्यूमयून किस्म के उत्पादों के निर्दिष्टिकरण के अनुसार होगा।

20. एल्यूमन फ्लैक प्रक्रिया सुखाने का संचालन

20.1 किण्वन सुखाने और क्यूरिंग कक्ष को धूल मुक्त स्थिति में और मक्खियों, कीटों तथा कृन्तक से मुक्त रखा जाएगा।

20.2 सुखाने की इकाई, रैकों और ट्रकों को साफ और स्वच्छता की स्थिति में रखा जाए।

20.3 सुखाने के बर्तन, ट्रे, बेल्टस, छिलने वाला या क्यूरिंग रैकों का यदि प्रयोग किया जाता है तो इनको स्वच्छता की दशा में रखा जाए।

20.4 तेल लगाने में प्रयोग किए गए तेलों और बाक्स का प्रयोग सुखाने वाले बर्तनों में ट्रेयों में खाद्य क्वालिटी के होंगे।

20.5 संप्रेषण या बदले सूखी एल्यूमन के लिए प्रयोग किए गए उपकरण स्वच्छ दशा में रखा जाएगा।

21. सुखाना संमिश्रण, पैकिंग और ताप उपचार कक्ष और सुविधाएं

21.1 सामान्य-प्रक्रिया कक्ष को स्वच्छता की स्थिति में रखा जाए तथा मक्खियों, कीटों और कृन्तकों से मुक्त रखा जाएगा, सुखाने संमिश्रण और पैकिंग कमरों को पूर्णतः प्रकाशमय होंगे और छत दीवार और सतह टाइल से बन्द की जाएगी तथा एनेमल पेण्ट या पानी के रिसाव की सामग्री से बचाया जाएगा।

(1) छत को सतह को टूटी हुई या खुरदरा होने से मुक्त रखा जाएगा जहां पर कि गंदे पानी का रिसाव हो।

(2) दीवार के अन्तरीय भाग और छत के गंदे पानी को निकालने के लिए नाली बनाई जाएगी।

(3) औजारों और उपसाधनों के भण्डारकरण के लिए धातु की भण्डारण रैकों या केबिनटों का प्रबन्ध किया जाएगा।

21.2 खाद्य अण्डा उत्पादों के सूखे संमिश्रण जिसमें खाद्य सूखे संघटों का संवर्धन भी सम्मिलित है और/अथवा छिड़काव सुखाने के उत्पादों की पैकिंग अन्य प्रसंस्करण संक्रियाओं से पृथक किसी कक्ष में की जाएगी। सूखे संमिश्रण किसी अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है परन्तु यह है कि यह किसी अनुमोदित बन्द संमिश्रण प्रणाली से संपादित हो।

(1) पास्चुरीकृत उत्पादों के लिए संमिश्रण और पैकिंग कक्ष में बाहर की अनुमोदित फिल्टरीकृत अनुकूल हवा आने का प्रबन्ध किया जाएगा।

(2) संमिश्रण और पैकिंग उपकरण और उपसाधन जो सूखे उत्पाद के सम्पर्क में आते हैं किसी अनुमोदित संरचना बिना खुली दरारों वाली होगी और ऐसी सामग्री की संरचना होगी जिसे साफ रखा जा सके तथा जिसका उत्पाद पर हानिकारक प्रभाव न पड़ सके। काम करने की मेजें बिना खुली परतों के अनुमोदित धातु की संरचना होगी और जिसकी सतहों की आसानी से पूर्णतः सफाई की जा सके।

(3) फ्लैज लाइनर स्वच्छता की किसी ऐसी रीति से रखे जाएंगे जिससे संचालन में प्रयोग किए गए उपकरण और प्रदाय फर्श से दूर रखा जा सके।

(4) सूखे अण्डों के पैकेजिंग में प्रयोग किए गए बर्तन हमेशा स्वच्छ रखे जाएंगे और जब भी संदूषित हो, स्वच्छता से साफ किए जाएंगे। उडगेंती, ब्रूशों, कापियों और अन्य समान उपकरण का ऐसे सेनीटरी केबिनेटों या रैकों में भण्डारण किया जाएगा जिनकी इस प्रयोग करने के लिए व्यवस्था की गई हो।

(5) स्वचालित डिब्बा पूरक किसी ऐसी किस्म का होगा जो डिब्बों में उत्पाद की दी गई मात्रा को यथोचित रूप से भर सके। भरे गए डिब्बों का भार यथोचित रूप से जांच करने के लिए पैमानों का प्रबन्ध किया जाएगा। सूखे अण्डा उत्पाद के यान्त्रिकतः पैकेजिंग में प्रयुक्त होने वाले सभी उपकरण प्रतिदिन निर्वात साफ होंगे।

21.3 उष्मा उपचार कक्ष किसी अनुमोदित संरचना के होंगे और उसका रख-रखाव स्वच्छ दशा में होगा। वह कक्ष या कमरे पर्याप्त आकार के होगा/होंगे, जिससे उष्मा उपचारित किए जाने वाले उत्पाद के लिए यथोचित उष्मा और हवा चक्रण के लिए खाली स्थान मिल सके। कक्ष यथोचित उष्मा प्रदाय और लगातार हवा चक्रण प्रणाली से युक्त होगा।

22. सूखे अण्डों का भण्डारण :—सूखे अण्डों का भण्डारण प्लांट में उत्पादन इस प्रकार होना चाहिए ताकि उसको उचित रूप से परिरक्षित किया जा सके और उसको साफ तथा सूखा और आपत्तिजनक गंधों से मुक्त रखा जाएगा।

23. धुलाई और कक्षों की सफाई या क्षेत्रीय सुविधाएं

23.1 कमरे या परिसरों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था होगी। तथा संचालन के समय जो अनुपात अपेक्षित हो उसके आधार पर संचालक पर्याप्त आकारों के उचित रूप से उन उपकरणों की धुलाई और सफाई अनुज्ञेय हो सके। पर्याप्त एग्जास्ट यह सुनिश्चित करने के लिए उगाए जाएंगे कि उनसे दुर्गन्ध और वाष्पों का तुरन्त उन्मूलन होता रहे तथा तोड़ने के कक्ष में हवा का प्रवाह नहीं होगा। यदि धुलाई और सफाई तोड़ने के कक्ष में नहीं जाती है तो वह क्षेत्र तोड़ने के क्षेत्रों से अलग होंगे तथा सुव्यस्थित रूप से हवा हेतु उसमें रोशनदान होंगे जो कि संचालन प्रक्रियाओं से सीधे नहीं जुड़े होंगे ताकि दुर्गन्ध और वाष्प तोड़ने के क्षेत्रों में प्रवेश न कर सके।

23.2 दीवारों और छतों की सतह टाइलों, एनेमल पेण्ट या कोई अन्य जलरोधी सामग्री से बनी होंगी।

23.3 फर्श में नालियों के लिए पर्याप्त ढलान होगी और वह कटाव और क्षरण सतह से मुक्त होंगे जहां पानी और धूल का प्रवेश नहीं होगा और दीवार के आन्तरिक भाग में पानी नहीं पहुंचेगा।

24. सफाई एवं स्वच्छता सम्बन्धी अपेक्षाएं

24.1 सफाई :

(1) अण्डे प्रसंस्करण प्रक्रिया में जो उपकरण तरल अण्डों या बाह्य खाद्य उत्पाद की सफाई के लिए जो आवर्णक तत्व को निकालने और वर्णक अवशिष्टों को निकालने के लिए हैं उन्हें स्वच्छतापूर्वक सफाई से रखा जाएगा, जबकि उन्हे विशेष प्रभाव से साफ न किया जाए, इसमें सफाई की कोई भी पद्धति अपनाई जा सकती है, परन्तु प्रमुख रूप से जब तक सफाई में उच्च दाब का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठोस उपकरणों को ठण्डे पानी से प्रवाहित कर देना चाहिए। जब भी आवश्यक हो उसको अण्डों में डिटर्जेण्ट युक्त गर्म पानी में प्रक्षालक से घूर्ण करके तथा पानी से खंगाल कर रखना चाहिए। यह आवश्यक होगा कि उपकरण की सतह को बारीकी से साफ किया जाए, यदि आवश्यक हो तो प्रभावी रूप से सफाई भी की जा सकती है।

(2) उपकरणों को ऐसी बारम्बारता से साफ किया जाएगा जिसमें कि सफाई सम्बन्धी अपेक्षाओं के अन्तर्गत अन्यत्र विनिर्दिष्ट विशेष प्रक्रिया और उपकरण का विशेष प्रकार सम्बन्ध होगा।

(3) स्थान पर ही सफाई मान्य होगी (सी. आई. पी.) यदि प्रक्रिया और पद्धति में मानव द्वारा सफाई की गयी हो या उस उपकरण की सफाई खण्डों में की गयी हो, उसी स्थिति में मान्य होगी। सक्षम प्राधिकारी स्थान पर ही सफाई अपेक्षाओं (प्रक्रियाओं) को स्वीकार्य करेगी और जीवाणु जांच की अपेक्षाएं तथा उपकरणों के कालिक खण्ड में ऐसी निश्चितताओं के आधार होंगे।

24.2 स्वच्छता :

(1) ऐसी पद्धति से सम्पन्न होगी जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हों।

(क) रसायन और मिश्रण जो स्वच्छता के लिए प्रयोग किए जाएंगे वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होंगे।

(ख) सफाई के लिए यदि हाईपोक्लोराइट प्रयोग किया जाता है या सफाई उपकरण की सतहों की सफाई करने के लिए ऐसा घोल जिसमें अधिकतम क्षमता 200 पी पी एम उपलब्ध क्लोरीन या उसके समतुल्य कोई घोल सम्पर्क होगा। जब कभी इन घोलों की क्षमता 100 पी पी एम या उपलब्ध क्लोरीन से कम या इसके समतुल्य हो जाती है तो बदल दिया जाएगा।

(2) अण्डे के छिलकों को स्वच्छता से और जिस उपकरण को साफ किया गया है और जो उपकरण खाद्य उत्पादों के सम्पर्क में आते हैं, उनको स्वच्छता के उपरान्त साफ जल से खंगाल। जाएगा। यदि हाईपोक्लोराइट से भिन्न कोई स्वच्छता माध्यम का प्रयोग किया जाता है तो वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा जब तक या या अन्यथा अनुमोदित नहीं किया जाता है, उनका प्रयोग नहीं किया जाएगा।

25. कार्मिकों का स्वास्थ्य और स्वच्छता

25.1 कार्मिक सुविधाएं, जिसमें प्रसाधन भी सम्मिलित होंगे, शौचालय, लांकर्स और ड्रेसिंग कक्ष यथोचित मात्रा में होंगे और खाद्य प्रसंस्करण प्लांट पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा।

25.2 प्रसाधन कक्ष और ड्रेसिंग कक्ष में साथ तथा दुर्गन्ध हटाने के लिए पर्याप्त मात्रा में रोशनदान होंगे तथा उनमें पर्याप्त मात्रा में साबुन, तौलिया और टिसूज रखे जाएंगे, प्रसाधन कक्ष के बाहर भी पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था होगी।

25.3 कोई भी व्यक्ति संक्रामक रोगों से प्रभावित नहीं होगा या छुआछूत की स्थिति में नहीं होगा या किसी असाध्य रोग से ग्रसित नहीं होगा या किसी भी प्रकार के फोड़े, घाव या छुआछूत वाले जख्म या हाथों पर पट्टियां नहीं बंधी होंगी वह किसी भी व्यवस्था में अण्डों के सम्पर्क में नहीं आएगा या ऐसे अण्डों की प्रक्रिया में जो उपकरण प्रयोग में आते हैं, उनके सम्पर्क में नहीं आएगा।

25.4 जो कार्मिक तरल या सूखे अण्डों, डिब्बों, आधानों या उपकरणों के सम्पर्क में आते हैं, एक चोगा पहनेंगे जो कि साफ होगा।

25.5 एकक कार्मिक खुले खाद्य उत्पाद पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अपने हाथ धोएंगे और कार्य कक्ष छोड़ने के पश्चात् काम से लौटने पर भी हाथों को साफ करेंगे।

25.6 थूकना खंखारना एवम अन्य अस्वास्थ्यकर तरीके अनुज्ञेय नहीं होंगे।

25.7 तम्बाकू का किसी भी अवस्था में प्रयोग न करना या आभूषण पहनना, नाखून, पालिश या सुगंधित द्रव किसी भी क्षेत्र में अनुज्ञेय नहीं होंगे जहां पर खाद्य पदार्थ खुले में रखे हों।

25.8 बालों की जाली या टोपी सभी कार्मिक उचित रूप से पहनेंगे चाहे वे तोड़ने के कक्ष में हों या पैकिंग कक्ष में हों।

26. तरल अण्डों का पेस्चुरीकरण

26.1 पेस्चुरीकरण सुविधाएं:—अण्डा उत्पादों के पेस्चुरीकरण के लिए सुविधाएं यथोचित होंगी और अनुमोदित संरचना की होंगी ताकि सभी उत्पादों की प्रक्रियाएं जैसी इस अध्याय में दी गई, वैसी ही किया जा सके। तरल अण्डा उत्पाद के लिए पेस्चुरीकरण उपकरण जिसमें एक होल्डिंग ट्यूब एक स्वचालित बहाव मोड़ने का थर्मल नियन्त्रण और पेस्चुरीकरण के लिए अनुपालना निश्चित करने के लिए अंकित करने की युक्तियां जो इस अध्याय के पैरा 26.2 में आगे दी गई हैं, भी सम्मिलित होंगी। उष्मायित तरल अण्डा उत्पाद का ताप प्रसंस्करण के दौरान लगातार और स्वचालित रूप से अंकित होगा।

26.2 पेस्चुरीकरण संकालन :—सभी उत्पादों के प्रत्येक कप को अपेक्षित ताप के लिए उष्मायित किया जाना चाहिए और अपेक्षित न्यूनतम समय लगाने तक के लिए जैसा इस अध्याय में आगे दिया गया है उस ताप का ठहराव किया जाना चाहिए। इस अध्याय की सारणी 2 में सूचीबद्ध ताप और समयधारणकरन न्यूनतम हैं। उत्पाद उच्च तापों में उष्मायित किया जा सकता है। पेस्चुरीकरण प्रक्रियाएं पेस्चुराइजेशन और उसके ठहराव पैकिंग सुविधाओं को पूर्ण सुनिश्चित करेगी और संचालन इस प्रकार से होगा जो उत्पाद का संदूषण से बचाव कर सकेगा।

26.3 पेस्चुराइजेशन की अन्य पद्धति सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होंगी, जब इस प्रकार के उपचार उन उत्पादों के लिए जो इस अध्याय के पैरा 26.2 में विनिर्दिष्ट उपचारों के समतुल्य प्रभाव देते हैं या अन्य उत्पाद और परिणामस्वरुप अन्य उत्पादनों में सालमोनेला शून्य नहीं होगा।

27. सूखे सफेद हेतु ताप उपचार :—सफेद सूखे उत्पाद के लिए ताप अपेक्षाएं पेस्चुराइजेशन पद्धति द्वारा अनुमोदितानुसार होंगी और उत्पाद को नियमित ऐसे समय में गर्म करते रहना चाहिए, परिणामस्वरूप ऐसें तापों में सालमोनेला की उपस्थिति गनण्य होगी।

27.1 तापीय उपचार किए जाने वाले उत्पाद को बन्द डिब्बों में अध्याय कक्ष में तापीय उपचार हेतु रखा जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उस स्थान में पर्याप्त ताप प्रवेश कर गया है और वायु चक्रय की पर्याप्त व्यवस्था है। प्रत्येक डिब्बे पर उत्पाद के प्रकार की पहचान होगी। स्प्रे या बर्तन में सुखाया हुआ और उस पर लाट न. या उत्पाद कोड नम्बर भी अंकित किया जाएगा।

27.2 स्प्रे या बर्तन में सुखाए हुए एल्युमेन के उष्म उपचार के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं निम्नलिखित होंगी :—

(1) छिड़क कर सुखाया हुआ एल्युमिन हमेशा 55 डिग्री सें. ग्रे. के तापमान से कम नहीं होगा और सात दिन से कम पर लगातार नहीं रखा जाएगा और जब तक कि उसमें सालमोनेल्ला शून्य न हो जाए।

(2) बर्तन में सुखाया हुआ एलयुमिन 52 डिग्री सें. ग्रे. से कम ताप पर निरन्तर रखा जाएगा और इसी ताप पर 5 दिन से कम नहीं रखा जाएगा जब तक कि उसमें सालमोनेला शून्य न हो जाए।

(3) इस अध्याय के पैरा 27.2 (1) और 27.2 (2) में सूचीबद्ध से भिन्न स्प्रे या बर्तन में सुखाए एलयूमिन के ताप उपचार की पद्धतियों उन संतोषजनक साक्ष्यों की प्राप्ति पर कि ऐसी पद्धतियां परिणामस्वरूप उत्पादों में सालमोनेल्ला नगण्य दिखाएगी जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जा सकेगी।

27.3 सुखाए गए सफेद भाग को शुष्क रूप में लाने के लिए उनको अधिकतम ताप पर गर्म किया जाएगा, उनका नमूना लिया जाएगा और सालमोनेल्ला की उपस्थिति का विश्लेषण किया जाएगा जैसा अध्याय XII के II में अपेक्षित है।

27.4 एक वर्ष के लिए निम्नलिखित अभिलेख रखे जाएंगे :—

(1) उत्पाद के प्रकार

(2) लॉट # की संख्या

(3) ऊष्मा उपचार कक्ष में के लिए

(4) उत्पाद का ताप

(5) ऊष्मा उपचार कक्ष में उत्पाद को दी गयी अवधि

(6) सालमोनेल्ला की उपस्थिति, प्रयोगशाला विश्लेषण के सभी परिणाम ।

27.5 इस अध्याय में विनिर्दिष्ट सभी लागू अपेक्षा जो सूखे सफेद भाग के प्रसंस्करण किए गए हैं उनके पेस्चुराइज लेबलित किया जाएगा ।

सारणी—1

तरल अण्डे उत्पाद के लिए न्यूनतम शीतन और ताप अपेक्षाएं

तोड़ने के 2 घण्टे के भीतर का अनपेस्चुराइड उत्पाद ताप

उत्पाद	तरल उत्पाद से भिन्न 8 घण्टे या उससे कम रखा जाने	तरल लवण उत्पाद से भिन्न, 8 घण्टे अधिक रखा जाने	तरल लवणीय उत्पाद	पेस्चुराइजिंग करने के उपरान्त 2 घण्टे के भीतर का ताप	स्थिरता के बाद 3 घण्टे के अन्तराल का तापमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सफेद (अस्थिर)	13° सी या न्यून	7 या न्यून	—	7° या न्यून	—
सफेद (स्थिर)	21° सी या न्यून	13 या न्यून	—	13° या न्यून, यदि 8 घण्टे रखा गया हो	(1) यदि 8 घण्टे रखा गया हो या 7° सें. ग्रे. न्यून या कम हो या 5 डिग्री सें. ग्रे. या न्यून
अन्य सभी उत्पाद (सिवाय जिसमें 10% नमक या उससे अधिक मिला हो	7° सी या न्यून	5 या न्यून	—	7° सें. ग्रे. न्यून या 5 डिग्री. सें. ग्रे. या 8 घण्टे न्यून	
तरल अण्डा उत्पाद जिसमें 10% नमक मिलाया गया हो	—		—		30 घण्टे या न्यून या अधिक 18 डिग्री सें. 7 डिग्री सें. ग्रे. 0 न्यूनतम न्यूनतम

1. ग्लोकोस निकालने के बाद जैसा कि संभव हो, स्थिर तरल श्वेत सुखाया जाएगा, लगातार प्रक्रिया के लिए तरल श्वेत का एक सीमा तक भण्डारण आवश्यक होगा।

2. शीतलन प्रक्रिया लगातार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई नमक का उत्पाद 24 घण्टे से अधिक समय तक ठण्डा किया गया हो, ठण्डा माना जाएगा और 7° सें० ग्रे० पर या उससे न्यूनतम पर स्थिर रखा जाएगा।

सारणी—2

पेस्चुराइजेशन अपेक्षाएं

तरल अण्डे उत्पाद	न्यूनतम ताप अपेक्षाएं (डिग्री सें. ग्रेड)		न्यूनतम रखे गए समय सम्बन्धी अपेक्षाएं (मिनटें)
(1)	(2)		(3)
एल्यूमिन (बिना रसायन के)	55	56	3.5
साबुत अण्डे	60	3.5	6.2
साबुत अण्डों का संमिश्रण 2%	61	3.5	
अण्डे के अतिरिक्त मिलाई गयी न्यूनतम सामग्री	60	6.2	
साबुत अण्डों को सुरक्षित रखना।	61		3.5
और इसका मिश्रण 24—38% ठोस अण्डे 2-12% अण्डों के अतिरिक्त मिश्रण सामग्री	60		6.2
साबुत अण्डों पर नमक लगाना।	63	3.5	
2% या उससे अधिक नमक सहित	62		6.2
साबुत अण्डों में शर्करा मिश्रण	61	3.5	
12—12% शर्करा सहित सादा,	60		6.2
सादा जर्दी	61		3.5
	60	6.2	
शर्करा जर्दी 12% या अधिक	63		3.5
अतिरिक्त शर्करा मिश्रण	62		6.2
नमक की जर्दी 12—12% अधिक	63		3.5
नमक मिश्रण	62		6.2

प्रयोगशाला

11. प्रयोगशाला परीक्षण और विश्लेषण

प्रयोगशाला के परीक्षण और विश्लेषण

अनुमोदित प्लांट नियमों और विनियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिये परीक्षण और विश्लेषण करेगी।

(1) नमूने तरल प्रतिशतित या सूखे अण्डे उत्पादों के लिये जायेंगे, और उत्पाद लेबल जो कि पहचान की अनुपालना यदि कोई हो मानक हेतु विश्लेषण किया जायेगा।

(2) यथोचित पेस्चरीकरण सुनिश्चित करने के लिये पेस्चरीकृत अण्डा उत्पादों और उष्मा उपचारित सूखे अण्डे का श्वेतन के नमूने लिये जाएंगे और ऐसे अनुक्रम, आवृत्ति तथा अनुमोदित प्रयोगशाला पद्धति जो इन नियमों में विदित है, के अनुसार साल्पोनेल्ला की उपस्थिति के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा विश्लेषण किया जायेगा।

(3) विश्लेषण और परीक्षण परिणाम सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करा दिये जाएंगे।

(4) सक्षम प्राधिकारी पुष्टिकरण नमूने लेगा तथा उनको प्लांट की जांच और विश्लेषण की यथेष्टता ज्ञात करने के लिये उसी के खर्च पर प्रयोगशाला में भेजेगी।

अध्याय—XIII

उत्पाद का पहचान करना

1. अण्डा उत्पाद में लेबलों की आवश्यकता :

खाद्य अण्डा उत्पादों के डिब्बे तथा सहजता से ले जाने वाली टंकियां पर अनुमोदित प्लांट को छोड़ने से पूर्व इस अध्याय के पैरा 2 से 5 तक के अनुसार लेबल लगाये जायेंगे तथा पैरा 3 की आकृति 2 या 5 की आकृति में दर्शित शासकीय चिन्ह धारण करेगा, तरल पेस्चुराइज्ड अण्डे उत्पाद का भारी यातायात पोत लदान गैर सरकारी मील द्वारा बन्द नहीं किया जाएगा।

2. अण्डा उत्पाद प्लांट के प्रयोग के लिये लेबलों का अनुमोदन तथा विधिक अपेक्षाएं

2.1 कोई डिब्बा, या पैकिंग सामग्री, जिस पर शासकीय पहचान लगी हो उस पर कोई झूठा या भ्रमिक करने वाला विवरण नहीं लगेगा, कोई भी लेबल, डिब्बा या पैकिंग सामग्री जिस पर शासकीय पहचान लगी हो केवल जो सक्षम प्राधिकारी विहित करे उसी तरीके के अनुसार ही प्रयोग किया जायेगा कोई भी लेबल, डिब्बा या पैकिंग सामग्री जिस पर शासकीय पहचान हो तब तक प्रयोग नहीं किया जायेगा जब तक कि इस अध्याय के पैरा 2.2 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हो, अन्तिम लेबलों का प्रयोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविहित अनुमोदन के अनुसार, किया जायेगा, यदि लेबल छपा हुआ हो या डिब्बा, पैकिंग सामग्री पर सीधा लगा दिया गया हो तो उस पर प्रदर्शित लेबल को प्रधान के रूप में माना जायेगा।

2.2 कोई भी लेबल डिब्बा या पैकिंग सामग्री जिस पर शासकीय पहचान हो तब तक नहीं छपवाया जा सकता या प्रयोग के लिये तैयार किया जा सकेगा जब तक मुद्रणकर्ता या अन्य अन्तिम प्रूफ, इस अध्याय के विनियमों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं किये जाते है। अनुमोदन के लिये दी गई प्रत्येक लेबल की प्रतियां निम्न-लिखित सहित संलग्न होंगी।

1. अण्डा उत्पाद जिस आकार में प्रयोग किया जाता है, का वर्णन जिसमें साधारण या प्रचलित शब्दों के प्रकार और तत्वों की प्रतिशतता प्रदर्शित की जायेगी (उदाहरणतया तरल या सूखा) समय-समय पर प्रतिशतता परिवर्तित होती रहती है, ऐसे मामलों में वहां लगभग प्रतिशतता रेंज दी जा सकेगी।

2. जब भी अपेक्षित होगा, वैज्ञानिक आंकड़े यह प्रदर्शित करेंगे कि तत्व या मिश्रण संरक्षित है और उसके आशयित प्रयोग करने पर प्रभावी होगा।

2.3 शासकीय पहचान धारण करने वाले उत्पाद के डिब्बों पर निम्नलिखित जानकारी प्रदर्शित की जायगी।

(i) साधारण या प्रचलित नाम, यदि कोई हो और यदि उत्पाद में दो या अधिक तत्व समाविष्ट है, भार तत्व आयतक के अनुसार अनुपातों में से अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किये जायेंगे, जब जल इसमें वह भी सम्मिलित है, जो संधारित सुखाए हुए तत्व सामान्य मिश्रण में वापिस आ जाते हैं, तरल या प्रशीतित अण्डों में मिलाया जाता है या उसे तरल तत्व में मिलाया जाता है, इन तत्वों में सामान्य से जल अधिक होगा, मिश्रित जल की कुल मात्रा जिसमें जल में सेलेगोस या सब्जी तत्व प्रयोग किये जाते हों, वह लेबल पर तत्वों के विवरण में कुल उत्पाद भार की प्रतिशतता लिखे हुए होंगे।

(ii) नाम, पता और निर्यातक का पिन कोड

(iii) लोट संख्या या उत्पाद की कोड संख्या

(iv) शुद्ध माल,

(v) शासकीय पहचान चिन्ह तथा प्लांट संख्या.

(vi) अण्डा उत्पाद जो कि अनुमोदित संयंत्र में वर्तमान उत्पादन से भिन्न के खाद्य छिलके उत्पादित हैं या अन्य अण्डा उत्पाद जो कि वर्तमान अण्डा उत्पादन से भिन्न के छिलके वाले अण्डों से उत्पादित किय गये हैं, उस पर स्पष्ट रूप से और एक दूसरे से अलग-अलग प्रकार का लेबल जो कि उत्पादन आम या सामान्य नाम के समीप होगा जैसा कि "वर्तमान उत्पादन से भिन्न के अण्डों से निर्मित"।

(vii) अण्डा उत्पाद जो कि खाद्य छिलके वाले अण्डों या उत्पादित हुए अण्डा उत्पाद को टर्की, बत्तख हंसनी या गिनिया फादन घरेलू मुर्गी से उत्पादित हुए हैं, उनके बारे में उत्पादों पर स्पष्ट रूप से अलग-से दिखाने वाले लेबलों पर उत्पाद का नाम या सामान्य नाम यह दिखाए कि अण्डों का प्रकार या अण्डा उत्पाद जो कि उत्पाद में प्रयोग में आये हैं जैसे कि "जमे हुए साबुत टर्की अण्डे जमे हुए साबुत चिकित और टर्की अण्डे" अण्डा उत्पादों जिन पर बिना अलग शब्दों में लेबल लगे हुए है, उनको घरेलू मुर्गी के छिलके वाले अण्डों से उत्पादित किये जाएगें या अण्डा उत्पाद वैसे ही छिलके वाले अण्डों से उत्पादित किये जाएंगे।

2.4 तरल या जमे हुए अण्डों उत्पाद जिनकी पहचान साबुत अण्डों और अनको प्राकृतिक अनुपात से भिन्न तैयार किया गया है, जैसे छिलके से टूटा हुआ, उनके अन्दर 24.20 प्रतिशत या अधिक कुल अण्डा ठोस अंतर्वस्तु विद्यमान होगी।

2.5 अण्डा उत्पादों पर लगाए गए लेबललोकं पर पोषण सामग्री की सभी सूचना सम्मिलित की जाएगी, ऐसी लेबलिंग के लिए प्रचालित विनियमों को जो कि लागू हैं उनकी शर्तों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए डिब्बा बन्द अण्डा उत्पादों की अपेक्षा जो कि बेचने या बांटने के लिए नहीं है, और विनियम उनसे अलग है, लेवल जो प्रस्तुत किए जाएंगे उनके साथ यह सूचना उपदर्शित होगी कि वह उपभोक्ता वाले या बड़े मात्रा के उत्पाद के डिब्बे है, उत्पाद में पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन और खनिज डाले गए हों तो पोषण तत्वों की लेबलिंग आवश्यक है या जब पोषकता के लिए घोषणा या सूचना प्रस्तुत की गयी है, लेबलिंग के सम्बन्ध में, निम्न-लिखित के बारे में जिनके अलावा जो पोषकता सम्बन्धी लेबलिंग से मुक्त हो

(1) अण्डा उत्पाद जो कि बड़ी मात्रा में केवल दूसरे खाद्यों के निर्माण के लिए भेजे गए हैं, परन्तु उपभोक्ताओं के लिए बड़ी मात्रा में या डिब्बों में नहीं रखे जायेंगे ।

(2) अण्डा उत्पाद जिनमें शामिल है विटामिन, खनिज या प्रोटीन, इनके बारे में लेबल पर पोषकता के बारे में घोषणा की गयी हो या विज्ञापन में जो कि संस्थान में केवल खाद्य प्रयोग के लिए प्रदाय किया गया है, परन्तु निर्माता के बारे में पोषकता के बारे में आवश्यक सूचना संस्थानों को सीधे उपलब्ध कराता है।

(3) कोई भी पोषकता मात्र प्रौद्योगिकी प्रयोजन के लिए उत्पाद में शामिल किए गए हैं, बिना पोषक तत्वों के लेबलिंग करने की अनुपालना की घोषणा केवल तत्वों के यदि पोषक तत्व की अन्यथा लेबलिंग के संदर्भ के प्रति निर्देश से या लेबलों के विज्ञापन में नहीं किया गया है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन नहीं किया जाएगा ।

3. शासकीय पहचान चिह्न और निरीक्षण निशान का रूप ।

3.1 इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए आकृति–1 में दी गई सील में अन्तर्विष्ट अक्षर शासकीय पहचान चिह्न होगा ।

सक्षम प्राधिकारी की मुहर

आकृति–1

3.2 खाद्य अण्डा उत्पादों के डिब्बों पर जो निरीक्षण का चिह्न प्रयोग में लाए जाते हैं, उनको आरेख की बाहरी रेखाओं के भीतर बनाया जाएगा और इस अध्याय की आकृति 2 में दिए गए शब्दों और डिजाइन वाला होगा; सिवाय इसके यदि किसी दूसरे डिब्बे पर लगाया जाता है तो संयंत्र संख्या को शासकीय पहचान हटाया जा सकता है ।

सक्षम प्राधिकारी की सील

निरीक्षण अण्डा उत्पाद ------
संयंत्र संख्या ----------

आकृति 2

4. उत्पाद जिन पर शासकीय निरीक्षण चिह्न लगा हो

अण्डा उत्पाद जिन पर निरीक्षण चिन्ह लगाने की आज्ञा मिल चुकी है उनका खाद्य छिलके वाले अण्डों से या दूसरे खाद्य अण्डा उत्पादों के अनुमोदित संयंत्र में प्रसंस्करण किए जाएंगे और उनमें दूसरे खाद्य तत्व हो सकते हैं, शासकीय चिह्न मुद्रित होगा या प्रस्तर मुद्रित होगा और डिब्बे के प्रधान पेनल संदर्श के एक भाग के रूप में लगाया जाएगा परन्तु अलग होने वाले ढक्कन पर नहीं लगाया जाएगा ।

5. अन्य शासकीय पहचान का प्रयोग

अन्य शासकीय पहचान जो इस अध्याय में दर्शित है मुद्रित होगी या प्रस्तर मुद्रित होगी और प्रधान पेनल पर दिखाया गया होगा लेकिन अलग होने वाले ढक्कन पर नहीं लगाया जाएगा, यदि किसी दूसरे लेबल पर या डिब्बे पर लगाया जाता है तो संयंत्र संख्या को पहचान से हटाया जा सकता है, ऐसे उत्पाद सभी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे जो कि अण्डा उत्पादों के लिए, पैरा 3 में वर्णित शासकीय निरीक्षण चिह्न धारण करने के लिए अनुताप पास्चुरीकरण, ताप उपचार के अलावा या अन्य ऐसी कोई उपचार की पद्धतियां जो सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाएंगी ।

5.1 अण्डा उत्पादों में पैक किए गए रूप में किसी अनुमोदित संयंत्र में भेजे गए सभी अपपास्चुरीकृत को इस अध्याय की आकृति 3 में दिए गए पहचान चिह्न से चिह्नित किया जाएगा । पास्चुरीकरण या उपचार के बाद उत्पाद पर 5.2 में दिखाए गए के अनुसार शासकीय निरीक्षण का निशान लगाया जा सकता है ।

अण्डा उत्पाद
अनुमोदित प्लांट में आगामी प्रसंस्करण

आकृति – 3

6. अनुमोदित लेबल का अप्राधिकृत प्रयोग अथवा उसका प्रयोग न किया जाना ।

6.1 डिब्बे अथवा लेबल जो पैरा 2 के अनुसरण में प्रयोग के लिए अनुमोदित शासकीय पहचान धारण करते हैं केवल उस प्रयोजन के लिए ही प्रयोग किए जाएंगे जिसके लिए अनुमोदित किए गए हैं । अनुमोदित डिब्बे या लेबलों के जो शासकीय पहचान धारण करते हैं किसी अप्राधिकृत प्रयोग अथवा उसका प्रयोग न किए जाने से अनुमोदन निरस्त हो जाएगा ।

6.2 इन नियमों के अनुसरण में किसी अनुमोदित संयंत्र में निरीक्षण सेवाओं की समाप्ति पर शासकीय पहचान धारण करने वाले सभी लेबल मुहरें, बंधन अथवा पैकिंग सामग्री को सक्षम प्राधिकारी के किसी व्यक्ति के पर्यवेक्षण के अधीन या तो नष्ट कर दिया जाएगा या शासकीय पहचान को पूर्ण रूप से मिटा दिया जाएगा या अविष्कृत कर दिया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी को स्वीकार्य किसी रीति में सील बन्द कर दिया जाएगा ।

7. चिन्हांकन और पैकिंग का पर्यवेक्षण

7.1 लेबल अनुमोदन की शर्त :–सक्षम प्राधिकारी किसी परीक्षण किए गए उत्पाद पर शासकीय पहचान के प्रयोग की अनुज्ञा तब तक नहीं देगा जब तक फाइल पर यह

साक्ष्य नहीं हो जाता है कि इस प्रकार की शासकीय पहचान या रखने वाली पैकिंग सामग्री पैरा 2 के निर्बंधन के अनुसार अनुमोदित की गई है ।

7.2 शासकीय पहचान का लगाया जाना :—समक्ष प्राधिकारी के अलावा किसी के द्वारा किसी उत्पाद या डिब्बा पर कोई शासकीय पहचान नहीं चिपकाई जाएगी या चिपकाया जाना कारित किया जाएगा या लगाई जाएगी । इस प्रकार सभी उत्पादों का निरीक्षण इन नियमों के अनुसार किया जाएगा, किसी शासकीय पहचान रखने वाली सभी सामग्री के प्रयोग और रख-रखाव पर सक्षम प्राधिकारी देखभाल करेगा ।

8. शासकीय पहचान रखने वाले डिब्बों का पुनः प्रयोग निषिद्ध :—किसी भी व्यक्ति द्वारा शासकीय पहचान रखने वाले डिब्बों का पुनः प्रयोग (किए जाने वाले) जब तक ऐसे पहचान उसमें पुनः पैक उत्पाद सभी प्रकार से लागू नहीं होते है । ऐसे दृष्टान्तों में डिब्बे और लेबल का प्रयोग किया जा सकता है परन्तु यह तब जब पैकेजिंग का कार्य सक्षम प्राधिकारी की देखरेख में सम्पन्न किया जाता है और डिब्बा अध्याय XII के पैरा 3 की अनुपालना में है ।

अध्याय – XIV

1. अण्डा

1.1 "अण्डे" से अभिप्राय है घरेलू मुर्गी, टर्की, बत्तख, हंसनी या गुइनिया फोउल कुछ नाम जो अण्डे के छिलके को लागू होते है वे निम्न प्रकार है :—

(i) "चैक" से अभिप्राय अण्डे का छिलका टूटा होना व छिलका में दरार परन्तु छिलका की झिल्ली पूरी ठीक हो और अन्तर्वस्तु रिसाव युक्त न हो ।

(ii) "साफ और छिलका अण्डा से अभिप्राय है अण्डा जिसका छिलका चिपकाने वाली सामग्री से मुक्त है और जो दरार मुक्त और टूटा हुआ नहीं है ।

(iii) "गन्दे अण्डे से अभिप्राय है कोई अण्डा जिसका छिलका टूटा हुआ नहीं है और जिस पर चिपकने वाली गंदगी बाह्य सामग्री या मुख्य धब्बे लगे हुए है ।

(iv) "अण्डा का स्वरित उत्पादन" अण्डे का तुरन्त किया हुआ उत्पादन जो कि विपणन के लिए उचित माध्यम से प्राप्त किया जाता है वह 60 दिन से अधिक अवधि का न हो ।

(v) "इनेडेबल" से अभिप्राय है अण्डे का काला रोट पीला रोट, सफेद रोट, मिश्रित सडापन, खट्टा, हरा, सफेद, स्टक पीला वाला अंडा, माल्डी अंडा सारसोई अंडा, खूनी अंडा परत के अंडे और एमब्री अंडा (खून के घेरों की सतह पर या उसके बाहर)

(vi) "लीकर" से अभिप्राय है वह अंडा जो जिसमें छिलके के दरार या टूटा है और उसकी झिल्ली इस मात्र तक विस्कृत है कि अंडे की अन्तर्वस्तु दिखाई दे या रिस रहा है या छिलका से रिसने के लिए मुक्त है ।

(vii) "अंडा सेने के यंत्र द्वारा अस्वीकृत" से अभिप्राय कोई अंडा जो सेने के लिए रखा गया है और जो अंडे सेने की क्रिया से अंडा सेंने के संचालन के दौरान उसे प्रजनन करने के अयोग्य या अन्यथा न सेंने योग्य होने के कारण हटा लिया जाता है ।

(viii) "क्षति" से अभिप्राय है जो अंडे मानव खाद्य के लिए अनुपयुक्त हैं, क्योंकि उसमें फूटने या टूटने के कारण उसके तत्व लीक कर रहे हैं, या अधिक उष्मायित या जमाए गए हैं, या संदूषित है, वे किसी अंडा सेने वाली मुर्गी द्वारा अस्वीकृत हैं या चूंकि उसमें खूनी सफेदी ज्यादा मास के धब्बे अधिक मात्रा में खून या अन्य बाह्य सामग्री मौजूद है ।

(ix) "प्रतिबंधित अंडे" से अभिप्राय है कोई छिलका में दरार वाला अंडा, गंदा अंडा सेने के यंत्र मे अस्वीकृत अखाद्य रिसने वाला या क्षति वाला अंडा ।

(x) "सफेद" या एल्यूबामिल" से अभिप्राय किसी अंडा उत्पाद को तोड़कर छिलका और जरदी से है अलग करके प्राप्त किए गए उत्पाद से है ।

[फाईल सं० 6/1/95-ई आई एण्ड ईपी]

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक

New Delhi, the 4th August, 1997

S.O. 2078.—In exercise of the powers conferred by Section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act 1963, (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules namely :—

1. Short title and commencement : (a) These rules may be called the Export of Egg Products (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 1997.

(b) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

PART-I [APPLICABLE FOR EXPORT TO EUROPEAN UNION (EU)]

2. Definitions : In this part unless the contexts otherwise requires, the following definitions shall be applicable :

(i) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "Agency" means any agency for quality control or inspection or both established or recognised under Section 7.

(c) "Batch" means a quantity of egg products which have been prepared under the same conditions and in particular treated in single continuous operation;

(d) "Certificate" means certificate issued under sub-section (3) of section 7 of the Act stating that the commodity conforms to the conditions regarding quality control and inspection;

(e) "Competent Authority" means any one of the Export Inspection Agencies at Bombay, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras established under Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act 1963;

(f) "Consignment" means a quantity of egg products for a single delivery to one destination for further processing by the food industry or intended for direct human consumption;

(g) "Council" means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;

(h) "Country of Destination" means the country to which egg products are despatched from India;

(i) "Egg Products" means products obtained from eggs, their various components or mixtures thereof after removal of the shell and membranes, intended for human consumption; they may be partially supplemented by other food-stuffs or additives; they may be liquid, concentrated, dried, crystallized, frozen, quick-frozen or coagulated;

(j) "Country of Despatch" means India;

(k) "Merchant Exporter" means an exporter who buy the egg products from the approved egg processing plants under these rules for the pupose of exports.

(l) "Farm of production" means Farm supplying eggs intended for manufacture of egg products;

(m) "Packing" means the packing of egg products in any form of package;

(n) "Plant" means any premises where egg products are processed;

(o) "Potable Water" means water that has been approved by State Health Authority or other Agency or Laboratory acceptable to the Competent Authority as safe for drinking and suitable for food processing.

3. Basis of compliance : It is primarily the responsibility of the processors to ensure that the egg products intended for exports are handled, processed at all stages of production, storage and transport under proper hygienic conditions so as to meet the health requirements laid down under these rules and that the products conforms to the specifications given in the order by the Central Government under Section 6 of the Act.

The Competent Authority shall ensure that all the processors comply with the requirements by regular monitoring of the plant as per the control measures prescribed in the para 4.18 of this part. For effective monitoring of the scheme, Council will issue necessary instructions in this regard from time to time.

4. The egg products for Exports shall be subjected to the following conditions :

4.1 Any statutory restriction imposed by any State/Central Government with respect to commercial environmental conservation measures from time to time shall strictly be adhered to.

4.2 They must have been obtained from hens, ducks, geeses, turkeys, guinea fowls or quaila eggs, but not a mixture of eggs of different species.

4.3 They must bear an indication of the percentage of egg ingredients they contain when they are partially supplemented by other food stuffs.

4.4 They must have been treated and prepared in an approved plant which complies with Annexure I and II of the Part I, and satisfy the requirements of these rules.

4.5 They must have been prepared under hygienic conditions complying with Annexure III and V of the Part I from eggs meeting the requirements laid down in Annexure IV of the Part I.

4.6 They must have undergone a treatment process which enables them to meet inter alia the analytical specifications laid down in Annexure VI of the Part I.

4.7 They must have undergone a health check in accordance with Annexure VII of the Part I.

4.8 They must have been packed in accordance with Annexure VIII of the Part I.

4.9 They must be stored and transported in accordance with Annexure IX and X of the Part I.

4.10 They must bear the mark of wholesomeness provided for in Annexure XI of the Part I and, where intended for direct human consumption, must meet the requirements of Council Directive 79/112/EEC of 18th December 1978 relating to the labelling, presentation and advertising of foodstuffs for sale to the ultimate consumer, as last amended by Directive 86/97/EEC.

4.11 Samples for laboratory examination are taken in order to check that the analytical specifications set out in Annexure VI of the Part I.

4.12 Egg products that may not be kept at the ambient temperature are transported or stored at the temperatures stipulated in Annexure IX and X of the Part I.

4.13 The period during which the conservation of egg products is assured as indicated by the processor.

4.14 The results of the various checks and tests are recorded and kept for presentation to the competent authority for a period of two years.

4.15 To detect any residues of substances having a pharmacological or hormonal action, and of antibiotics, pesticides, detergents and other substances which are harmful or which might alter the organileptic characteristics of egg products or make their consumption dangerous or harmful to human health.

4.16 If the egg products examined show traces of residues in excess of the permitted levels fixed, they must not be allowed either for the manufacture of foodstuffs or for direct human consumption.

4.17 Tests for residues must be carried out in accordance with proven and scientifically recognised methods.

4.18 Having satisfied itself that the plant meets the requirements with regard to the nature of the activities if carried out, the competent authority shall accord approval to such plant.

4.19 The Competent Authority may take the assistance of a representative each from Agricultural and Processed Food Export Development Authority (APEDA), Directorate of Marketing and Inspection (DMI), Ministry of Food Processing Industries and representative of industry in the matter of approval of processing plants.

4.20 The competent authority shall draw up a list of the approved plants, each of which have an official number and the competent authority shall furnish to appropriate authorities the list of approved plants and subsequent change thereof.

4.21 The inspection and monitoring of plant and packaging centres shall be carried out regularly by the competent authority, which shall at all times have free access to all parts of the plant, in order to ensure that these rules are being observed.

PART—II [APPLICABLE FOR UNITED STATES OF AMERICA (USA)]

2. Definition : In these rules unless the context otherwise requires, the following definitions shall be applicable :

(a) "Act" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

(b) "Acceptable" means suitable for the purpose intended and acceptable to the Competent Authority;

(c) "Agency" means any agency for quality control or inspection or both established or recognised under Section 7;

(d) "Applicant" means any person who requests any inspection, service as authorised under the rules or the regulations of this part;

(e) "Capable of use as human food" means any egg product, unless it is denatured, or otherwise identified, deter its use as human food;

(f) "Certificate" means certificate issued under sub-section (3) of Section 7 of the Act stating that the commodity conforms to the conditions regarding quality control and inspection;

(g) "Competent Authority" means any one of the Export Inspection Agencies at Mumbai, Calcutta, Cochin, Delhi and Madras established under Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection Act, 1963;

(h) "Condition" means any condition (including, but not limited to the state of preservation, cleanliness, soundness, wholesomeness, or fitness for human food) of any product which affects its merchant ability or any condition, including but not being limited to, the processing, handling or packaging which affects products;

(i) "Container" or 'Package' includes any box, can, tin, plastic or other receptacle, wrapper or cover;

(j) "Council" means the Export Inspection Council established under Section 3 of the Act;

(k) "Merchant Exporter" means an exporter who buy the egg products from the approved egg processing plants under these rules for the purpose of exports.

(l) "Egg product" means the products obtained from eggs their various components or mixtures thereof, after removal of the shell and membranes, intended for suman consumption; they may be partially supplemented by other foodstuffs or additives; they may be liquid, concentrated, dried, crystallized, frozen, quick-frozen or coagulated;

Explanation : In this aforesaid definition "egg product" shall not include products such as freez dried products, imitation egg products, egg substitutes, dietary foods, dried no-bake custard mixes, egg nog mixes, acidic dressings, noodles, milk and egg dip, cake mixes, french toast, and sandwiches containing eggs or egg products. Balut and other similar ethenic delicacies are also not included;

(m) "Incubator reject" means an egg that has been subjected to incubation and has been removed from incubation during the hatching operations as infertile or otherwise unhatchable;

(n) "Lebel" means a display of any printed, graphic, or other method of identification upon the shipping container if any, or upon the immediate container;

(o) "Pasteurize" means subjecting of each particle of egg products to heat or other treatments to destroy harmful viable microoganisms by such processes as may be prescribed by these regulations;

(p) "Plant" means any premises where egg products are processed;

(q) "Potable water" means water that has been approved by State Health Authority or other Agency or Laboratory accentable to the Competent Authority as safe for drinking and suitable for food processing;

(r) "Processing" means manufacturing of egg products, including breaking eggs or filtering, mixing, blending, pasteurizing, stabilizing, cooling, freezing or drying or packaging egg products plants approved by the Competent Authority;

(s) "Sampling" means the act of taking samples of any product for inspection or analysis;

(t) "Sanitize" means the application of bactericidal treatment which is approved as being effective in destroying micoorganisms, including pathogens;

(u) "Shipping Container" means any container used in packaging a product;

(v) "Stabilization" means the subjection of any egg product to a desugaring processing;

(w) "White or albumen" means for the purpose of this part, the product obtained from the egg as broken from the shell and separated from the yolk.

3. Basis of Compliance : It is primarily the responsibility of the processor to ensure that the egg products intended for export are handled, processed at all stages of production, storage and transport under proper hygienic conditions so as to meet the health requirement laid down under these rules and that the product conforms to the specifications given in the order by the Central Government under Section 6 of the Act.

The Competent Authority shall ensure that all the processors comply with the requirement by regular monitoring of the plant as per the control measures prescribed in para 4.4 of this part. For effective monitoring of the scheme, Council will issue necessaray instructions in this regard.

4. The egg products for export shall be subjected to the following conditions :

4.1 Any statutory restriction imposed by any State/Central Government with respect to commercial/environmental conservation measures from time to time shall strictly be adhered.

4.2 They must comply with sanitary, processing and facility requirements laid down in Annexure XII of the Part II.

4.3 They must comply with Identifying and marking of egg products laid down in Annexure XIII of the Part II.

4.4 Having satisfied itself that the plant meets the requirements with regard to the nature of the activities they carry out, the competent authority shall accord approval to such plant;

4.5 The Competent Authority may take the assistance of a representative each from Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) and Directorate of Marketing and Inspection (DMI), Ministry of Food Processing Industries and a representative of Industry in the matter of approval of processing plants.

4.6 The competent authority shall draw up a list of the approved plants, each of which have an official number and the competent authority shall notify to appropriate authorities of its list of approved plant and subsequent change thereof

4.7 The inspection and monitoring of plant and packaging centres shall be carried out regularly by the competent authority, which shall at all times have free access to all parts of the plant, in order to ensure that these rules are being observed.

5. CERTIFICATION

On request from the plant unit, the competent authority shall issue veterinary health certificate in the prescribed proforma after satisfying itself that plants having valid approval number and after satisfying the relevant requirement.

5.1 The Competent Authority shall also issue any other certificates on request from the processor or exporter after satisfying itself that the requirements of the relevant standards are met ;

6. FEE :

6.1 A fee of Rs. 2000 shall be paid by the processor alongwith the application for approval of the egg processing plant as per clause 4.18 of Part I and 4.4 of Part II of these rules ;

6.2 A fee at the rate of 0.2% of F.O.B. value shall be paid by the processor, exporter or merchant exporter of the egg processing plants approved under rule 6.1 above, to the Competent Authority.

NOTE :

The amount of fee for each consignment payable by the processor/exporter shall be rounded off to the nearest rupee and, for this purpose, where such amount contains a part of a rupee then if such a part is 50 paise or more, it shall be increased to one rupee and, if such part is less than 50 paise, it shall be ignored.

7. Competent Authority shall take measures if the requirement ceases to be met.

8. APPEAL :

8.1 Any person aggrieved by the :

(i) Decision of the competent authority is not according the approval as per rule 4.18 of Part I and rule 4.4 of Part II ;

(ii) Refusal of competent authority to issue Veterinary Health Certificate as per rule 5 of this notification ;

(iii) Decision of the competent authority to withdraw approval as per rule 7 of this notification.

8.2 Any person aggrieved by the Appellate Authority may prefer an appeal within 10 days of receipt of such decision to an Appellate Authority appointed by the Central Government ;

8.3 The Appellate Authority shall consist of five members appointed for the purpose by the Central Government ;

8.4 At least two-thirds of the total membership of the Appellate Authority shall consist of non-officials ;

8.5 The quorum for any meeting of the Appellate Authority shall be three ;

8.6 The appeal shall be disposed off within 15 days of its receipt.

ANNEXURE I

GENERAL CONDITIONS OF APPROVAL AND OPERATION

I. ESTABLISHMENTS MUST POSSESS AT LEAST :

1. In areas where eggs are stored and where egg products are manufactured or stored :

1.1 Waterproof flooring which is easy to clean and disinfect, rotproof and laid in such a way as to facilitate the draining of water : the water must be channelled towards drains fitted with gratings and raps to prevent odours ;

1.2 Smooth, durable, impermeable walls, with a light-coloured, washable coating up to a height of at least two metres and upto at least storage height in chilling or refrigeration rooms and in stores. Wall to floor junctions must be rounded or similarly finished in such a way as to facilitate cleaning ;

1.3. Doors in material that does not deteriorate and, if of wood, with a smooth and impereable covering on both sides ;

1.4 Ceilings which are easy to clean and which have been built and finished in such a way as to prevent the accumulation of dirt and the formation of mould, the possible peeling of paint-work and the condensation of water vapour ;

1.5 Adequate ventilation and, if necessary, good steam extraction ;

1.6 Adequate natural or artificial lighting ;

1.7 As near as possible to the work stations :

An adequate number of facilities for the cleaning and disinfecting of hands and the cleaning of equipment with hot water. Taps must not be operable by hand or the arms. For the cleaning of hands, these facilities must be provided with hot and cold running water or water premixed to a suitable temperature, cleaning and disinfecting products and hand towels which can be used once only;

Facilities for the disinfacting of tools;

2. An appropriate number of changing rooms, with smooth, implermeable and washable walls and floors, wash-basins and flush lavatories. The latter must not give directly on to the work-area Wash-basins must have hot and cold running water or water premixed to a suitable temperature, materials for cleaning and disinfecting hands, and hand towels which can be used once only. Wash-basin taps must not be hand-operable. There must be a sufficient number of wash-basins close to the lavatories ;

3. A separate area and adequate facilities for cleaning and disinfecting fixed and mobile containers and tanks. However, this area and these facilities shall not be required if there are provisions for the cleaning and disinfecting of containers and tanks at other centres ;

4. Facilities for the supply of potable water. However, facilities supplying non-potable water are authorised for steam production, fire fighting and the cooling of refrigeration equipment, provided that the pipe installed for this purpose preclude the use of such water for other purposes and present no risk of contamination to the egg products. The steam and water concerned may not come in to contact with the egg or be used for cleaning or disinfecting containers, plant or equipment which come into contact with the egg products. Pipes carrying non-potable water must be clearly distinguished from those carrying potable water ;

5. Appropriate equipment for protecting against pests such as insects and rodents ;

6. Equipment, couplings and instruments or their surfaces which are intended to come into contact with egg products must be made of smooth material which is easy to wash, clean and disinfect, resistant to corrosion and does not transfer substances to the egg products in such quantities as to endanger human health, cause deterioration in the composition of the egg products or adversely affect their organoleptic characteristics.

ANNEXURE II

SPECIAL CONDITIONS FOR THE APPROVAL OF PLANT

In addition to the general conditions laid down in Annexure-I establishments must have at least :

1. Suitable rooms large enough for the separate storage of the eggs and the finished egg products, where necessary, with refrigeration equipment to keep the egg products at the appropriate temperatures, cold stores must be equipped with a thermometer or a remote recording thermometer;

2. Where dirty eggs are used, facilities for washing and disinfecting the eggs; a list of products authorised for performing this disinfection shall be drawn,

3. i. A special room with appropriate facilities for breaking eggs and collecting their contents and removing the parts of shell and membrane;

(ii) A separate room for operations other than those referred to in (i). Where egg products are pasteurized, pasteurization may be carried out in the room referred to in (i), when the establishment has a closed pasteurization system; in other cases pasteurization must be carried out in a separate (room referred to (ii)). In the latter case, every step must be taken to prevent the contamination of egg products after their pasteurization;

4. Suitable facilities for in-plant conveying of egg contents;

5 In the cases, provided for in these rules, equipment approved by the competent authority for the treatment of egg products, fitted at least with :

(i). In the case of pasteurization :

— Automatic temperature control

— A recording theremometer,

— An automaic safety device preventing insufficient heating;

(ii) In the case of a continuous pasteurization system, the equipment must also be fitted with :

— An adequate safety system preventing the mixture of pasteurized egg products with incompletely pateurized egg products, and

— An automatic safety recording device preventing the aforementioned mixture;

6. A separate room for the storage of other food stuffs and additives;

7. Where the products are packed in disposable containers, an appropriate and, if necessary, separate area for the storage of such containers and the raw materials intended for their manufacture

8. Facilities for the immediate removal and separate storage of empty shells, and of eggs and egg products which are unfit for human consumption;

9. Suitable equipment for the hygienic packaging of egg products;

10. To carry out analysis and examinations in accordance with the requirements of these rules on raw materials and egg products, the plant must have a laboratory. If it does not, it must secure the services of a laboratory that fulfils these requirements. In the latter case, it shall inform the competent authority accordingly;

11. Where required, suitable equipment for the thawing of frozen egg products which must undergo treatment and further handling in an approved plant;

12. A separate room for the storage of cleaning and disinfection of products.

ANNEXURE III

HYGIENE REQUIREMENTS RELATING TO THE PREMISES, EQUIPMENT AND STAFF OF PLANTS

The highest degree of cleanliness must be required of staff, premises and equipment :

1. Staff who treat or handle eggs and egg products must, in particular, wear clean working clothes and headgear. They must wash and disinfect their hands several times in the course of each working day and on each resumption of work. It must be forbidden to smoke, eat, spit or chew in areas where eggs and egg products are handled and stored;

2 No animal should enter in the plant. Any rodents, insects or other vermin found must be systematically destroyed;

3 Premises, equipment and instruments used for working on egg products must be kept clean and in a good condition. Equipment and instruments must be carefully cleaned and disinfected several times if necessary during the working day, at the end of the day's work and before being reused where they have been soiled. Closed pipeline systems for conveying egg products must be provided with an appropriate cleaning system which ensures their cleaning and disinfection in all parts. After having been cleaned and disinfected, pipes must be rinsed out with potable water;

4. Premises, instruments and equipments must not be used for purposes other than the processing of egg products except the processing of other foodstuffs either simultaneously or at different times after the authorization of the competent authority has been obtained, provided that all appropriate measures are taken to prevent contamination of or adverse changes in the products covered by these rules;

5. Potable water must be used for all purposes, however non-potable water may be used in exceptional cases for steam production provided that the pipes installed for this purpose preclude the use of this water for other purposes and present no danger of contamination of eggs or egg products. In addition, the use of non-potable water may be authorized in exceptional cases for the cooling of refrigeration equipment. Non-potable water pipes must be clearly distinguished from pipes used for potable water;

Detergents, disinfectants and similar substances must be used and stored in such a way that instruments, equipment and egg products are not adversely affected. Their use must be followed thorough rinsing of such instruments and equipment with potable water;

7. Persons who are possible sources of contamination must be prohibited from working with or handling egg or egg products;

8. Any person employed to work or handle eggs or egg products must be required to produce a medical certificate. The medical certificate must be renewed yearly unless another staff medical checkup scheme offering similar guarantees is recognised by the competent authority.

ANNEXURE IV

REQUIREMENTS CONCERNING EGGS INTENDED FOR THE MANUFACTURE OF EGG PRODUCTS

1. Eggs used for the manufacture of egg products must be put up in suitable packaging.

2. (i) For the manufacture of egg products, only non-incubated eggs which are fit for human consumption may be used; their shells must be fully developed and contain no breaks;

(ii) By way of derogating from (i), cracked eggs may be used for the manufacture of egg products provided they are delivered directly from and the farm of production to an approved plant, where they shall be broken as quickly as possible.

3. Eggs and egg products which are unfit for human consumption must be removed and denatured in such a way that they cannot be re-used for human consumption. They must immediately be placed in the room provided for in point 8 of Annexure-II.

ANNEXURE V

SPECIAL HYGIENE REQUIREMENTS FOR THE MANUFACTURE OF EGG PRODUCTS

All operations must be carried out in such a way as to avoid all contamination during the production, handling and storage of egg products and in particular;

1. Eggs and egg products presented for subsequent treatment at an approved plant must be stored immediately on arrival in the rooms provided for in Annexure-II point 1 until they are processed. The temperature of these rooms must be such as to ensure that they are not contaminated. Trays of shell eggs should not be placed directly on the floor;

2. Eggs must be unpacked, and, if necessary, washed and disinfected, in a room which is separate from the breaking room, packaging material should not be taken into the breaking room;

3. Eggs must be broken in the room provided for in Annexure-II, point 3(i); cracked eggs as mentioned in Annexure-IV, point 2(ii) must be processed without delay;

4. Dirty eggs must be cleaned before being broken; this must be carried out in a room which is separate from the breaking room or from any room where exposed egg contents are handled. Cleaning procedure must be such as to prevent contamination or adulteration of the egg contents. Shells must be sufficiently dry at the time of breaking to prevent adulteration of the egg contents by the remains of the cleaning water;

5. Eggs other than hen eggs or those of turkeys or guinea fowl must be handled and processed separately. All equipment must be cleaned and disinfected when processing of hen eggs and those of turkeys and guine fowl is resumed ;

6. Breaking, whatever procedure is used, must be carried out in such a way as to avoid as far as possible contamination of the egg contents. To that end, the contents of eggs may not be obtained by the centrifugation or crushing of eggs, nor may centrifugation be used to obtain the remains of egg whites from empty shells. The remains of shells or membranes must be kept out of the egg product as far as possible and must not exceed the quantity specified in point 2(iii) of Annexure-VI;

7. After breaking, each particle of egg product must undergo treatment as quickly as possible: heat treatment consists of treating the egg product at an appropriate temperature for an appropriate period in order to eliminate any pathogenic organisms present. During heat treatment, temperatures must be registered continuously. The records of each batch having undergone treatment must be kept at the disposal of the competent authority for two years. A batch which has been insufficiently treated may immediately undergo treatment again in the same plant provided that the new treatment renders it fit for human consumption: should it be found to be unfit for human consumption, it must be denatured in accordance with point 3 of Annexure-IV;

8. If treatment is not carried out immediately after breaking, the egg contents must be stored under satisfactory hygienic conditions either frozen or at a temperature of not more than 4 Degree Celcius. The storage period at 4 Degree Celcius must not exceed 48 hours, except in the case of ingredients to be desugared;

9. The following general conditions are complied with :

(i) They must be packaged checked, transported and handled in accordance with the requirements of these rules;

(ii) They must be labelled in accordance with the requirements laid down in Annexure-XI. The nature of the goods must be indicated as follows :

'non-pasteurized egg products—to be treated at place of destination—date and time of breaking;

10. Further processing operations after treatment must ensure that there is no recontamination of the egg product; liquid products or concentrated products which have not been stabilized so as to keep at room temperature must be either dried or cooled to a temperature not exceeding 4 Degree Celcius immediately, or after undergoing a fermentation process; products for freezing must be frozen immediately after treatment

11. Egg products must be kept at the temperatures required by these rules until they are used for the manufacture of other foodstuffs;

12. In approved plants, the preparation of egg products from raw materials which are not suitable for the manufacture of foodstuffs is prohibited, even for non-food purposes.

ANNEXURE VI

ANALYTICAL SPECIFICATIONS

1. MICROBIOLOGICAL CRITERIA :

All batches of egg products must, after treatment, undergo microbiological checks by sampling in treatment plants in order to guarantee that they meet the following criteria :

(i) Salmonellae : absence in 25 g or ml of egg products;

(ii) Other criteria :

— Mesohilic aerobic bacteria : $M=10^5$ in 1 g or 1 ml,

— Enterobacteriaceae : $M=10^3$ in 1 g or 1 ml,

— Etaphylococci : absence in 1 g of egg product,

— M = value for the number of bacteria; the result is considered unsatisfactory if the number of bacteria in one or more sample units is M or more.

2. OTHER CRITERIA :

All batches of egg products must undergo checks by sampling in treatment establishments in order to guarantee that they meet the following criteria :

(i) The concentration of 3 OH-butyric acid must not exceed 10 mg/kg in the dry matter of the unmodified egg products;

(ii) In order to ensure the hygienic handling eggs and egg products before treatment, the following standards shall apply :

— The lactic acid content must not exceed 1000 mg/kg of egg products dry matter (applicable only to the untreated product).

— The succinic acid content must not exceed 25 mg/kg of egg product dry matter.

In the case of fermented products, however, these values are those recorded before the fermentation process;

(iii) The quantity of egg shell remains, egg membrane and any other particles in the egg produce must not exceed 100 mg/kg of egg product;

(iv) The residual quantities of the substances may not exceed the tolerances limits.

ANNEXURE VII

HEALTH CONTROL AND SUPERVISION OF PRODUCTION

1. Plants will be subject to supervision by the competent authority Supervision by the competent authority will include any supervision measures considered necessary to ensure that manufacturers of egg products meet the requirements of these rules, and in particular :

— Checks on the origin of eggs and the destination of egg products and of the records.

— Inspection of eggs intended for the manufacture of egg products.

— Inspection of egg products on despatch from the plants.

— Verification of the cleanliness of the premises, facilities and instruments and of staff hygiene.

— Taking of any samples required for laboratory tests to ensure that eggs and egg products comply with the requirements of

these rules the results of such tests must be entered in a register and notified to the egg products manufacturer.

2. At the request of the competent authority, manufacturers of egg products must increase the frequency of the laboratory tests where this is considered necessary to ensure hygienic production of the egg products.

ANNEXURE VIII

PACKAGING OF EGG PRODUCTS

1. Egg products must be packaged in satisfactory hygiene conditions so as to ensure that they are not contaminated.

Containers must comply with all rules of hygiene, including the following :

— They must not be such as to impair the organoleptic characteristics of the egg products ;

— They must not be capable of transmitting to the egg products sustances harmful to human health ;

— They must be strong enough to protect the egg products adequately.

2. The room in which containers are stored must be dust and vermin free ; materials for making disposable containers must not be stored on the floor.

3. Containers used for egg products must be cleaned prior to being filled ; re-usable containers must be cleaned, disinfected and reinsed before being filled.

4. Containers must be brought into the work room in a hygienic manner and must be used without undue delay.

5. Immediately after packaging, the containers must be closed and placed in the storage rooms referred to in Annexure—II, point I.

6. Containers intended for egg products may be used for other foodstuffs if required, provided they are cleaned and disinfected so as not to contaminate the egg products.

7. Containers which are to be used for the transport of egg products in bulk must comply with all the rules of hygiene, and in particular the following :

— Their inside surfaces and any other part which may come into contact with the egg product must be made of a smooth material which is easy to wash, clean and disinfect, resists corrosion and does not transfer substances to the egg product in such quantities as to endanger human health, cause deterioration in the composition of the egg product or adversely affect its organoleptic characteristics ;

— They must be designed so that the egg product can be removed completely, if they are fitted with taps, these must be easy to remove, dismantle, wash, clean and disinfect ;

— They must be washed, cleaned, disinfected and rinsed immediately after each use and, if necessary, before re-use .

— They must be appropriately sealed after being filled and remain sealed during transportation until they are used ;

— They must be reserved for the transport of egg products.

ANNEXURE IX

STORAGE

1. Egg products must be stored in the storage rooms referred to in point 1 and Annexure-II.

2. Egg products for which certain storage temperatures are required must be maintained at those temperatures. The storage temperatures must be recorded continuously, the cooling rate must be such that the product reaches the required temperatures as quickly as possible and the containers must be stored in such a way that air can freely circulate round them.

3. The temperature in storage must not exceed the following values :

— Deep frozen products—18 Degree Celcius.

— Frozen products—12 Degree Celcius.

— Chilled products +4 Degree Celcius.

— Dehydrated products (excluding egg whites) +15 Degree Celcius.

ANNEXURE X

TRANSPORT

1. Vehicles and containers for the transport of egg products must be designed and equipped in such a way that the temperature required by these rules can be maintained continuously throughout the period of transport.

2. Egg products must be despatched in such a way that they are adequately protected during transportation from anything which may be detrimental to them.

3. The temperatures prescribed in point 3 of Annexure-IX, must be maintained during transport.

ANNEXURE XI

MARKING OF EGG PRODUCTS

1. Every consignment of egg products in the plant must have label bearing the following particulars :

(i) EITHER :

— On the upper part, the initial letter or letters of the consigning country in capital, i.e. B|D|DK|KL|ESP|F|IRL|I|L|NL|P|UK, followed by the approval number of the plant .

— On the lower part, one of the following sets of initials : CEE-EEC-EEG-EOK-EWG-EOF ;

(ii) OR :

— On the upper part, the name of the consigning country in capitals ;

— In the centre, the approval number of the plant ;

— On the lower part, one of the following sets of initials : CEE-EEC-EEG-EOK-EWG-EOF ;

(iii) The temperature at which the egg products must be maintained and the period during which their conservation may thus be assured. The label must be legible, indelible and in easily decipherable characters.

2. The transport documents must in particular include :

(i) The nature of the products with an indication of the species of origin ;

(ii) The batch numbers ;

(iii) The place of destination and the name and address of the first addressee.

(iv) This information, and that contained in the mark of wholesomeness, must be given in the Official language or language of the country of destination.

ANNEXURE XII (APPLICABLE FOR EXPORT TO USA)

I. SANITARY, PROCESSING AND FACILITY REQUIREMENTS :

1. PLANT REQUIREMENTS :

1.1 The plant shall be free from objectionable odours, dust, and smokeless air.

1.2 The premises shall be free from refuse, rubbish, waste, and other materials and conditions which constitute a source of odours or a harbour for insects, rodents, and other vermin.

1.3 The buildings shall be of sound construction and kept in good repair to prevent the entrance or harbouring of vermin.

1.4 Rooms shall be kept free from refuse, rubbish waste materials, odours, insects, rodents, and from any conditions which may constitute a source of odours or engender insects and rodents. Materials and equipment not currently needed shall be handled or stored in a manner so as not to constitute a sanitary hazard.

1.5 Doors and windows that open to the outside shall be protected against the entrance of flies and other insects. Doors and windows, serving rooms where edible product is exposed shall be so designed and installed to prevent the entrance of dust and dirt. Doors leading into rooms where edible product is processed shall be of solid construction and such doors, other than freezer and cooler doors, shall be fitted with self-closing devices.

1.6 Doors and other openings which are accessible to rodents shall be of rodent-proof construction.

1.7 There shall be an efficient drainage and plumbing system for the plant and premises. Drains and gutter shall be properly installed with approved traps and vents. The sewage system shall have adequate slope and capacity to readily remove waste from the various processing operations. Floor drains shall be equipped with traps, and constructed so as to minimize clogging. In new or remodelled construction the drainage systems from toilets and lavoratories shall not be connected with other drainage systems within the plant.

1.8 The water supply (both hot and cold) shall be ample, clean, and potable, with adequate pressure and facilities for its distribution throughout the plant or portion thereof utilized for egg processing and handling operations and protected against contamination and pollution.

1.9 The floors, walls, ceiling partitions, posts, doors, and other parts of all structures shall be of such materials, construction, and finish to permit their ready and thorough cleaning. The floors and curbing shall be water-tight.

1.10 Each room and each compartment in which any shell eggs or egg products are handled or processed shall be so designed, constructed, and maintained to ensure processing and operating conditions of a clean and orderly character, free from objectionable odours and vapours, and maintained in a clean and sanitary conditions.

1.11 Every precaution shall be taken to exclude dogs, cats, and vermin (including, but not being limited to, rodents and insects) from the plant, or portion thereof utilized in which shell eggs or egg products are handled or stored.

1.12 (i) There shall be a sufficient number of adequately lighted dressing rooms and toilet rooms, ample in size, conveniently located and seperated from the rooms and compartments in which shell eggs or egg products are handled, processed, or stored. The dressing rooms and toilet rooms shall be seperately ventilated, and shall meet all requirements as to sanitary construction and equipment.

(ii) The following formula shall serve as a basis for determining the toilet facilities required :

PERSON OF SAME SEX	TOILET BOWLS REQUIRED
01 to 15, inclusive	1
16 to 35, inclusive	2
36 to55, inclusive	3
56 to 80, inclusive	4
For eabh additional20 persons in excess 80	

1.13 Lavoratory accommodations (including, but not being limited to, hot and cold running water, single service towels, and soap which does not impart an odour which interferes with accurate evaluation of the product) shall be placed at such locations in the plant to assure cleanliness of each person handling any shell eggs or egg products. The hand washing facilities in the processing areas shall be operated by other than hand operated controls and the drains shall be trapped and connected to the plumbing system.

1.14 Suitable facilities for cleaning and sanitizing utensils and equipment shall be provided at convenient locations through-out the plant.

1.15 Refuse rooms shall be provided for the accumulation and storage of shells, trash and other refuse. There shall be separate rooms completely enclosed without door ways opening into breaking rooms or rooms where egg products or packaging materials are handled or stored and have concrete floors with approved drains, facilities for cleaning and an approved exhaust system vented to the outside. Alternative systems of handling shells, trash and other refuse may be approved by the Competent Authority when such system adequately contain all refuse and provide equivalent sanitary methods for the handling and removal of refuse.

2. EQUIPMENT AND UTENSILS : POLYCHLORINATED BIPHENYLS (PCB) CONTAINING EQUIPMENT

2.1 Equipment and utensils used in processing shell eggs and egg products shall be of such design, material and construction as will :

(i) Enable the examination, segregation and processing of such products in an efficient, clean and satisfactory manner;

(ii) Permit easy access to all parts to insure thorough cleaning and sanitizing. So far as is practicable, all such equipment shall be made of metal or other impervious material which will not affect the product by chemical action or physical contact.

2.2 Except as authorized by the Competent Authority in new or remodeled equipment and its installations, the equipment installed shall comply with the applicable Sanitary Standards and Accepted Practices in effect for such equipment.

2.3 New or replacement equipment or machinery (including any replacement parts) brought on to the premises of any approved plant shall not contain liquid polychlorinated biphenyls (PCBs) in concentrations above 50 PPM by weight of the liquid medium. This provision applies to both food processing and non-food processing equipment and machinery and any replacement part for such equipment and machinery. Totally enclosed capacitors containing less than 3 pounds of PCBs are exempted from this prohibition.

3. GENERAL OPERATING PROCEDURE :

3.1 Operations involving processing, storing, and handling of shell eggs, ingredients and egg products shall be strictly in accordance with clean and sanitary methods and shall be conducted treatment, stabilization and other processes shall be in accordance with this part and as approved by the Competent Authority. Processing methods and temperatures in all operations shall be in such a way as will prevent deterioration of the egg products.

3.2 Shell eggs and egg products processed in approved plants shall be subjected to constant and continuous inspection throughout each and every processing operation. Any shell egg or egg product which has not been processed in accordance with these regulations or is not fit for human food shall be removed and segregated.

3.3 All loss and inedible eggs or egg products shall be placed in a container clearly labelled "inedible" and containing a sufficient amount of approved denaturant or decharacterant, such as brown, blue, black or green colours, meat grain and milling by-products or any other products as approved by the Competent Authority, that will accomplish the purposes of this section. Shell eggs shall be crushed and the substance shall be dispersed through the product in amounts sufficient to give the product a distinctive appearance or odour. Notwithstanding the foregoin, and upon permission of the Competent Authority the appearance or odour. Notwithstanding the foregoing, clearly labelled inedible which do not contain a denaturant if such inedible product is denatured or decharacterized prior to shipment from the approved plant: provided, that such product is properly packaged, labelled, segregated and inventory controls are maintained. In addition, product shipped from the approved plant for industrial use or animal food need not be denatured or decharacterized if it is shipped under Government seal.

3.4 The Competent Authority may, prior to receipt of laboratory results for salmonella, or for other reasons such as labelling as to solids content, permit egg products to be shipped from the approved plant when they have no reason to suspect non-compliance with any of the provisions of this Annexure. However, such shipments shall be made under circumstances which will assure the return of the product to the plant for reprocessing, relabelling, or under such other conditions as the Competent Authority may determine to assure compliance with this Annexure.

3.5 Pasteurizing stabilizing, or drying operations shall start as soon as practicable after breaking to prevent deterioration of product preferably within 72 hours from time of breaking for egg products other than whites which are to be desugared.

3.6 Each person who is to handle any exposed or unpacked egg products or any utensils or container which may come into contact with egg product, shall wash his hands and maintain them in a clean condition.

3.7 No product or material which creates an objectionable condition shall be processed, stored or handled in any room, compartment, or place where any shell eggs or egg products are processed stored or handled.

3.8 Only germicides, insecticides, rodenticides, detergents, or wetting agents or other similar compounds which will not deleteriously affect the eggs or egg products and which have been approved by the Competent Authority may be used in an approved plant. The use of such compounds shall be in a manner satisfactory to the Competent Authority.

3.9 Utensils and equipment which are contaminated during the course of processing any shell eggs or egg products shall be removed from use immediately and shall not be used again until cleaned and sanitized.

3.10 Any substance or ingredient added in the processing of any egg product shall be clean and fit for human food.

3.11 Packages or containers for egg products shall be of sanitary design and clean when being filled with any egg products and all reasonable precautions shall be taken to avoid soiling or contaminating the surface of any package or container liner which is, or will be, in direct contact with such egg products. Only new containers or used containers that are clean, in sound condition and lied with suitable inner lining shall be used for packaging edible egg products. Fiber containers used without liners require the approval of the Competent Authority.

3.12 Egg products shall be inspected to determine the wholesomeness of the finished product.

3.13 Egg products shall be processed in such a manner as to ensure the immediate removal of blood and meat spots, shell particles, and foreign materials.

3.14 Utensils and equipment, except drying units, powder conveyors, sifters, blenders, and mechanical powder coolers shall be cleaned and sanitized at the start of processing operations. Equipment and utensils shall be kept clean and sanitized during all processing operations.

3.15 Egg products prior to being released into consuming channels shall be pasteurized in accordance with para 26 of this Annexure except that dried whites prepared from unpasteurized liquid shall be heat treated in accordance with para 27 of this Annexure.

(i) To assure adequate pasteurization, egg products shall be sampled and tested for the presence of salmonella. Sampling for the presence of salmonella shall be in accordance with II of Annexure-XII and product if found to be salmonella positive shall be reprocessed, pasteurized, and analyzed for the presence of salmonella, or denatured.

(ii) Unpasteurized or salmonella positive egg product may be pasteurized, repasteurized, or heat treated in an approved plant. The containers of such unpasteurized or salmonella positive product shall be marked with the identification mark shown in Figure 3 of Annexure-XIII.

3.16 Air which is to come in contact with product or with product contact surfaces shall come from approved filtered outside air sources.

3.17 All liquid and solid waste material in the approved plant shall be disposed off in a manner approved by the Competent Authority to prevent product contamination and in accordance with acceptable environmental protection practices.

4. Candling and Transfer-room facilities and Equipment :

4.1 The room shall be so constructed that it can be adequately darkened to assure accuracy in removal of inedible or loss eggs by candling. Equipment shall be arranged so as to facilitate cleaning and the removal of refuse and excess packing material.

4.2 The construction of the floor shall allow thorough cleaning. The floors shall be of water-resistant composition and provided with proper drainage.

4.3 An approved exhaust system shall be provided for the continuous removal directly to the outside of any steam, vapours, odours, or dust in the room. The room shall be maintained at reasonable working temperatures during operations.

4.4 Candling devices of an approved type shall be provided to enable candlers to detect loss, inedible, dirty, or checked eggs and eggs other than hen's eggs.

4.5 Leaker trays shall be made of a material and of such design that is conducive to easy cleaning and sanitizing.

4.6 Containers made out of material and of such design, which are conducive to easy cleaning shall be provided for inedible eggs. All such containers shall be conspicuously marked.

4.7 Containers made out of material and of such design, which are conducive to easy cleaning shall be provided for trash unless clean, disposable containers are furnished daily.

4.8 Shell egg conveyors shall be constructed so that they can be thoroughly cleaned.

5. Candling and Transfer-room Operations :

5.1 Candling and transfer rooms and equipment shall be kept clean, free from cobwebs, dust, objectionable odours and excess packing materials.

5.2 Containers for trash and inedible eggs shall be removed from the candling rooms, as often as necessary, but at least once daily; and shall be cleaned and treated in such a manner as to prevent objectionable odours or conditions in the plant.

5.3 Shell eggs shall be handled in a manner to minimize sweating prior to breaking.

5.4 Shell eggs with extensively damaged shells, unless prohibited under 6.4 of this Annexure shall be placed into leaker trays and shll be broken promptly.

6. Classifications of shell eggs used in the processing of egg products :

6.1 The shell eggs shall be sorted and classified into the following categories in a manner approved by the Competent Authority.

(i) Eggs listed in paragraph 6.4 of this Annexure.

(ii) Dirty.

(iii) Leakers as described in paragraph 6.3(ii) of this Annexure.

(iv) Eggs from other than chicken, duck, turkey, guinea, fowl and goose eggs.

(v) Other eggs-satisfactory for use as breaking stock.

6.2 Shell eggs having strong odours or eggs received in cases having strong odours shall be candled and broken separately to determine their acceptability.

6.3 Shell eggs, when presented for breaking, should be of edible interior quality and the shell has to be sound and free from adhering dirt and foreign material except that :

(i) Checks and eggs with a portion of the shell missing may be used when the shell is free of adhering dirt and foreign material and the shell membranes are not ruptured.

(ii) Eggs with clean shells which are damaged in candling and/or transfer and have a portion of the shell and shell membranes missing may be used only when the yolk is unbroken and the contents of the egg are not exuding over the outside shell. Such eggs shall be placed in leaker trays and be broken promptly.

(iii) Eggs with meat or blood spots may be used if the spots are removed in an acceptable manner.

6.4 All loss or inedible eggs shall be placed in a designated container and be handled as required in 3.3 of this Annexure. Inedible and loss eggs for the purpose of this Annexure and 9.9 of this Annexure are defined to include black rots, white rots, mixed rots, green whites, eggs with diffused blood in the albumen or on yolk, crusted yolks, stuck yolks, developed embryos at or beyond the blood ring stage, mouldy eggs, sour eggs and eggs that are adulterated as such term is defined pursuant to this part, and any other filthy and decomposed eggs including the following :

(i) Any egg with visible foreign matter other than removable blood and meat spots in the egg meat.

(ii) Any egg with a portion of the shell and shell membranes missing and with egg meat adhering to or in contact with the outside of the shell.

(iii) Any egg with dirt or foreign material adhering to the shell and with cracks in the shell and shell membranes.

(iv) Liquid egg recovered from shell egg containers and leaker trays.

(v) Open leakers made in the washing operation.

(vi) Any egg which shows evidence that the contents are or have been exuding prior to transfer from the case.

6.5 Incubator reject eggs shall not be brought into the approved plant.

7. Egg Cleaning Operations :

7.1 The following requirements shall be met when washing shell eggs to be presented for breaking.

(i) Shell egg cleaning equipment shall be kept in good repair and shall be cleaned after each day's use or more frequently, if necessary.

(ii) The temperature of the wash water shall be maintained at 32 Degree C or higher, and shall be atleast 11 Degree C warmer than the temperature of the eggs to be washed. These temperature shall be maintained throughout the cleaning cycle.

(iii) An approved cleaning compound shall be used in the wash water. (The use of metered equipment for dispensing the compound into solution is recommended).

(iv) Wash water shall be changed approximately every 4 hours or more often if needed to maintain sanitary conditions and at the end of each shift. Remedial measures shall be taken to prevent excess foaming during the egg washing operation.

(v) Replacement water shall be added continuously to the wash water of washers to maintain a continuous overflow. Rinse water and chlorine sanitizing rinse may be used as part of the replacement water. Iodine sanitizing rinse may not be used as part of the replacement water.

(vi) Waste water from the egg washing operation shall be piped directly to drains.

(vii) The washing operation shall be continuous and shall be completed as rapidly as possible. Eggs shall not be allowed to stand or soak in water. Immersion-type washers shall not be used.

(viii) Prewetting shell eggs prior to washing may be accomplished by spraying a continuous flow of water over the eggs in a manner which permits the water to drain away, or by other methods which may be approved by the Competent Authority. The tempe-

rature of the water shall be the same as prescribed in this Annexure.

(ix) Washed eggs shall be spray rinsed with an approved sanitizer of not less than 100 PPM nor more than 200 PPM of available chlorine its equivalent.

7.2 Shell eggs shall not be washed in the breaking room or any room where edible products are processed.

7.3 Shell eggs shall be sufficiently dry at time of breaking, to prevent contamination or adulteration of the liquid egg products from free moisture on the shell.

8. Breaking room facilities :

8.1 The breaking room shall have atleast 30 foot-candles of light on all working surfaces except that light intensity shall be atleast 50 feet candles at breaking and inspection stations. Lights shall be protected with adequate safety devices.

8.2 The surface of the ceiling and walls shall be smooth and made of water-resistant material.

8.3 The floor shall be of water-proof composition, reasonably free from cracks or rough surfaces sloped for adequate drainage, and the intersections with walls be impervious to water.

8.4 Ventilation shall provide for :—

(i) A positive flow of outside filtered air through the room;

(ii) Air of suitable working temperature during operations.

8.5 There shall be adequate hand washing facilities which are easily accessible to all egg breaking personnel, and adequate supply of warm water, clean towels or other facilities for drying hands, odourless soap, and containers for used towels. Hand washing facilities shall be operated by other than hand operated controls.

8.6 Containers for packaging egg products are not acceptable as liquid egg buckets.

8.7 A suitable container conspicuously identified shall be provided fo the disposal of ejected liquid.

8.8 Strainers, filters, or centrifugal clarifiers of approved construction shall be provided for the effective removal of shell particles and foreign material, unless specific approval is obtained from the Competent Authority for other mechanical devices.

8.9 A separate drawoff room with a filtered positive air ventilation system shall be provided for packaging liquid egg product, except product packaged by automatic, closed packaging systems.

9. Breaking room operations :

9.1 The beaking room shall be kept in a dust-free clean condition and free from flies, insects, and rodents. The floor shall be kept clean and reasonably dry during breaking operations and free of egg meat and shells.

9.2 All breaking room personnel shall wash their hands thoroughly with odourless soap and water each time they enter the breaking room and prior to receiving clean equipment after breaking an inedible egg.

9.3 Paper towels or tissues shall be used at breaking tables, and shall be reused. Cloth towels are not permitted.

9.4 Breakers shall be use a complete set of clean equipment when starting work and after lunch periods. All table equipment shall be rotated with clean equipment every 2—5 hours.

9.5 Cups shall not be filled to overflowing.

9.6 Each shall egg shall be broken in a satisfactory and sanitary manner and inspected for wholesomeness by smelling the shell or the egg meat and by visual examination at the time of breaking. All egg meat shall be re-examined by a person qualified to perform such functions before being empited into the tank or churn, except as otherwise approved by the Competent Authority.

9.7 Shell particles, meat and blood spots, and other foreign material accidentally falling into the cups or trays shall be removed with a spoon or other approved instrument.

9.8 Whenever an inedible egg is broken, the affected breaking equipment shall be cleaned and sanitized.

9.9 Inedible and loss eggs as defined in 6 of this Annexure should apply.

9.10 The contents of any cup or other liquid egg receptable containing one or more inedible or loss eggs shall be rejected.

9.11 Contents of drip trays shall be emptied into a cup and smelled carefully before pouring into liquid egg bucket Drip trays shall be emptied at least once for each 15 dozen eggs or every 15 minutes.

9.12 Edible leakers as defined in 6.3(ii) of this Annexure and checks which are liable to be smashed in the breaking operation shall be broken at a separate station by specially traind personnel.

9.13 Ingredients and additives used in, or for, processing egg products, shall be handled in a clean and sanitary manner.

9.14 Liquid egg containers shall not pass through the candling room.

9.15 Test kits shall be provided and used to determine the strength of the sanitizing solution.

9.16 Leaker trays shall be washed and sanitized, whenever they become soiled and at the end of each shift.

9.17 Shell egg containers whenever dirty shall be cleaned and drained; and shall be cleaned, sanitized, and drained in the tend of each shift.

9.18 Belt type shell egg conveyors shall be cleaned and sanitized approximately every 4 hours, in addition to continuous cleaning during operation. When not in use, belts shall be raised to permit air drying.

9.19 Cups, knives, racks, separators, trays, spoons liquid egg pails, and other breaking equipment, except for mechanical egg breaking equipment, shall be cleaned and sanitized at least every 2—3 hours. This equipment shall be cleaned at the end of each shift and shall be cleaned and sanitized immediately prior to use.

9.20 Utensils and dismantled equipment shall be drained and air dried on approved self-draining metal racks and shall not be nested.

9.21 Dump tanks, drawoff tanks, and churns shall be cleaned approximately every 4 hours. All such equipment and all other liquid handling equipment, unless cleaned by acceptable cleaned in place methods, shall be dismantled and cleaned after each shift. Pasteurization equipment shall be cleaned at the end of each day's use or more often if necessary. All such equipment shall be cleaned and shall be sanitized prior to placing in use.

9.22 Strainers, clarifiers, filtering and other devices used for removal of shell particles and other foreign material shall be cleaned and sanitized each time. It is necessary to change such equipment, but at least once each 4 hours of operation.

9.23 Breaking room processing equipment shall not be stored on the floor.

9.24 Metal containers and lids for other than dried products shall be thoroughly washed, rinsed, sanitized, and drained immediately, prior to filling. The foregoing sequence shall not be required if equally effective measures approved by the Competent authority inwriting are followed to assure clean and sanitary containers at the time of filing.

9.25 Liquid egg holding wats and containers (including tank trucks) used for transporting liquid eggs shall be cleaned after each use. Such equipment shall be cleaned and sanitized immediately prior to placing in use.

9.26 Tables, shell conveyors, and containers for inedible egg product shall be cleaned at the end of each shift.

9.27 Mechanical egg breaking machines shall be operated at a rate to maintain complete control and accurately inspect and segregate each egg to ensure the romoval of all loss and inedible eggs. The machine shall be operated in a sanitary manner.

(i) When an inedible egg is encountered on mechanical egg breaking equipment, the inedible egg and contaminated liquid shall be removed. The machine shall be cleaned and sanitized, or contaminated parts replaced with clean ones for the type of inedible egg encountered and the kind of egg breaking machine.

(ii) Systems for pumping egg liquid directly from egg breaking machines shall be of approved sanitary design and construction, and designed to minimize the entrance of shells into the system and be disconnected when inedible eggs are encountered. The pipeline of the pumping system shall be cleaned or flushed as often as needed to maintain them in a sanitary condition, and they shall be cleaned and sanitized at the end of each shift. Other pumping system equipment shall be cleaned and sanitized approximately every 4 hours or as often as needed to maintain it in a sanitary condition. All liquid egg pumped directly from egg breaking machines shall be re-examined, except as otherwise prescribed and approved by the Competent Authority

(iii) Mechanical egg breaking equipment shall be cleaned and sanitized prior to use, and during operations, they shall be cleaned and sanitized approximately every 4 hours or more often, if needed, to maintain them in a sanitary condition. This equipment shall be cleaned at the end of each shift.

10. Liquid Egg Cooling :

10.1 Liquid egg storage rooms, including surface coolers and holding tank rooms, shall be kept clean and free from objectionable odours and condensation. Surface coolers and liquid holding vats containing product shall be kept covered while in use. Liquid cooling units shall be of approved construction and have sufficient capacity to cool all liquid eggs to the temperature requirements specified in this Annexure.

10.2 Compliance with temperature requirements applying to liquid eggs shall be considered as satisfactory only if the entire mass of the liquid meets the requirements.

10.3 The cooling and temperature requirements for liquid egg products shall be as specified in Table-I of this Annexure.

10.4 Upon written request and under such conditions as may be prescribed by the Competent Authority, liquid cooling and holding temperatures not otherwise provided for in this Annexure may be approved.

10.5 Agitators shall be operated in such a manner so as to minimise foaming.

10.6 When ice is used as an emergency refrigerant by being plyaced directly into the egg meat, the source of the ice must be certified by the local or State Board of health approved by State Health Authority or other Agency or Laboratory acceptable to the Competent Authority as safe and suitable for food processing.

11. Liquid Egg Holding :

11.1 Tanks and vats used for holding liquid eggs shall be of approved construction, fitted with covers, and located in rooms maintained in a sanitary condition. Notwithstanding the foregoing, tanks designed for installation partially outside of a room or building are acceptable, providing all openings into the tanks terminate in the processing room.

11.2 Liquid egg holding tanks or vats shall be equipped with suitable thermometers and agitators.

11.3 Inlets to holding tanks or vats shall be such as to prevent excessive foaming.

11.4 Gaskets, if such, shall be of a sanitary type.

12. Freezing Facilities :

12.1 Freezing rooms, either on or off the premises shall be capable of freezing all liquid egg products in accordance with the freezing requirements as set forth in 13 of this Annexure. Use of off-premise freezing facilities is permitted only when prior approval is obtained in writing from the Competent authority.

12.2 Adequate air circulation shall be provided in all freezing rooms.

13. Freezing operations :

13.1 Freezing rooms shall be kept clean and free from objectionable odours.

13.2 Requirements :

(i) Unpasteurized egg products which are to be frozen shall be solidly frozen or reduced to a temperature of —12 Degrees C or lower within 60 hours from time of breaking.

(ii) Pasteurized egg products which are to be frozen shall be solidly frozen or reduced to a temperature of —12 Degree C or lower within 60 hours from time of pasteurization.

(iii) The temperature of the products not solidly frozen shall be taken at the centre of the container to determine compliance with this Annexure.

13.3 Containers shall be stacked so as to permit circulation of air around the containers.

13.4 The outside of liquid egg containers shall be clean and free from evidence of liquid egg.

13.5 Frozen egg products shall be examined by organoleptic examination after freezing to determine their fitness for human food. Any such products which are found to be unfit for human food shall be denatured and any official identification mark which appears on any container thereof shall be removed or completely removed or completely obliterated.

14. Defrosting Facilities :

14.1 Approved metal defrosting tanks or vats constructed so as to permit ready and thorough cleaning shall be provided.

14.2 Frozen egg crushers, when used, shall be of approved metal construction. The crushers shall permit ready and thorough cleaning and the bearings and housing shall be fabricated in such a manner as to prevent contamination of the egg products.

14.3 Service tables shall be of approved metal construction without open seams and the surfaces shall be smooth to allow thorough cleaning.

15. Defrosting operations :

15.1 Frozen egg products which are to be defrosted shall be defrosted in a sanitary manner.

15.2 Each container of frozen eggs shall be checked for condition and odour just prior to being emptied into the crusher or receiving tank. Frozen eggs which have objectionable odours and are unfit for human food (e.g., sour, musty, fermented, or decomposed odours) shall be denatured.

15.3 Frozen whites to be used in the production of dried albumen may be defrosted at room temperature. All other whites shall be defrosted in accordance with para 15.4 of this Annexure.

15.4 Frozen whole eggs, whites and yolks may be tempered or partially defrosted for not to exceed 48 hours at a room temperature no higher than 5 Degrees C or not to exceed 24 hours at a room temperature above 5 Degrees C : Provided, that no portion of the defrosted liquid shall exceed 10 Degrees C while in or out of the container.

(i) Frozen eggs packed in metal containers may be placed in running cold tap water without submersion to speed defrosting.

(ii) The defrosted liquid shall be held at 5 Degrees C or less except for product to be pasteurized or stabilized by glucose removal. Defrosted liquid shall not be held for more than 16 hours prior to processing or drying.

15.5 Sanitary methods shall be used in handling containers and removing egg product.

15.6 Crushers and other equipment used in frosting operations shall be dismantled at the end of each shift and shall be washed, rinsed, and sanitized:

(i) Where crushers are used intermittently, they shall be flushed after each use and again before being placed in use.

(ii) Floors and work tables shall be kept clean.

16. Spray process drying facilities :

16.1 Driers shall be of a continuous discharge type and so constructed and equipped to prevent an excess accumulation of powder in the drier, bags, and powder conveyors.

16.2 Driers shall be of approved construction and materials, with welded seams, and the surfaces shall be smooth to allow for thorough cleaning.

16.3 Driers shall be equipped with approved air intake filters.

16.4 Air shall be drawn into the drier from sources free from foul odours, dust, and dirt.

16.5 Indirect heat or the use of an approved premixing device or other approved devices for securing complete combustion in direct-fired units is required. A premix-type burner, if used, shall be equipped with approved air filters at blower intake

16.6 High-pressure pump heads and lines shall be of stainless steel construction or equivalent which will fallow for thorough cleaning.

16.7 Preheating units, if used, shall be of stainless steel construction, or equivalent which will allow thorough cleaning.

16.8 Power conveying equipment shall be so constructed as will facilitate thorough cleaning.

16.9 Sifters shall be constructed of an approved metal or metal lined interior. The sifting screens and frames shall be of an approved metal construction. Sifters shall be so constructed that accumulations of large particles or lumps of dried eggs can be removed continuously while the sifters are in operation

17. Spray process drying operations :—

17.1 The drying room shall be kept in a clean condition and free of flies, insects, and rodents.

17.2 Low pressure lines, high pressure lines, high and low pressure lines, high and low pressure pumps, homogenizers, and pasteurizers shall be cleaned by acceptable in place cleaning methods or dismantled and cleaned after use or as necessary when operations have been interrupted.

(i) Spray nozzles, orifices, cores, or whizzers shall be cleaned immediately after cessation of drying operations.

(ii) Equipment shall be sanitized within 2 hours prior to resuming operations.

17.3 Drying units, conveyors, sifters, and packaging systems shall be cleaned whenever wet powder is encountered or when other conditions occur which would adversely affect the product. The complete drying unit including sifters, conveyors, and powder coolers shall be either wet washed or dry cleaned. A combination of wet washing and dry cleaning of the complete drying unit shall not be permitted unless that segment of the unit to be cleaned in a different manner is completely detached or disconnected from the balance of the drying unit.

(i) Sifters and conveyors used for other than dried albumen shall be cleaned of powder when such equipment is not to be used for a period of 24 hours or longer.

(ii) Collector bags shall be cleaned as often as needed to maintain them in an acceptable clean condition.

17.4 Powder shall be sifted and the screen shall be replaced whenever torn or worn.

17.5 Accumulations of large particles or lumps of dried eggs shall be removed from the sifter screens continuously.

17.6 All openings into the drier around ports, augers, high-pressure lines, etc., shall be closed to the extent possible during the drying operation to prevent entrance of unfiltered air.

17.7 Openings into the drying unit shall be closed when the drier is not in use, except when the drying unit has been completely emptied of powder and wet washed. This includes, but is not limited to, openings, for the air intake and exhaust systems, nozzle openings, ports, augers, etc.

18. Spray Process Powder : Definitions and Requirements.

18.1 Definition of product :

(i) "Primary powder" is that powder which is continuously removed from the primary or main drying chamber while the drying unit is in operation.

(ii) "Secondary powder" is that powder which is continuously and automatically removed from the secondary chamber and/or bag collector chamber while the drying unit is in operation.

(iii) "Sweep-down powder" is that powder which is recovered in the brush-down process from the primary or secondary chamber and conveyors.

(iv) "Brush bag powder" is that powder which is brushed from the collector bags.

18.2 Secondary powder shall be continuously discharged and mixed with the primary powder by methods approved by the Competent Authority.

18.3 Edible dried egg products, including edible ingredients which may be added to such dried products, may be dry blended. provided, that the blending is done in a room as provided in 21 of this Annexure or in a closed blending system and in accordance with clean, sanitary practices and such procedures as may be prescribed by the competent Authority.

18.4 Any edible, dried egg powder may be reconstituted, repasteurized, and redried when accomplished in a clean, sanitary manner and in accordance with such procedures as may be prescribed by the Competent Authority.

18.5 Edible dried egg powder obtained from the sweep down, screenings, brush bag (except for brush bag powder from albumen driers), and improperly dried or scorched powder shall be reconstituted, repatseurized, and redried

18.6 Approximately the first and last 80 kgs of powder from the main driers for each continuous operation shall be checked for improperly dried or scorched powder.

19. Albumen Flake Process Drying Facilities :

19.1 Drying facilities shall be constructed in such a manner as will allow thorough cleaning and be equipped with approved intake filters.

19.2 The intake air source shall be free from foul odours, dust and dirt.

19.3 Premix type burners, if used, shall be equipped with approved airfilters at blower intake.

19.4 Fermentation tanks, drying pans, trays or belts, scrapers curing racks, and equipment used for pulverizing pan dried albumen shall be constructed of approved materials in such a manner as will permit thorough cleaning.

19.5 Sifting screens shall be constructed of approved materials in such a manner as will permit thorough cleaning and be in accordance with the specification for the type of albumen produced.

20. Albumen flake process drying operations .

20.1 The fermentation drying, and curing rooms shall be kept in a dustfree condition and free of flies, insects, and rodents

20.2 Drying units, racks, and trucks shall be kept in a clean and sanitary condition.

20.3 Drying pans, trays, belts, scrapers, or curing racks, if used, shall be kept in a clean condition

20.4 Oils and waxes used in oiling drying pans or trays shall be of edible quality.

20.5 Equipment used for pulverizing or sifting dried albumen shall be kept in a clean condition.

21. Drying, Blending, Packaging and heat treatment rooms and facilities :

21.1 General : Processing rooms shall be maintained in a clean condition and free of flies, insects, and rodents. The drying, blending, and packaging rooms shall be well-lighted and have ceilings and walls of a tile surface, enamel paint, or other water-resistant material.

(i) The floors shall be free from cracks or rough surfaces where water or dirt could accumulate.

(ii) The intersections of the walls and floors shall be impervious to water and the floor shall be sloped for adequate drainage.

(iii) Metal storage racks or cabinets shall be provided for storing of tools and accessories.

21.2 Drying blending of edible egg products, including adding edible dry ingredients, and/or packaging of spraydried products shall be done in a room separate from other processing operations. Dry blending may also be done in other areas provided that it is accompanied in an approved closed blending system.

(i) Blending and packaging rooms for pasteurized products shall be provided with an adequate positive flow of approved outside filtered air.

(ii) Blending and packaging equipment and accessories which come into contact with the dried product shall be of an approved construction without open seams and of or materials that can be kept clean and which will have no deleterious effect on the product. Service tables shall be of approved metal construction without open seams and surfaces shall be smooth to permit thorough cleaning.

(iii) Package liners shall be inserted in a sanitary manner, and equipment and supplies used in the operation shall be kept off the floor.

(iv) Utensils used in packaging dried eggs shall be kept clean at all times and whenever contaminated shall be cleaned and sanitized. When not in use, scoops, brushes, tampers, and other similar equipment shall be stored in sanitary cabinets or racks provided for this purpose.

(v) Automatic container fillers shall be of a type that will accurately fill given quantities of product into the containers. Scales shall be provided to accurately check the weight of the filled containers. All equipment used in mechanically packaging dried egg products shall be vaccum cleaned daily.

21.3 The heat treatment room shall be of an approved construction and be maintained in a clean condition. The room or rooms shall be of sufficient size so that product to be heat treated can be so Spaced to assure adequate heat and air circulation. The room shall have an adequate heat supply and a continuous air circulation system.

22. Dried egg storage :

Dried egg storage shall be sufficient to adequately handle the production of the plant and shall be kept clean, dry, and free from objectionable odours.

23. Washing and Sanitizing room or area facilities :

23.1 This room or area shall be well lighted, and of sufficient size to permit operators to properly wash and sanitize all equipment at the rate required by the size of the operation. Adequate exhaust shall be provided to assure the prompt removal of odours and vapours and the air flow shall be away from the breaking room. If the washing and sanitizing is not done in a separate room, it shall be in an area well segregated from the breaking areas and well-ventilated with air movement directed away from the breaking operations so that odours and vapours do not permeate the breaking areas.

23.2 Ceiling and walls shall have a surface of tile, enamel paint, or other water-resistant material.

23.3 Floors shall be adequately sloped for proper drainage, be free from cracks or rough surfaces where water and dirt could accumulate and the intersections with walls shall be impervious to water.

24. Cleaning and sanitizing requirements :

24.1 Cleaning :

(i) Equipment used in egg processing operations which comes in contact with liquid eggs or exposed edible products shall be cleaned to eliminate organic matter and inorganic residues. This may be accomplished by any sanitary means but it is preferable (unless high pressure cleaning is used) to flush soiled equipment with clean cool water, dismantle it when possible, wash by brushing with warm water containing a detergent and followed by rinsing with water. It is essential to have the equipment surfaces thoroughly clean if effective sanitizing is to be attained.

(ii) Equipment shall be cleaned with such frequency as is specified elsewhere under the sanitary requirements for the particular kind of operation and type of equipment involved.

(iii) C.I.P. (cleaned-in-place) shall be considered to be acceptable only if the methods and procedures used accomplish cleaning equivalent to that obtained by thorough manual washing and sanitizing of dismantled equipment. The Competent Authority shall determine the acceptability of C.I.P. cleaning procedures and may require bacteriological tests and periodic dismantling of equipment as a basis for such determination.

24.2 Sanitizing :

(i) Sanitizing shall be accomplished by such methods as approved by the Competent Authority.

(a) Chemicals and compounds used for sanirizing shall have approved by the Competent Authority.

(b) Sanitizing by use of hypochlorite or other approved sanitizing solutions shall be accomplished by subjecting the equipment surfaces to such sanitizing solution containing a maximum strength of 200 PPM of available chlorine or its equivalent. These solutions shall be changed whenever the strength drops to 100 PPM or less of available chlorine or its equivalent.

(ii) Shell eggs which have been sanitized and equipment which have been sanitized and equipment which comes in contact with edible products shall be rinsed with clean water after sanitizing if other than hypochlorites are used as sanitizing agents unless or otherwise approved by the Competent Authority.

25. Health and hygine of personnel :

25.1 Personnel facilities, including toilets, lavatories, lockers, and dressing rooms shall be adequate and meet requirements for food processing plants.

25.2 Toilets and dressing rooms shall be kept clean and adequately ventilated to eliminate odours and kept adequately supplied with soap, towels, and tissues. Toilet rooms shall be ventilated to the outside of the building.

25.3 No person affected with any communicable disease in a transmissible stage or a carrier of such disease or with boils, sores, infected wounds, or wearing cloth bandages on hands shall be permitted to come in contact with eggs in any form or with equipment used to process such eggs.

25.4 Workers coming into contact with liquid or dried eggs, containers, or equipment shall wear clean outer uniforms.

25.5 Plant personnel handling exposed edible product shall wash their hands before beginning work, and upon returning to work after leaving the work room.

25.6 Expectorating, or other unsanitary practices, shall not be permitted.

25.7 Use of tobacco in any form or the wearing of jewellery, nail polish, or perfumes shall not be permitted in any area, where edible products are exposed.

25.8 Hair nets or caps shall be properly worn by all persons in breaking and packaging rooms.

26. Pasteurization of Liquid Eggs :

26.1 Pasteurization facilities : The facilities for pasteurization of egg products shall be adequate and of approved construction so that all products will be processed as provided for in this Annexure. Pasteurization equipment for liquid egg product shall include a holding tube, an automatic flow diversion valve, thermal controls, and recording devices to determine compliance for pasteurization as set forth in para 26.2 of this Annexure. The temperature of the heated liquid egg product shall be continuously and automatically recorded during the process.

26.2 Pasteurizing operations : Every particle of all products must be rapidly heated to the required temperature and held at that temperature for the required minimum holding time as set forth in this Annexure. The temperatures and holding times listed in Table II of this Annexure are minimum. The product may be heated to higher temperatures and held for longer periods of time. Pasteurization procedures shall assure complete pasteurization, and holding, packaging, facilities and operations shall be such as to prevent contamination of the product.

26.3 Other methods of pasteurization may be approved by the Competent Authority when such treatments give equivalent effects to those specified in para

26.2 of this Annexure for those products or other products and results in a salmonella negative product.

27. Heat Treatment of Dried Whites :

Heat treatment of dried whites is an approved method for pasteurization and the product shall be heated throughout for such times and at such temperatures as will result in salmonella negative product.

27.1 The product to be heat treated shall be held in the heat treatment room in closed containers and shall be spaced to assure adequate heat penetration and air circulation. Each container shall be identified as to type of product (spray or pan dried) and with the lot number or production code number.

27.2 The minimum requirements for heat treatment of spray or pan dried albumen shall be as follows :

(i) Spray dried albumen shall be heated throughout to a temperature not less than 55 Degrees C and held continuously at such temperature not less than 7 days and until it is salmonella negative.

(ii) Pan dried albumen shall be heated throughout to a temperature of not less than 52 Degrees C and held continuously at such temperature not less than 5 days and until it is salmonella negative.

(iii) Methods of heat treatment of spray dried or pan dried albumen, other than listed in para 27.2 (i) and (ii) of this Annexure may be approved by the Competent Authority upon receipt of satisfactory evidence that such methodes will result in salmonella negative products.

27.3 Dried whites which have been heat treated in the dried form shall be sampled and analyzed for the presence of salmonellae as required in II of Annexure-XII.

27.4 Records shall be maintained for one year of the following

(i) Types of product;

(ii) Lot number;

(iii) Heat treatment room temperatures.

(iv) Product temperatures;

(v) Length of time product is held in heat treatment room;

(vi) Results of all laboratory analysis made for the presence of salmonella.

27.5 Dried whites processed and tested in accordance with all of the applicable requirements specified in this Annexure may be labelled "Pasteurized."

TABLE—1

MINIMUM COOLING AND TEMPERATURE REQUIREMENTS FOR LIQUID EGG PRODUCTS

(Unpasteurized product temprature within 2 hours from time of breaking)

Product	Liquid (other than salt product) to be held 8 hrs. or less	Liquid (other than salt product) to be held in excess or 8 hours
1	2	3
White (not to be stabilized)	13°C or lower	7°C or lower
Whites (to be stabilized)	21°C or lower	13°C or lower
All other product (except product with 10 per cent or more salt added)	7°C or lower	5°C or lower
Liquid egg product with 10 percent or more salt added	.....	.....

Liquid salt product	Temperature within 2 hours after pasteurization	Temperature within 3 hours after stabilization
4	5	6
.....	7°C or lower	
.....	13°C or lower	(1)
.....	if to be held 8 hours or less 7 Deg. C or lower. (or) 5°C or lower if to.	if to be held 8 hours or less 7 Deg. C or lower. (or) 5°C or lower if to

If to be held 30 hrs ..... or less ; or more 18 Deg. C ; 7 Deg. C*

*lower : or lower

1. Stabilized liquid whites shall be dried as soon as possible after removal of glucose. The temperature of stabilized liquid whites shall be limited to that necessary to provide a continuous operation.
2. The cooling process shall be continued to assure that any sale product to be held in excess 24 hours is cooled and maintained at 7 Degrees C or lower.

TABLE—II

PASTEURIZATION REQUIREMENTS

Liquid Egg Product	Minimum Temperature Requirements (Deg. C)	Minimum Holding Time Requirements (Minutes)	
1	2	3	4
Albumen (without use of chemicals)	55	56	3.5
			6.2
Whole egg	60	3.5	
Whole egg blends (less than 2 per cent added non-egg ingredients)	61	3.5	
	60	6.2	
Fortified whole egg and blends (24-38 per cent egg solids. 2-12 per cent added non-egg ingredients)	61		3.5
	60		6.2
Salt whole egg (with 2 per cent or more salt added)	63	3.5	
	62		6.2
Sugar whole egg (2-12 per cent sugar added)	61	3.5	
	60		6.2
Plain yolk	61		3.5
	60	6.2	
Sugar yolk (2 per cent or more sugar added)	63		3.5
	62		6.2
Salt yolk (2-12 per cent salt added)	63		3.5
	62		6.2

LABORATORY

II. LABORATORY TESTS AND ANALYSIS

Laboratory tests and analysis :

The approved plant, at their expense, shall make tests and analysis to determine compliance with the rules and the regulations.

(i) Sample shall be drawen from liquid, frozen, or dried egg products and analyzed for compliance with the standards of identity (if any) and with the product label.

(ii) To ensure adequate pasteurization, pasteurized egg products and heat treated dried egg whites shall be sampled and analyzed for the presence of salmonella in accordance with such sequence, frequency, and approved laboratory methods as prescribed in these rules by the Competent Authority. The samples of pasteurized egg products and heat treated dried egg whites shall be drawn from the final packed form.

(iii) Results of the analysis and tests shall be made available to the Competent Authority.

(iv). Competent Authority will draw confirmation samples and send them to their laboratory at their expenses to determine the adequacy of the plants tests and analysis.

ANNEXURE XIII

IDENTIFYING AND MARKING PRODUCT

1. EGG PRODUCTS REQUIRED TO BE LABELLED :

Containers and portable tanks of edible egg products, prior to leaving the approved plant shall be labelled in accordance with para 2 to 5 of this Annexure and shall bear the official identification shown in figure 2 of para 3 or figure 3 of para 5. Bulk transport shipments of liquid pasteurized egg products to non-official outlets need not be sealed.

2. REQUIREMENT OF FORMULAS AND APPROVAL OF LABELS FOR USE IN APPROVED PLANTS FOR EGG PRODUCTS:

2.1 No label, container, or packaging material which bears official identification may bear any statement that is false or misleading. Any label, container or packaging material which bears any official identification shall be used only in such manner as the Competent Authority may prescribe. No label, container, or packaging material bearing official identification may be used unless it is approved by the Competent Authority in accordance with para 2.2 of this Annexure. The use of finished labels must be approved as prescribed by the Competent Authority. If the label is printed in or otherwise applied directly to the container or packaging material the principal display panel thereof shall be considered as the tabel.

2.2 No label, container, or packaging material bearing official identification may be printed or prepared for use until the painters or other final proof has been approved by the Competent Authority in accordance with the regulations in this Annexure. Copies of each label submitted for approval shall be accompanied by :

(i) A statement showing by their common or usual names the kinds and percentages of the ingredients comprising the egg product in the form in which it is to be used (i.e. liquid oil dried). Approximate percentages (range) may be given in cases where the percentages may vary from time to time.

(ii) When required, scientific data demonstrating that the substance or mixture is safe and effective for its intended use.

2.3 Containers of product bearing official identification shall display the following information:

(i) The common or usual name, if any, and if the product is comprised of two or more ingredients, such ingredients shall be listed in the order of descending proportions by weight/volume. When water (excluding that used to reconstitute dehydrated ingredients back to their normal composition) is added to a liquid or frozen egg product or water content of that ingredient). The total amount of water added including the water content of any cellulose or vegetable gums used shall be expressed as a percentage of the total product weight in the ingredient statement on the label.

(ii) The name, address, and pin code of the exporter.

(iii) The lot number or production code number.

(iv) The net contents.

(v) Official identification and plant number.

(vi) Egg products which are produced in an approved plant from edbile shell eggs of other than current production or from other egg products produced from shell eggs of other than current production shall be clearly and distinctly labelled in close proximity to the common or usual name of the product e.g., "Manufactured from eggs of other than current production".

(vii) Egg products produced from edible shell eggs or the egg product produced from such shell eggs or the turkey, duck, goose or guinea fowl shall be clearly and distinctly labelled as to the common or usual name of the product indicating the type of eggs or egg products used in the product e.g., "Frozen whole turkey eggs", "Frozen whole chicken and turkey eggs". Egg products labelled without qualifying words as to the type of shell egg used in the product shall be produced only from the edible shell egg of the domesticated hen or the egg product produced from such shell eggs.

2.4 Liquid or frozen egg products indentified as whole eggs and prepared other than in natural proportions as broken from the shell, shall have a total egg solids content of 24.20 per cent of greater.

2.5 Nutrition information may be included on the label of egg products providing such labelling complies with the provisions of the prevailing regulations in force. Since these regulations have different requirements for consumer packaged products than for bulk packaged egg products not for sale or distribution to household consumers, label submission shall be accompanied with information indicating whether the label covers consumer packaged or bulk packaged product. Nutrition labelling is required when nutrients such as proteins, vitamins and minerals are added to the product or when a nutritional claim or information is presented on the labelling except for the following which are exempt from nutrition labelling requirements:

(i) Egg products shipped in bulk form for use solely in the manufacture of other food and not for distribtuion to household consumers in such bulk form or containers.

(ii) Products containing an added vitamin, mineral or protein or for which a nutritional claim is made on the label or in advertising which is supplied for institutional food use only; provided, that the manufacturer directly to those institutions.

(iii) Any nutrient(s) included in product solely for technological purpose may be declared solely in the ingredients statements, without complying with nutrition labelling. If the nutrient(s) is otherwise not referred to in labelling or in advertising labels will not be approved by the Competent Authority.

3. FORM OF OFFICIAL IDENTIFICATION SYMBOL AND INSPECTION MARK:

3.1 The shield set forth in Figure 1 containing the letters shall be the official identification symbol for purpose of this chapter.

SEAL OF THE
COMPETENT
AUTHORITY

FIGURE—1

3.2 The inspection mark which is to be used on containers of edible egg products shall be contained within the outline of a shield and with the wording and design set forth in Figure 2 of this Annexure except the plant number may be omitted from the official identification if applied else where on the container.

SEAL OF THE
COMPETENT
AUTHORITY

INSPECTED
EGG PRODUCTS
PLANT NO. .....

FIGURE--2

4. PRODUCTS BEARING THE OFFICIAL INSPECTION MARK.—Egg products which are permitted to bear the inspection mark shall be processed in an approved plant from edible shell eggs or other edible egg products and may contain other edible ingredients. The official mark shall be printed or lithographed and applied as a part of the principal display panel of the container but shall not be applied to a detachable cover.

5. USE OF OTHER OFFICIAL IDENTIFICATION.—Other official indentification as shown in this Annexure shall be printed or lithographed and applied as a part of the principal display panel but shall not be applied to a detachable cover. The plant number may be omitted from the identification if applied elsewhere on the label or container. Such products shall meet all requirements for egg products which are permitted to bear the official inspection mark shown in para 3 except for pasteurization heat treatment or other such methods of treatment approved by the Competent Authority.

5.1 All unpasteurised egg products shipped from an approved plant in packed form shall be marked with the identification set forth in Figure—3 of this chapter. After pasteurization or treatment, the product may bear the official inspection mark as shown in Figure 3.

EGG PRODUCTS
FOR FURTHER PROCESSING
IN AN APPROVED PLANT

FIGURE—3

6. UNAUTHORISED USE OR DISPOSITION OF APPROVED LABELS.—

6.1 Containers or lebels which bear official identification approved for use pursuant to para 2 shall be used only for the purpose for which approved. Any unauthorized use or disposition of approved containers or labels which bear any official identification may result in cancellation of the approval.

6.2 Upon termination of inspection service in an approved plant pursuant to these rules, all labels, seals, tags or packaging material bearing official identification shall under the supervision of a person of the Competent Authority either be destroyed or the official identification completely obliterated or inventorised and sealed in a manner acceptable to the Competeat Authority.

7. SUPERVISION OF MAKING AND PACKAGEING :

7.1 Evidence of lable approval :

The Competent Authority shall not allow the use of official identification on any inspected product unless it has on file evidence that such official identification or packaging material bearing such official identification has been approved in accordance with the provision of para 2.

7.2 Affixing of official identification :

No official identification shall be or caused to be affixed to or placed on any product or container except by the Competent Authority. All such products shall have been inspected in accordance with these rules. The Competent Authority shall have supervision over the use and handling of all material bearing any official identification.

8. REUSE OF CONTAINERS BEARING OFFICIAL IDENTIFICATION PROHIBITED

The reuse, by any person, of containers bearing official identification is prohibited unless such identification is applicable in all respects to product being re-packed therein. In such instances the container and label may be used provided the packaging is accomplished under the supervision of the Competent Authority and the container is in compliance with para 3 of Annexure—XII.

ANNEXURE XIV

1. "EGG" :

1.1 "Egg" is the shell egg of the domesticated hen, turkey, duck, goose, or guinea fowl. Some of the terms applicable to shell eggs are as follows :

(i) "Check" is an egg that has a broken shell or crack in the shell but has its shell membranes intact and contents not leaking.

(ii) "Clean and sound shell egg" is any egg whose shell is free of adhering dirt or foreign material and is not cracked or broken.

(iii) "Dirty egg" or "Dirties" is an egg(s) that has a shell that is unbroken and has adhering dirt, foreign material or prominent stains.

(iv) "Eggs of current production" is shell eggs which have moved through the usual marketing channels since the time they were laid and are not in excess of 60 days old.

(v) "Inedible" is eggs of the following descriptions : Black rots, yellow rots, white rots, mixed rots, sour eggs, eggs with green whites, eggs with stuck yolks, moldy eggs, musty eggs, eggs showing blood rings and eggs containing embryo chicks (at or beyond the blood ring stage).

(vi) "Leaker" is an egg that has a crack or break in the shell and shell membrane to the extent that the egg contents are exposed or are exuding or free to exude through the shell.

(vii) "Incubator reject" is an egg that has been subjected to incubation and has been removed from incubation during the hatching operations as infertile or otherwise unhatchable.

(viii) "Loss" is an egg that is unfit for human food because it is smashed or broken so that its contents are leaking or overheated, frozen or contaminated or an incubator reject or because it contains a bloody white, large meat spots, a large quantity of blood or other foreign material.

(ix) "Restricted egg" is any check, dirty egg, incubator reject, inedible, leaker or loss.

(x) "White or albumen" means for the purpose of this part the product obtained from the egg as broken from the shell and separated from the yolk.

[F. No. 6/1/95-EI & EP.]
KUM. SUMA SUBBANNA, Director

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1997

का०आ० 2079—मैं पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन 299 सैक्टर 16 क चंडीगढ़ 160015 को फ्लड लाईटिंग उपकरण के आयात के लिए 1,07,27,000 रु० (एक करोड़ सात लाख सत्ताईस हजार रुपये मात्र) के लिए एक आयात लाइसेंस सं० पी/ए/1532405 दिनांक 30-10-95 प्रदान किया गया था ।

2. फर्म ने इस आधार पर कि उक्त लाइसेंस की मूल विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है या अस्थानस्थ हो गई है उपर्युक्त लाइसेंस की विनिमय नियंत्रण प्रयोजन की डुप्लीकेट प्रति जारी करने हेतु आवेदन किया है। फर्म ने आगे यह कहा है कि विनिमय नियंत्रण प्रति नहावशेवा और नई दिल्ली (सीमा शुल्क सदन) में पंजीकृत थी और सीमा शुल्क प्रयोजन प्रति का 2,35,67,000/- रु० के लिए उपयोग किया गया है ।

3. अपने कथन के समर्थन में, लाइसेंस-धारक ने नोटरी पब्लिक चंडीगढ़ के समक्ष बाकायदा शपथ लेकर स्टैम्प पेपर पर हलफनामा दाखिल किया है । तदनुसार, मैं संतुष्ट हूं कि आयात लाइसेंस सं० पी/ए/1532405 दिनांक 30-10-95 की मूल विनिमय नियंत्रण प्रति फर्म द्वारा खो गई है या अस्थानस्थ हो गई है । डी जी एफ टी, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश सं० का० आ० 1060 (अ) दिनांक 1-12-93 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन को जारी विनिमय नियंत्रण प्रति सं० पी/ए/1532405 दिनांक 31-10-95 को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है ।

4. उक्त लाइसेंस की डुप्लीकेट विनिमय नियंत्रण प्रति पार्टी को अलग से जारी की जा रही है ।

[फा० सं० एम पी एन/एन एस-11/978/ए एम० 96/एस एल एस/302]

एस० के० सामल, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार

(Directorate General of Foreign Trade)

New Delhi, the 4th August, 1997

S.O. 2079.—M/s Punjab Cricket Association, 299, Sector 16-A, Chandigarh-160015 were granted an import licence No. P/A/1532405 dated 30-10-95 for Rs. 1,07,27,000 (Rupees One Crore seven lakhs twenty seven thousand only) for import of Flood Lighting Equipment.

The firm has applied for issue of duplicate copy of Exchange control purpose copy of the above mentioned licence on the ground that the original exchange control copy of the licence has been lost or misplace. It has further been stated that the Exchange Control copy of the licence was registered with Nhavasheva and New Delhi (Custom House) and as such the value of Customs purpose copy has been utilised for Rs. 35,67,000.

2. In support of their contention, the licensee has filed an Affidavit on Stamped paper duly sworn in before Notary Public, Chandigarh on 27-6-87. I am accordingly certified that the original Exchange Control Copy of import Licence No. P/A/1532405 dated 30-10-95 has been lost or misplaced by the firm. In exercise of the powers conferred on me under order S.O. 1060(E) dated 31-12-93 issued by DGIT, New Delhi, Exchange Control Copy No. P/A/1532405 dated 30-10-95 issued to M/s. Punjab Cricket Association is hereby cancelled.

Duplicate Exchange Control Copy of the said licence is being issued to the party separately.

[F. No. SPL/NS-11/978/AM.96/SLS/302]
S. K. SAMAL, Dy. Director General of Foreign Trade

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1997

का.आ. 2080.—केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट (नीचे आकृति देखिए) पर विचार करने के पश्चात्, समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल बाट और माप मानक अधिनियम 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडल का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि वह लगातार प्रयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा देता रहेगा;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यम यथार्थता वर्ग III की जी.टी.सी. सिरीज टाइप के "गोल्ड टेक" ब्रांड नाम वाले स्वतः सूचक गैर-स्वचालित तुला चौकियों का अंकीय संप्रदाय वाले यंत्रों में रूपांतरण करने के एक रूपांतरण किट के माडल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) जिसका विनिर्माण मैसर्स प्रेसिशन इलेक्ट्रॉनिक इन्स्ट्रूमेंटस सी० ओ० 1600, एम. आई. ई. ए. बहादुरगढ़ द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न सहित आई.एन.डी./09/96/71 समनुदिष्ट किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है।

(आकृति)

माडल (आकृति देखिए) एक मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग III) का तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 40000 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 100 किलोग्राम है। सत्यापन मापमाप अन्तर (ई) 5 किलोग्राम है। इसमें एक टेयर युक्ति है। जिसका व्यकलनात्मक प्रतिधारण प्रभार 100 प्रतिशत है। भारग्राही आयतकार सैक्शन का है जिसका आकार 9 × 3 मीटर है। प्रकाश उत्सर्जन डायोड संप्रदर्श तोल परिणाम उपदर्शित करता है। यह उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर प्रचलित होता है।

आगे, केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के अनुमोदन के इस प्रमाण पत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से, जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है विनिर्मित 5 टन /5 किलोग्राम, 10 टन/5 किलोग्राम, 20 टन/5 किलोग्राम, 40 टन/10 किलोग्राम, 50 टन/5 किलोग्राम, 60 टन/10 किलोग्राम और 100 टन/20 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाले समरूप मेक, यथार्थता और उसी सिरीज के कार्यकरण वाले तोलन उपकरण भी हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू एम 21(5)/95]

राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

New Delhi, the 5th August, 1997

S.O. 1080.—Whereas the Central Government after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model (figure below) described in the said report is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the model of a conversion kit for converting self-indicating, non-automatic, mechanical weight-bridges into machines with digital display of type GTC series of class III (Medium) accuracy with brand name "GOLDTECH" (hereinafter referred to as the model) manufactured by M/s Precision Electronic Instruments Co., 1680, M.I.E., Bahadurgarh, and which is assigned the approval mark IND/09/96/71;

The model (see figure) is a medium accuracy (accuracy class III) weighing instrument with a maximum capacity of 40000 kg and minimun capacity of 100 kg. The verification scale interval (e) is 5 kilogram. It has a tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The load receptor is of rectangular section of size 9X3 metre. The Light Emitting Diodes display indicates the weghing result. The instrument operates on 230 volts, 50 Hertz alternate current power supply;

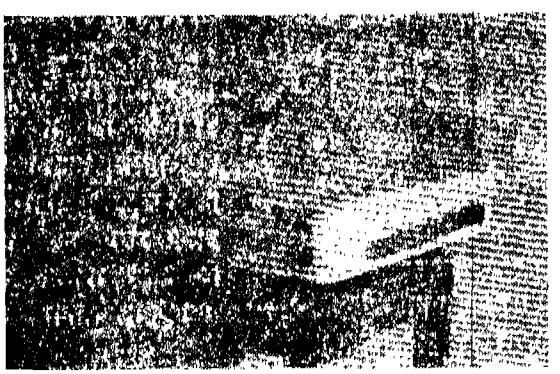

(Figure)

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity of 5t/5 kg, 10 t/5 kg, 20 t/5 kg, 40 t/10 kg, 50 t/5 kg, 60 t/10 kg and 100 t/20 kg manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[File No. WM 21 (5)/95]

RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1997

का.आ. 2081.—केन्द्रीय सरकार को विहित प्राधिकारी द्वारा निवेदित रिपोर्ट (नीचे आकृति देखिए) पर विचार करने के पश्चात् समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित माडल बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) और बाट और माप मानक (माडल का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि वह लगातार प्रयोग की अवधि में यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा देता रहेगा;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 उपधारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माध्यम यथार्थता वर्ग III कि "ई एस डी 501" सीरीज टाइप के और "लेक्ट्रानिक्स" ट्रेडमार्क वाले अंकीय संप्रदर्श वाले स्वतः सूचक गैर-स्वचालित (हाईब्रिड इलैक्ट्रानिक तुला चौकी) के माडल का (जिसे इसमें इसके पश्चात् माडल कहा गया है) जिसका विनिर्माण मैसर्स लेक्ट्रानिक्स एण्ड स्केल्स प्राइवेट लिमिटेड 155, फोकल पॉइंट, अमृतसर द्वारा किया गया है और जिसे अनुमोदन चिह्न आई. एन. डी. 09/95/58 समनुदिष्ट किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित करती है ।

माडल (आकृति देखिए) एक मध्यम यथार्थत (यथार्थत वर्ग III) की तुला चौकी है जिसकी अधिकतम क्षमता 40 टन और न्यूनतम क्षमता 100 किलोग्राम है । सत्यापन मापमान अन्तर (ई) 5 किलोग्राम है – इसमें एक टेयर युक्ति है जिसका व्यकलनात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाव 100 प्रतिशत है आधार और प्लेटफार्म धात्विक है । भारग्राही आयताकार सैक्शन का है जिस की भुजाएं 10 मीटर × 3 मीटर है । प्रकाश उत्सर्जन डायोड (एस सी डी) संप्रदर्श तोल परिणाम उपदर्शित करता है । यह उपकरण 230 वोल्ट, 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर प्रचालित होता है ।

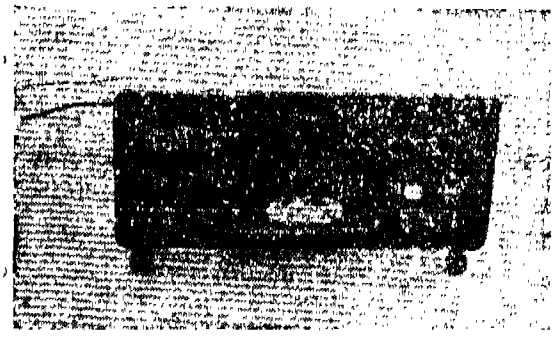

आकृति

आगे, केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि माडल के अनुमोदन के इस पत्र के अन्तर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से, जिससे अनुमोदित माडल का विनिर्माण किया गया है विनिर्मित 5 टन/1 किलोग्राम, 10 टन/2 किलोग्राम, 15 टन/2 किलोग्राम, 20 टन/5 किलोग्राम, 25 टन/5 किलोग्राम, 30 टन/5 किलोग्राम, 50 टन/5 किलोग्राम, 60 टन/10 किलोग्राम, 80 टन/10 किलोग्राम और 100 टन/10 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता और "ई" मान वाले समरूप मैक, यथार्थता और उसी सिरीज के कार्यकरण वाले तोलन उपकरण है ।

[फा. सं. डब्ल्यू एम 21(5)/95]

राजीव श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 11th August, 1997

S.O. 2081.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 36 of the said Act, the Central Government hereby publishes the certificate of approval of the Model of the self-indicating, non-automatic hybrid electronic weighbridge with digital display of type "ESD 501" series of class III medium accuracy and with the trade mark "Leotronics" (hereinafter referred to as the Model) manufactured by M/s Leotronics & Scales Pvt. Ltd., 155, Focal Point, Amritsar and which is assigned the approval mark IND/09/95/58;

The model (see figure) is a medium accuracy (accuracy class III) weighbridge with a maximum capacity of 40 tonne and minimum capacity of 100 kg. The verification scale interval (e) is 5 kg. It has tare device with a 100 percent subtractive retained tare effect. The base and the plateform are metallic. The load receptor is of rectangular section of sides 10 m × 3 m. The LED/LCD display indicates the weighing result. The instrument operates on 230 volts, 50 Hertz alternate current power supply.

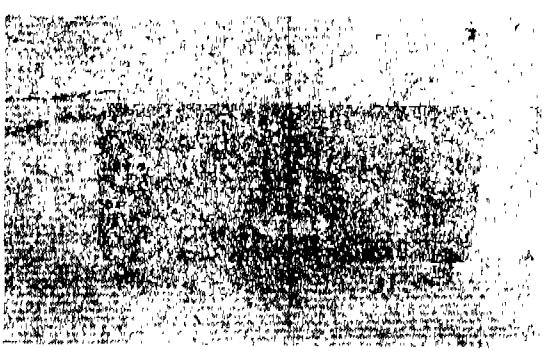

(figure)

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of the said section, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the Model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capaciry and 'e' value of 5 t/1 kg, 10 t/2 kg, 15 t/2 kg, 20 t/5 kg, 25 t/5kg, 30 t/5 kg, 50 t/5 kg, 60 t/10 kg, 80 t/10 kg and 100 t/10kg manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the approved Model has been manufactured.

[File No. WM 21(5)/95]

RAJIV SRIVASTAVA, Jt. Secy.

कोयला मंत्रालय

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1997

का.आ. 2082:—भारत के राजपत्र तारीख 26 मार्च, 1997 के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में पृष्ठ क्रमांक 1370 से 1872 पर प्रकाशित भारत सरकार कोयला मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 899 तारीख 5 अप्रैल, 1997 में :—

पृष्ठ क्रमांक 1871 पर—

1. अधिसूचना में अनुच्छेद दो में "ईस्टर्न" के स्थान पर "वैस्टर्न" पढ़िए।

2. अनुसूचि में तहसील स्तम्भ के नीचे "वनी" के स्थान पर "वणी" पढ़िए और जहां कहीं वनी शब्द प्रयुक्त हुआ हो उसी स्थान पर "वणी" पढ़िए और जिला स्तम्भ के नीचे "यावतमाल" के स्थान पर "यवतमाल" पढ़िए और जहां कहीं यावतमाल शब्द प्रयुक्त हुआ हो उसी स्थान पर "यवतमाल" पढ़िए।

3. ग्राम का नाम स्तम्भ के नीचे क्रम संख्या 4 में "मैनाक" के स्थान पर "मेनक" पढ़िए और जहां कहीं मैनाक शब्द प्रयुक्त हुआ हो उसी स्थान पर "मेनक" पढ़िए और क्रमसंख्या 5 में "साखरेरा" के स्थान पर "साखरा" पढ़िए और जहां कहीं साखरेरा शब्द प्रयुक्त हुआ हो उसी स्थान पर "साखरा" पढ़िए।

4. सीमा वर्णन में रेखा घ—ङ में "पेण गंगा" के स्थान पर "पैनगंगा" पढ़िए और "सिखाली" के स्थान पर "सिखली" पढ़िए और जहां कहीं सिखाली शब्द प्रयुक्त हुआ हो उसी स्थान पर "सिखली" पढ़िए।

[सं. 43015/18/96-एल.डब्ल्यू.]

श्रीमति प्रेमलता सैनी, अवर सचिव

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 1997

का.आ. 2083—केन्द्रीय सरकार ने कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) की धारा 7 उपधारा (1) के अधीन जारी और भारत के राजपत्र दिनांक 26 मई, 1997 के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) पृष्ठ संख्यांक 1 से 3 पर प्रकाशित भारत सरकार कोयला मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 411(अ) दिनांक 26 मई, 1997, द्वारा इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि का अधिग्रहण करने के अपने आशय की सूचना दी थी। और केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई कि राजपत्र में प्रकाशित उपरोक्त अधिसूचना में मुद्रण की कुछ गलतियां हैं।

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समर्थ करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

पृष्ठ संख्यांक 2 में :—

1. ग्राम कोरिया उमरा में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्यांक में—

प्लॉट संख्यांक "191/18" के स्थान पर "191/18 भाग" पढ़िए।

ऐसी भूमि में जिसकी बाबत उपरोक्त संशोधन जारी किया गया है, हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के जारी किए जाने के तीस दिन के भीतर उक्त भूमि संपूर्ण या किसी भाग के उक्त ऐसी भूमि में या उस पर किसी अधिकारी के अर्जित किए जाने के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के निबंधनों के अनुसार आक्षेप कर सकेगा।

स्पष्टीकरण :

केवल इस अधिसूचना के द्वारा संशोधित प्लॉट संख्यांकों की बाबत उक्त अधिनियम की धारा 8(1) के निबंधनों के अनुसार तीस दिन की उक्त अवधि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित किये जाने की तारीख से आरम्भ होगी।

[सं. 43015/20/94-एल.डब्ल्यू.]

श्रीमती प्रेमलता सैनी, अवर सचिव

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 1997

का.आ. 2084:—केन्द्रीय सरकार का दिल्ली की मुख्य योजना क्षेत्रीय योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे एतद्द्वारा जनता की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में कोई आपत्ति हो सुझाव देना चाहता हो तो वह अपनी आपत्ति/सुझावों को लिखित रूप में इस सूचना के जारी होने की तिथि से 30 दिन की अवधि के अन्दर, आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, "बी" ब्लाक, आई.एन.ए., नई दिल्ली को भेज सकते हैं। आपत्ति करने/सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम और पता भी दें।

संशोधन :—

(1) "लगभग 4.00 हैक्टे. (10 एकड़) क्षेत्र, जो योजना जोन "ओ" (यमुना नदी) में आता है और उत्तर में सड़क (पन्टून पुल की ओर जाने वाली) से, पूर्व एवं दक्षिण में यमुना नदी तट तथा पश्चिम में उच्च वोल्टेज की लाइन से घिरा हुआ है, का भूमि उपयोग "कृषि एवं जलाशय" से "सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं" (श्मशान भूमि)" में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।

(2) "योजना जोन "एफ" (दक्षिण दिल्ली) में आने वाले लगभग 0.8 हैक्टे. (2 एकड़) क्षेत्र जो उत्तर में 24 मी. मार्गाधिकार (80 फुट चौड़ी सड़क), पूर्व और दक्षिण में ई.पी.आर कालोनी तथा पश्चिम में ग्रेटर कैलाश पार्ट-1 से घिरा हुआ है, का भूमि उपयोग "प्राथमिक विद्यालय" से "सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं" (थाने)" में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।"

(3) "मुण्डका गांव (पश्चिम दिल्ली) की राजस्व सम्पदा में आने वाले लगभग 37.5 हैक्टे. (92.62 एकड़) क्षेत्र जो उत्तर में रोहतक रोड (एन.एच.—10) पूर्व में गांव को सड़क/ग्रामीण क्षेत्र में तथा दक्षिण एवं पश्चिम में ग्रामीण क्षेत्र से घिरा हुआ है का भूमि उपयोग "ग्रामीण उपयोग जोन" से "उपयोगिताओं" (400/220 के.वी. सब-स्टेशन)" में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।"

(4) "गांव पिंडवालां कलां की राजस्व सम्पदा में आने वाले लगभग 1.4 हैक्टे. (3.46 एकड़) क्षेत्र जो पूर्व में घुमनहेड़ा नजफगढ़ रोड से, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में ग्रामीण क्षेत्र से घिरा हुआ है, का भूमि उपयोग "ग्रामीण उपयोग जोन" से "सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक सुविधाओं" (अस्पताल)" में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव है।"

2. प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण हेतु संयुक्त निदेशक, मुख्य निदेशक योजना अनुभाग, दि.वि.प्रा. छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली के कार्यालय में उपर्युक्त अवधि के अन्दर सभी कार्य-दिवसों में उपलब्ध रहेगा।

[सं.एफ. 20(20)/93-एम.पी.]
विनय मोहन बंसल, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Master Plan Section)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 14th August, 1997

S.O. 2084.—The following modification which the Central Government proposes to make in the Master Plan/Zonal Plan for Delhi, are hereby published for public information. Any person having any objeections/suggestions with respect to the proposed modifications may send the objections/ suggeestions in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, 'B' Block, I.N.A., New Delhi, within a period of 30 days from the date of issue of this notice. The person making the objection(suggestion should also give his/her name and address.

MODIFICATIONS :—

(i) "The land use of an area, measuring about 4.00 ha (10 acres) falling in planning zone 'O' (River Yamuna), bounded by Road (leading to Pantoon Bridge) in the North, River Yamuna Bed in the East and South and High Tension Line in the West, is proposed to be changed from 'agricultural and water body' to 'public and semi-public facilities' (Cremation Ground)."

(ii) "The land use of an area, measuring about 0.8 ha (2 acres) falling in planning zone 'F' (South Delhi) bounded by 24 m R/W (80' wide road) in the North, EPR Colony in the East; and South and Greater Kailash Part-I in the West, is proposed to be changed from 'Primary School' to 'Public and semi-public facilities' (Police Station)".

(iii) "The land use of an area, measuring about 37.5 ha (92.62 acres) falling in the revenue estate of Mundka Village. (West Delhi), bounded by Rohtak Road (N.H. 10) in the North, village road, rural area in the East, and Rural Area in the South and West, is proposed to be changed from 'rural use zone' to 'utilities' (400/220 KV Sub-Station)."

(iv) "The land use of an area, measuring about 1.4 ha (3.46 acres) falling in the revenue estate of village Pindwalan Kalan bounded by Ghummanhera-Najafgarh Road in the East and Rural area in the North, West and South is preposed to be changed from 'rural use zone' to 'public and semi-public facilities' (Hospital)."

2. The Plans indicating the proposed modifications will be available for inspection at the office of the Joint Director, Master Plan Section, DDA, 6th Floor. Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi on all working days within the period referred above.

New Delhi :

Dated : 23-8-1997.

[No. F. 20(20)/93-MP]
V. M. BANSAL, Commissioner-cum-Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1997

का.आ. 2085.—केन्द्रीय सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग, राजभाषा (संघ) के शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग (नियम 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में एतद्द्वारा भारतीय पशु-चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर का बंगलौर स्थित केन्द्र (भा.कृ.अ.प.) जिसके 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को अधिसूचित करती है।

[संख्या 13-5/95-हिंदी]
आर पी. सरोज, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

Department of Agri. Res. & Education

New Delhi, the 28th July, 1997

S.O. 2085.—In purusance of Sub-Rule 4 of Rule 10 of the Official Language (Use of Official purpose of the Union) Rule 1976, the Central Government, Ministry of Agriculture, Department of Agricultural Research and Education hereby notifies the Bangalore Centre of Indian Veterinary Researth Institute (ICAR) Izatnagar where more than 80 per cent of Staff have acquired the working knowledge of Hindi.

[No. 13-5/95-HINDI]
R. P. SAROJ, Under Secy.

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

संशोधन

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1997

का.आ. 2086—भारत के राजपत्र दिनांक 24-2-97 के भाग II खंड 3 उपखण्ड (ii) में पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के का.आ. संख्या 142 ई पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 6 की उपधारा (ii) के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना जो कि ग्राम कोठी तालुका-भरूच, जिले भरूच के संबंध में था, को निम्नानुसार पढ़ा जाये :—

राजपत्र के अनुसार		निम्न संशोधन के अनुसार पढ़ा जाये	
क्रम सं. सर्वे सं.	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सर्वे सं.	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
01. 154	0-18-00	153	0-18-00
02. 165	0-04-50	154	0-04-50
03. 668	0-09-00	669	0-09-00
04. 248	0-01-00	266	0-01-00

[संख्या एल-14016/8/96-जी.पी.]

आई.एस.एन. प्रसाद, उप सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

CORRIGENDUM

New Delhi, the 11th August, 1997

S.O. 2086.—In the Gazette of India Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 142E published on 24-2-97 under section 6(i) of the Petroleum and Mineral Pipeline (Acquisition of Right of users in land) Act 1962 (50 of 1962) in respect of Village Kothi Taluka Bharuch Distt. Bharuch be read as follows :

As per Gazette		Be read as corrected below	
S. No. Survey No.	Area in Hectare	Survey No.	Area in Hectare
1. 154	00-18-00	153	00-18-00
2. 165	00-04-50	154	00-04-50
3. 668	00-09-00	669	00-09-00
4. 248	00-01-00	266	00-01-00

[No. L-14016/8/96-G.P.]

I.S.N. PRASAD, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 1997

का.आ. 2087—पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 411 तारीख 15-2-97 द्वारा भारत सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के अधिकार को पाइपलाईन बिछाने के लिये अर्जित करने का आशय घोषित किया था।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

तत्पश्चात् भारत सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

इस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में अधिकार भारत सरकार में निहित होने के बजाय गैस अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

पुनासन जी.जी.एस. से विमल आइल

राज्य : गुजरात जिला : मेहसाणा तालुका : मेहसाणा

गांव	क्रम सं. ब्लाक नं.	क्षेत्र		
		हैक्टेयर	आरे	सेंटीआर
हेबुवा	116	00	05	33

[सं. एल-14016/2/96-जी.पी.]

आई.एस.एन. प्रसाद, उप सचिव

New Delhi, the 11th August, 1997

S.O. 2087.—Whereas by Notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. 411, dattd 15-2-97 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that Notification for purpose of laying pipeline.

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after Considering the said report, decided to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to this notification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule to this appended notification hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of power conferredd by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

SCHEDULE

PUNSAN G.G.S. TO VIMAL OIL

State : Gujarat Tal : Mehsana Dist. : Mehsana

Village	Survey No/ Block No.	Area of R.O.U.		
		Hecatare	Are	Centiare
Hebuva	116	—00	—05	33

[No. L-14016/2/96-GP],

I.S.N. PRASAD, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1997

का.आ. 2088--चूंकि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि जनहित में यह आवश्यक है कि कानावाडा ई.पी.एस से जी ई अपार गुजरात राज्य तक पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिये पाइपलाईन गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाई जानी चाहिये।

और चूंकि यह प्रतीत होता है कि ऐसी लाईन को बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्पाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है।

अतः, अब, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उसमें उपयोग का अधिकार अर्जित करने का अपना आशय एतद्द्वारा घोषित करती है।

बशर्ते कि उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिये आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड, बड़ौदा को इस अधिसूचना की तारीख से 21 दिनों के भीतर कर सकेगा।

और ऐसा आक्षेप करने वाला हर व्यक्ति विनिर्दिष्टतः यह भी कथन करेगा कि क्या वह चाहता है कि उसकी सुनवाई व्यक्तिगत या किसी विधि व्यवसायी की मार्फत।

अनुसूची

कानावाडा ई.पी.एस. से जी.ई. अपार
लम्बासी तक पाइपलाईन

राज्य : गुजरात तालुका : कैम्बे जिला : खेड़ा

गांव	सर्वे नं. ब्लाक नं.	आर.ओ.यू. का एरिया		
		हैक्टेयर	आरे	सेंटीआर
कानावाडा	395	00	04	94
	380	00	03	92
	398	00	06	24
	397	00	06	30
	396	00	05	28
		00	26	68

[सं. एल.-14016/3/95-जी.पी.]
आई.एस.एन. प्रसाद, उप सचिव

New Delhi, the 12th August, 1997

S.O. 2088.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for for the transport of Petroleum and Natural Gas from Kanawad EPS to GE apar in Gujarat State pipeline shoulld be laid by the Gas Authority of India Ltd.

And whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the schedule annexed hereto;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the Sction 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in the Land) Act 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Provided that any person interest in the said land may, within 21 days from the date of this notification, object to the laying of the pipeline under the land to the Competent Authority, Gas Authority of India Ltd. Baroda.

And every person making such an objection shall also state specifically whether he wishes to be heard in person or by legal practitioner.

SCHEDULE
KANAWADA EPS TO GE APAR AT LIMBASI

RTATE: GUJRAT TAL: CAMBAY DIST. KHEDA

Village	Survey No/ Block No.	Area of R.O.U.		
		Hectare	Are	Centiare
Kanawada	395	00	04	94
	380	—00	03	92
	398	—00	06	24
	397	—00	06	30
	396	—00	05	28
		—00	26	68

[No. L-14016/3/95-GP]
I.S.N. PRASAD, Dy. Secy.

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1997

का.आ. 2089--भारत के राजपत्र दिनांक 4-11-95 के भाग II खंड 3 उपखंड (ii) में पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के का.आ. संख्या 2895 दि. 20-10-95 से पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाईन (भूमि में उपयोग के अधिकारी का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (i) के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना जो कि ग्राम कानावाडा तालुका कैम्बे, जिले-खेड़ा के संबंध में था, को निम्नानुसार पढ़ा जाये :—

राजपत्र के अनुसार			निम्न संशोधन के अनुसार पढ़ा जाये	
क्रम सं.	सर्वे सं.	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	सर्वे सं.	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
01	382	0-10-66	332	0-17-16
02.	401/1 2	0-07-80	401	0-03-01

[संख्या एल-14016/3/95-जी.पी.]
आई.एस.एन. प्रसाद, उप सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th August, 1997

S.O. 2089.—In the Gazette of India Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2895 dt. 20-10-95 published on 4-11-95 under section (i) of section 3 of the Petroleum and Mineral Pipeline (Acquisition of Right of users in land) Act 1962 (50 of 1962) in respect of Village Kanewada Taluka Cambay Distt. Kheda be read as follows:—

As per Gazette			Be read as corrected below	
S. No.	Survey No.	Area in Hectare Hectare	Survey No.	Area in Hectare
1.	382	0-10-66	382	0-17-16
2.	401/2	0-07-80	401	0-03-01

[No. L-14016/3/95-G.P.]
I.S.N. PRASAD, Dy. Secy.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली 6 अगस्त, 1997

का. आ. 2090.— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962(1962 का 50) (जिसे इसमें इसकेपश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1094, तारीख 27 मार्च, 1997 द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में बिनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 26 अप्रैल, 1997 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर बिचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में बिनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना चाहिए ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में बिनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करने की धोषणा करती है;

यह और कि केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए सभी विल्लुगंमों से मुक्त भारत ओमान रिफाईनरीज़ लिमिटेड में निहित होगा।

2007 G3/97—10

अनुसूची

तालुका: सावली जिला: वडोदरा राज्य: गुजरात

गांव का नाम	सर्वेक्षण सं./ खंड सं.	क्षेत्र हेक्टर	आरे	सेन्टीआरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वरसडा	131/1	0	18	52
	130	0	10	40
	134/1	0	07	97
	105/59/1	0	06	66
	105/58/ए	0	17	72
	105/58/बी	0	16	58
	105/57	0	05	87
	105/63/ए	0	18	64
	105/63/बी	0	00	75
	105/64	0	28	95
	105/65/बी	0	23	55
	105/66/ए	0	04	18
	105/28	0	18	99
	105/27	0	09	00
	145/3	0	06	08
	144/1	0	18	60
	144/2	0	23	40
	143/1/ए	0	18	13
	105/41/बी	0	12	83
	105/42/ए	0	04	51
	141	0	27	09
	105/45/बी	0	20	85
	105/20	0	40	35
	105/18/ए	0	31	05
	156/2	0	14	70
	156/3	0	13	20
	157	0	28	50
	105/19/ए	0	33	00
	105/19/बी	0	30	30
	165	0	27	60
	159	0	02	95
	164/1	0	21	90
	171/2	0	15	00
	168	0	17	10
	179/1	0	28	79
	179	0	06	95

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	182/3	0	29	13
	182/4	0	02	78
	182/2	0	31	35
	204	0	12	20
	205/2	0	23	62
	205/1	0	26	40
	219	0	38	00
	218	0	07	50
	220	0	15	15
	221	0	12	00
	222	0	12	60
	226/1	0	00	88
	228	0	34	13
	227	0	40	05
	242/1	0	65	26
	276	0	06	72
	277/1/ए	0	09	30
	277/1/बी	0	12	00
	277	0	09	00
	275	0	00	85
	315/1	0	21	92
	316/1	0	07	95
	316/2	0	18	92
	318/1	0	24	75
	319/1	0	00	47
	319/2	0	12	80
	320	0	02	48
	336	0	36	04
	335	0	31	42
	333	0	00	80
	334	0	10	63
	353	0	06	25
	345	0	21	97
	353/ए	0	21	30
	353/बी	0	20	70
	352/ए	0	24	00
	352/बी	0	15	60
	352/के	0	11	38
	350/1	0	33	28
	350/2	0	24	69
जाम्बुगोरल	160	0	29	55
	161/1	0	06	32
	161/2	0	22	14
	175	0	31	21
	174	0	02	05
	602	0	20	87
	188	0	02	40
	189	0	19	43
	191/1	0	15	90
	194	0	18	60
	195/1	0	18	60
	196/1	0	13	80
	196	0	14	70
	200	0	25	20
	201/1	0	25	25
	201/2	0	00	14
	206	0	24	23
	205/2	0	27	60
	203	0	18	90
	204	0	05	81
	70/1	0	00	75
	70/2	0	13	85
	69	0	13	50
	66	0	04	62
	67	0	01	72
	68	0	18	91
	63	0	23	85
	60	0	22	20
	31	0	27	00
	24/1	0	15	61
	7	0	07	84
	5	0	05	55
	6	0	13	23
	570/1 पैकी	0	32	40
	570/1 पैकी	0	32	40
	573	0	22	35
	569	0	00	16
	568	0	15	24
	574	0	05	57
	567	0	20	22

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	566	0	23	00
	477/1	0	19	80
	478	0	36	30
	479/2	0	29	55
	491	0	21	90
	493	0	17	19
	494/2/1	0	09	77
	495	0	04	18
	506/1	0	23	66
	505/2	0	09	18
	505/3	0	10	89
	504	0	05	50
	507/2	0	01	98
	507/1	0	00	15
	503/2	0	00	18
	503/1	0	01	05
	508/1/1	0	15	30
	509/1	0	15	30
	452	0	05	40
	453/2	0	73	65
	448/1	0	38	83
	448/2	0	13	92
	447/1	0	12	38
	447/2	0	11	50
	446/2	0	04	35
	218/8	0	24	30
	218/40	0	16	65
	218/42 पैकी	0	24	30
	218/42 पैकी	0	24	30
	218/43	0	68	10
	218/67	0	48	60
	218/68	0	39	60
	218/73	0	44	40
	218/74	0	45	00
	218/77	0	48	00
	218/79	0	58	50
	218/81	0	61	20
	218/82	0	54	00
तुलसीगाम	115	0	26	40
	114	0	72	60
	106/2	0	22	80
	106/1	0	58	02
	93	0	51	75
	84	0	62	30
	15/42	0	64	95
	16/2	0	53	10
	23/1	0	29	10
	19/1	0	39	00
	19/2	0	37	20
	20/1	0	53	25
वच्छेसर	106	0	63	15
	107/2	0	11	70
	103	0	38	40
	102	0	54	20
	101	0	06	00
	129/ए/2	0	16	40
	129/बी/1	0	16	50
	131	0	13	20
	130/1/2	0	25	50
	4	0	59	64
	10	0	15	35
	11/1	0	19	20
	11/2	0	13	50
	11/3	0	11	25
	11/बी	0	15	60
	14/1	0	17	10
	14/2	0	20	10
	18	0	20	25
	19	0	00	54
	135	0	43	04
	134	0	02	99
	41/1/बी	0	07	50
	20	0	46	27
	21	0	03	00

[फा. सं. आर-31015/27/96-ओआर II]

के. सी. कटोच, अवर सचिव

Ministry of Petroleum and Natural Gas

New Delhi, the 6th August, 1997

S.O. 2090.— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S. O. 1094 dated the 27th March 1997, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Aquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of petroleum;

And whereas, the copies of the said gazette notification were made available to the public on the 26th day of April, 1997;

And whereas, the competent authority in pursuance of sub-section (1) of section 6 of the said Act has made his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification should be acquired;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired;

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumbrances, in the Bharat Oman Refinaries Limited.

Schedule

Taluka: Savli District : Vadodara State: Gujarat

Name of Village	Survey/Block Number	Area Hectare	Are	Centare
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Varsada	131/1	0	18	52
	130	0	10	40
	134/1	0	07	97
	105/59/1	0	06	66
	105/58/A	0	17	72
	105/58/B	0	16	58
	105/57	0	05	87
	105/63/A	0	18	64
	105/63/B	0	00	75
	105/64	0	28	95
	105/65/B	0	23	55
	105/66/A	0	04	18
	105/28	0	18	99
	105/27	0	09	00
	145/3	0	06	08
	144/1	0	18	60
	144/2	0	23	40
	143/1/A	0	18	13
	105/41/B	0	12	83
	105/42/A	0	04	51
	141	0	27	09
	105/45/B	0	20	85
	105/20	0	40	35
	105/18/A	0	31	05
	156/2	0	14	70
	156/3	0	13	20
	157	0	28	50
	105/19/A	0	33	00
	105/19/B	0	30	30
	165	0	27	60
	159	0	02	95
	164/1	0	21	90
	171/2	0	15	00
	168	0	17	10
	179/1	0	28	79
	179	0	06	95

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	182/3	0	29	13
	182/4	0	02	78
	182/2	0	31	35
	204	0	12	20
	205/2	0	23	62
	205/1	0	26	40
	219	0	38	00
	218	0	07	50
	220	0	15	15
	221	0	12	00
	222	0	12	60
	226/1	0	00	88
	228	0	34	13
	227	0	40	05
	242/1	0	65	26
	276	0	06	72
	277/1/A	0	09	30
	277/1/B	0	12	00
	277	0	09	00
	275	0	00	85
	315/1	0	21	02
	316/1	0	07	95
	316/2	0	18	92
	318/1	0	24	75
	319/1	0	00	47
	319/2	0	12	80
	320	0	02	48
	336	0	36	04
	335	0	31	42
	333	0	00	80
	334	0	10	63
	353	0	06	25
	345	0	21	97
	353/A	0	21	30
	353/B	0	20	70
	352/A	0	24	00
	352/B	0	15	60
	352/K	0	11	38
	350/1	0	33	28
	350/2	0	24	69
Jambugoral	160	0	29	55
	161/1	0	06	32
	161/2	0	22	14
	175	0	31	21
	174	0	02	05
	602	0	20	87
	188	0	02	40
	189	0	19	43
	191/1	0	15	90
	194	0	18	60
	195/1	0	18	60
	196/1	0	13	80
	196	0	14	70
	200	0	25	20
	201/1	0	25	25
	201/2	0	00	14
	206	0	24	23
	205/2	0	27	60
	203	0	18	90
	204	0	05	81
	70/1	0	00	75
	70/2	0	13	85
	69	0	13	50
	66	0	04	62
	67	0	01	72
	68	0	18	91
	63	0	23	85
	60	0	22	20
	31	0	27	00
	24/1	0	15	61
	7	0	07	84
	5	0	05	55
	6	0	13	23
	570/1 Paiki	0	32	40
	570/1 Paiki	0	32	40
	573	0	22	35
	569	0	00	16
	568	0	15	24
	574	0	05	57
	567	0	20	22

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	566	0	23	00
	477/1	0	19	80
	478	0	36	30
	479/2	0	29	55
	491	0	21	90
	493	0	17	19
	494/2/1	0	09	77
	495	0	04	18
	506/1	0	23	66
	505/2	0	09	18
	505/3	0	10	89
	504	0	05	50
	507/2	0	01	98
	507/1	0	00	15
	503/2	0	00	18
	503/1	0	01	05
	508/1/1	0	15	30
	509/1	0	15	30
	452	0	05	40
	453/2	0	73	65
	448/1	0	38	83
	448/2	0	13	92
	447/1	0	12	38
	447/2	0	11	50
	446/2	0	04	35
	218/8	0	24	30
	218/40	0	16	65
	218/42 Paiki	0	24	30
	218/42 Paiki	0	24	30
	218/43	0	68	10
	218/67	0	48	60
	218/68	0	39	60
	218/73	0	44	40
	218/74	0	45	00
	218/77	0	48	00
	218/79	0	58	50
	218/81	0	61	20
	218/82	0	54	00
Tulsigam	115	0	26	40
	114	0	72	60
	106/2	0	22	80
	106/1	0	58	02
	93	0	51	75
	84	0	63	30
	15/42	0	64	95
	16/2	0	53	10
	23/1	0	29	10
	19/1	0	39	00
	19/2	0	37	20
	20/1	0	53	25
Wacchesar	106	0	63	15
	107/2	0	11	70
	103	0	38	40
	102	0	54	20
	101	0	06	00
	129/A/2	0	16	40
	129/B/1	0	16	50
	131	0	13	20
	130/1/2	0	25	50
	4	0	59	64
	10	0	15	35
	11/1	0	19	20
	11/2	0	13	50
	11/3	0	11	25
	11/B	0	15	60
	14/1	0	17	10
	14/2	0	20	10
	18	0	20	25
	19	0	00	54
	135	0	43	04
	134	0	02	99
	41/1/B	0	07	50
	20	0	46	27
	21	0	03	00

[File No. R-31015/27/96-OR.II]
K.C. Katoch, Under Secy.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली 12 अगस्त, 1997

का. आ. 2091.— .- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में वाडीनार से मध्य प्रदेश राज्य में बीना तक पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए भारत ओमन रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को यह भी प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाई जानेके प्रयोजन के लिए, इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसमें के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस तारीखसे, जिसको भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के संबंध में या उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने संबंधी लिखित में आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, श्री के. एन. दूबे, मध्य भारत परिष्करणी परियोजना, भारत ओमन रिफाइनरीज लिमिटेड, ए-1/3, "प्रशांति", वेदनगर, सॉवेर रोड , उज्जैन - 456 001, मध्य प्रदेश को कर सकता है।

अनुसूची

तहसील: रतलाम **जिला**: रतलाम **राज्य** : मध्य प्रदेश

ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	क्षेत्र हैक्टेयर/आरे
(1)	(2)	(3)
सुजलाना	287/1	0.450
	288	0.274
	495	0.305
	497	0.347
	- 503/P	0 603
	504	0.016
	526	0.200
	527/2	0.244
	528	0.257
	529/2	0.196
	530	0.665
	538	0.367
	539	0.063
	540/P	0.275
	540/P	0.139
	540/P	0.297

[सं. आर -31015/19/96- ओआर. II]

के. सी. कटोच, अवर सचिव

Ministry of Petroleum and Natural Gas

New Delhi, the 12th August, 1997

S.O. 2091.— Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum products from Vadinar in the State of Gujarat to Bina in the State of Madhya Pradesh, a pipeline should be laid by the Bharat Oman Refineries Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may within twenty-one days from the date on which the copies of this notification, as published in the gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Shri K. N. Dubey, the competent authority of Central India Refinery Project of Bharat Oman Refineries Limited, A-1/3, 'PRASHANTI', Vednagar, Sanwer Road, Ujjain - 456 001, Madhya Pradesh.

Schedule

Tehsil : Ratlam **Dist.** :Ratlam **State** : Madhya pradesh

Name of village	Survey No.	Area Hectare/are
(1)	(2)	(3)
Sujalana	287/1	0.450
	288	0.274
	495	0.305
	497	0.347
	503/P	0.603
	504	0.016
	526	0.200
	527/2	0.244
	528	0.257
	529/2	0.196
	530	0.665
	538	0.367
	539	0.063
	540/P	0.275
	540/P	0.139
	540/P	0.297

[File No. R-31015/19/96 - OR. II]

K. C. Katoch, Under Secy.

नई दिल्ली 13 अगस्त, 1997

का. आ. 2092.— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में ऐसा आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा से पंजाब राज्य में जालंधर तक पेट्रोलियम के परिवहन के लिए बिछाई गई पाइपलाइन, जो कि पंजाब के लुधियाना और नवांशहर के बीच सतलुज नदी को पार करती है, इसके सतलुज नदी में गुजरने वाले तथा दोनों किनारों के भाग को इसके वर्तमान स्थान से पचास मीटर दूर नदी के बहाव की दिशा में पुनः स्थापित किया जाए। इस प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि पंजाब राज्य के लुधियाना जिले में गांव हैदरनगर से नवांशहर जिले में गाँव खोजा तक एक पाइपलाइन, वर्तमान पाइपलाइन में जोड़ने के लिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बिछाई जाए।

और ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची मे वर्णित भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करना आवश्यक है।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन), अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनमें के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध करा दिये जाने की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर, उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन या भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के सम्बन्ध में आपत्ति लिखित रूप में श्री एस.डी. पाण्डे, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मथुरा - जालंधर पाइपलाइन, बिजवासन, नई दिल्ली को कर सकेगा।

अनुसूची

तहसील : नवांशहर जिला : नवांशहर राज्य: पंजाब

गाँव का नाम	हदबस्त सं.	मुस्ततील/ किला सं.	क्षेत्र हेक्टेयर	एयर	सेंटीएयर
1	2	3	4	5	6
खोजा	284	46/3	0	2	53
		7	0	14	67
		8	0	8	09
		13	0	6	07
		14	0	27	31

2051 GI/97—11

[सं. आर-31015/15/97-ओ.आर.-1]

के. सी. कटोच, अवर सचिव

New Delhi the 13th August, 1997

S.O. 2092.— Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that the portion of the pipeline, already laid from Mathura in Uttar Pradesh to Jalandhar in Punjab for the transportation of petroleum products and crossing river Satluj between Ludhiana and Nawan Shahar in Punjab, passing through the Satluj river and a part of it on both sides of river should be shifted fifty meters down stream of river from its present location. It is necessary for this purpose that a portion of the pipeline be laid from Haidernagar village in Ludhiana district to Khoja village in Nawan Shahar district of Punjab State, for connecting it to the existing pipeline by Indian Oil Corporation Limited;

And, whereas, it appears that for the purpose of laying such pipeline it is necessary to acquire the right of user in the land described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to Shri S.D. Pandey, Competent Authority, Mathura Jalandhar Pipeline, Indian Oil Corporation Limited, Bijwasan, New Delhi-110061.

Schedule

Tehsil : Nawan Shahar District : Nawan Shahar State: Punjab

Name of village	Hadbast No.	Mustateel/ Killa No.	Area		
			Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5	6
Khoja	284	46/3	0	2	53
		7	0	14	67
		8	0	8	09
		13	0	6	07
		14	0	27	31

[No.R-31015/15/97-OR-I]
K. C. KATOCH, Under Secy.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली 18 अगस्त, 1997

का. आ. 2093.— केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि गुजरात राज्य में वाडीनार से मध्य प्रदेश राज्य में बीना तक पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के लिए भारत ओमन रिफाइनरीज लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ;

और केन्द्रीय सरकार को यह भी प्रतीत होता है कि उक्त पाइपलाइन बिछाई जानेके प्रयोजन के लिए इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में, उपयोग का अधिकार अर्जित करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसमें के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, उस तारीखसे, जिसको भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर,उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के संबंध में या उनमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने संबंधी लिखित में आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, श्री के. एन. दूबे, मध्य भारत परिष्करणी परियोजना, भारत ओमन रिफाइनरीज लिमिटेड, ए-1/3, "प्रशांति", वेदनगर, साँवेर रोड , उज्जैन, मध्य प्रदेश - (456 001) को कर सकता है।

अनुसूची

तहसील : नालखेड़ा **जिला** : शाजापुर **राज्य** : मध्य प्रदेश

ग्राम का नाम	सर्वे क्रमांक	क्षेत्र हैक्टेयर/आरे
(1)	(2)	(3)
दिकोन	312	0.030
	313	0.210
	314	0.250
	316	0 010
	317	0.020
	318	0.220
	365	0.500
	366	0.330
	367	0.010
	371	0.010
	372	0.300
	373	0.010
	374	0.340
	378	0 210
	1138/1	0.290
	1138/3	0.080
	1138/4	0.460
	1139	0.080
	1145	0.010
	1146	0 190
	1147	0.010
	1151	0.140
	1152	0 050
	1153	0 230

(1)	(2)	(3)
	1154	0.060
	1157	0.180
	1159	0.040
	1177	0.020
	1178	0.210
	1179	0.060
	1232/2	0.290
	1234/1	0.140
	1298/2	0.090
	1298/3	0.010
	1298/4	0.010
	1298/5	0.190
	1298/6	0.170
	1298/7	0.190
	1298/10	0.460
	1298/11	0.050
	1299/1	0.170
	1299/2/1	0.020
	1299/2/2	0.160
	1299/3	0.160
	1299/4	0.050
	1441	0.124
	1489/1	0.280
	1489/2	0.330
	1490	0.080
	1548/2	0.140
	1549/1	0.010
	1549/2	0.350
	1551	0.120
	1552	0.110
	1553	0.140
	1554	0.100
	1564	0.080
	1565/1	0.060
	1565/2	0.060
	1566	0.180
	1567	0.250
	1570/2	0.210
	1571	0.040
	1589	0.340
	1591	0.260
	1631/1	0.320
	1632	0.095
	1635	0.030
	1638/3	0.140
	1638/4	0.100
	1638/5	0.180
	1638/6	0.140
	1638/7	0.010
	1638/8	0.010
	1638/11	0.100
	1638/13	0.130
गुंजारिया	4	0.120
	7	0.300
	25	0.530
	27	0.190

[सं. आर 31015/20/97 - ओआर. II]

के. सी. कटोच, अवर सचिव

Ministry of Petroleum and Natural Gas

New Delhi, the 18th August, 1997

S.O. 2093.—Whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transport of petroleum products from Vadinar in the State of Gujarat to Bina in the State of Madhya Pradesh, a pipeline should be laid by the Bharat Oman Refineries Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may within twenty-one days from the date on which the copies of this notification, as published in the gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipelines in the said land to Shri K. N. Dubey, competent authority of Central India Refinery Project of Bharat Oman Refineries Limited, A-1/3, 'Prashanti' , Vednagar, Sanwer Road, Ujjain, Madhya Pradesh - (456 001).

Schedule

Tehsil : Nalkheda **Dist.** : Shajapur **State** : Madhya pradesh

Name of village	Survey no.	Area Hectare/are
(1)	(2)	(3)
Tikon	312	0.030
	313	0.210
	314	0.250
	316	0.010
	317	0.020
	318	0.220
	365	0.500
	366	0.330
	367	0.010
	371	0.010
	372	0.300
	373	0.010
	374	0.340
	378	0.210
	1138/1	0.290
	1138/3	0.080
	1138/4	0.460
	1139	0.080
	1145	0.010
	1146	0.190
	1147	0.010
	1151	0.140
	1152	0.050
	1153	0.230
	1154	0.060

(1)	(2)	(3)
	1157	0.180
	1159	0.040
	1177	0.020
	1178	0.210
	1179	0.060
	1232/2	0.290
	1234/1	0.140
	1298/2	0.090
	1298/3	0.010
	1298/4	0.010
	1298/5	0.190
	1298/6	0.170
	1298/7	0.190
	1298/10	0.460
	1298/11	0.050
	1299/1	0.170
	1299/2/1	0.020
	1299/2/2	0.160
	1299/3	0.160
	1299/4	0.050
	1441	0.124
	1489/1	0.280
	1489/2	0.330
	1490	0.080
	1548/2	0.140
	1549/1	0.010
	1549/2	0.350
	1551	0.120
	1552	0.110
	1553	0.140
	1554	0.100
	1564	0.080
	1565/1	0.060
	1565/2	0.060
	1566	0.180
	1567	0.250
	1570/2	0.210
	1571	0.040
	1589	0.340
	1591	0.260
	1631/1	0.320
	1632	0.095
	1635	0.030
	1638/3	0.140
	1638/4	0.100
	1638/5	0.180
	1638/6	0.140
	1638/7	0.010
	1638/8	0.010
	1638/11	0.100
	1638/13	0.130
Gunjaria	4	0.120
	7	0.300
	25	0.530
	27	0.190

[No. R 31015/20/97 OR-II.]

K. C. Katoch, Under Secy.

नई दिल्ली 20 अगस्त, 1997

का. आ. 2094.— केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3240 तारीख 23 नवम्बर, 1996 द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी,

और उक्त अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 08 दिसम्बर, 1996 को उपलब्ध करा दी गई थी,

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना चाहिए,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है,

यह और कि केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

अंचल – नाला जिला – दुमका राज्य – बिहार

गाँव	थाना नं०	प्लॉट नं०	क्षेत्र		
			हेक्टेयर	एयर	सेन्टीएयर
1	2	3	4	5	6
परासी	14	188	0	17	40
डांर पूजा	15	626	0	00	40
अम्बा बाक	13	1242	0	01	21
		1244	0	00	40
डुमरिया	21	785	0	00	40
		1571	0	00	81
डुमडुमी	22	154	0	00	81
मझीलाडीह	44	266/757	0	07	28
		300	0	02	43
		293	0	03	24
		294	0	00	81
सेमलदुवी	12	13	0	03	24
		147	0	01	21
		428	0	01	62
		592	0	02	43
		566	0	02	43
		607	0	01	62
		649	0	01	62
राख	26	642	0	01	21
उदलजोरी	4	915	0	00	40
		933	0	00	40
		1385	0	00	40
		1367	0	00	40
		1300	0	02	02
		1292	0	00	81
		1289	0	00	40
मनुहारी	5	868	0	08	90
सुन्दरपुर	6	184	0	00	40
		185	0	00	81
जरकुरी	7	162/613	0	01	21
कालीपाथर	4	213	0	00	40
देवली	19	281	0	32	78
		2554	0	05	67
बामनडीह	17	897	0	06	88
खुर्रियम	16	798	0	00	81
		796	0	02	43

अंचल – कुन्डहीत जिला – दुमका राज्य – बिहार

1	2	3	4	5	6
शिबराम	14	595	0	00	40
		850	0	00	40
		856	0	00	81
पहाड़गोरा	33	205	0	08	09
		434	0	02	43
कुन्डहीत	42	587	0	13	76
		677	0	01	21
		990	0	00	81
		1937	0	00	40
बाघासोला	47	599	0	02	43
		594	0	00	40
		1474	0	00	40
		1479	0	00	40
खजूरी	17	455	0	03	24
		609	0	01	62
		892	0	01	62
		790	0	00	40
		796	0	00	40
		788	0	00	81
		784	0	00	40
		754	0	00	81
		889	0	00	81
		1152	0	06	48
		1153	0	01	21
		1154	0	00	40
		1740	0	00	40
		1742	0	00	40
		1741	0	00	40
		1730	0	00	40
		1735	0	01	21
		1732	0	01	21
		1726	0	01	21
		2989	0	00	81
सुब्राक्षिपुर					
शीट-I	13	315	0	06	07
धनकुडी	13	230	0	00	40
		1024	0	00	81
		1095	0	00	40
		1100	0	02	43
		1159	0	00	40
पालाजोरी	12	1618	0	00	40
गरजुरी	10	2431	0	00	40

	2	3	4	5	6
		2439	0	00	81
प्रसादपुर	19	32	0	00	40
		685	0	00	40
		684	0	00	40
		1245	0	00	40
चिमहली	36	191	0	01	21
		218	0	00	81
		213	0	00	40
		212	0	06	88
		343	0	00	81
		583	0	00	81
		594	0	00	40
		582	0	06	07
सिंगारपुर	37	436	0	00	40
		487	0	00	81
मुद्राक्षिपुर	13	353	0	00	40
		314	0	00	40
		2673	0	00	81
		4918	0	00	40
		2138	0	12	55
		2118	0	02	83
		4904	0	00	40
		3970	0	01	62
		4901	0	00	81

[सं. आर-31015/16/96-ओ.आर.-1]

के. सी. कटोच, अवर सचिव

New Delhi, the 20th August, 1997

S.O. 2094.—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No.S.O. 3240 dated the 23rd day of November, 1996, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for the transport of Petroleum from Haldia, in the State of West Bengal to Barauni in the State of Bihar;

And whereas, the copies of the said notification were made available to the public on the 8th day of December, 1996;

And whereas, the competent authority in pursuance of sub-section (1) of the section 6 of the said Act has submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section (6) of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired;

And further, in exercise of the powers conferred by the sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumberances in the Indian Oil Corporation Limited.

Schedule

Anchal—Nala **District—Dumka** **State—Bihar**

Village	Thana No.	Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5	6
Parasi	14	188	0	17	40
Danr Puja	15	626	0	00	40
Ambabak	13	1242	0	01	21
		1244	0	00	40
Dumaria	21	785	0	00	40
		1571	0	00	81
Dumdumi	22	154	0	00	81
Majhiladih	44	266/757	0	07	28
		300	0	02	43
		293	0	03	24
		294	0	00	81
Semaldubi	12	13	0	03	24
		147	0	01	21
		428	0	01	62
		592	0	02	43
		566	0	02	43
		607	0	01	62
		649	0	01	62
Rakh	26	642	0	01	21
Udaljori	4	915	0	00	40
		933	0	00	40
		1385	0	00	40
		1367	0	00	40
		1300	0	02	02
		1292	0	00	81
		1289	0	00	40
Manuhari	5	868	0	08	90
Sundarpur	6	184	0	00	40
		185	0	00	81
Jarkuri	7	162/613	0	01	21
Kalipathar	4	213	0	00	40
Deoli	19	281	0	32	78
		2554	0	05	67
Bamundih	17	897	0	06	88
Khuriam	16	798	0	00	81
		796	0	02	43

Anchal — Kundhit **District — Dumka** **State — Bihar**

Sibram	14	595	0	00	40
		850	0	00	40

1	2	3	4	5	6
		856	0	00	81
Pahargora	33	205	0	08	09
		434	0	02	43
Kundahit	42	587	0	13	76
		677	0	01	21
		990	0	00	81
		1937	0	00	40
Baghasola	47	599	0	02	43
		594	0	00	40
		1474	0	00	40
		1479	0	00	40
Khajuri	17	455	0	03	24
		609	0	01	62
		892	0	01	62
		790	0	00	40
		796	0	00	40
		788	0	00	81
		784	0	00	40
		754	0	00	81
		889	0	00	81
		1152	0	06	48
		1153	0	01	21
		1154	0	00	40
		1740	0	00	40
		1742	0	00	40
		1741	0	00	40
		1730	0	00	40
		1735	0	01	21
		1732	0	01	21
		1726	0	01	21
		2989	0	00	81
Sudrakshipur Sheet-I	13	315	0	06	07
Dhankudi	13	230	0	00	40
		1024	0	00	81
		1095	0	00	40
		1100	0	02	43
		1159	0	00	40
Palajori	12	1618	0	00	40
Garjuri	10	2431	0	00	40
		2439	0	00	81
Prashadpur	19	32	0	00	40
		685	0	00	40
		684	0	00	40
		1245	0	00	40
Panchmahli	36	191	0	01	21

1	2	3	4	5	6
		218	0	00	81
		213	0	00	40
		212	0	06	88
		343	0	00	81
		583	0	00	81
		594	0	00	40
		582	0	06	07
Singarpur	37	436	0	00	40
		487	0	00	81
Sudrakshipur	13	353	0	00	40
		314	0	00	40
		2673	0	00	81
		4918	0	00	40
		2138	0	12	55
		2118	0	02	83
		4904	0	00	40
		3970	0	01	62
		4901	0	00	81

[No.R-31015/16/96-OR-I]
K. C. KATOCH, Under Secy.

का. आ. 2095.—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3241 तारीख 23 नवम्बर, 1996 द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी,

और उक्त अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 08 दिसम्बर, 1996 को उपलब्ध करा दी गई थी,

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना चाहिए,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है,

यह और कि केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

अंचल – देवघर	जिला – देवघर		राज्य – बिहार		
गाँव	थाना नं०	प्लॉट नं०	क्षेत्र		
			हेक्टेयर	एयर	सेन्टीएयर
1	2	3	4	5	6
गड़जोरा	6	14	0	04	45
		16	0	00	81
बंधाकेन्दुआ	216	299	0	00	40
		351	0	03	24
		394	0	04	86
		568	0	03	24
		574	0	04	45
		594	0	08	09
कुशमाहा	222	749	0	00	40
		821	0	01	62
		820	0	03	24
सरसा	226	1005	0	00	40
देवपुर	227	249	0	06	88
बसमनडीह	228	18	0	06	48
शंकरी	229	82	0	01	62
गिधनी	244	396	0	08	90
अंचल – सारवाँ	**जिला – देवघर**		**राज्य – बिहार**		
सारवाँ	104	992	0	04	05
पहाड़पुर	97	98	0	00	40
बाँधडीह	134	69	0	00	40
लशकरडीह	133	318	0	00	40
राकती	142	1644	0	00	81
बन्दरचुटा	177	40	0	01	21
नौखिला	144	138/1191	0	02	43
		73	0	01	62
		344	0	00	40
अंचल – सारठ	**जिला – देवघर**		**राज्य – बिहार**		
सबाईजोर	240	143	0	00	40
महेशलिट्टी	233	250	0	00	40
ढोड़ोडुमर	255	195	0	00	40
		6	0	00	40
गोपलारायडीह	447	227	0	01	21
		291	0	00	40

	2	3	4	5	6
देवली	238	522	0	00	81
		525	0	02	02
		570	0	00	40

अंचल – पालाजोरी		जिला – देवघर		राज्य – बिहार	
फराआम	454	154	0	00	81
कोरियाडीह	453	983	0	00	40
वरादाहा	456	585	0	00	40
सोनातर	459	803	0	05	67
रघुवाडीह	460	205	0	00	40
खागा	470	815	0	00	40
		816	0	02	02
		818	0	03	64
		1349	0	00	40
		1352	0	00	40
रामजीवनपुर	468	48	0	00	40
सलदाहा	465	55	0	00	40
		57	0	00	40
		59	0	00	40
		439	0	00	40
पथलावहाल	464	73	0	00	40
		115	0	00	40
		128	0	00	40
जगदीशपुर	622	108	0	00	81
सिमला	625	1270	0	00	40
		1335	0	00	81
		1338	0	02	43
		1339	0	00	81
		1340	0	02	43
		1341	0	00	81
		1423	0	00	40
		1424	0	05	26
		1453	0	01	21
आमगाछी	658	263	0	00	40
श्रीरामपुर	660	1174	0	00	40
घोरमारा	662	454	0	00	40
रामपुर	685	317	0	00	81
		325	0	00	40
		319	0	02	02

2007 GI/97 - 13

अंचल - मोहनपुर		जिला — देवघर	राज्य — बिहार		
1	2	3	4	5	6
गौरीगंज	555	30	0	02	43
[illegible]रखंडी	646	975	0	00	40
वाघमारी	687	5	0	00	40
[illegible]जुरिया	420	61	0	70	82
		63	0	35	61
[illegible]पड़िया	578	316	0	06	48
		297	0	02	83
हरकट्टा	678	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		200	0	09	71
	688	491	0	03	64
मेदिनीडीह	[illegible]	[illegible]	0	15	78

[No.R-31015/16/96-OR-I]
K. C. KATOCH, Under Secy.

New Delhi, the 20th August, 1997

S.O. 2095.—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No.S.O. 3241 dated the 23rd day of November, 1996, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for the transport of Petroleum from Haldia, in the State of West Bengal to Barauni in the State of Bihar;

And whereas, the copies of the said notification were made available to the public on the 8th day of December, 1996;

And whereas, the competent authority in pursuance of sub-section (1) of the section 6 of the said Act has submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section (6) of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired;

And further, in exercise of the powers conferred by the sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumberances, in the Indian Oil Corporation Limited.

Schedule

Anchal—Deoghar		District—Deoghar	State—Bihar		
Village	Thana No.	Plot No.	Area Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5	6
Garjora	6	14	0	04	45
		16	0	00	81
Bandhakendua	216	299	0	00	40
		351	0	03	24
		394	0	04	86
		568	0	03	24
		574	0	04	45
		594	0	08	09
Kushmaha	222	749	0	00	40
		821	0	01	62
		820	0	03	24
Sarsa	226	1005	0	00	40
Deopur	227	249	0	06	88
Basmundih	228	18	0	06	48
Sankari	229	82	0	01	62
Gidhni	224	396	0	08	90
Anchal—Sarwan		**District—Deoghar**	**State—Bihar**		
Sarwan	104	992	0	04	05
Paharpur	97	98	0	00	40
Bandhdih	134	69	0	00	40
Laskardih	133	318	0	00	40
Rakti	142	1644	0	00	81
Bandarchuta	177	40	0	01	21
Naukhila	144	138/1191	0	02	43
		73	0	01	62
		344	0	00	40
Anchal—Sarath		**District—Deoghar**	**State—Bihar**		
Sabaljor	240	143	0	00	40
Maheshliti	233	250	0	00	40
Dhorodumar	255	195	0	00	40
		6	0	00	40
Gopalraidih	447	227	0	01	21
		291	0	00	40
Deoli	238	522	0	00	81
		525	0	02	02
		570	0	00	40

Anchal—Palajori		District—Deoghar	State—Bihar		
1	2	3	4	5	6
Faram	454	154	0	00	81
Koriadih	453	983	0	00	40
Baradaha	456	585	0	00	40
Sonatar	459	803	0	05	67
Raghuadih	460	205	0	00	40
Khaga	470	815	0	00	40
		816	0	02	20
		818	0	03	64
		1349	0	00	40
		1352	0	00	40
Ramjibanpur	468	48	0	00	40
Saldaha	465	55	0	00	40
		57	0	00	40
		59	0	00	40
		439	0	00	40
Pathlabahal	464	73	0	00	40
		115	0	00	40
		128	0	00	40
Jagdishpur	622	108	0	00	81
Simla	625	1270	0	00	40
		1335	0	00	81
		1338	0	02	43
		1339	0	00	81
		1340	0	02	43
		1341	0	00	81
		1423	0	00	40
		1424	0	05	26
		1453	0	01	21
Amgachi	658	263	0	00	40
Srirampur	660	1174	0	00	40
Ghormara	662	454	0	00	40
Rampur	685	317	0	00	81
		325	0	00	40
		319	0	02	02

Anchal—Mohanpur		District—Deoghar	State—Bihar		
Gouriganj	555	30	0	02	43
Jharkhandi	646	975	0	00	40
Baghmari	687	5	0	00	40
Khajuria	420	61	0	70	82
		63	0	35	61

1	2	3	4	5	6
Amgaria	578	316	0	06	48
		297	0	02	83
Harkata	678	2	0	31	16
		200	0	09	71
Thari	688	491	0	03	64
Medinidih	681	528	0	15	78

नई दिल्ली 20 अगस्त, 1997

का. आ. 2096.— केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 272 तारीख 08 फ़रवरी, 1997 द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिदिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी,

और उक्त अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 24 फ़रवरी, 1997 को उपलब्ध करा दी गई थी,

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना चाहिए,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है,

यह और कि केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

अंचल – नाला	जिला – दुमका		राज्य – बिहार		
गाँव	थाना नं०	प्लॉट नं०	क्षेत्र		
			हेक्टेयर	एयर	सेन्टीएयर
1	2	3	4	5	6
राख	26	451	0	00	78
		450	0	00	36
		443	0	01	26
		442	0	00	66
		441	0	00	30
		440	0	00	36
		439	0	00	36
डुमरिया	21	1511	0	00	91
कालीपाथर	4	262	0	00	40

अंचल – कुन्डहीत	जिला – दुमका		राज्य – बिहार		
सुब्रक्षिपुर शीट-II	13	295	0	08	98

[सं. आर-31015/20/96-ओ.आर.-1]
के. सी. कटोच, अवर सचिव

New Delhi, the 20th August, 1997

S.O. 2096.— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 272 dated the 8th day of February, 1997, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for the transport of Petroleum from Haldia, in the State of West Bengal to Barauni in the State of Bihar;

And whereas, the copies of the said notification were made available to the public on the 24th day of February, 1997;

And whereas, the competent authority in pursuance of sub-section (1) of the section 6 of the said Act has submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section (6) of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired;

And further, in exercise of the powers conferred by the sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumberances in the Indian Oil Corporation Limited.

Schedule

Anchal—Nala **District—Dumka** **State—Bihar**

Village	Thana No.	Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5	6
Rakh	26	451	0	00	78
		450	0	00	36
		443	0	01	26
		442	0	00	66
		441	0	00	30
		440	0	00	36
		439	0	00	36
Dumaria	21	1511	0	00	81
Kalipathar	4	262	0	00	40

Anchal — Kundhit **District — Dumka** **State — Bihar**

Sudrakshipur Sheet-II	13	295	0	08	98

[No.R-31015/20/96-OR-I]
K. C. KATOCH, Under Secy.

नई दिल्ली 20 अगस्त, 1997

का. आ. 2097.— केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 273 तारीख 08 फ़रवरी, 1997 द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी,

और उक्त अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 24 फरवरी, 1997 को उपलब्ध करा दी गई थी,

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना चाहिए,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है,

यह और कि केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

अंचल — देवघर	जिला — देवघर		राज्य — बिहार		
गाँव	थाना नं०	प्लॉट नं०	क्षेत्र		
			हेक्टेयर	एयर	सेन्टीएयर
1	2	3	4	5	6
बंधाकेन्दुआ	216	620	0	00	81
		350	0	03	24
		569	0	02	43
सरसा	226	1034	0	00	40

2007 GI/97 - 14

1	2	3	4	5	6
कुसमाहा	222	949	0	00	81
		983	0	02	43
		825	0	03	24
बसमनडीह	228	23	0	00	40
		42	0	03	64
		43	0	06	81
		44	0	01	21
		10	0	00	40
गरीबखील	243	158	0	00	40
बहरोकी	2	138	0	03	24
भलसुमिया	1	89	0	02	43
तुलसीटांर	5	99	0	04	05
बिसुनपुर	4	393	0	12	14
		391	0	05	26
		29	0	00	40
		22	0	04	05
		28	0	00	81

अंचल – मोहनपुर		जिला – देवघर	राज्य – बिहार		
सिंगारडीह	702	418	0	02	40
		416	0	01	80
		413	0	01	80
		412	0	00	84
		411	0	01	08
		410	0	00	30
उपर रंगाटांर	560	119	0	00	81
किसुनीडीह	662	807	0	02	83
तिवारी केनारी	654	44	0	09	31
अंचल – सारठ		जिला – देवघर	राज्य – बिहार		
छोड़ोडुमर	225	7	0	01	20
		9	0	00	48
		10	0	00	84
		114	0	04	98
पारबांक	235	76	0	00	81

अंचल – पालाजोरी		जिला – देवघर	राज्य – बिहार		
शिमला	625	1433	0	01	21

[सं. आर-31015/20/96-ओ.आर.-1]

के. सी. कटोच, अवर सचिव

New Delhi, the 20th August, 1997

S.O. 2097.— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 273 dated the 8th day of February, 1997, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for the transport of Petroleum from Haldia, in the State of West Bengal to Barauni in the State of Bihar;

And whereas, the copies of the said notification were made available to the public on the 24th day of February, 1997;

And whereas, the competent authority in pursuance of sub-section (1) of the section 6 of the said Act has submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section (6) of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired;

And further, in exercise of the powers conferred by the sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumberances in the Indian Oil Corporation Limited.

Schedule

Anchal—Deoghar **District—Deoghar** **State—Bihar**

Village	Thana No.	Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5	6
Bandhakendua	216	620	0	00	81
		350	0	03	24
		569	0	02	43
Sarsa	226	1034	0	00	40
Kushmaha	222	949	0	00	81
		983	0	02	43
		825	0	03	24

Basmundih	228	23	0	00	40
		42	0	03	64
		43	0	00	81
		44	0	01	21
		10	0	00	40
Garibkhil	243	158	0	00	40
Bahroki	2	138	0	03	24
Bhalsumia	1	89	0	02	43
Tulsitanr	5	99	0	04	05
Bishunpur	4	393	0	12	14
		391	0	05	26
		29	0	00	40
		22	0	04	05
		28	0	00	81

Anchal — Mohanpur District — Deoghar State — Bihar

Singardih	702	418	0	02	40
		416	0	01	80
		413	0	01	80
		412	0	00	84
		411	0	01	08
		410	0	00	30
Upar Rangatanr	560	119	0	00	81
Kisunidih	662	807	0	02	83
Tewary Kenari	654	44	0	09	31

Anchal — Sarath District — Deoghar State — Bihar

1	2	3	4	5	6
Dhorodumar	225	7	0	01	20
		9	0	00	48
		10	0	00	84
		114	0	04	98
Parbank	235	76	0	00	81

Anchal — Palajori District — Deoghar State — Bihar

Simla	625	1433	0	01	21

[No.R-31015/20/96-OR-I]
K. C. KATOCH, Under Secy.

नई दिल्ली 20 अगस्त, 1997

का. आ. 2098.— केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 274 तारीख 08 फ़रवरी, 1997 द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी,

और उक्त अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 24 फरवरी, 1997 को उपलब्ध करा दी गई थी,

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना चाहिए,

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है,

यह और कि केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लगमों से मुक्त इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

अंचल – लखीसराय जिला – लखीसराय राज्य – बिहार

गाँव	थाना नं०	प्लॉट नं०	क्षेत्र		
			हेक्टेयर	एयर	सेन्टीएयर
1	2	3	4	5	6
जुआस	136	446	0	06	48
		445	0	08	90
		444	0	00	81
		443	0	00	40
		489	0	23	47
बड़हिया इंगलिश	137	1	0	03	24
		2	0	02	43
		4	0	04	05
		5	0	03	24
		6	0	04	05
		21	0	21	85
		22	0	18	21
		31	0	00	40
		20	0	13	36
		18	0	02	02
		19	0	07	28
		29	0	04	05
मखदुमपुर	139	151	0	00	81
खुटूपार	78	863	0	00	81
गोहारी	65	81	0	03	24
		41	0	00	81
		40	0	04	05
जयनगर	124	1525	0	06	07
सिलहट	86	35	0	06	07
		33	0	01	21
किउल	122	1610	0	00	48
		1611	0	00	90
		1612	0	00	42
		1613	0	00	96
		1615	0	00	24
		1617	0	01	80
		1627	0	00	72
		1625	0	00	62
		1633	0	01	14
		1635	0	00	18
		1624	0	00	62

[सं. आर-31015/20/96-ओ.आर.-1]

प्रबन्धक

के. सी. कटोच, अवर सचिव

New Delhi, the 20th August, 1997

S.O. 2098.— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No.S.O. 274 dated the 8th day of February, 1997, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for the transport of Petroleum from Haldia, in the State of West Bengal to Barauni in the State of Bihar;

And whereas, the copies of the said notification were made available to the public on the 24th day of February, 1997;

And whereas, the competent authority in pursuance of sub-section (1) of the section 6 of the said Act has submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section (6) of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired;

And further, in exercise of the powers conferred by the sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumberances in the Indian Oil Corporation Limited.

Schedule

Anchal—Luckee Saral **District—Luckee Saral** **State—Bihar**

Village	Thana No.	Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5	6
Juas	136	446	0	06	48
		445	0	08	90
		444	0	00	81
		443	0	00	40
		489	0	23	47
Barhia English	137	1	0	03	24
		2	0	02	43
		4	0	04	05
		5	0	03	24
		6	0	04	05
		21	0	21	85
		22	0	18	21
		31	0	00	40
		20	0	13	36
		18	0	02	02
		19	0	07	28
		29	0	04	05
Makhdumpur	139	151	0	00	81
Khutupar	78	863	0	00	81
Goharl	65	81	0	03	24
		41	0	00	81
		40	0	04	05
Jal Nagar	124	1525	0	06	07
Silhat	86	35	0	06	07
		33	0	01	21
Klul	122	1610	0	00	48
		1611	0	00	90
		1612	0	00	42
		1613	0	00	96
		1615	0	00	24
		1617	0	01	80
		1627	0	00	72
		1625	0	00	62
		1633	0	01	14
		1635	0	00	18
		1624	0	00	62

[No.R-31015/20/96-OR-I]
K. C. KATOCH, Under Secy

नई दिल्ली 20 अगस्त, 1997

का. आ. 2099.— केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ 275 तारीख 08 फ़रवरी, 1997 द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी,

और उक्त अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 24 फरवरी, 1997 को उपलब्ध करा दी गई थी,

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना चाहिए,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है,

यह और कि केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त भूमि मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

अंचल – जमुई	जिला – जमुई		राज्य – बिहार		
गाँव	थाना नं०	प्लॉट नं०	क्षेत्र		
			हेक्टेयर	एयर	सेन्टीएयर
1	2	3	4	5	6
कटौना	22	1246	0	02	43
		1248	0	00	81
अछरा	19	402	0	02	02
		404	0	00	81
अंचल – झाझा	**जिला – जमुई**		**राज्य – बिहार**		
महापुर टोला					
दत किचवा	3	103	0	04	05
महापुर बाराजोर	3	2259	0	04	05
		2264	0	00	81
अंचल – लक्ष्मीपुर	**जिला – जमुई**		**राज्य – बिहार**		
रतनपुर	137	517	0	03	00
		508	0	04	50
अंचल – चकाई	**जिला – जमुई**		**राज्य – बिहार**		
टेलवा					
शीट नं० 45	29	284	0	01	50
		294	0	02	10
		296	0	00	60
		295	0	00	40
		331	0	02	02
		332	0	01	62
		333	0	00	81
टेलवा					
शीट नं० 46	29	1477	0	04	05
बारो	37	1236	0	02	43
		1250	0	02	43
		1237	0	00	81

[सं. आर-31015/20/96-ओ.आर.-1]

के. सी. कटोच, अवर सचिव

New Delhi, the 20th August, 1997

S.O. 2099.— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No.S.O. 275 dated the 8th day of February, 1997, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for the transport of Petroleum from Haldia, in the State of West Bengal to Barauni in the State of Bihar;

And whereas, the copies of the said notification were made available to the public on the 24th day of February, 1997;

And whereas, the competent authority in pursuance of sub-section (1) of the section 6 of the said Act has submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section (6) of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired;

And further, in exercise of the powers conferred by the sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumberances in the Indian Oil Corporation Limited.

Schedule

Anchal—Jamui **District—Jamui** **State—Bihar**

Village	Thana No.	Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5	6
Khatauna	22	1246	0	02	43
		1248	0	00	81
Achhara	19	402	0	02	02
		404	0	00	81
Anchal—Jhajha		**District—Jamui**		**State—Bihar**	
Mahapur Tola					
Dat Kichawa	3	103	0	04	05
Mahapur Barajor	3	2259	0	04	05
		2264	0	00	81
Anchal—Lakshmipur		**District—Jamui**		**State—Bihar**	
Ratanpur	137	517	0	03	00
		508	0	04	50
Anchal—Chakai		**District—Jamui**		**State—Bihar**	
Telwa					
Sheet No. 45	29	284	0	01	50
		294	0	02	10
		296	0	00	60
		295	0	00	40
		331	0	02	02
		332	0	01	62
		333	0	00	81
Telwa					
Sheet No. 46	29	1477	0	04	05
Baro	37	1236	0	02	43
		1250	0	02	43
		1237	0	00	81

[No.R-31015/20/96-OR-I]
K. C. KATOCH, Under Secy.

नई दिल्ली 20 अगस्त, 1997

का. आ. 2100.— केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 827 तारीख 29 मार्च, 1997 द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी,

और उक्त अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 30 मई, 1997 को उपलब्ध करा दी गई थी,

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना चाहिए,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है,

यह और कि केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

2007 | GI | 97-16

अनुसूची

पुलिस थाना : खनकुल जिला : हुगली राज्य : पश्चिमी बंगाल

गाँव	अधिकारिता सूची सं०	प्लाट सं.	क्षेत्र		
			हेक्टेयर	एयर	सैंटीएयर
1	2	3	4	5	6
घोराघाट	5[illegible]	3024	0	4	86
		7328/8147	0	0	81
		7329/8148	0	1	21
		7348	0	0	40
		7065	0	1	62
		2346	0	0	20
		4292	0	0	40
		5612	0	0	40
		7443	0	0	40
		7444	0	0	61
		2926/3328	0	1	62
		2926/3327	0	1	62
		2926/3326	0	2	43
रामचन्द्रपुर	54	300	0	0	12
हीरापुर	52	754	0	1	21
धर्मपुर	23	1249	0	0	10
		216	0	0	12
रामनगर	42	537	0	1	42
		642	0	1	62
		647	0	0	8
कृष्णानगर	37	565	0	0	20
साइबोना	31	27	0	6	47
		1	0	9	31
गौरान	33	1352	0	4	4
		1353	0	1	21

[सं. आर-31015/2/97-ओ.आर.-1]

के. सी. कटोच, अवर सचिव

New Delhi, the 20th August, 1997

S.O. 2100.— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No.S.O. 827 dated the 29th day of March, 1997, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for the transport of Petroleum from Haldia, in the State of West Bengal to Barauni in the State of Bihar;

And whereas, the copies of the said notification were made available to the public on the 30th day of May, 1997;

And whereas, the competent authority in pursuance of sub-section (1) of the section 6 of the said Act has submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section (6) of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired;

And further, in exercise of the powers conferred by the sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumberances.

Schedule

Police Station: Khanakul District: Hooghly State : West Bengal

Village	Jurisdiction List No.	Plot No.	Area		
			Hectares	Ares	Centiares
1	2	3	4	5	6
Ghoradaha	57	3024	0	4	66
		7328/8147	0	0	81
		7329/8148	0	1	21
		7348	0	0	40
		7065	0	1	62
		2349	0	0	20
		4292	0	0	40
		5612	0	0	40
		7443	0	0	40
		7444	0	0	61
		2926/3328	0	1	62
		2926/3327	0	1	62
		2926/3326	0	2	43
Ramchandrapur	54	300	0	0	12
Hirapur	52	754	0	1	21
Dharampur	23	1249	0	0	10
		216	0	0	12
Ramnagar	42	537	0	1	42
		642	0	1	62
		647	0	0	8
Krishnanagar	37	555	0	0	20
Saibona	31	27	0	6	47
		1	0	9	31
Gouran	33	1352	0	4	4
		1353	0	1	21

नई दिल्ली 20 अगस्त, 1997

का. आ. 2101.— केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 828 तारीख 29 मार्च, 1997 द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी,

और उक्त अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 30 मई, 1997 को उपलब्ध करा दी गई थी,

और उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार को उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना चाहिए,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है,

यह और कि केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त भूमि मे उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगमों से मुक्त इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

पुलिस थाना : आरामबाग जिला : हुगली राज्य : पश्चिमी बंगाल

गाँव	अधिकारिता सूची सं.	प्लाट सं.	क्षेत्र		
			हेक्टेयर	एयर	सेंटीएयर
1	2	3	4	5	6
खतमासा	162	837	0	7	28
सीतलपुर	157	1320	0	6	47
खेलालपुर	144	1129	0	10	12
		1130	0	3	44
		1307	0	0	10

1	2	3	4	5	6
		1131	0	4	86
		1132	0	1	82
		1133	0	2	43
		1134	0	4	86
		1135	0	2	43
		1136	0	1	21
		1137	0	3	64
		1139	0	1	1
		1138	0	8	9
		1141	0	3	64
		1142	0	3	44
		1143	0	5	87
		1117	0	0	81
		1381	0	2	2
		1118	0	1	62
		1066	0	2	2
		1357	0	7	28
		1359	0	0	20
पीरीचपुर	143	630	0	3	24
		575	0	2	43
		576	0	0	20
		577	0	4	45
		578	0	2	43
		588	0	1	21
		587	0	0	61
		585	0	8	9
		586	0	5	26
		571	0	0	81
		631	0	2	43

1	2	3	4	5	6
दक्षिण रसूलपुर	132	47	0	0	61
असानपुर	78	693/964	0	7	28
		673	0	8	50

[सं. आर-31015/2/97-ओ.आर.-1]
के. सी. कटोच, अवर सचिव

New Delhi, the 20th August, 1997

S.O. 2101.— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No.S.O. 828 dated the 29th day of March, 1997, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipelines for the transport of Petroleum from Haldia, in the State of West Bengal to Barauni in the State of Bihar;

And whereas, the copies of the said notification were made available to the public on the 30th day of May, 1997;

And whereas, the competent authority in pursuance of sub-section (1) of the section 6 of the said Act has submitted his report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the said report is satisfied that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section (6) of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the lands specified in the Schedule appended to this notification are hereby acquired;

And further, in exercise of the powers conferred by the sub-section (4) of the said section, the Central Government hereby directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in the Central Government, vest, free from all encumberances in the Indian Oil Corporation Limited.

Schedule

Police Station: Arambagh District: Hooghly State : West Bengal

Village	Jurisdiction List No.	Plot No	Area		
			Hectares	Ares	Centiares
1	2	3	4	5	6
Satmasa	162	837	0	7	28
Sitalpur	157	1320	0	6	47
Selalpur	144	1129	0	10	12

1	2	3	4	5	6
		1130	0	3	44
		1307	0	0	10
		1131	0	4	86
		1132	0	1	82
		1133	0	2	43
		1134	0	4	86
		1135	0	2	43
		1136	0	1	21
		1137	0	3	64
		1139	0	1	1
		1138	0	8	9
		1141	0	3	64
		1142	0	3	44
		1143	0	5	87
		1117	0	0	81
		1381	0	2	2
		1118	0	1	82
		1088	0	2	2
		1357	0	7	28
		1359	0	0	20
Pirichpur	143	630	0	3	24
		575	0	2	43
		576	0	0	20
		577	0	4	45
		578	0	2	43
		588	0	1	21
		587	0	0	61
		585	0	8	9
		586	0	5	28
		571	0	0	81
		631	0	2	43
Dakshin Rasulpur	132	47	0	0	61
Asanpur	78	693/964	0	7	28
		673	0	8	50

[No.R-31015/2/97-OR-I]
K. C. KATOCH, Under Secy.

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 1997

का.आ. 2102.—केन्द्रीय सरकार ने, पैट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत के राजपत्र भाग-2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 26 जुलाई 1997, पृष्ठ संख्या 3582 से 3626 पर प्रकाशित भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1850 तारीख 15 जुलाई 1997 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी,

और केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह लाया गया है कि राजपत्र के प्रकाशन में मुद्रण सम्बन्धी कुछ गलतियां हो गई हैं,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त राजपत्र अधिसूचना में निम्नलिखित रूप में संशोधन करती है :—

पृष्ठ सं. 3594 को पृ. सं. 3604 के स्थान पर पढ़ा जाए और क्रमशः पृष्ठ सं. 3604 को पृष्ठ सं. 3594 के स्थान पर पढ़ा जाए'।

[सं. आर-31015/10/96-ओ.आर. I]

के. सी. कटोच, अवर सचिव

CORRIGENDA

New Delhi, the 21st August, 1997

S.O. 2102.—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 1850 dated the 15th July, 1997, published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, sub section (ii), dated 26th July 1997 at pages 3582 to 3626, issued under sub-section (1) of section 6 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government gave notice of its intention to acquire the land specified in the Schedule appended to this notification ;

And whereas, it has been brought to the notice of the Central Govt. that certain errors of the printing nature have occurred in the publication of the said notification in the official Gazette ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Govt. hereby amend the said Gazette notification as follows :—

"page no. 3594 to be read as 3604 ; and accordingly page no. 3604 to be read as 3594".

[No. R-31015/10/96-OR-I]

K. C. KATOCH, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1997

का.आ. 2103.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सैन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं.-1, धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-7-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42011/1/89-आई.आर. (विविध)]

बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 23rd July, 1997

S.O. 2103.—In pursuance of Section II of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, No. I, Dhanbad as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Central Warehousing Corporation and their workman, which was received by the Central Government on 23-7-1997.

[No. L-42011/1/89-IR (M)]

B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1 AT DHANBAD

PRESENT :

Shri T. Prasad, Presiding Officer.

In the matter of an industrial dispute under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947

Reference No. 45 of 1989

PARTIES :

Employers in relation to the management of Central Warehousing Corporation, Patna and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen—Shri S. Bose, Secretary, R.C.M.S.

On behalf of the employers—Shri J. P. Singh, Advocate.

STATE : Bihar INDUSTRY : Warehousing

Dhanbad, the 14th July, 1997

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-42011/1/89-I.R. (Misc.), dated, the 2nd May, 1989.

SCHEDULE

"Whether the demand of the Food and Allied Workers Union, Patna on the management of Central Warehousing Corporation, Patna for reinstatement of 40 Food Handling Workers employed through their contractor, Shri Nageshwar Singh whose services were terminated w.e.f. 17-7-86 thus justified ? It so, what relief are the concerned workmen entitled to ?"

2. The workmen and the union have appeared and filed their W.S. stating therein that the concerned workmen as per Annexure to the reference were doing duties under the management as Food Handling Workers at Mokameh depot of the management which is a Central Government Undertaking under the Ministry of Food and Civil Supplies doing the business of handling and scientific storage of notified goods and commodities from different parties on payment of charges. It is also said that the management has no certified contractor nor the management has such certificate for engaging the contractor and all the 40 workmen were engaged by the management from 1977 and have completed for more than 240 days continuous service in all calendar year and as such they became permanent workmen of the management. It is also said that the management is to engage some middleman describing them as contractor just to deprive the workmen from their legitimate wages and other benefits. It is also said that the change of name of costractor from one person to another was made from time to time by the management which was just an eye wash and the workmen were never informed about the same.

3. It is further said that there was no break in the service of the workmen and they were doing work all along with the management and sometime in April, 1986 they could no that they were being shown as workmen of one contractor namely Shri Nageshwar Singh and later on they could know on enquiry that prior to April, 1986 they were shown the workmen of one Panchanan Sharma contractor.

4. It is further said that the workmen represented the management for their regularisation as per regular and permanent employees as they were performing duties since 1972. It is further said that the officials of the management and Nageshwar Singh created some problem at Mokameh depot and a Police case was instituted against 40 workmen and they were stopped entry at the working place and new hands were engaged at lower rate of payment and to get rid of old workmen from their services they were terminated with effect from 17-6-86 without any notice or notice compensation. It is further said that neither the management nor the contractor had registration certificate to engage contractor for the supply of contract labour and as such they were entitled for reinstatement and regularisation. It was therefore finally said that the concerned workmen be reinstated and regularised in their service with effect from their termination i.e. from 17-6-86 with full back wages. A list of workmen is attached with their W.S. as Annexure A.

5. The management have appeared and filed the W.S. stating inter alia that this reference is not maintainable in law and it is further said that the workmen were employed by the contractor Nageshwar Singh and the management never employed them and there was no employer and employee relationship between the management and the workmen and they were simply the workmen of the contractor, as such the dispute can be raised only against the contractor under Section 2(k) of the I. D. Act and not against the management Corporation. It is also said that as per authority of the Hon'ble Supreme Court given in so many cases a dispute under Contractor Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 can be raised by the appropriate Government under Section 10 of the Act and this cannot be the subject matter of the dispute under the I. D. Act. It is also said that during the conciliation proceeding no list of the name of the workmen were given by the sponsoring union and now the list as given as Annexure A of the W.S. is bogus and fictitious one.

6. It is further submitted that the management is a Central Government Undertaking doing the work of Warehousing as per Warehousing Corporation Act, 1962 spread all over the country, and the main function of the management has been noted in para 3 of the W.S. which includes acquiring and building godowns and warehouses in India, runing warehouses for the storage of agricultural produce, seeds, manures, fertilizers, arranging facilities for the transport of agricultural produce and other items, acting as agent etc. It is futher said that their loading and unloading operation is not primary function of the management and the depositors deposit the goods and make their own arrangement for handling and transportation and in some cases the management does engage handling contractors is also made by the management himself and it is not the appointed engage his own men as per his choice and payment is also made by the contractor himself and it is not the primary work of the management. The management used to pay the contractor as per terms agreed upon. It is therefore incorrect to say that the persons who were previously admitted to be the employees of the contractor were actually the employees of the management.

7. Parawise rejoinder to the W.S. of the workmen/union has been given specifically denying the contention of the workmen and the sponsoring union and same is said to be wrong, mischievous, malicious and baseless and denied. It is finally said that the Award be passed accordingly holding that the workmen are not the employees of the management nor they were terminated from service by the management and the question of their reinstatement and regularisation did not arise as all.

8. I further find that no rejoinder has been filed by the workmen to the W.S. of the management.

9. Now the points for consideration in this reference are :—

(a) Whether the demand of the workmen/Union for reinstatement of 40 concerned workmen as Food Handling Workers employed through the contractor Shri Nageshwar Singh, whose services were terminated with effect from 17-7-86 is justified ?

(b) If not, what relief the concerned workmen are entitled ?

10. Both the points are inter linked and are taken up together for their consideration.

11. It is to be noted here that several adjournments were granted to the union to produce their witness but no evidence was adduced by the workman and vide order dated 22-11-95 passed by the then Presiding Officer the case of the workmen/union was closed for evidence and the management was directed to produce evidence. Neither documentary nor oral evidence was adduced by the workmen/union and later on the management examined one witness MW-1 Shri M. N. Jha who is working at Central Regional Office at Patna. He has stated that Mokameh Warehouse Depot was under the Regional Office Patna and Warehouse Manager was posted at Mokameh and the total staff were there 17 to 18 in number. He has stated that food grains and other notified good grains are stored by the depositors in the Warehouse. Public concern like FCI also used to store their grains in the Warehouse and the contractors are employed for two years who are paid through the management by the depositors and the workmen are employed by the contractor for carrying articles from the Warehouse and the payment was made to the contractors workers by the contractor and not by the management. He has further stated that depot Manager was assaulted by the workmen of the contractor and a criminal case was filed and the judgement of the said case has been filed in this reference. Mokameh is still functioning. There was no relationship of employer and employee between them. In the cross-examination he has stated that he is working as Assistant Manager at the Regional Office since 1972 and was never posted at Mokameh depot. He visited Mokameh depot in the official capacity many times but did not visit the same between

January to June, 1986 and he did not visit Mokameh depot prior to that. He could not say how much quantity of goods was stored at Mokameh depot and this matter was looked into by the Commercial Wing as he was in the personnel and administrative department. He also could not say how many workmen were working in the Mokameh depot from January to June, 1986. He has stated that tender for engaging the contractors workers is issued by the Regional Manager but no tender paper has been filed in this Court. He could not say what was the anuual turnover in the year 1994 nor he could say the details of Mokameh depot. He also could not say as to when the Manager of Mokameh was assaulted by the workers nor he knows the details of the Criminal Case. He has further stated that the permanent employees are recruited by the management for carrying permanent nature of work and had denied that as the workmen were claiming regularisation they were involved in the Criminal case. There is no other witness in this case, nor any document was filed by the management also.

12. However, in course of argument certified photo copy of judgement of Sessions Trial No. 95/87 of the Addl. Sessions Judge I Barh dated 22-6-93 has been filed where 26 persons were facing trial and all of them were acquitted except one Heera Mahto alias Heera Sardar who was convicted sentence to undergo R.I. for 1½ year under Section 147 I.P.C. From the annexure attached with the W.S. of the workmen I find that the name of this Hira Mahato is in Sl. No. 1.

13. While arguing the case it has been submitted on behalf of the workmen that they were performing duties as handling mazdoor at Mokameh depot since 1977 till 17-6-84 when they were stopped work by the management without any notice and notice compensation and it is also said that the workmen represented before the management for their work after stoppage but nothing was done and then through the sponsoring union the matter was raised before the conciliation authority and on the failure of conciliation report this reference has been made. It is further submitted that the management is a Central Government undertaking under the control of Central Ministry of Food and Civil Supplies and was doing business of handling transpiration and scientific storage of notified goods and commodities from different parties on payment of charges which is as per evidence of MW-1 and as argued by the management itself. It is further said that the management initiated a criminal case against 26 workmen out of 40 which was finally disposed off by the learned Addl. Sessions Judge-I Barh vide judgement dated 22-6-93 marked Ext. W-1 and they were acquitted of charges except Heera Mahato alias Heera Sardar who was held guilty and convicted under Session 147 I.P.C. It is said that in view of the aforesaid judgement the action of the management in terminating the services of the concerned workmen without complying with the provision of Section 25-F of the I. D. Act is illegal and void abinitio. In this connection the authority of Patna High Court in Padamchandra Jain versus Chairman Industrial Tribunal II, Central Dhanbad reported in 1991 Lab I.C. page 633 have been cited where it was found that termination of services of the workmen was illegal and as such they were entitled reinstatement with full back wages. It is finally said that the Award be passed in favour of the workmen accordingly.

14. On the other hand it has been submitted on behalf of the management that the concerned workmen were the workers of contractors who was a registered contractor and by him they were removed as mentioned in the reference itself and there was no relationship of employer and employee between the management and the workmen and in this view of the matter the reference is not itself maintainable. It is also submitted that no oral or documentary evidence was adduced by he workmen to substantiate that they were all along working directly with the management from the year 1977 to 1986 when they were allegedly terminated from the services of the management despite giving a number of dates by this Tribunal to adduce and ultimately their case was closed. There is nothing on record to prove that contention that actually they worked with the management for more than 240 days or continuous service within 12 calendar months and they were in any case terminated/stopped from work in June 1986 by the management, and as such there is no question of giving any notice or notice compensation under Section 25-F of the I. D. Act as the case does not come under this purview.

15. It was also submitted that as held by the Hon'ble Supreme Court in 1971 II L.L.J. 567 (SC) in case of Vegoils Pvt. Ltd. v. The workmen, Their Lordships have held that "jurisdiction to decide about abolition of contract labour, or to put it differently, to prohibit employment of contract labour, has now to be done in accordance with Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970. Therefore the jurisdiction of the Industrial Tribunals to adjudicate upon the disputes relating to abolition of contract labour or its absorption by the employer has been taken away". It is also submitted that there is nothing to show that the said contractor Nageshwar Singh was simply a paper arrangement and sham and camouflage entered into by the management to deprive the workmen of their legitimate wages and other benefits as no evidence was led by the workmen and the sponsoring union in support of their contention and the reference was in pursuance of the demand of the workman. So it was for the workmen and the sponsoring union to prove their case and the management has simply to deny it and it has been vehemently denied that there was relationship of employer and employee and no contrary evidence has been brought on record. Accordingly it is submitted that admittedly the concerned workmen were the workers of the contractor Nageshwar Singh as mentioned in the reference itself. So if they were terminated from service it was by the said contractor Nageshwar Singh and not by this management and if any claim of the workman is made out that should be dealt with under Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 and their demand against the management is not justified and the concerned workmen are not entitled to any relief.

16. I find much force in the plea taken by the management in the written argument and certainly it was for the workmen to prove their case that their demand for reinstatement and regularisation with the managemnet with effect from 17-6-86 was genuine and justified as they have completed more than 240 days in a calendar year but no evidence at all has been brought on record by the workmen and the sponsoring union. So far Ext. W-1 certified photo copy of the Sessions case No. 95/87 is concerned I find that there are 26 accused persons only shown whereas in the present reference there are 40 workmen and certainly all of them except Heera Mahato alias Heera Sardar was acquitted of the charges framed against them but from filing of this copy of the judgement it cannot be inferred that the workmen have worked with the management for a long period as claimed from the year 1977 to 1986 and they were entitled for being regularised and absorbed as permanent employees of the management. In absence of any evidence on record I find that the demand and claim of the workmen for their reinstatement and regularisation with the management with back wages cannot be said to be justified and genuine. Accordingly both the points are decided against the workmen. Hence, the following Award is rendered :—

> "The demand of the Food and Allied Workers Union, Patna on the management of Central Warehousing Corporation, Patna for reinstatement of 40 Food Handling Workers employed through their contractor, Shri Nageshwar Singh, whose services were terminated w.e.f. 17-7-86 is not justified. Consequently, the concerned workmen are not entitled to any relief."

17. However, there will be no order as to costs.

T. PRASAD, Presiding Officer

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1997

का.आ. 2104.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार हिन्दुस्तान कॉपर लि. के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक

विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-7-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-43012/17/86-डी-III (बी)]

बी. एम. डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 23rd July, 1997

S.O. 2014.—In pursuance of Section II of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Hindustan Copper Ltd., and their workman, which was received by the Central Government on 23-7-1997.

[No. L-43012/17/86-D.III (B)]

B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबंध

केस नं. सी.आई.टी. 38/87

रैफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्र. एल-43012/17/86-डी-III (बी) दिनांक 8-7-87

श्री ओंकार सिंह पुत्र श्री गोरधन लाल हैल्पर, निवासी मकान नं. 202/28, धानी नदी, नई बस्ती, बालूपुरा रोड, अजमेर —प्रार्थी

बनाम

हिन्दुस्तान कॉपर लि., खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, खेतड़ी नगर, जिला झुंझुनू —अप्रार्थी

उपस्थित

प्रार्थी की ओर से :	कोई हाजिर नहीं
अप्रार्थी की ओर से :	श्री मनोज शर्मा
दिनांक अवार्ड :	22-4-1997

अवार्ड

केन्द्रीय सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित अधिसूचना अधिनिर्णय के लिए इस न्यायालय को भेजी गई है :

"क्या खेतड़ी कॉपर कॉम्पलैक्स, खेतड़ी नगर के प्रबंधतंत्र को श्री ओंकार सिंह (कर्मकार) के नाम को दिनांक 17-11-1983 से कॉम्पलैक्स के हाजिरी रजिस्टर से काटने की कार्यवाही न्यायोचित है? यदि नहीं तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है?"

2. प्रार्थी ने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम पेश किया और उसका कथन है कि श्रमिक को वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी द्वारा हैल्पर के पद पर वेतन श्रृंखला 210-5-230-6-320 में उसके पत्र क्रमांक के.सी.सी./रिक्रूट/(8-16) 77 टैक दिनांक 5-11-77 द्वारा लगाया गया और उसने अपनी ड्यूटी 5 11 77 को जोइन की और उसे सेवा में स्थाई किया गया। श्रमिक का कथन है कि वह 2-11-83 से 5-11-83 तक तीन दिवस का अवकाश लेकर व मुख्यालय छोड़ने की अनुमति लेकर अजमेर गया परन्तु 6-11-83 से वह बीमार पड़ गया और वहां के स्थानीय अस्पताल जे. एल. एन. में जेरे इलाज रहा। 31-12-83 तक जेरे इलाज रहा। उसने कार्मिक अधिकारी को 10-11-83, 25-11-83 व 15-12-83 को छुट्टी के लिए पत्र लिखे जिसमें रोग प्रमाणपत्र भी शामिल किया गया परन्तु कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। प्रार्थी का यह भी कथन है कि 1-1-84 को उसने कार्मिक अधिकारी को अपनी जोइनिंग रिपोर्ट दी परन्तु उसे ड्यूटी पर नहीं लिया गया और कहा गया कि बाद में फैसला कर देंगे। प्रार्थी का यह भी कथन है कि पत्र दिनांक 2-12-83 के अनुसार उसे यह बताया गया कि 7-11-83 से 17-11-83 तक अनुपस्थित रहने के कारण उसका नाम नियम 15.5 के अन्तर्गत काट दिया गया है जबकि यह अनाधिकृत है और ऐसा समझौता वैध नहीं है और वह बीमारी के कारण अनुपस्थित था इसलिए सेवा समाप्ति के आदेश दिनांक 2-12-83 को अवैध करते हुए तमाम लाभों सहित सेवा में लिया जावे।

3. विपक्षी ने जवाब पेश किया और उसका कथन है कि प्रार्थी 2-11-83 से 5-11-83 तक अवकाश लेकर गया था, उसको दिनांक 7-11-83 को उपस्थित होना चाहिये था पर यह उपस्थित नहीं हुआ इसलिए समझौते के खण्ड 5.15 के अनुसार उसका नाम नोटिस देने के पश्चात् काट दिया गया जो उचित है इसलिए प्रार्थी कोई लाभ पाने का अधिकारी नहीं है और क्लेम खारिज किया जावे।

4. इस न्यायालय द्वारा इसके पश्चात् अनुपस्थिति के दुराचरण के बारे में विपक्षी को साक्ष्य पेश करने का अवसर 13-9-95 को दिया गया। विपक्षी ने श्री परशुराम वर्मा के बयान करवाये तथा प्रदर्श डब्ल्यू-1 से डब्ल्यू-6 दस्तावेज पेश किये व प्रार्थी की ओर से अनैक्सचर-1 से 4 पेश किये गये हैं। बहस के समय प्रार्थी अथवा उनके कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं आये। विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि श्री मनोज शर्मा की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि श्री मनोज शर्मा का तर्क है कि प्रार्थी दिनांक 7-11-83 से 17-11-83 तक अनुपस्थित रहा और 17-11-83 को दिनांक 7-11-83 से अनुपस्थित रहने के कारण प्रदर्श एम-1 पंजीकृत पत्र भेजा गया परन्तु वह उपस्थित नहीं हुआ और इसके पश्चात् उसे प्रदर्श एम-3 पत्र भेजा गया जिसमें उसकी सेवाएं 17-11-83 से समाप्त की गई और यह पत्र दिनांक 2-12-83 का था और यूनियन व नियोजक के बीच समझौते के खण्ड 15.5 के अनुसार जो कि निम्नलिखित है, सेवाएं समाप्त की गई इसलिए सेवा समाप्ति उचित एवं वैध है :

15.5 If a workman remains absent unauthorisedly for more than 10 days continuously he

shall be deemed to have lost his lien on his appointment, unless :—

(a) returns within 10 days of the date of his losing the lien, and

(b) explains to the satisfaction of the management the reasons for unauthorised absence.

6. विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि श्री शर्मा का यह भी तर्क है कि प्रार्थी यह कह कर आया है कि वह बीमार था जबकि प्रदर्श एम-6 में यह लिखकर देता है कि वह घरेलू कारणों से नहीं आ सका इसलिए उसने उचित कारण नहीं बताया है। दूसरे वह पहले भी कई बार अनुपस्थित रहा है जो कि अनैक्सचर-3 से स्पष्ट है। इसलिए भी सेवा समाप्ति उचित है।

7. मेरे विचार में विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि के तर्कों में काफी सार प्रतीत होता है। श्री परशु राम वर्मा के शपथ पत्र को प्रस्तुत करना आवश्यक है जो निम्नलिखित है :

"1. यह कि मैं, खेतड़ी कॉपर कम्पलैक्स में सहायक प्रबंधक (कार्मिक के पद पर कार्यरत) हूं मुझे नियमों व इस केस बारे में केस के तथ्यों की जानकारी है।

2. यह कि श्री ओंकार सिंह को 2-11-83 से 5-11-83 तक अवकाश स्वीकृत किया गया था। और श्री ओंकार सिंह को दिनांक 7-11-83 को अपनी ड्यूटी जोइन करनी थी। श्री ओंकार सिंह ने 7-11-83 से अनुपस्थिति रहने के लिए कोई सूचना प्रबंधन को नहीं भेजी।

3. यह कि श्री ओंकार सिंह विपक्षीय समझौता दिनांक 15-4-80 एवं उसके तहत बने छुट्टी के नियमों की सेवा शर्तों से बाध्य थे। और इस समझौते की शर्तों एवं श्रमिकों के अवकाश के नियमों के नियम 15.5 के विरूद्ध कार्य पर अनाधिकृत तौर से दिनांक 7-11-83 से अनुपस्थिति रहे।

4. यह कि प्रबंधन के तत्कालीन सक्षम अनुशासनिक अधिकारी ने एक रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 7/18 नवम्बर 1883 के द्वारा श्री ओंकार सिंह को उसका दुराचरण 7-11-83 से अनाधिकृत गैर हाजिर माने जाने की सूचना एवं ड्यूटी पर आने या के. सी. सी. अस्पताल में दस दिन के अन्दर हाजिर होने का अवसर दिया था एवम श्री ओंकार सिंह सिंह प्राप्त हो गया था जिसकी पावती की असल पोस्टल रसीद मैं प्रस्तुत करता हूं। पत्र दिनांक 17 18 नवम्बर 1983 की प्रतिलिपि पत्रावली पर प्रदर्श एम-1 है। इस पर तत्कालीन अनुशासनिक अधिकारी के हस्ताक्षर अ से ब के मध्य है। यह कि प्रदर्श एम-1 की पावती को असल पोस्टल रसीद प्रदर्श एम-2 में साबित करता हूं इस पर से अ ब के मध्य ओंकार सिंह प्रार्थी के हस्ताक्षर हैं जो सही है।

5. यह है कि प्रार्थी ओंकार सिंह ने जब नियम अनुसार अनाधिकृत गैर हाजिर रहने के दुराचरण पर अपनी सफाई नहीं दी तब प्रबंधन ने पत्र दिनांक 2-12-83 प्रदर्श एम-3 द्वारा उसके गम्भीर दुराचरण को सिद्ध मानते हुए एवं उसके पिछले व्यवहार को देखते हुए उसको सेवा मुक्ति कर दी।

6. यह कि श्री ओंकार सिंह अनाधिकृत तौर पर कार्य से अनुपस्थित रहने के आदि थे इस तथ्य को सेवा मुक्ति के समय प्रबंधन ने विचार में लिया था। श्री ओंकार सिंह को 1-10-79 से 24-10-79 की अवधि में अनाधिकृत तौर पर कार्य से अनुपस्थित रहने पर एक आरोप पत्र दिनांक 25-10-97 दिया गया था जो प्रदर्श एम-4 है और 10-11-79 को इन्हें इस आशा एवं सलाह के साथ कार्य पर लिया गया था कि वह भविष्य में बिना सूचना एवं स्वीकृति से कार्य पर से अनुपस्थित नहीं रहेंगे। इसका प्रदर्श एम-5 है। यह कि श्री ओंकार सिंह को दिनांक 21-6 83 को पुनः बार बार अनाधिकृत तौर पर कार्य पर से अनुपस्थित रहने के लिए ताड़ना दी गई थी। यह तथ्य केन्द्रीय समझौता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये थे। जो कि रिकार्ड पर प्रस्तुत असफल वार्ता में भी लिखे हुए हैं।

6. यह कि श्री ओंकार सिंह ने अपने बचाव में झूठे कथन व झूठा मेडिकल का बहाना बनाया था व इस न्यायालय में झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट दिनांक 21-12-83 पेश किया है जो कि ओंकार सिंह के पत्र दिनांक 24-12-83 प्रदर्श एम-5 में है इस पर अ से ब हस्ताक्षर ओंकार सिंह के ह और स से द के मध्य प्रबंधन के अधिकारी के लिखावट व हस्ताक्षर हैं।

8. मेरे विचार में विपक्षी एवं प्रार्थना के मध्य हुए समझौते के खंड 15.5 के अनुसार अगर कोई श्रमिक लगातार 10 दिन अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सेवाएं समाप्त हो जायेगी परन्तु श्रमिक को यह अधिकार होगा कि उसके 10 दिन अनुपस्थित रहने के बाद अगले 10 दिन तक वह अनुपस्थित के कारण का स्पष्टीकरण दे सकता है अगर वह स्पष्टीकरण उचित समझा जाता है तो उसे सेवा में ले लिया जायेगा अन्यथा उसकी सेवाएं 10 दिन की अनाधिकृत अवधि में समाप्त समझी जायेंगी। परशुराम वर्मा के शपथ पत्र व प्रदर्श डब्ल्यू-1 से डब्ल्यू-6 से यह साबित होता है कि प्रार्थी श्रमिक ओंकार सिंह 2-11-83 से 5-11-83 तक स्वीकृत अवकाश पर गया था

परन्तु उसके पश्चात् 7-11-83 से अनुपस्थित हो गया और उसको प्रदर्श एम-1 पंजीकृत पत्र 10 दिन की अनुपस्थिति के बाद ड्यूटी जोइन करने के लिए भेजा गया परन्तु उसके पश्चात् प्रदर्श एम-3 पत्र 2-12-83 को उसकी सेवा समाप्त करने का परिशिष्ट 15.5 के अन्तर्गत भेजा गया परन्तु वह 24-12-83 को उपस्थित हुआ उसने पत्र एम-6 लिखकर दिया जो निम्नलिखित है :

"नम्र निवेदन है कि मैं 2-11-83 से 6-11-83 तक छुट्टी लेकर मेरे घर अजमेर गया था वहां पर घरेलू परिस्थिति से मैं आज 24-12-83 तक ड्यूटी पर आने में असमर्थ रहा । मैं उपरोक्त समय के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी, इन्फार्म इत्यादि नहीं कर सका, इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं । मेरे घर पर आपसी बंटवारे संबंधी झगड़ों के कारण मेरा दिमाग एकदम से खराब हो गया जिस वजह से मैं न तो यहां उपस्थित हो सका एवं न ही कोई छुट्टी वगैरह दे सका । भविष्य में मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मेरी इतनी बड़ी गलती को आप नजर-अन्दाज करके मुझे आपकी सेवा करने का एक और अवसर देकर अपने उदार दिल से मुझे अनुग्रहित करेंगे । मैं उपरोक्त तिथि का मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपकी सेवा में पेश कर रहा हूं ।

9. प्रदर्श एम-6 के अनुसार उसने घरेलू झगड़ों के कारण नहीं आना बताया है जब कि वह अपना बचाव पक्ष यह लेकर आया है कि वह 31-12-73 तक बीमार था और जे. एल. एन. अजमेर में इलाज करवा रहा था । इस प्रकार प्रदर्श एम-6 पत्र से यह साबित होता है कि प्रार्थी ने जो बचाव पक्ष बनाया है और उसके बारे में रोग प्रमाण पत्र व अनैक्सचर 1 व 2 प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि पेश की है वह असत्य है । दूसरे अगर वह अस्पताल में इलाज करवा रहा था और 31-12-83 तक बीमार था तो वह 24-12-83 को खेतड़ी संस्थान में कैसे पहुंचा यह तथ्य भी साबित करता है कि वह जो बचाव पक्ष लेकर आया है कि वह बीमार था, बिल्कुल निराधार है जो मानने योग्य नहीं है । दूसरे प्रार्थी ने अपनी अनुपस्थिति के संबंध में स्वयं को कभी साक्ष्य में पेश नहीं किया इसलिए भी बचाव पक्ष को नहीं मानने का समुचित आधार है । इन परिस्थितियों में विपक्षी का शपथ पत्र अखिण्डत रह जाता है जिससे साबित होता है कि प्रार्थी 7-11-83 से 2-12-83 तक बिना किसी कारण अनुपस्थित रहा और उसने 10 दिन की अनुपस्थिति के बाद भी अनुपस्थिति का स्पष्टीकरण नहीं दिया और जो स्पष्टीकरण न्यायालय के समक्ष पेश किया है वह निराधार है और असत्य है और माने जाने योग्य नहीं है । इसलिए समझौते के खंड 15.5 के अनुसार प्रार्थी को विपक्षी द्वारा 10 दिन की अनुपस्थिति के कारण दिनांक 17-11-83 से जो सेवामुक्ति की गई है व विपक्षी प्रबंधन के हाजिरी रजिस्टर से जो प्रार्थी का नाम काटा गया है वह उचित एवं वैध है और प्रार्थी कोई हादरसी पाने का अधिकारी नहीं है ।

10. अतः प्रकरण में निम्नलिखित अवार्ड पारित किया जाता है ।

"व्यवस्थापक, खेतड़ी कॉपर कॉम्पलैक्स, खेतड़ी नगर द्वारा श्रमिक श्री ओंकार सिंह का दिनांक 17-11-83 से संस्थान के हाजिरी रजिस्टर से नाम काट दिया जाना उचित एवं वैध है और प्रार्थी कोई हादरसी पाने का अधिकारी नहीं है ।"

11. अवार्ड आज दिनांक 22-4-97 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो राज्य सरकार को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे ।

एस. के. बंगल, न्यायधीश

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1997

का०आ० 2105.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपर के पंचाट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 23-7-47 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल-29012/8/89-आई० आर० विविध)]
बी० एम० डेविड, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 23rd July, 1997

S.O. 2105.—In pursuance of Section II of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Hindustan Zinc Ltd., and theiri workman, which was received by the Central Government on 23-7-1997.

[No. L-29012/8/89-IR (Misc)]
B. M. DAVID, Desk Officer

अनुबंध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायधिकरण, जयपुर
केस नं० सी० आई० टी० 53/1989

रैफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश क्र० एल-29012/8/89/आई० आर० (विविधि) दिनांक 2-5-1989

श्री मोहन लाल पुत्र श्री रघु जी चमार, ग्राम मेन्दुरिया तहसील रेलमगरा, पोस्ट दरबा, जिला उदयपुर ।

—प्रार्थी

बनाम

जनरल मैनेजर, मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड,
राजपुरा दरीबा माइन्स, पोस्ट दरीबा, जिला उदयपुर
—प्रार्थी

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री एस० के० बंसल,
आर० एच० जे० एस०

प्रार्थी की ओर से : श्री जे० एल० शाह

अप्रार्थी की ओर से : श्री मनोज कुमार शर्मा

दिनांक : 30-4-1997

अवार्ड

यह अधिसूचना भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित विवादित बिन्दु का अधिनिर्णय करने के लिए प्रेषित की गई है :

"Whether the action of the management of M/s. Hindustan Zinc Ltd. Udaipur in discharging from service Shri Mohan Lal Chamar, D. B. Assistant R. D. Mines w.e.f. 11-1-88 is justified? If not to what relief is the worker concerned entitled?".

2. प्रार्थी ने स्टेटमैंट ऑफ क्लेम पेश किया और उसका कथन है कि प्रार्थी मोहन लाल चमार कर्मचारी सं० 35123 सेवा से पृथक करने की तिथि 11-1-88 से पूर्व डी० बी० असिस्टैंट के पद पर सेवारत था। विपक्षी ने उसको 7-11-87 को एक आरोप पत्र दिया और उसे उसी दिन निलंबित कर दिया गया परन्तु जांच नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं थी इसलिए अनुचित है। प्रार्थी का यह भी कथन है कि जांच अधिकारी ने जो जांच की एवं जो फाइंण्डिग दी वह दोषपूर्ण है उसका यह प्रमाण है कि आरोप पत्र में लिखा है कि एक नई क्रॉस बीट मार्ईज 12×4—5 थैले में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने उसकी तलाशी ली तो पाई गई परन्तु आरोप पत्र में जो आरोप लगाया गया है वह 45 एम एम के क्रॉस बिट के चोरी होने का है परन्तु जो क्रॉसबिट प्रस्तुत की गई वह 57 एम एम की है और इस विरोधाभास के बाद भी जांच अधिकारी ने उसे चोरी का दोषी माना है जो कि गलत है इसलिए उसने यह विवाद समझौता अधिकारी के समक्ष उठाया पर समझौता न हो सका इसलिए श्रम मंत्रालय ने यह अधिसूचना इस न्यायालय का निर्णय के लिए भेजी है। प्रार्थी का क्लेम है कि यह घोषित किया जाये कि प्रार्थी को सेवा से पृथक अवैध व गलत तरीके से व अनुचित श्रम व्यवहार के कारण किया गया है इसलिए सेवा समाप्ति दिनांक 11-1-88 को असमाप्त कर उसे तमाम वेतन व लाभ सहित पुनः सेवा में लिया जावे।

3. विपक्षी ने जवाब पेश किया और उसका कथन है कि प्रार्थी उनकी सेवा में था और प्रार्थी को सी० आई० एफ० एस० की लिखित रिपोर्ट की गम्भीरता को देखते हुए ड्यूटी से निलंबित किया गया और जांच नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार की गई है। विपक्षी का यह भी अभिकथन है कि वास्तव में तो मूल से चोरी गए पार्ट "क्रासबीट" जो कि 57 एम.एम के नाम से आमतौर पर जाना जाता है उसे पीछे का भाग 45 एम.एम का होता है और बजाय आमतौर पर जाने वाले नाम के स्थान पर आरोप पत्र में 45 एम.एम क्रॉसबिट" लिख दिया गया और इस प्रकार लिखे जाने से चोरी किये गये क्रॉसबीट के आरोप को बदला हुआ नहीं माना जा सकता जो माल क्रॉसबीट चोरी किया गया था व पकड़ा गया था व मोहन लाल के कब्जे से पकड़ा गया वही जांच में एग्जीबिट किया गया था। इसलिए जांच सही की गई है और अगर जांच को सही नहीं माना जावे तो प्रार्थी के विरुद्ध लगाये गये दुराचरण के आरोप को साबित करने का अवसर दिया जाये और मोहनलाल की सेवा मुक्ति वैध मानते हुए क्लेम निरस्त किया जाये।

4. दिनांक 8-12-89 को जांच अनुचित व अवैध मानी गई। इस पर विपक्षी ने दुराचरण सिद्ध करने के लिए साक्ष्य पेश करने का मौका चाहा जो दिया गया। व्यवस्थापक ने सर्व श्री त्रिभुवन सिंह, सज्जन सिंह, डी.एस. यादव, व रफीक सैय्यद के शपथपत्र प्रस्तुत किये जिन पर प्रतिपरीक्षण किया गया। विपक्षी की ओर से एम-1 से एम-11 दस्तावेज व प्रदर्श पेश किए गए। प्रार्थी की ओर से मोहन लाल ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर विपक्षी ने प्रतिपरीक्षण किया। बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. विपक्षी के मुख्य साक्ष्य में त्रिभुवन सिंह का शपथपत्र में कथन है कि.

"दिनांक 7-11-87 को लगभग 9.20 बजे सुबह मोहन लाल जिनका टोकन नं. 35123 था साइकिल के साथ मेन गेट से बाहर निकल रहे थे। साइकिल के हैण्डल पर एक काला हैण्डबैग लटका हुआ था। मैंने श्री मोहन लाल को हैण्ड बैग दिखाने के लिए बोला तो श्री मोहन लाल ने हैण्डबैग से सबसे पहले एक लाल लंगोट निकाला और बोला कि इसमें कुछ नहीं है मैंने सफेद कपड़े को निकालने के लिए बोला. तब श्री मोहन लाल ने जैसे ही सफेद कपड़ा (धोती) उठाई तो उसके नीचे पीले रंग का लोहे का एक पार्ट दिखाई दिया। तब मैंने लोहे के पार्ट को निकलवाया। वह पीले रंग का पार्ट जिसका नाम श्री मोहनलाल ने क्रॉसबिट बताया। जिस पर जो नम्बर खुदाई में लिखे थे वह मैंने मेरे बयान में उस उप निरीक्षक सी आई एस एफ. के थे, न मुझसे जो पूछताछ की गई लिखवाए थे। श्री डी एस. यादव उप निरीक्षक सी आई एस एफ. द्वारा जो मेरा बयान लिखा गया था वह पत्रावली पर प्रदर्श एम-1 है

उस पर अ से अ मेरे हस्ताक्षर हैं और स से द (श्री डी.एस. यादव के हैं। जो काला बैग क्रॉस बिट 'लोहे का पार्ट) लाल लंगोट सफेद धोती, तोलिया और आइडेनटिटी कार्ड था वह आज न्यायाधिकरण में मौजूद है और मैं उनको पहचानता हूं। यह वही वस्तुएं है जो मैंने श्री मोहनलाल के कब्जे से इनको पकड़ते समय ली थी। यह कि काला बैग प्रदर्श एम-2 लाल लंगोट, प्रदर्श एम-3 लोहे का पार्ट (क्रॉस बिट) प्रदर्श एम-4 सफेद धोती प्रदर्श एम-5, तोलिया प्रदर्श एम-6 एवं आइडेन्टिटी कार्ड प्रदर्श एम-7 पढ़ा जाये।

6. विपक्षी के साक्ष्य श्री डी.एस. यादव का शपथ पत्र में कथन है कि :

"दिनांक 7-11-87 को मेरी ड्यूटी उपनिरीक्षक एडमिनिस्ट्रेशन की सामान्य पारी में थी। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कार्यालय मुख्य द्वार पर ही था अतः सुबह समय लगभग 9.20 बजे मैं मुख्य द्वार पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के करीब ही था। इसी समय एक कर्मचारी जिनकी साइकिल के हैण्डल पर काला हैण्ड बैग लटका हुआ था। मेनगेट से बाहर जाने के लिए आया अतः मेनगेट पर तैनात आरक्षक त्रिभुवन सिंह ने उस कर्मचारी को अपना हैण्ड बैग दिखाने में आना कानी करने लगा क्योंकि मैं मुख्य द्वार पर ऊपर बरामदे में खड़ा था अतः उस कर्मचारी की आनाकानी को देखकर मैंने तथा आरक्षक त्रिभुवन सिंह ने कर्मचारी को हैण्ड बैग दिखाने को बाध्य किया। कर्मचारी ने हैण्डबैग से सबसे पहले एक लाल लंगोट निकाला और बोला इसमें कुछ नहीं है। लाल लंगोट के नीचे एक सफेद कपड़ा (धोती) था तो आरक्षक त्रिभुवन सिंह ने सफेद कपड़ा निकालने के लिए बोला तब श्री मोहनलाल ने जैसे ही सफेद कपड़ा (धोती) उठाई तो उसके नीचे पीले से रंग का लोहे का पार्ट दिखाई दिया और आरक्षक त्रिभुवन सिंह ने कर्मचारी से लोहे के पार्ट को हैण्डबैग से निकलवाया और उस लोहे के पार्ट का नाम क्रिल क्रॉस बिट है और आरक्षक त्रिभुवन सिंह ने सभी वस्तुओं के साथ (लाल लंगोट, धोती सफेद, क्रिल क्रॉस बिट तोलिया व काला हैण्ड बैग) उस कर्मचारी को मेरे हवाले कर दिया। मैंने कर्मचारी का परिचय पूछा तो उस कर्मचारी ने अपना नाम मोहन लाल बताया तथा साथ ही प्रार्थना करने लगा कि उससे गलती हो गई है उसे छोड़ दिया जाये भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगा। मैंने श्री मोहन लाल का परिचय पत्र क्रमांक 35123 अपने अधिकार में ले लिया। मैंने यह सब देखकर तुरन्त कागजी कार्यवाही एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु ग्राम प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की थी। मैं और श्री त्रिभुवन सिंह को श्री मोहनलाल को सी आई.एफ.एस. कार्यालय में ले गए वहां श्री त्रिभुवन सिंह का बयान मोहनलाल के समक्ष लिया। वहां और भी श्रमिक आ गये थे। मैंने श्री त्रिभुवन सिंह का बयान लेने के बाद एक सीजर मेमो बनाया था जो कि एक्जीबिट एम-8 है इस पर अ से ब हस्ताक्षर श्री मोहनलाल के है और श्री मोहनलाल के बायें हाथ के अंगूठे के निशान स से द है और मेरे हस्ताक्षर क से ख हैं।

2. यह कि श्री त्रिभुवन सिंह को सीजर मेमो एक्जीबिट बनाने के तुरन्त बाद उसके ड्यूटी स्थल पर भेज दिया गया। और मैंने अपने सहयोगियों को हस्ताक्षर सीजर मेमो एक्जीबिट 8 पर लिये थे। इस प्रदर्श एम-8 सीजर मेमो पर श्री लेखराम, सहायक उपनिरीक्षक (2) श्री एस एस. पंवार, प्रधान आरक्षक (3) श्री कर्नल सिंह, आरक्षक के हस्ताक्षर हैं।

3 सीजर मेमो कार्य को समाप्त कर श्री मोहन लाल का बयान लिया था जो कि मेरे द्वारा लिखा गया बयान पत्रावली पर प्रदर्श एम-9 है इस पर श्री मोहनलाल के हस्ताक्षर अ से ब उसे बाये हाथ के अंगूठे का निशान क से ख है।

4. यह कि श्री मोहनलाल का बयान प्रदर्श एम-9 व सीजर मेमो एम-8 एवं श्री त्रिभुवन सिंह का बयान एम 1 तत्कालीन सहायक कमांडेंट श्री बी सी. जोशी को अग्रिम कार्यवाही हेतु दिया गया था और श्री जोशी ने अपना नोट कार्यालय टिप्पणी के कागज पर अंग्रेजी में टाइप कराकर अपने हस्ताक्षर किये थे। यह नोट पत्रावली प्रदर्श एम-10 है इस पर अ से ब हस्ताक्षर श्री बी.सी. जोशी है। इस कार्यालय टिप्पणी के पश्चात् श्री मोहनलाल को लेकर मैं और बी.सी. जोशी तत्कालीन यूनिट हैड जो उस समय एस.ओ.एम. जाने जाते थे। ले गए उस समय एस.ओ.एम. श्री अशोक अग्रवाल थे और जब मैं और ए.सी. साहब श्री मोहनलाल को श्री अग्रवाल साहब के पास ले गए। उसके बाद हमें आदेश क्रमांक राट/कार्मिक/3/87/356 दिनांक 7-11-87 को प्रति जो प्रदर्श एम-11 है से ज्ञात हुआ कि श्री मोहनलाल के विरुद्ध गंभीर जांच तक के लिए ड्यूटी से निलंबित कर दिया गया है।

प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि श्री शाह का तर्क है कि आरोप पत्र में जो क्रॉस बिट बताई गई है वह 45 एम.एम. का है जबकि जो साक्ष्य में पेश हुआ है वह 57 एम एम का है इस प्रकार यह क्रॉस बिट बदल गया है और बदलने का कारण यह है कि वह क्रॉस बिट अन्य ने रखा था। जैसा कि प्रार्थी ने आरोप पत्र के जवाब में कहा है। इसलिए आरोप सिद्ध नहीं होता और प्रार्थी को आरोप से दोषमुक्त किया जाना चाहिए।

7. विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि श्री मनोज कुमार शर्मा का जवाब में कहना है कि क्रॉस बिट वही है जिसका आगे का भाग 57 एम० एम० का जाना जाता है और पीछे का भाग 45 एम० एम० 1 जो माल क्रॉस बिट चोरी किया गया था वह मोहनलाल श्रमिक के कब्जे से पकड़ा गया है और इसमें कोई विरोधाभास नहीं है । इसलिए प्रार्थी के खिलाफ चोरी का आरोप सिद्ध होता है । यह भी तर्क है कि प्रार्थी ने ऐसा कोई कथन प्रदर्श एम-9 कथन में नहीं किया जो कि कथन उसी दिन सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया है इसलिए प्रार्थी का कथन माने जाने योग्य नहीं है और दुराचरण साबित होता है ।

8. मेरे विचार में इन तर्कों का विवेचन करने के लिए आरोप पत्र को प्रस्तुत करना आवश्यक है जो निम्नलिखित है :

> "दिनांक 7-11-87 को प्रातः करीब 9.20 बजे आप परिसर से मेनगेट से बाहर निकल रहे थे तो केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारी द्वारा आपकी तलाशी लेने पर "क्रास बीट साईज 12 × 4.5 मी० पीले रंग को " चोरी कर ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़े गये । आपकी यह कार्यवाही कम्पनी के प्रमाणित स्थाई आदेशों के खंड 18(3)9 एवं (36) के अन्तर्गत गंभीर दुराचरण हैं । इससे संतुष्ट होने पर आपको तुरन्त प्रभाव से जांच कार्यवाही पूरी होने तक ड्यूटी से निलंबित किया जाता है । "

9. प्रार्थी ने इस आरोप पत्र का 12-11-87 को जवाब पेश किया । दिनांक 17-11-87 को वह माताजी का खेड़ा से मेहन्दरिया जा रहा था लेकिन उसें कपड़े बक्से में पड़े होने के कारण वह खनन भवन गया तथा उसकी साईकिल मेगजीन कार्यालय के पास खड़ी करके वह खनन आराम कक्ष में गया वहां पर उसने स्नान किया तथा वापस गीले कपड़ों को लेकर मेगजीन कार्यालय के बाहर साईकिल के पास आया तथा कपड़े थैले में रखे तथा साईकिल का ताला खोलने के लिए चाबी जेब से निकालने लगा तो चाबी नहीं मिली तो विचार किया कि चाबी व परिचय पत्र लॉकर्स के पास ही भूल गया । वापसी में चाबी व परिचय पत्र लेकर आया तथा साईकिल लेकर मेनगेट पर आ गया । मेनगेट पर आया तो सुरक्षा प्रहरी द्वारा उसे रोक कर थैला चैक किया गया तो थैले में गीले कपड़े के पास एक बिट मिला तो उसे हैरानी हुई कि यह बिट कहां से आ गया । इसलिए उसे फसाने के लिए बिट उसके थैले में डाल दिया गया है । उसकी पिछली सेवाएं व व्यवहार को देखते हुए उसे दोष-मुक्त किया जाये और गरीब को सेवा में लेने का कष्ट किया जाये, ताकि वह अपने बुजुर्ग माता-पिता व परिवार का भरण पोषण कर सके ।

9. मेरे विचार में प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि के तर्कों में कोई सार प्रतीत नहीं होता । प्रथम तो यह कि डी० एस० यादव त्रिभुवन सिंह के बयानों से यह साबित होता है है कि त्रिभुवन सिंह ने 7-11-87 को मेनगेट पर प्रार्थी का हैण्ड बैग चैक किया तो उसमें प्रार्थी ने आर्टीकिल 2 से 7 तक कपड़े व परिचय पत्र मिला और वह क्रॉस बिट मिली और त्रिभुवन सिंह का बयान प्रदर्श एम-1 लिया गया और मोहन लाल का बयान उसी समय प्रदर्श एम-9 लिया गया । प्रदर्श एम-9 में प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया कि उसके थैले में किसी ने बिट रख दी इसलिए उसका अब अपने शपथ पत्र में यह कथन व जवाब में यह कथन कि क्रॉस बिट किसी अन्य व्यक्ति ने थैले में रख दी, बाद में सोचा गया कथन है जिसको नहीं माना जा सकता । दूसरे प्रार्थी ने जो क्लेम पेश किया है उसमें भी ऐसा कहीं कथन नहीं किया कि किसी अन्य व्यक्ति ने क्रॉस बिट थैले में रख दिया था । त्रिभुवन सिंह से क्रॉस करते समय भी ऐसा प्रश्न नहीं किया कि किसी अन्य ने थैले में बिट रख दी । यदि ऐसा होता तो वह इस बारे में अवश्य पूछता । इसलिए भी प्रर्थी का यह कथन कि किसी अन्य ने थैले में क्रॉस बिट रख दी, नहीं माना जा सकता। तीसरे मोहन लाल का अपने शपथ पत्र में कथन कि चाबी लेकर आया और साईकिल लेकर मेनगेट को ओर गया, वहां सुरक्षा प्रहरी ने उसके थैले में बिट होना बताया । प्रार्थी का यह कथन तथ्यों के विपरीत है । प्रथम तो यह कि त्रिभुवन सिंह के बयानों से साबित है कि उसने प्रार्थी की तलाशी ली और जब कपड़े देख रहा था तब प्रार्थी के समक्ष ही क्रॉस बिट पाया गया और ऐसा नहीं है कि सुरक्षा प्रहरी ने उसे क्रॉस बिट पाया जाना बताया हो किन्तु तलाशी लेने पर यह क्रॉस बिट मिला अतः प्रार्थी का यह कथन माने जाने योग्य नहीं है । अतः प्रार्थी के कपड़े से उसके थैले में आर्टीकिल-4 क्रॉस बिट बरामद हुआ जिसका पूर्व बरामदगी मौके पर एम-8 बनाई गई । दूसरे दिन क्रॉस बिट 45 एम एम का था या 57 एम एम का था, के बारे में विवाद उठाया गया है, मेरे विचार में इस विवाद में कोई सार नहीं है प्रथम तो यह कि क्रॉस बिट प्रार्थी से बरामद हुआ है जो प्रार्थी भी अपने थैले में होना मानता है । इसलिए जब बिट बरामद हुआ है तो विपक्षी को उसके बदले जाने में क्या फायदा हो सकता है । इसलिए प्रकरण को परिस्थितियों में प्रार्थी का यह कथन कि बिट बदला गया है, माने जाने योग्य नहीं है । दूसरे प्रार्थी का कथन प्रदर्श एम-9 7-11-87 को ही लिया गया है उसमें क्रॉस बिट का नम्बर बताया गया है । मोहन लाल का प्रदर्श एम-9 में निम्नलिखित कथन है :

> "मैं मोहन लाल सुपुत्र श्री रघुजी, टोकन नं० 35123, ड्रोला अन्डर ग्राऊंड माइनिंग में कार्यरत हूं। दिनांक 6-11-87 को मेरी द्वितीय पारी 16.00 बजे से 21.00 बजे थी तथा ड्यूटी पूरी करने के बाद निवास स्थान मैहन्द्रीया चौराहा चला गया लेकिन आज दिनांक 7-11-87 को प्लांट के अंदर स्नान करने के लिए 8.00 बजे आया क्रॉस बिट जिस पर

आर० 32-57 7/3/7733.1057 एम्बास किया हुआ था मिली तथा यह बिट के० ओ० आरक्षक टी० बी० सिंह ने मेरे हैण्ड बैग से मेरे सामने निकाली।"

10. मैंने उक्त बयान को देखा जिसमें बिट का नम्बर 7733-1057 लिखा हुआ है। इस प्रकार जो नम्बर प्रार्थी के बयानों में प्रदर्श एम-9 में है वही श्री त्रिभुवन सिंह के पूर्व के बयान प्रदर्श एम-1 में लिखा गया है और उसी नम्बर की यह बिट अदालत के समक्ष है। इसलिए ये क्रॉस बिट वही है जो कि प्रार्थी से बरामद हुई। तीसरे प्रार्थी ने अपने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसका मेक यही था। इस प्रकार मेक वही होना भी यह दर्शाता है कि बिट वही थी। चौथे प्रार्थी का प्रति परीक्षण में कथन है कि उसका आगे का भाग 57 एम एम हो व पीछे का भाग 45 एम एम तो उसे पता नहीं। इस प्रकार प्रार्थी जब बिट से काम करता है और उसे इस बारे में ज्ञान नहीं हो यह बात समझ में नहीं आती। इस प्रकार प्रार्थी के द्वारा अज्ञानता का कथन करना यह दर्शाता है कि प्रार्थी ने सत्यता को छिपाया है। इस प्रकार यह बिट आगे से 57 एम एम की व पीछे से 45 एम एम की होने से यह विरोधाभास आरोप पत्र में आया है जिसका कोई प्रभाव नहीं है। दूसरे सुरक्षा अधिकारी एक तकनीकी व्यक्ति नहीं है इस लिए उनके द्वारा आगे के पीछे के भाग को 45 एम एम लिख देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि बिट वही है जो प्रार्थी से बरामद हुई। इसलिए एम-4 बिट वही है जो प्रार्थी से बरामद हुई। इसलिए 57 एम एम या 45 एम एम लिखने से कोई अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों ही नामों से जानी जाती है। इसलिए प्रार्थी के कब्जे से 9.20 बजे दिनांक 7-11-87 को त्रिभुवन सिंह सुरक्षा प्रहरी ने कम्पनी की क्रॉस बिट आर्टीकल एम-4 बरामद की। इन परिस्थितियों में प्रार्थी के कथन को कि ये वह बिट नहीं है जो बरामद की गई, को नहीं माना जा सकता। अतः प्रार्थी के कब्जे से प्रार्थी द्वारा चोरी की हुई क्रॉस बिट बरामद होना सिद्ध होता है। इस प्रकार स्थाई आदेशों के खंड 18.3 के अन्तर्गत प्रार्थी के खिलाफ लगाया गया आरोप सिद्ध होता है।

11. प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि श्री जे० एल० शाह का यह भी तर्क है कि अगर आरोप सिद्ध भी हो गया तो भी इन पहलुओं को देखते हुए कि प्रार्थी ने अपना आरोप को उसी समय स्वीकार कर लिया था, उसको 8 वर्ष की सेवा थी, उसका व्यवहार व आचरण कभी भी खराब नहीं रहा, उसे गरीब व्यक्ति होने से सुधरने का एक न मौका दिया जाना चाहिये। यह भी तर्क है कि प्रार्थी जाति का चमार है और अनुसूचित जनजाति का है और गरीब है तथा भविष्य में ऐसा नहीं करेगा, इसलिए सुधरने का एक मौका उसे दिया जाये। यह भी तर्क है कि प्रार्थी ऐसे पद पर नहीं था जिससे कि कम्पनी का कोई विश्वास प्रार्थी ने खो दिया हो इस लिए प्रार्थी को पुनः सेवा में लिया जावे और उसे तमाम लाभ दिलवायें जायें। प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने इस तर्क के समर्थन में 1 एल० एल० जे० 1991 (मान० मद्रास उच्च न्या०) पेज 291 एयर लंका लि० बनाम नायर वगैरह व ए० आई० आर० 1989 (एल० सी०) 149, स्कूटर इण्डिया लि०, लखनऊ बनाम लखनऊ लेबर कोर्ट को पेश किया है।

12. विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि श्री मनोज कुमार शर्मा का जवाब में कहना है कि प्रार्थी के खिलाफ चोरी का आरोप सिद्ध होता है जिससे उसने अपना विश्वास खो दिया है इसलिए उसे सेवा में नहीं लिया जाना चाहिये और जो दण्ड दिया गया है वह उचित है। यह भी तर्क है कि श्रमिक को पहले ही सिम्पलीसीटर डिस्चार्ज किया गया है और इस प्रकार पहले ही उसके प्रति उदारता का रूख अपनाया गया है इसलिए प्रकरण की परिस्थितियों में क्लेम खारिज किया जाये। विपक्षी के विद्वान प्रति निधि ने इस तर्क के समर्थन में ए० आई० आर० 1978 (एल० सी०) पेज 1428 मैनेजमेंट ऑफ मुंगेर फैक्ट्री ऑफ आई० टी० सी० लि० मुंगेर बिहार बनाम पीठासीन अधिकारी लेबर कोर्ट, पटना, ए० आई० आर० 1975 (एस० सी०) 2025 रस्टन एंड हर्नस्बी (1) लि० बनाम टी०बी० कादम को पेश किया है।

13. प्रार्थी मोहन लाल के शपथ पत्र के पैरा नं. 1 से यह साबित होता है कि उसकी नियुक्ति संस्थान में 1977 में हुई थी शपथपत्र से यह भी साबित होता है कि दिनांक 7-11-87 को उसे यह आरोप पत्र दिया गया था। इस प्रकार उस समय वह लगभग 8 वर्ष की सेवा पूरी कर चुका था। दूसरे प्रार्थी के शपथ पत्र से यह भी साबित होता है कि वह जाति से चमार है और अनुसूचित जाति का है। विपक्षी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई कि इन 8 वर्षों में उसने कोई दुराचरण किया हो या कोई दुर्व्यवहार किया हो। इस प्रकार इससे पूर्व में प्रार्थी द्वारा कोई दुराचरण या दुर्व्यवहार या अनुशासनहीनता करना साबित नहीं होता। इस प्रकार प्रार्थी का यह पहला दुराचरण है। दूसरे प्रार्थी का 7-11-87 को भी विभाग द्वारा कथन प्रदर्श एम-9 लिपिबद्ध किया गया है जिसमें उसने अपने आरोप को स्वीकार किया है और गलती नहीं करने का वचन दिया है। इस प्रकार प्रार्थी ने अपने आरोप को उसी समय स्वीकार कर क्षमा चाही थी। प्रार्थी ने अपने जवाब व साक्ष्य में भी क्रॉस बिट बरामद होना स्वीकार किया है। इस प्रकार न्यायालय के समक्ष भी अप्रत्यक्ष रूप से चोरी का स्वीकार किया है। चौथे विपक्षी द्वारा प्रार्थी को डिस्चार्ज किया गया है और सेवामुक्त नहीं किया गया। इस प्रकार विपक्षी ने भी इस आरोप को इतना गंभीर नहीं माना है। अतः प्रार्थी के सेवा काल की अवधि को देखते हुए, पूर्व में उसके द्वारा कोई दुराचरण अथवा दुर्व्यवहार नहीं करने, प्रार्थी का अनुसूचित जाति का होने, प्रार्थी का घटना के समय ही अपनी गलती स्वीकार कर लेने, विपक्षी व्यवस्थापक को भी उसे डिस्चार्ज किये जाने और आरोप का गंभीर न मानने, इन सभी तथ्यों से मेरे विचार में जो दण्ड प्रार्थी को दिया गया है वह दोष के अनुपात में अधिक प्रतीत होता है। प्रार्थी चोरी करते हुए पकड़ा गया है इसलिए विपक्षी

का उस पर से विश्वास उठ गया है इसलिए दुबारा सेवा में उसे लिये जाने का आदेश दिया जाना उचित नहीं होगा। अतः दोष के अनुपात में दण्ड अधिक होने से वह प्रकरण की परिस्थितियों में प्रार्थी को हर्जाना दिलाया जाना उचित होगा। 1 एल.एल.जे. 1991 (सुपरा) में भी लगभग ऐसे ही तथ्य थे जिसमें माननीय न्यायाधिपति ने निम्नलिखित विनिश्चय किया जिससे भी मेरे विचार का समर्थन होता है:

> "Whether the employer losses confidence in its employee who is discharging an office of trust and confidence. There is no jurisdiction for directing his reinstatement when there is loss of confidence compensation would be only adequate relief. .... Where the relationship is strained between employer and the employee and when the post held by the aggrieved employee is one of trust and confidence, reinstatement would not be desirable or expedient even if the order of dismissal is unsustainable owing to some infirmity in the impugned' order and in such cases the workman may be provided with monetary compensation for loss of future employment."

14. अतः प्रार्थी के सेवा काल को देखते हुए और प्रार्थी के शपथ पत्र से यह साबित होता है कि वह उस समय 2,000/- रुपये मासिक ले रहा था, इस प्रकार लगभग 4 वर्ष का वेतन बतौर हर्जाना दिलवाया जाना उचित है। अतः प्रार्थी श्री मोहनलाल को एक लाख (1,10,000) रुपया बतौर हर्जाना पाने का अधिकारी है।

15. ए.आई.आर. 1978 (एस.सी.) पेज 1428 (सुपरा) में श्रमिक को कई बार निलंबित किया गया था और कई बार वह अपने कार्य में नेगलीजेन्ट रहा था इसलिए उसके पूर्व के कृत्यों को देखते हुए उसे सेवा में लेने का आदेश अपास्त कर हर्जाना दिलवाया गया। परन्तु इस प्रकरण में ऐसे तथ्य नहीं हैं क्योंकि पूर्व में उसका ऐसा कोई कृत्य नहीं है इसलिए यह निर्णय विपक्षी को कोई मदद नहीं करता और केवल प्रार्थी को हर्जाना दिलाये जाने की हद तक मदद करता है। ए.आई.आर. 1475 (एससी) 2025 (सुपरा) में तथ्य ये थे कि एक चौकीदार ने चोरी करने का प्रयत्न किया था जिसमें सेवा मुक्ति के दण्ड को उचित माना गया परन्तु इस प्रकरण में ऐसे तथ्य नहीं हैं। प्रार्थी कोई चौकीदार नहीं था परन्तु उसने चोरी की है इसलिए उसने विपक्षी का विश्वास खो दिया है इसलिए उसकी सेवा में लिया जाना उचित नहीं है और प्रकरण की परिस्थितियों में यह निर्णय विपक्षी की कोई मदद नहीं करता। अतः निर्देश में निम्नलिखित अवार्ड पारित किया जाता है:

अवार्ड

"मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि., उदयपुर के व्यवस्थापक द्वारा मोहन लाल चमार को सेवा से दिनांक 11-1-88 से डिस्चार्ज किया जाना उचित एवं वैध है। परन्तु दण्ड दोष के अनुपात में अधिक होने से उसको एक लाख रुपये (10,00,050 रुपये) बतौर हर्जाना दिलवाया जाता है। विपक्षी यह राशि श्रमिक मोहन लाल को तीन माह में अदा करेंगे अन्यथा प्रार्थी आज की तारीख से 12 प्रतिशत ब्याज वसूली तक पाने का अधिकारी होगा।"

16. अवार्ड आज दिनांक 30-4-97 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ भेजा जावे।

एस. के. बंसल, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1997

का.आ. 2106:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मैसर्स एस.डी.एस. कार्पोरेशन के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, सं.-1 मुम्बई के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-7-1997 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल.-31012/15/96-आई.आर. (विविध)]
बी.एम. डेविड, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 23rd July, 1997

S.O. 2106.—In pursuance of Sectinn II of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal No. 1, Mumbai as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. SDS Corporation and their workman, which was received by the Central Government on 23-7-1997.

[No L-31012/15/96-IR (M)]
B. M. DAVID, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, MUMBAI

PRESENT :

Shri Justice R. S. Verma, Presiding Officer.

Reference No. CGIT-38 of 1996

PARTIES :

Employers in relation to the management of M/s. SDS Corporation

AND

Their workmen.

APPEARANCES :

For the Management—No appearance.

For the Workamn—Shri A. I. Mulla with Shri N. A. Ghatte, Advocate.

STATE : Maharashtra

Mumbai, the 8th day of July, 1997

AWARD

Shri A. I. Mulla with Shri N. A. Ghatte, Advocate.

None—for the management.

Mr. N. A. Ghatte has filed the rejoinder. Shri Ghatte seeks permission to withdraw his claim with liberty to seek redressal before competent Magistrate/Tribunal. He is permitted to do so. The claim is allowed to be withdrawn with liberty to move the appropriate Magistrate/Tribunal. The matter is disposed of accordingly.

R. S. VERMA, Presidinig Officer

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1997

का. आ. 2107 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार ई. सी. एल. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, आसनसोल के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-7-1997 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल.-22012/89/95-आई. आर. (सी.-II)]

एस. रविश अली, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th July, 1997

S.O. 2107.—In pursuance of Section II of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal Asansol as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of F.C. Ltd., and their workman, which was received by the Central Government on 23-7-97.

[No. L-22012/89/95-IR(C-II)]

S. RAVISH ALI, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL, ASANSOL

Reference No. 47/95

PRESENT :

Shri R. S. Mishra, Presiding Officer

PARTIES :

Employers in relation to the management of Moria Colliery of M/s. E.C. Ltd.,

AND

Their Workmen

APPEARANCES :

For the Employer—Sri P. K. Das, Advocate.

For the Workmen—None.

INDUSTRY : Coal STATE : Bengal

Dated, the 7th July, 1997

AWARD

The Government of India in the Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide Ministry's Order No. L-22012/89/95-IR(C.II) dated 22-9-95.

"Whether the action of the management in denial of employment to the dependent son of Sh. Bairagi Ahir, voluntary retired ex-under ground loader of Moria Colliery under Bankola Area of M/s. ECL is justified or not ? If not, what relief the workman is entitled to ?"

2. Though the General Secretary of the union appeared on 4-3-97 and applied for time to file Written Statement, it is not ultimately filed. No other step is also taken by the union. Presumably the union is not interested in the dispute.

3. Hence 'No Dispute Award' is passed.

R. S. MISHRA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1997

का. आ. 2108 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एफ. सी. आई. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, धनबाद नं 2 के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 22-7-1997 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल.-22012/17/95-आई. आर. (सी.-II)]

एस. रविश अली, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th July, 1997

S.O. 2108.—In pursuance of Section II of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Dhanbad No. 2, as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of F.C.I. and their workman, which was received by the Central Government on 22-7-97.

[No. L-22012/17/95-IR (C-II)]

S. RAVISH ALI, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (No. 1) AT DHANBAD

PRESENT :

Shri T. Prasad, Presiding Officer

In the matter of an Industrial Dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act., 1947.

Reference No. 94 of 1996

PARTIES :

Employers in relation to the management of F.C.I. Patna and their workmen.

APPEARANCES :

On behalf of the workmen—Shri V. Kumar, State Joint Secretary, F.C.I. Executive Staff., Union,

On behalf of the employers—Shri R. K. Mourya, DM Shri M .A. Raja, DM, IR.

STATE : Bihar. INDUSTRY : Food.

Dated. Dhanbad, the 7th July, 1997

AWARD

The Govt. of India, Ministry of Labour, in exercise of the powers conferred on them under Section 10(1)(d) of the I. D. Act, 1947 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication vide their Order No. L-22012/17/95-I.R. (C-II), dated, the 18th October, 1996.

SCHEDULE

"Whether the action of the management of Food Corporation of India, Patna in retrenching and denying the regularisation of the workman S/Shri Udai Kumar and 15 others from the date shown against their names in this dispute is justified and legal ? If not, what relief the workmen are entitled to ?"

LIST OF WORKMEN

	Name	Date of Employment	Date of retrenchment
1.	Shrif Udai Kumar	2.9.86	1.7.87
2.	" Baidya Nath Singh	1.9.86	1.7.87
3.	" Atish Kumar	1-9-86	1-7-87
4.	" Mahesh Pd. Singh	1.9.86	1.7.87
5.	" Bipul Kumar	1.9.86	1.2.88
6.	" Suryadeo Sharma	1.9.86	1.4.88
7.	" Umesh Kumar	1.7.87	1.6.88
8.	" Prem Kant	1.7.87	1.6.88
9.	" Sunil Kumar	1.7.87	1.6.88
10.	" Nagendra Kumar	3.10.87	1.11.88
11.	" Chandrasekhar Kumar	1.12.87	1.4.89
12.	" Sheo Kumar	1.6.88	1.4.89
13.	" Mano Kamna Sharma	2.4.88	1.4.89
14.	" Ramjee Singh	1.6.88	1.4.89
15.	" Pankaj Shrma	1.6.88	1.4.89
16.	" Rakesh Kumar	6/88	1.4.89

2. The workmen and the sponsoring union have appeared and filed W.S. stating therein that the workman whose names are given in the annexure of this W.S. were employed by the F.C.I. Management at F.S.D. Patahi under the District Manager, F.C.I. Muzaffarpur as casual Class IV workers and were performing the job of Watchman/ Messengar/Labourers to fill loose grains, sweeping the godowns and office and to provide water to the staff and other misc. jobs. They were also performing their jobs under the control and supervision of the management of the F.C.I. and their attendance was marked by the regular employees of the management but they were not allowed to put their signature in the attendance sheet only 'A' and 'P' were marked by the employees of the management. It was said that they were doing duties as per direction of the management since their date of employment but they were stopped from work from the dates shown against their names in the annexure all of a sudden without any notice, notice pay and compansation by the Assistant Depot Supdt. Patahi and order of the District Manager, F.C.I. Muzaffarpur.

3. It is further said that all the workmen have completed more than 240 days in 12 calendar months of regular work and they were entitled for protection under Section 25F of the I.D. Act., 1947 but the stoppage of work-cum-retrenchment were in violation of Section 25F of the I.D. Act and the same become void abinitio and for that they are entitled reinstatement with full back wages. It was also said that they were discharging their work as regular Class IV workmen of the management but they were getting very less payment of wages and without any other benefits as given to the regular employees. It was also said that a large number of such casual workers were regularised in the service by the management as Watchman in the year 1988 and were still being regularised but the case of the concerned workmen were not considered by the management. However, the services of a co-worker Shri Jagdish Mahato was regularised in the year 1994 but the legal and valid claim of the workmen were ignored by the management. It was also said that this matter of regularisation and the reinstatement of the workmen were taken up with the management by the sponsoring union and the workmen but nothing was done by the management. Thereafter a dispute was raised before the ALC(C) Patna, and the present case has been referred on the basis of the report submitted by the ALC(C) Patna was also that the action of the management of F.C.I. in retrenching and stopping work of the workmen without complying with the provision of Section 25F was void abinitio and they are entitled for their reinstatement and regularisation with full back wages, as such it is prayed that the Award be passed accordingly. A detailed list of the workmen have been given with the W.S.

4. The management of the F.C.I. have appeared and filed W.S. stating inter alia that the present reference is not maintainable and it is said that the concerned workmen have claimed themselves as workmen of the FCI Patahi Depot under the District Manager, FCI but from the perusal of payment voucher and Cash Book relating to F.S.D. Patahi it would be clear that none of the concerned workmen have worked during the period of their claim i.e. from September, 1986 to June, 1988. It is also said that the sponsoring union in connivance with the interested dealing clerk have manufactured some documents in collussion of the said dealing clerk and on the basis of these manufactured documents the workmen have raised the present dispute and the very basis of their case is based on fabricated documents and concocted facts.

5. It is further said that the F.S.D. Patahi was a temporary establishment which opened with effect from 1-6-78 in a rented building and was closed with effect from 30-6-89. The permanent workmen of the said depot who were transferred from other office and temporarily posted were transferred to the permanent post and there was one casual workman of F.S.D. Patahi whose services were terminated at the time of closure of temporary establishment. The said casual worker namely Jagdish Mahato had regularly worked in the establishment and his case was taken up for regularisation and the same has been regularised in the year 1994 and after regularisation of Shri Jagdish Mahato several attempts have been made by the sponsoring union to induct into employment the strangers to the management of FCI. A Writ Petition was also filed in the Hon'ble Patna High Court, Ranchi Bench on behalf of Upendra Kumar and Ramesh Kumar and the Writ Petition was C.W.J.C. 1967 of 1995 (R) and vide order dt. 15-7-96 the Hon'ble Court had accepted the contention of the management that industrial dispute was not maintainable even after a delay of 7 years. Likewise another Writ Petition was also filed by the sponsoring union number being C.W.J.C. 1947 of 1995 (R) and the same order was based in this Writ also and the prayer of the workmen were not allowed in raising the dispute after a delay of 7 years.

6. It is further said that the sponsoring Union has raised the present dispute for the workmen Udai Kumar and 15 others before the ALC(C) Patna and the union managed to get the reference made before the management could not file its W.S. and the present reference is made without proper application of mind by the competent authority and in view of the decision of Patna High Court, Ranchi Bench it is not maintainable in view of the aforesaid two C.W.J.Cs.

7. It is also said that after closure of the Industrial establishment no dispute under the I.D. Act, 1947 can be raised on the issue of regularisation of the workmen and the

temporary casuals appointed in a temporary establishment cannot demand regularisation after closure of the temporary establishment. It is also said that a casual worker having 240 days of attendance in a calendar year in a clause establishment is entitled for retrenchment compensation under Section 25F of the I.D. Act and the present case cannot come under the provision of Section 25F of the I.D. Act. As such it is submitted that the workmen are not entitled for relief as claimed and an Award be passed accordingly.

8. A rejoinder to the W.S. has also been filed in continuation of the W.S. where the contention of the workmen and the sponsoring union have been denied specifically and parawise and the same is said to be incorrect, untenable and denied. The claim of the workmen is also said to be not fully correct and denied.

9. I further find that no rejoinder has been filed by the workmen to the W.S. of the management.

10. On the basis of the pleadings of the parties the points for consideration in this reference are :—

(a) As to whether or not the action of the management of F.C.I. Patna in retrenching and denying regularisation of the workmen S/Shri Udai Kumar and 15 others from the dates shown against their names in the reference is justified ,

(b) If not, to what relief or reliefs the concerned workmen are entitled ?'

11. Both the points are interlinked and as such they are taken uptogether for their consideration.

12. I further find that the management examined as many as four witnesses in support of its case. They are MW-1 Shri Janardan Prasad who has prepared list of casual labour on the basis of the Cash Book and vouchers marked Ext. M-1, MW-2 Shri R. N. Choubey a Cashier of F.C.I. Muzaffarpur District Office who has filed the Cash Book and number of entries made therein on the basis of vouchers. He has further said that Contingent advance taken by the depot incharge is noted in the Cash Book and details of expenses are mentioned by the depot incharge in the adjustment expenses vouchers filed by him later on. MW-3 S. R. Sharma working as Assistant Manager, F.C.I. Muzaffarpur and MW-4 Shri A. N. Jha who was working as supervisor at Patahi from June, 1986 to September, 1989. All these witnesses have tried to support the case of the management as given in the W.S. and rejoinder. MW-1 has further stated that Patahi godown was hired in the year 1978 and was dehired from June, 1989. He has also stated that Ext. M-1 has been prepared by him at the office but to-day here at Dhanbad it has been typed and he was posted in the Accounts Branch Muzaffarpur office from December, 1987 and Mr. Mourya, District Manager has joined just one month back. He has further stated that bills of casual workers were prepared by the depot incharge which was sent to the district office for passing and thereafter payments were made to the workers. He has stated that he used to take Contg. advance for misc. expenses and such advance used to be entered in the Cash Book and details were not given at the time of taking such advance but details are entered in the vouchers submitted by the depot incharge. He has also stated that attendance for the staff of the deport was maintained but he could not say on what paper it is maintained. He has denied that payments to such casuals were made by taking contingent advance and as per his knowledge only Jagdish Mahato has worked as casual worker in the depot. He could not say the details of other cases filed by the other workers before the Hon'ble Patna High Court, Ranchi bench for their regularisation. MW-2 has filed Cash Book of District Office Muzaffarpur from 1985 to 1993 and the entries are made by him on the basis of the vouchers. He has also admitted that the Contg. advance taken by the Depot incharge is shown in the Cash Book and details of expenses done by depot incharge is noted in the vouchers filed later on.

13. MW-3 Shri S. R. Sharma was the Assistant Manager in F.C.I. Muzaffarpur since 1992 and he has got prepared Contg. vouchers and the statement under his supervision which are marked Ext. M-5 and no payment to any casual worker was made from this voucher although payment to Jagdish Mahato and few others were made from other vouchers and no payment to any other concerned workman was made at Patahi depot from these vouchers and there was no other system of payment of casual workers except through vouchers. He had no knowledge that these workmen worked at Patahi in between the period from 1986 to 1989 but as per records available they have not worked there during the period. He has further admitted that Ext. M-7 and M-7/1 have been typed and signed by him at Dhanbad. He has denied that it has been prepared under the advice of the lawyer. He has further denied that all the vouchers were not brought by him and the specific vouchers through which payment to the concerned workman was made was deliberately concealed. He has denied that Ext. M-7 and M-7/1 was incomplete and these were prepared at Dhanbad for the purpose of this case only. He has also stated that Mr. M. [illegible] Sami was the District Manager, Muzaffarpur during his tenure but could not say that he had recommended for regularisation of the concerned workmen only on the plea that they have worked in the depot nor he could say he wrote to the higher authority for regularisation of these workmen as they were stopped illegally. However, he had admitted that some other casual worker like the present workmen have been regularised as Class IV employees of the F.C.I. in the year 1988-89. He could not say that Manoj Kumar and 5 others have filed case before the Hon'ble High Court, Ranchi Bench for their regularisation which is still pending nor he could say that the Hon'ble High Court has passed direction for consideration of their case if they have worked. He did not attend the conciliation proceeding before the ALC(C) Patna. He also could not say the plea taken by the management before the ALC(C) Patna that they have worked for less than 240 days and they have raised the dispute after long days. Evidence of MW-4 is on the same line and he has stated that no workman except Jagdish Mahato has worked as casual worker at Patahi depot and their attendance was marked on plain paper. He has stated that wage bill and attendance sheet were prepared as per Ext. M-4 and M-5 but have denied that attendance of workmen was marked as per Ext. M-8 which is not genuine document. He has admitted that Mr. Ramesh Ch. Sinha was the depot incharge during his tenure and attendance and bills were prepared as per Ext. M-4 and M-5 and it was signed by the depot incharge or by other officer in his absence. He could not identify the signature of Shri Sinha on Ext. W-8 series nor could he say that Mr. Sinha has admitted his signature on Ext. W-8 series. He could not say about the contents of Ext. W-6 nor could say that all the attendance registers were prepared before the ALC(C) by the management nor could say that three cases were filed relating to Patahi depot in which attendance register was produced which was admitted by the management. He also could not say that Mr. Sami had given in writing for regularisation of the concerned workman. He has stated that attendance of the workmen marked on register or sheet was forwarded to the District Office and no copy of the attendance sheet is kept in the depot for further reference. He denied that he has stated wrongly that only Jagdish Mahato was working there and his service was regularised. Further he has stated that 3 to 4 workmen were occasionally working for fugnitation and other workmen were engaged for 22 to 25 days in a month and payment was made to them as per daily wages fixed rate. In the godown there were handling labours who were transferred to Narayan depot after closure of Patahi depot and later on were made permanent under Muzaffarpur District and some other staff of Patahi depot also transferred to nearby other depots. He has further stated that on closure of Patahi depot regular staff were transferred to other depot but casual workers were stopped without giving notice and notice compensation at the time of their terminstion. His further evidence is that [illegible] Jagdish Mahato, Co-worker was working as Water Boy but he has denied that he is adducing falsely at the instance of the management.

14. The workmen have examined only one witness WW-1 Shri Abhilash Prasad Singh who was working as Watchman at Patahi depot from 1978 to 1989 and had admitted that Mr. R. C. Sinha was depot incharge from 1985 to 1989. He has further stated that the concerned workmen were working in the depot and they were engaged ranging from 4 to 10 as per requirement He has denied that only Jagdish

Mahato was working as casual worker and these workmen were working for other misc. work, and that they used to work for the whole day like other Class IV workmen doing sweeping and stitching work but they were paid less than a regular worker. He has also stated that Ext. W-8 series were signed Shri R. C. Sinha and other officers in his absence which are photo copies as original were not produced by the management. He has further stated that the the concerned workmen were stopped in Patahi depot and other handling labourers were also engaged who were made permanent except the concerned workmen. About 60 to 70 were regularised in the year 1988-89 and casual workers Jagdish Mahato was regularised only one and half year back. He has admitted in the cross-examination that he is working as Watchman from the year 1978 and his grievance is pending with the management for the promotional matters and that he is a member of executive in which Mr. V. Kumar is the Joint Secretary. He has denied that he is adducing falsely at his instance and have also denied that he is adducing on behalf of the workmen as he had grievance against the management and that he was adducing falsely. No other witness was examined by the workmen.

15. Some documents have been filed by the management and Ext. M-1 is details chart of engagement of casual worker at Patahi depot from 6/86 to 5/89. Ext. M-2 is a letter of S.R.M. F.C.I., Patna. Ext. M-2/1 is a letter of agreement dated 1-6-78, Ext. M-2/2 is a lease agreement whereas Ext. M-2/3 and M-2/4 are regarding taking over the godown and vacation. Ext. M-3 is a certificate dated 29-6-79 about handing over and taking over of the godown. Ext. M-4 is a monthly bill in original from June, 1986 to April, 1989. Ext. M-5 series are original Cash Book six in numbers. Ext. M-6 is certified copy of the order of the Hon'ble Court in C.W.J.C. No. 1967 of 1995(R) and C.W.J.C. 1947 of 1995(R). Ext. M-7 and M-7/1 are the statement showing the Contg advance and expenses bills payment from April, 1986 to June, 1989.

16. On the other hand some documents have also been filed by the concerned workmen which are Ext. W-1, copy of W.S. filed before the ALC(C), Patna on 25-9-93, Ext. W-2 copy of W.S. filed before the ALC(C), Patna dated 30-12-93. Ext. W-3 is copy of the W.S. filed before the ALC(C), dated 13-10-94, W-5 is the reply of the management dated 22-11-94. W-5 is copy of letter dated 17-5-95 of Sr. Manager, F.C.I., W-6 copy of letter dated 15-4-95, W-7 is a copy of letter dated 30-3-95 of Shri R. C. Sinha, depot incharge, Ext. W-8 photo copies of attendance register from August, 1985 to June, 1989, W-9 series are copies of staff position in Bihar region as on 30-11-88, 31-12-94 and 3-1-96. Ext. W-10 series are settlement of Jagdish Mahato and the subsequent order. Ext. W-11 and W-12 are copies of F.O.C. report Parts I and II submitted by the ALC(C), Patna to the Labour Ministry, Ext. W-13 is Labour Ministry's letter dated 13-12-94, Ext. W-14 is copy of reply of F.C.I. to the Ministry of Food. Ext. W-15 is copy of F.O.C. report Part II in respect of Upendra Kumar and Ramesh Singh, Ext. W-16 is copy of letter of the Labour Ministry dated 30-8-95. Ext. W-17 is copy of order in C.W.J.C. No. 2253 of 1995 dated 18-7-96. Ext. W-18 is copy of staff position on 31-12-96, Exts. W-19 to 21 are copies of Ext. W-8 and certified copy of the same from the file of the Ministry of Labour, New Delhi.

17. As per the documents filed on behalf of the management it has been tried to show that only Jagdish Mahato was working as casual worker in Patahi depot during the period who was regularised in service in the year 1995 as per the agreement between the management and the union and no other casual workmen was working there and these workmen have not worked and had they been worked, there, their payment must have been made to them by vouchers and such vouchers must have been entered in the Cash Book in Ext. M-5 series and it was also submitted that Ext. M-1 is shown engagement of casual workers at Patahi depot and Ext. M-4 are monthly bills of casual workers from June, 1986 to April, 1989. Similarly, Ext. M-5 series are original Cash Book for the same period and Ext. M-7 are the statements showing the contingent advance and expenditure bills of Patahi depot for the same period from 1986 to 1989 and neither such vouchers, Contg. advance bills or the Cash Books the names of these workmen find place and that any payment was made to them for working as casual worker at Patahi depot during the period from 1986 to 1989. It was also said that the attendance sheets Ext. W-8 series submitted by the workmen are forged and fabricated which were prepared in connivance with the dealing clerk who is a member of the same union and in which Mr. V. Kumar is the Joint Secretary who is conducting the case on behalf of the sponsoring union. It is also submitted that the workmen never completed 240 days of working days of work in regular 12 calendar months in a year or they have not completed 90 days regular work as on 2-5-86 as per circular of the Headquarters of the year 1987 and as such they are not entitled for any regularisation as claimed. It is also submitted that as per Ext. M-6 judgement of the Hon'ble Court in two C.W.J.C. No. 1967/95(R) and 1947/95(R) the Hon'ble Patna High Court has held that there was more than seven years delay in raising the dispute and as such they were not entitled for any relief as claimed. From these judgements I find that the Hon'ble Court has directed the management to consider the case of the workmen as per headquarters circular dated 6-5-87 for their regular appointment in view of the fact that similarly situated persons including some retrenched workmen have already been provided regular appointment and the management was directed to look into the matter if the workmen have completed 90 days of work on 2-5-86 under the management and the case of the workmen be considered for their regular appointment against existing or future vacancy and such a decision was to be taken by the respondents within four months from the date of representation of the petition union. But there is nothing to show on record that the management considered the case of the workmen on filing such representation on behalf of the union about the regularisation of such workmen and other casuals of Patahi depot who had raised the dispute in three different cases before the ALC(C) Patna.

18. On the other hand it is submitted on behalf of the workman that from the documents filed on their behalf it is clear that they have completed more than 240 days or more as casual worker with the management and they have also completed many more 90 days as on 2-5-86 as per circular of the headquarters and they were entitled for their regularisation as in case of co worker Jagdish Mahato has been regularised in service by the management as per agreement in the year 1994 but their case was not considered at the time and this action of the management is discriminatory. It was also submitted that after their arbitrary stoppage of work in the years 1987, 1988, 1989 (as per date mentioned in the annexure with the W.S.) much prior to the closure of Patahi depot, no notice or notice compensation was given to them and it was clear violation of Section 25F of the I.D. Act. Thereafter they were regularly agitating the matter before the management for their regularisation and even the District Manager, F.C.I. as well as Depot Incharge, R. C. Sinha has written to the higher management for their regularisation as they have completed more than 240 days regular work and their termination was arbitrary and without compliance of the provision of Section 25F of the I.D. Act. Even then their matter was not considered by the management and when only Jagdish Mahato a co-worker was regularised in service in 1994 then they have raised the matter before the ALC(C) and the plea of stale claim as taken by the management has got no leg to stand This fact was mentioned in the confidential report Part II of the ALC(C) to the Ministry vide Ext. W-11 and Ext. W-15 that the management has not disputed the claim of the workmen in the conciliation proceeding that they have not completed more than 240 days rather the simply objection of the management was that it was a stale claim. But this plea of satle claim was also disallowed by the ALC(C), Patna on the plea that the matter was under consideration of the management for the entire period after their termination in the year 1989 on one pretext or the other and finally the case of Jagdish Mahato was considered and regularised in the year 1994 and the concerned workmen were left out and this action of the management was arbitrary and thereafter the dispute was raised before the ALC(C), Patna and the cause of action naturally arose in the year 1995 and as such this plea of stale claim is not convincing and plasuible at all on the other hand the workmen have given satisfactory explanation for delay in raising their dispute before the ALC(C), Patna in their W.S. filed in the conciliation proceeding which is clear from their petition as well as in the report Exts. W-11 and W-15

19. It is also submitted that vide Ext. W-16 the Ministry refused to make reference on the plea of delay in raising

the dispute and not giving satisfactory explanation. Therefore, C.W.J.C. No. 2258/95(R) was filed by the sponsoring union before the Hon'ble Patna High Court, Ranchi Bench and vide Order dated 18-8-96 Hon'ble Court rejected the plea and directed the Labour Ministry to make reference within a period of one month from the date of production/receipt of the copy of this order which is Ext. W-17 and therefore the present reference has been made by the Ministry vide letter dated 18-10-96 against F.O.C. report of ALC(C), Patna vide No. 1/78/94-ALC(C)II dated 21-12-94.

20. Latest staff position and vacancy in F.C.I. Bihar Region has been given vide Ext. W-18, dated 31st January, 1997 where it has been shown that there is sufficient number of vacancies in Class IV as Watchman in Bihar Region and against those vacancies the workmen can be regularised. It is further submitted that in the two judgements of the Hon'ble Patna High Court, Ranchi Bench filed by the workmen vide Ext. M-6 the Hon'ble Court has directed the management to consider the case of the workmen for their regularisation in view of the headquarters circular dated 6th May, 1987 against the existing vacancies or the future vacancies. As such the management cannot take the plea that there was no vacancy for regularisation of the workmen.

21. So far closure of F.C.I. Patahi depot is concerned it is submitted that it was a temporary depot which has been winded up by the management but not the F.C.I. as a whole has been closed in Bihar circle and closure of one small unit cannot be considered to be the closure of the entire management of F.C.I. It is further submitted that it has come in evidence of MWs that the permanent staffs were transferred to other depots after closure of Patahi depot and only temporary workers were transferred to Narayan depot where they were regularised subsequently. But these workmen were terminated much prior to the closure of Patahi depot and as such their case cannot be considered under Section 25FFF of the I.D. Act, 1947 as contended by the management. I agree with the contention of the workman that their case does not come under the ambit of Section 25FFF of the I.D. Act rather it is covered under Section 25F of the I.D. Act which has been violated by the management grossly and their termination becomes void abinitio. So far copies of attendance sheet Ext. W-8 series are concerned the plea of the management that these are false and manufactured documents. I find that in report of the ALC(C) sent to the Ministry it is clear that the management enquired the matter from Shri R. C. Sinha after raising the dispute by the workmen where he has confirmed his signature on Ext. W-8 series. So this cannot be said to be bogus or manufactured one. Moreover it is the contention of the management that after their best efforts and thorough search they could not trace out original attendance sheet of workmen of Patahi depot and in absence of the original, on what basis these Ext. W-8 series can be termed to be forged and fabricated documents specifically in the light of admission of Shri R. C. Sinha the then depot incharge confirming his signature to be genuine on these attendance sheet. The originals were called for by the workmen in this case also but the management has failed to produce the same then it has come with a plea that these documents are fabricated documents manufactured by the dealing clerk and in no case this plea cannot be taken to be tenable. I further find that a plea has been taken by the management while filing the written argument and an affidavit has been sworn in by one Shri S. S. Patra stating therein that some documents filed by the workmen were exhibited without his consent or any one's consent of the management and this has been done by the sponsoring union misleading the Tribunal However, from the that one Mr. S. S. Patra, A.M. was present on that day and a petition was filed on behalf of the workmen to call for the documents from the ALC(C), Patna and the Secretary, Ministry of Labour and some documents were filed with a list to the management and having no objection those documents were taken into exhibits vide Ext. W-1 to W-11. Thereafter a number of dates were given in this reference and ultimately nowhere such objection was raised and such plea was never taken that these documents were taken into exhibits on behalf of the workmen arbitrarily without the knowledge of the management and for the first time such plea has been taken by the management while filing written argument dated 15th May, 1997. In this view of the matter this plea of the management as taken in the written argument seems to be an after thought and cannot be considered to be genuine at this belated stage when the case was closed and it was fixed for passing award.

22. I also find that photo copies of two judgements passed by the Special C.B.I. Court being Case No. 11/82 and 10/82 has been filed by the management with the written argument to show that Mr. V. Kumar Joint Secretary of the sponsoring union who was conducting the case on behalf of the workmen was found guilty in these two criminal cases under Prevention of Corruption Act. However, these are extrancous materials not connected with the reference as these judgements are related to the individual Joint Secretary of the sponsoring union not against the workmen. Moreover, it was pointed out on behalf of the workmen that appeal has been filed which is pending in the Hon'ble High Court and the matter is under sub-judice and no opinion can be formed on the basis of these judgements. It was also submitted on behalf of the workmen that an Award was passed in Ref. No. 5/90 by CGIT No. II, Dhanbad in which the action of the management of F.C.I. in placing Mr. V. Kumar under suspension with effect from 23rd March, 1982 was held to be not justified and all

benefits were to be given Mr. Kumar with effect from 23rd March, 1982 and against this Award the management has filed Writ being No. CWJC 1519|91 Patna and vide order dated 12th January, 1994 the then Hon'ble Chief Justice Mr. B. C. Basak and Hon'ble Mr. Justice Chaudhury S. N. Mishra has held that Mr. Kumar was victimised by the management and directed the management to give him all his dues with cost of Rs. 5000 and the orders of the Tribunal was to be carried by 31st January, 1994 including all payment and costs as directed above. It is submitted that photo copy of the Award and the order of the Hon'ble High Court have been filed in the L.C. Case No. 15|96 of this Court. Thereafter the management has exonerated him from all the charges and have given him promotion and due wages etc. in the light of the direction of the Hon'ble Court in the Writ petition. Certainly these are extraneous matter not related with the action of the management justifying termination of the poor workmen without compliance of the provision of Section 25F of the I.D. Act, 1947. Thus aforesaid judgement cannot have any bearing against the action of the management rather this judgement goes to support the contention of workmen and the sponsoring union that the management of F.C.I. is in the habit of taking arbitrary and illegal action against the workmen and victimising them for no fault of theirs. In view of the strong observation made by the Hon'ble High Court against the management I find that much force in this plea taken by the sponsoring union and the workmen and certainly the action of the management in stopping|retrenching the workmen and denying their regularisation cannot be said to be justified and valid in any way.

23. So far other pleas taken by the management that the workmen have not completed 240 days of work in 12 calendar months and the dispute was raised after delay have already been discussed and in the conciliation proceeding before the ALC(C) Patna these facts were not disputed by the management and only a plea of stale claim was taken by the management which is clear from the Part II Confidential Report of the ALC(C) vide Ext. W-11 and W-15 and it seems that these pleas have not been taken just for the sake of the case and such waivering pleas of the management could not justify illegal and arbitrary action. The matter of stale claim has also been set at rest by the judgement of the Hon'ble High Court in Writ Petition being No. 2558|97 (R) Ext. W-17 where the Hon'ble Court has held that the Ministry has to make reference after sending the F.O.C report and from the report of the ALC(C) Patna the plea of delay has been fully explained and it has been held that actutlly there was no delay on the part of the workmen rather if any delay has been caused it was due to the action of the management as the matter was kept pending for years together and only in the year 1994 a co-worker Shri Jagdish Mahato was regularised and reinstated and this gave rise of the cause of the workmen and thereafter the matter was raised before the Conciliation Officer immediately. In this view of the matter all such pleas taken by the management justifying its action in retrenching and not regularising and paying back wages to them has got at all no valid grounds to stand. Accordingly, both the points are decided in favour of the workmen and against the management. In the result, I find that the action of the management of F.C.I. Patna in retrenching and denying regularising the concerned workmen as per list is not justified and valid at all. The concerned workmen are entitled for the relief of reinstatement and regularisation from the date of their stoppage of work as shown in the list stated above.

24. So far the question of payment of back wages is concerned, no specific date has been mentioned about reinstatement and regularisation of the workmen in the reference and it is clear also that the workmen were forced to sit idle but for the illegal and arbitrary action of the management and as such they are entitled for their back wages. It is also true that as per principle of 'No work no pay' the concerned workmen have not worked for the management for the aforesaid idle period and the dispute was raised under the I.D. Act in the year 1994 and F.O.C. report was sent from the ALC(C) Patna vide letter dated 21st December, 1994. Accordingly the management is directed to pay 40 per cent of full back wages to the workmen from 1st January, 1994 although their notional reinstatement and regularisation in the service has to be made from the date of their stoppage as per list annexed to the reference as well as to the list attached to the W.S. of the workmen. Hence, the following Award is rendered :—

> "The action of the management of Food Corporation of India, Patna in retrenching and denying the regularisation of the workmen S|Shri Udai Kumar and 15 others from the date shown against their names in this dispute is not justified and legal. Consequently, the concerned workmen are entitled reinstatement and regularisation with effect from the dates as shown in the annexure to the reference as well as to the list attached to the W.S. of the workmen with 40 per cent full back wages from 1st January, 1994."

The management is directed to reinstate and regularise the concerned workmen with effect from the date of stoppage of work|retrenchment as shown to the annexure to the order of reference as well as to the list attached with the W.C. of the workmen with payment of 40 per cent of their full back

wages with effect from 1st April, 1994 within two months from the date of publication of the Award in the Gazette of India.

25. However, there will be no order as to costs.

T. PRASAD, Presiding Officer

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1997

का. आ. 2109.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण, में, केन्द्रीय सरकार एफ.सी.आई. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-7-97 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या-एल.-22012/549/94-आई.आर. (सी.II]

एस. रविश अली, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th July, 1997

S.O. 2109.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of F.C.I. and their workman, which was received by the Central Government on 23-7-1997.

[No. L-22012/549/94-IR (C-II)]

S. RAVISH ALI, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 64 of 1995

In the matter of dispute :

BETWEEN

The Senior Regional Manager
Food Corporation of India
5/6 Habibullah Estate Hazaratganj
Lucknow.

AND

The State Secretary
Bhartiya Khadya Nigam Karamchari Sangh
5/6 Habibullah Estate Hazaratganj
Lucknow.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-22012/549/94-IR (C-II) dated 1-6-95 has referred the following disptue for its adjudication to this Tribunal—

Whether the action of the Sr. Regional Manager Food Corporation of India Lucknow in imposing penalty of Sri Mohd. Shoeb TA-III and also not releasing promotion order to the post of TA-II w.e.f. 7-11-85 is legal and justified ? If not to what relief he is entitled to ?

2. There is no dispute that the concerned workman Mohd. Shoeb was working as T.A.-III under District Manager of the opposite party FCI Gorakhpur. He was served with a charge-sheet dated 17-3-87 which runs as under—

1. Said Sri Mohd. Shoeb T.A.-III while working under District Manager FCI Gorakhpur, during the period 1981 to 1985 failed to maintain deyotion to duty and acted as unbecoming servant of the Corporation in as much as he absented himself from duty w.e.f. 13-10-81 to 12-10-85 without any intimation/permission of the competent authority.
2. Sri Mohd. Shoeb T.A.-III had cheated the Corporation by way of submitting false medical fitness certificate said to have been issued by one Dr. Anrudh Singh for regularisation for unauthorised absence, thus Sri Mohd Shoeb T.A.-III contravened sub. regulation 31 and 32 of regularisation of 32-A of F.C.I. Staff Regulation, 1971.

A A. Qazmi was appointed Enquiry Officer. After completing enquiry he submitted his finding on 25-9-90 holding that charges were fully proved. The disciplinary authority agreeing with this finding awarded punishment by way of deduction to the minimum of time scale of pay of T.A. Gr. III w.e.f. 1-11-90, on permanent basis. It was further ordered that he would draw the normal increments starting from the minimum of scale in future. As regards absence from duty w.e.f. 13-10-81 to 12-10-85 it was treated as unauthorised absence without pay. Further for the period of suspension no pay was allowed. Feeling aggrieved by this order of punishment the concerned workman has raised the instant industrial dispute in which it has been alleged that the concerned workman was genuinely prevented from attending office because of illness in respect of which medical certificate was filed. It was further alleged that enquiry was not fairly and properly held. On the other hand management has alleged that enquiry was fairly and properly held. On investigation it was found that the concerned workman had filed forged certificate of illness. In fact he was not ill.

3. In the rejoinder nothing new was alleged.

4. On pleadings of the parties a preliminary issue regarding fairness of domestic enquiry was framed Vide finding dated 5-11-96, it was held that enquiry was not fairly and properly held, hence the same was set aside and the management was given fresh opportunity to prove the misconduct on merits.

5. After the above development the management has examined R. B. Bajpai, Divisional Manager, MW-1 who has stated that the concerned workman had filed forged certificate of Dr. Anuradh Singh of Azamgarh in respect of which he has made local investigation and had also visited the dispensary of Dr. Anuradh Singh who had told him that he had not issued such certificate.

6. The workman did not care to adduce any evidence, Ultimately he was debarred from giving evidence on 3-5-97. An application was moved on 26-6-97 by the workman for getting the hand writing of Dr. Singh examined by hand writing in support of his case. It was rejected as the stage for such examination by hand writing expert had not arisen. The occassion for such stage arises when the author of such certificate would have denied his writing. No attempt was made to produce the doctor to prove the genuineness of medical certificate. It was in this back ground that the application was rejected.

6. As result above discussion it will be evident that there is unrebutted evidence of management regarding forged certificate and averment of misconduct. Hence, I accept the unrebutted evidence of management and hold that both the misconduct are proved.

7 As regards the proportionality of punishment under Section 11-A of I. D. Act this Tribunal has no jurisdiction to go into it because it has power to interfere only when punishment by way of dismissal or removal from service was given. Hence, my award is that the action of the management in imposing the penalty in question is justified and the workman is not entitled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1997

का.आ. 2110:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय केन्द्रीय सरकार मै. इंडियन एयर लाइन्स के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 19-7-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं० एल.-11012/17/90-आई.आर. (विविध)आई आर (सी-I)]

बज मोहन, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th July, 1997

S.O. 2110.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of M/s. Indian Airlines and their workmen, which was received by the Central Government on 19-7-1997.

[No. L-11012/17/90 IR (Misc)/IR (C-I)]

BRAJ MOHAN, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GANPATI SHARMA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI

I. D. No. 124/90

In the matter of dispute :

BETWEEN

Shri R. K. Mehta Driver
C/o Shri Dinesh Kumar, 1675, F. Block,
Khanpur, Tigri, New Delhi.

Versus

The Management of Indian Airlines
through The Regional Manager, Indian Airlines,
Thaper House, Janpath, New Delhi-110001.

APPEARANCES :

Shri K. S. Balashankar—for the workman.

Shri Sunil Gupta—for the Management.

AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-11012/17/90-IR (Misc) dated 25-10-90 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :—

"Whether the action of the management of Indian Airlines, New Delhi in not allowing Shri R. K. Mehta, Driver on duty since September 89, and subsequently asking him to work as Helper is justified ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. In the statement of claim the workman has alleged that he was employed as Driver with the Management on basic pay of Rs. 1450 with total emoluments of Rs. 3698.10 p. The workman had also applied to the management for taking into account his post service in the defence but the Management instead of granting him the service benefit attempted to declare the workman Psychiatric case and sent the workman for medical examination to Mool Chand Hospital in October, 87. The Doctor declared the workman medically fit. The workman continued performing his duties with the management without any complaint and was again got medically examined in September, 89 and referred to Mool Chand Hospital. He was supposed to remain admitted in the above hospital on 6-10-89 to 18-10-89 and the hospital authorities thereafter issued the discharge slip but no report was given by him but the management after a period of two months communicated to the workman vide letter dated 18-1-90 that he has been declared fit for any other duties. The Management thereafter offered the workman the post of helper in the M.T. Section of the management. The workman forwarded a report of the Dr. R. K. Patnaik Senior Psychiatric of Government Hospital "Civil Hospital" Ambala City wherein he was declared fit for duty but the workman asked the management to supply copy of the report of the Doctor concerned of Mool Chand Hospital but the Management did not supply him the same. The Management did not take any action on the representative of the workman. The management again gave him the duties of a driver in March, 91 which itself shows that the management was vindictive towards him. Though the workman is on duty from the last week of March, 91 but he has not so far been made payment of salary/wages for the period of August, 81 to March, 91 and is not granted the benefit of service increments etc. in regard to his defence services as per rules. Hence this reference for payment of wages of the workman for the period from August, 81 to March, 91 with all other benefits.

3. The Management in its written statement besides taking technical objections has referred to certain facts and events relating to the behaviour and abnormal conduct of the workman as follows :—

4-12-79—Shri R. K. Mehta born on 16th August, 1944 upon his discharge from the Indian Air Force as an M.P.T. Driver, was appointed as a Driver with the Indian Airlines at a basic wage of Rs. 150 per month. Though his application for being appointed as a Driver with the Indian Airlines, the workman submitted a copy of the certificate of discharge from the regular Air Force Service dated 31st May, 1979 where his general behaviour and trade proficiency was certified.

14-7-80—On 14th July, 1980 the workman was confirmed as a Driver with the Indian Airlines w.e.f. 4-6-1980.

20-1-82—He was cautioned, in accordance with the provisions of the Standing Orders, for remaining absent for 18 days without leave in the year 1979-80.

17-12-82—The workman was cautioned for unauthorised absence for 7 days in the year 1980-81 and his increment was postponed by 7 days.

30-12-82—The workman mishandled vehicle No. DEP 2968 over the Safdarjung Flyover causing extensive damage to the vehicle. His explanation was called for where he informed the Indian Airlines that the vehicle was damaged because of puncture of both rear tyers.

20-6-83—It was found that the reply tendered by the workman was unsatisfactory and he was issued a warning to be more careful in future.

24-7-83—The workman informed the Control Room of the Indian Airlines that vehicle No. DEB 9535 which was being driven by him had broken down near Tilak Nagar, New Delhi. When the repair staff and mechanics of the Indian Airlines reached the place where the vehicle was parked, they found the w[illegible] to be sleeping in the vehicle. On examini[illegible]vehicle, it was found that the bolts of the m[illegible]iving shaft were missing. When the mechani[illegible]alled upon the workman to explain this, there wa[illegible] serious altercation in which the main mechanic Sh[illegible] Gopal was assaulted by the workman.

26-7-83—When action was proposed to be initiated against the workman for this incident, the mechanic Shri Gopal and the workman filed a letter stating that the dispute between them had been amicably resolved and a compromise had been arrived at.

6/14-9-83—A severe warning was issued to the workman in regard to the scuffle of the 24th of July, 1983.

12-3-84—The workman was advised to be more cautious because he was absent for 8 days without leave in the year 1982.

1987—In 1987 the workman not with 4 accidents while driving vehicles of Indian Airlines. These accidents not only resulted in damage to the vehicles but loss in serious manhours because of the delays in getting the flight staff as also the technical staff to duty in time. The particulars of these accidents are as under :—

Sl. No.	Date	Vehicle No.	Insurance claim
1.	12-4-87	DEP—6783	Rs. 940.00
2.	17-7-87	DEP—6783	Rs. 960.00
3.	5-10-87	DEP—2968	Rs. 1800.00
4.	28-12-87	DEP—2962	Rs. 4075.00

There was a recurrence of accidents of vehicles being driven by Shri R. K. Mehta leading not only demage to vehicles but also loss of manhours in transportation of night staff as also operational staff from the place of residence to the place of work. The particulars of these accidents are as under :—

Sl. No.	Date	Vehicle No.	Insurance Claim
1.	2-8-88	DEP—690	Rs. 4825.00
2.	17-9-88	DEP—2869	Insurance claim in dispute.
3.	22-12-88	DEP—2963	Rs. 8185.00

14-12-88—The workman was advised to be more cautious because of his unauthorised absence from work for 2 days in the year 1987.

4-2-89—There was a serious accident of vehicle No. DEP 423 being driven by the workman.

7-5-89—Accident o fvehicle No. WNC 3895 being driven by the workman resulting in serious damage to the vehicle and insurance claim of Rs. 10,122.20 p. being made.

15-7-89—Vehicle No. DEP 7423 being driven by the workman was involved in a serious collision with the Prime Minister's escort car leading to the making of a hit and run case.

19-8-89—Vehicle No. DEP 2964 being driven by the workman Shri R. K. Mehta was involved in an accident leading to an insurance claim of Rs. 9520.

4-9-89—Seeing that a large number [illegible]ccidents to the vehicles driven by Shri R. K. M[illegible] were involved the Deputy Officer of the MT [illegible] Indian Airlines took him off duty and by [illegible] 6th September, 1989 the Transport Manage[illegible]lam made a confidential report informing the s[illegible]or officers of the high accident rate, the use of [illegible]sive language and sudden stopping of vehicles by [illegible] R. K. Mehta from time to time. On the rece[illegible] of the said report, the Management of Indian Airlines decided to refer Shri R. K. Mehta for treatment by the Psychiatrist at Mool Chand Khairati Ram Hospital.

25-10-89—Dr. V. Kumar, consultant Psychiarist after observing Shri R. K. Mehta in the hospital from 6-10-89 to 18-10-89 tendered a report that Shri R. K. Mehta was not considered compatible with safe driving.

30-10-89—After the report was received from Dr. V. Kumar, the Psychiarist, the Medical Board of the Indian Airlines after a detailed medical examination advised that Shri Mehta be taken off duty of driving vehicles and advised that he be advised any other job.

19-12-89—In view of the prognosis and reports by the Psychiatrist, Dr. V. Kumar as also of the Medical Board of Indian Airlines, Shri Mehta was advised to join as an Helper MT and his basic pay was protected and he was given continuity of service.

15-3-90—A chargesheet was issued to Shri Mehta alleging that he had been remaining absent from duty unauthorisedly without any intimation/permission with effect from 1st February, 1990 and as such, an enquiry was being instituted against him. Shri Mehta participated in the enquiry, examned his witnesses and cross-examined the witnesses of the Indian Airlines. A report was tendered by the Enquiry Officer finding Shri Mehta guilty of the charges levelled against him in the charge sheet. Further action on the enquiry report has been kept in abeyance in view of the pendency of the alleged dispute before this Hon'ble Tribunal.

11-1-91—Shri Mehta was referred to the Dr. Ram Manohar Lohia Hospital for further examination as provided in circular No. HPDOI/X-3100 dated 29th July, 1975.

18-3-91—After the examination by the Psychiatric Department of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, a report was tendered by the doctors there, inter-alia, finding him fit to work as a driver. The said report of the doctors of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital reads as under :—

"Form of Medical Certificate of Fitness to Report to duty.

I, Dr. N. Bohra, do hereby certify that I have carefully examined Shri R. K. Mehta of the Indian Airlines whose signature is given below and find that he is now fit to resume duty in Government service. I also certify that before arriving at this decision, I have examined the original medical certificate(s) and statement(s) of the case (or certified copies thereof) on which leave was granted or extended and have taken this into consideration for arriving at my decision."

15-4-91—Shri Mehta after resuming duties was once again involved in dereliction of duty when he did not turn up with the coach at Kalkaji from where he was to bring the officers and staff to the Airport.

It is stated that upon the aforesaid narration of facts, it is manifest that Shri Mehta is unfit to carry out the duties as a Driver and on compassionate grounds he was offered the job of an MT Helper on the same basic pay as he was drawing as a Driver and continuity in service.

3-6-91—Shri R. K. Mehta was detained to bring staff for 0815 Hrs. shift on coach No. DEP 5723. The staff were brought late by him at 0.835 hrs. without any satisfactory reason. Instead of going further for the next duty Shri Mehta came back to movement for change of duty on pretext of pain in his arm. As a result of this, the next shift staff were also brought late at 1000 hrs. instead of 0915 hrs.

4. It was further alleged that Shri R. K. Mehta was absent without leave from 1-2-90. He was not entitled to receive any wages for that period till he resumed the duties following the report of Private Secretary at Ram Manohar Lohia Hospital on 18-3-91. The Management further alleged that it was on the report of the specialist that decision to take him on driving duties was taken in view of the doctor's report. The Committee of these member senior medical officers who examined the petitioner alongwith the report of the specialist and concluded that the petitioner was not fit so work as Driver. The workman has intentionally suppressed material facts from the Government before making this reference. It was further alleged in the written statement that the workman was taken on day on March, 91 but it was correct that he has been made payment of salary for the period October, 91 to March, 91 because he was absent without leave during this period.

5. The Management in support of its case examined Shri Gurdeep Singh, Manager Personnel MW-1. Workman, however, did not appear in the witness box nor filed his affidavit though he was given more than 10 opportunities to produce his evidence and his evidence was ordered to be closed.

6. I have heard representative for the parties and have gone through the record.

7. Representative for the management has urged that the workman in the statement of claim his entitlement to pay salary and wages for the period August, 89 to March, 91 with all increment and benefits of defence services. Though the reference made by the Ministry of Labour is regarding the correctness or otherwise of the action of the management in not allowing the workman driver on duty since September, 89 and later on asking him to work as helper. He has further urged that the evidence on record was sufficient to hold the workman not entitled to the duties of a driver in the light of the medical evidence produced by the management before this Tribunal. The workman himself has not appeared into the witness box inspite of many opportunities granted to him for the purpose. The workman had not reported for duty to the job which was offered to him and he was not entitled to the emoluments for that period.

8. The workman has only urged before me that he was fit to work as Driver but the duties of the driver were not given to him and the arrears of his wages for the period from September, 89 to 1991 were not paid to him.

9. I have gone through the record of this case and the points urged before me by the workman as well as by the representative for the management. The details of the incident which took place in respect of this workman start from 4-12-79 and a perusal of this incident show that the workman's conduct was not fit enough to be kept as a driver. Dr. V. Kumar whose report is on the file has recorded that he was not considered competent for safe driving in general and particularly at the Airport was a very responsible job which cannot be taken lightly by the authorities as the life and property of so many people and the Government is involved therein. He was not taken away from the service and was appointed as a helper by the management keeping in view his mental state and also his physical condition. There is no substitute for the safety of the passengers and his conduct reported by the management shows this negligence. Management in December, 89 had ordered taking of a lenient and compassionate view of the matter and decided to offer him the service of a Motor Transport Helper assuring him alongwith emoluments which he was drawing would be protected and he would be given continuity of service. However, he did not join the said post and remained absent from the duty. An enquiry was also conducted by the management in which the workman participated. He also examined his witness and cross-examined the witnesses of the Management and the action on the enquiry officer report was kept pending due to the pendency of the dispute.

10 Keeping in view my above discussion, I am of the opinion that asking the workman to work as helper on the report of the medical expert on his fitness instead of driver was fully justified. However, keeping in view the circumstances of this case and taking lenient and compassionate view of the matter in view of the bad health of the workman, I order that all his dues whatever are payable to him according to rules be paid to him henceforth, if not paid already. Parties are, however, left to bear their own costs.

13th May, 1997.

GANPATI SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 1997

का.आ. 2111.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार नोर्दन रेलवे, इलाहाबाद, के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-7-97 को प्राप्त हुआ था ।

[संख्या एल.-41012/143/95-आई. आर. (बी.)]

के. वी. बी. उण्णी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th July, 1997

S.O. 2111.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Northern Rly. Allahabad and their workmen, which was received by the Central Government on 23-7-97.

[No. L-41012/143/95-IR(B)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, DEOKI PALACE ROAD, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 115 of 1996

In the matter of dispute :

BETWEEN

Divisional Rail Manager,
Northern Railway,
Allahabad.

AND

Sudhir Kumar Singh,
C/o Dr. Santosh Kumar Gupta,
Plot No. 3268, Awas Vikas Yojna-3,
Panki Road, Kalyanpur, Kanpur.

AWARD

1. Central Government Ministry of Labour, New Delhi vide its Notification No. L-41012/143/

95-I.R.(B), dated 29-11-96 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

Whether the action of the management of DRM, Northern Rly. Allahabad in terminating the services of Shri R. P. Singh is legal and justified ? If not, to what relief is the workman entitled ?

2. It is unnecessary to give the detail of the case as after sufficient opportunity the workman has not filed claim statement. Hence the reference is answered against the workman for want of prosecution and proof and he will not be entitled for any relief.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1997

का.आ. 2122.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार मै. सैन्ट्रल कोलफील्डस लि. के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, (सं.-1), धनबाद के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-7-97 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-20012/144/95-आई.आर. (सी.-I)]

के.वी.बी. उन्नी, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1997

S.O. 2112.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, No. 1, Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employees in relation to the management of M/s. Central Coalfields Ltd. and their workmen, which was received by the Central Government on 25-7-97.

[No. L-20012|144|95-IR(C?I)]

K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD

In the matter of a reference under Section 10 (1)(d)(2A) of the Industrial Disputes Act, 1947.

Reference No. 45 of 1996

PARTIES :

Employers in relation to the management of M/s. Central Coalfields Ltd.

AND

Their Workman

PRESENT :

Shri Tarkeshwar Prasad, Presiding Officer

APPEARANCES :

For the Employers—Shri B. Joshi, Advocate
For the Workmen—None.

STATE : Bihar INDUSTRY : Coal

Dated, the 14th July, 1997

AWARD

By Order No. L-20012|144|95-I.R.(C-I), dated 6-8-1996 the Central Government in the Ministry of Labour has, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

"Whether the action of the management N.K. Area Dakra, CCL, in depriving Sh. Mohan Kumar and 7 others (as per list) the protection of Minimum Guaranted wages was proper and justified ? If not, what relief the concerned workmen are entitled ?"

2. The order of reference was received in this Tribunal on 21-8-1996 and thereafter notices were issued to the parties for filing written statement on behalf of the workmen. Despite giving adjournments no written statement was filed on behalf of the workmen. Thereafter two notices were sent to the sponsoring union by registered post which were returned back. It, therefore, appears that neither the concerned workmen nor the sponsoring union are interested in prosecuting the reference case.

3. Under such circumstances, I render a 'No Dispute' award in the present reference case.

TARKESHWAR PRASAD, Presiding Officer

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1997

का.आ. 2113.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार आर्मिस्टेड इंजीनियर केबल्स (टेक्नीकाम) वाराणसी के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-7-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/72/91-डी II(बी)]

के.वी.बी. उण्णी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 31st July, 1997

S.O. 2113.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Asstt. Engineer Cables (Telecom) Varanasi and their workman, which was received by the Central Government on 30-7-97.

[No. L-40012|72|91-D-II(B)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, DEOKI PALACE ROAD, KANPUR

Industrial Dispute No. 187 of 1991

In the matter of dispute :

BETWEEN

Shiv Kumar Gupta S/o Rameshwar,
C|o. R. C. Pandey,
2/323, GTB Nagar,
Kareily, Allahabad.

AND

Assistant Engineer (Phones),
Cables, Varanasi.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its Notification No. L-40012|72|91-D-2B, dated 19-11-91, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

> Whether the action of the management of Asstt. Engineer Cables (Telecom), Varanasi in terminating the services of Sri Shiv Kumar Gupta, son of Sri Rameshwar w.e.f. 7-3-89 is justified ? If not, what relief he is entitled to and from what date ?

2. The case of the concerned workman is that he was engaged as casual labour by SDO Phones on 1-6-78, and he had worked upto 31-3-89, whereafter he was removed from service without payment of retrenchment compensation and notice pay as required under Section 25-F of I.D. Act, 1947.

3. The opposite party has filed written statement in which it has been alleged that the concerned workman was engaged at Jaunpur which was altogether a different appointment. Thereafter he was engaged at Varanasi on a project and was specifically told that he would be removed from service after completion of project. Since project was over he was asked to go to Jaunpur. Further in 1981 there had been a ban in appointment as such his appointment was irregular. Lastly it was alleged that opposite party is not an industry, hence this reference is bad in law.

4. In the rejoinder it has been denied that appointment was on a project alone.

5. In support of his case concerned workman Shiv Kumar Gupta has examined himself as W.W.1. In rebuttal there is evidence of J. P. Singh M.W.1 Section Supervisor of the opposite party.

6. In the instant case it is to be seen if the concerned workman had worked continuously from 1-6-78 to 31-3-89 continuously. In this regard there is evidence of the concerned workman who has stated that that from 1-6-78 to October, 1978 he had worked for 153 days whereafter in Varanasi he had worked w.e.f. October 1986 to March 1989 continuously. When he was removed from service no notice pay and retrenchment compensation was given to him. In rebuttal there is evidence of J. P. Jaiswal M.W. 1 who has stated that work at Varanasi came to an end. No work was taken from him and he was asked to go to Jaunpur. He has not stated that the concerned workman was employed on any project or for a fixed period. There is no documentary evidence in this regard.

7. As regards the evidence of the concerned workman that he had worked continuously from October 1986 to March 1989 has not been rebutted by the management witness. I accept it, and hold that during this period he had continuously worked. It is not established that he had worked on project. However, it is alleged that there was a ban on recruitment from the higher authorities. Admittedly no notice pay and retrenchment compensation was paid hence my finding is that this removal from service being in breach of Section 25-F of I.D. Act is bad in law. The new fact that there was a ban will not render this engagement bad. If engagment was made by an officer in defiance of ban, he should be punished and the workman who had no knowledge about such ban.

8. As regards the plea of industry this point was taken as preliminary issue and this tribunal vide finding dated 2-1-96 had hold that opposite party is an industry.

9. In the end my award is that termination of the workman is bad in law and he should be entitled for reinstatement. The opposite party is directed to reinstate the workman within a month from the date of publication of this award.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1997

का.आ. 2114.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस.डी.ओ. (फोन्स) वाराणसी के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-7-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/239/91—आई आर. (डी.यू.)]
के.वी.बी. उण्णी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 31st July, 1997

S.O. 2114.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industial dispute between the employers in relation to the management of SDO (Phones), Varanasi and their workman, which was received by the Central Government on the 30-7-1997.

[No. L-40012/239/91-IR(DU)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Dispute No. 124 of 1992

In the matter of dispute :

BETWEEN

Sri Ashok Kumar Singh,
S/o Shiv Pal Singh,
C/o Sri N. C. Pandey,
C-323 GTB Nagar, Kanpur.

AND

District Telecom Manager,
Varanasi.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its Notification No. L-40012/239/91-I.R.(DU) dated 30-9-92, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Whether the action of the SDO (Phones) Varanasi in terminating the services of Shri Ashok Kumar singh S/o Sh. Shiv Pal Singh w.e.f. 1-4-89 is legal and justified ? If not, what relief he is entitled to ?

2. The case of the concerned workman is that he was engaged as casual labour by SDO (Phones) Allahabad on 27-1-78 and he had worked upto 7-7-79 continuously for a period of 454 days. Thereafter he fell ill and could not attend the office till 31-1-87. He was again engaged by Assistant Engineer Varanasi and there he continuously worked as a daily rated casual labour w.e.f. 1-2-87 to 6-5-87 and from 1-8-87 to 31-3-89, whereafter he was removed from service w.e.f. 10-4-89 without payment of retrenchment compensation and notice pay and also in disregard of provisions of section 25G i.e. first come last go.

3. The opposite party has filed written statement in which it has been alleged that the concerned workman was engaged in Allahabad which was altogether a different appointment. Thereafter he was engaged at Varanasi on a project and was specifically told that he would be removed from service after completion of project. Since project was over he was asked to go to Allahabad. Further in 1981 there had been ban in appointment, as such his appointment was irregular. Lastly, it was alleged that opposite party is not an Industry, hence this reference is bad in law.

4. In the rejoinder it has been denied that appointment was on a project alone.

5. In support of his case the concerned workman Ashok Singh has examined himself as W.W. 1. Beside he has filed documents Ext. W-1 to W-2. In rebuttal there is evidence of J. P. Jaiswal M.W. 1 Section supervisor of the opposite party.

4. As regards the plea of the concerned workman that the concerned workman fell and could not attend the office, it appears to be after thought and has been contrived to fill the lacuna of this period. Hence, I refuse to accept it. Further there is no evidence in this regard.

5. I am also not inclined to take the period of Service from 7-5-87 to 31-7-87.

6. However, it will be considered if the concerned workman had worked from 1-8-87 to 31-3-89, continuously. In this regard there is evidence of concerned workman who has stated that he had continuously worked and when he was removed from service no notice pay and retrenchment compenesation was given to him. In rebuttal there is evidence of J. P. Jaiswal, who has stated that work at Varanasi came to an end. No work was taken from him and he was asked to go to Allahabad. He has not stated that the concerned workman was employed on any project or for a fixed period. There is no documentary evidence in this regard.

8. As the evidence of the concerned workman that he worked continuously from 1-8-87 to 31-3-89 has not been rebutted by the management witness,

I accept it and hold that during this period he had continuously worked. It is not established that he had worked on project. However, it is alleged that there was a ban on recruitment from the higher authorities. Admittedly no notice and retrenchment compensation was paid hence my finding is that this removal from service being in breach of section 25F of I.D. Act, is bad in law. The new fact that there was a ban will not render this engagement bad. If engagement made by an officer in defiance of ban, he should be punished and not the workman who had no knowledge about such ban. There is no breach of section 25H of I.D. Act.

9. As regards the plea of Indusutry this point was taken as preliminary, issue and this tribunal vice finding dt. 2-1-96 had held that opposite party is not an Industry.

10. In the end my award is that termination of the workman is bad in law and he should be entitled for reinstatement. The opposite party is directed to reinstate the workman within a month from the date of publication of this award.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1997

का.आ. 2115.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस.डी.ओ (टेलीफोन) भदोही के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-7-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/258/91-आई आर (डीयू)]
के. वी. बी. उण्णी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 31st July, 1997

S.O. 2115.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of SDO (Telecom), Bhadohi and their workman, which was received by the Central Government on the 30-7-1997.

[No. L-40012/258/91-IR(DU)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, DEOKI PALACE ROAD, KANPUR

Industrial Dispute No. 118 of 1992
In the matter of dispute :

BETWEEN

Shiv Chand,
Putra Sri Jhinak Dwar,
C|o Sri Jagrup,
House No. 279,
Post Office Cantt Varanasi.

AND

Telecom District Manager,
Varanasi.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, vide its Notification No. L-40012|258|91-IR D.U. dated 30-9-92, has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Kya SDOT Bhadohi dwara Sri Shiv Chand S|o Sri Jhinak Ram ko dinank 1-4-89 se naukari se nishkashit karna nyayochit hai ? Yadi nahi to sambandhit karmkar kis rahat ko pane ka haqdar hai ?

2. The case of the concerned workman is that he was engaged as casual labour by SDO Phones Azamgarh in November, 1980 and he had worked upto December, 1983. Thereafter he fell ill and could not attend the office till 1986. He was again engaged w.e.f. October, 1986 by the Assistant Engineer Cables Varanasi and there he continuously worked as daily rated casual labour upto May 1988 thereafter he was removed from service without payment of retrenchment compensation and notice pay and also in disregard of provisions of section 25G i.e. first come last go.

3. The opposite party has filed written statement in which it has been alleged that the concerned workman was engaged in Azamgarh which was altogether a different appointment. Thereafter, he was engaged at Varanasi on a project and was specifically told that he could be removed from service after completion of project. Since project was over he was asked to go to Azamgarh. Further in 1981 there had been ban in appointment as such his appointment was irregular. Lastly it was alleged that opposite party is not an Industry, hence this reference is bad in law.

4. In the rejoinder it has been denied that appointment was on a project alone.

5. In support of his case the concerned workman has examined himself as W.W. 1. In rebuttal there is evidence of J. P. Saiswal M.W. 1 Section Supervisor of the opposite party.

6. As regards the plea of concerned workman that he fell ill and could not attend office till September 1986, it appears to be after thought and has been contrived to fill the lacuna of this period. Hence, I refuse to accept it. Further there is no evidence in this regard.

7. I am also not inclined to take the period of service from 1-1-87 to 31-3-87. However, it will be considered if the concerned workman had worked from October 1986 till 1-4-89 continuously. In this regard there is evidence of concerned workman who has stated that he had continuously worked and when he was removed from service no notice pay and retrenchment compensation was given to him. In rebuttal there is evidence of J. P. Singh, who has stated that work at Varanasi came to an end. No work was taken from him and he asked to go to Azamgarh. He has not stated that the concerned workman was employed on any project or for a fixed period. There is no documentary evidence in this regard.

7. As the evidence of the concerned workman that he worked continuously w.e.f. October 1986 to 1-4-89 has not been rebutted by the management witness, I accept it and hold that during this period he had continuously worked. It is not established that he had worked on project. However, it is alleged that there was a ban on recruitment from the higher authorities. Admittedly no notice and retrenchment compensation was paid, hence my finding is that this removal from service being in breach of Section 25F of I.D. Act is bad in law. The new fact that there was a ban will not render this engagement bad. If engagement was made by an officer in defiance of ban he should be punished and not the workman who had no knowledge about such ban.

8. As regards the plea of Industry this point was taken as preliminary issue and this Tribunal vide finding dated 2-1-96 had held that opposite party is an industry.

9. In the end my award is that termination of the workman is bad in law and he should be entitled for reinstatement in service. Opposite party is directed to reinstate the workman within a month from the date of publication of the award.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 1997

का.आ. 216.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार असिस्टंट इंजीनियर केबल्स, वाराणसी के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 30-7-97 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/259/91-आई.आर. (डी.यू.)]
के.वी. बी उण्णी, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 31st July, 1997

S.O. 2116.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Asstt. Engineer Cables, Varanasi and their workman, which was received by the Central Government on the 30-7-1997.

[No. L-40012|259|91-IR(DU)]
K. V. B. UNNY, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI B. K. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, PANDU NAGAR, DEOKI PALACE ROAD, KANPUR

Industrial Dispute No. 117 of 1992

In the matter of dispute :

BETWEEN

Bhragnnath Singh Jadav,
S|o Sitaram Yadav,
Village Benipur,
Post Bharauli Kalan,
District Ghazipur-233001.

AND

Divisional Engineer (Phones),
Varanasi-221001.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-40012|259|91-IR(DU) dated 10-9-92 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal—

Kya Assistant Engineer Cables, Varanasi Divisional Engg. Phones, Varanasi dwara

Bhragaunath Singh Yadav Putra Sri Sitaram Yadav Akasmik Mazdoor ko dinank 1-4-89 se naukari se nataya jana uchit avam vaidya hai? Yadi nahi to karmchari kis ranat ko pane ka adhikari hai?

2. The case of the concerned workman is that he was engaged as casual labour by SDO Phones Azamgarh in April, 1982 and he had worked upto 30-8-83 for a period of 282 days. Thereafter he fell ill and could not attend the office till 23-12-86. He was again engaged w.e.f. 1-1-87 by Assistant Engineer Cables Varanasi and there he continuously worked as a daily rated casual labour upto 31-3-87, thereafter, w.e.f. 1-12-87 to 31-3-89, whereafter he was removed from service without payment of retrenchment compansation and notice pay and also in disregard of provisions of Section 25G i.e. first come last go.

3. The opposite party has filed written statement in which it has been alleged that the concerned workman was engaged in Azamgarh which was altogether a different appointment. Thereafter, he was engaged at Varanasi on a project and was specifically told that he would be removed from service after completion of project. Since project was over he was asked to go to Azambarh. Further in 1981 there had been ban in appointment as such his appointment was irregular. Lastly it was alleged that opposite party is not an industry, hence this reference is bad in law.

4. In the rejoinder it has been denied that appointment was on a project, alone.

5. In support of his case the concerned workman Bhragunath Singh Yadav has examined himself as W.W. 1. Besides he has filed documents Ext. W-1 to W-2. In rebuttal there is evidence of J. P. Jaiswal, M.W. 1 section supervisor of the opposite party.

6. As regards the plea of the concerned workman that 30-8-83, he fell ill and could not attend the office till 23-12-86, it appears to be after thought and has been contrived to fill the lacuna of this period. Hence, I refuse to accept it. Further there is no evidence in this regard.

7. I am also not inclined to take the period of service from 1-1-87 to 31-3-87.

8. However, it will be considered if the concerned workman had worked from 1-12-87 to 31-3-89 continuously. In this regard there is evidence of concerned workman who has stated that he had continuously worked and when he was removed from service no notice pay and retrenchment compensation was given to him. In rebuttal there is evidence of J. P. Jaiswal, who has stated that work at Varanasi came to an end. No work was taken from him and he was asked to go to Azamgarh. He has not stated that the concerned workman was employed on any project or for a fixed period. There is no documentry evidencee in this regard.

8. As the evidence of the concerned workman that he worked continuously from 1-12-87 to 31-3-89 has not been rebutted by the management witness, I accept it and hold that during this period he had continuously worked. It is not established that he had worked on project. However, it is alleged that there was a ban on recruitment from the higher authorities. Admittedly no notice and retrenchment compensation was paid hence my finding is that this removal from service being in breach of section25F of I.D. Act, is bad in law. The new fact that there was a ban will not render this engagement bad. If engagement was made by an officer in defiance of ban, he should be punished and not the workman who had no knowledge about such ban. There is no breach of section 25H of I.D. Act.

9. As regards the plea of Industry this point was taken as preliminary issue and this tribunal vide finding dt. 2-1-96 had held that opposite party is an industry.

10. In the end, my award is that termination of the workman is bad in law and he should be entitled for reinstatement. The opposite party is directed to reinstate the workman within a month from the date of publication of this award.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 1997

का.आ. 2117.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-7-97 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल 17011/6/96-आई आर(बी-II)
पी.जे. माईकल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 24th July, 1997

S.O. 2117.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Govt. hereby publishes the award of the Central Govt. Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of LIC of India and their workmen, which was received by the Central Government on 23rd July, 1997.

[No. L-17011|6|96-IR (B-II)]
P. J. MICHAEL, Desk Officer

अनुबन्ध

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, कानपुर

फा. नं. सी. आई. टी. 63/90

रेफरेंस : केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश श्रा. एल. 17011/6/96/आई. आर. बी-ii दिनांक 29-8-90

हजारी लाल मीणा पुत्र श्री घीसा लाल मीणा।

—प्रार्थी श्रमिक

बनाम

सीनियर डिवीजनल मैनेजर, लाईफ इन्श्योरेन्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया, भवानी सिंह रोड, जयपुर।

—अप्रार्थी

उपस्थित

पीठासीन अधिकारी : श्री एस. के. बंसल, आर. एच. जे. एस.

प्रार्थी की ओर से :	श्री एम. एफ. बेग
अप्रार्थी की ओर से :	श्री एस. डी. अग्रवाल
दिनांक अवार्ड :	1-4-1997

अवार्ड

निम्न अधिसूचना भारत सरकार द्वारा इस न्यायालय को निर्णय के लिए प्रेषित की गई है :—

"Whether the Senior Divisional Manager Life Insurance Corporation of India Jaipur in terminating the services of Shri Hazarilal Meena, Development Officer w.e.f. 14-9-87 is justified? If not,what relief the workman concerned is entitled for?"

2. प्रार्थी श्रमिक ने स्टेटमेंट आफ क्लेम पेश किया और उसका कथन है कि उसकी नियुक्ति डेवेलपमेंट ऑफीसर के पद पर दिनांक 29-10-84 को विपक्षी के अधीन हुई थी और दिनांक 28-10-85 को प्रार्थी श्रमिक ने अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। प्रार्थी का यह भी कथन है कि उसको डेवलपमेंट ऑफीसर (एप्रेन्टिस) के पद पर नियोजक के पत्र दिनांक 29-10-85 द्वारा परिवीक्षा काल पर एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति दी गई और प्रार्थी श्रमिक ने नियुक्ति आदेश की पालना में दिनांक 29-10-85 को अपना कार्यभार संभाला तथा अपना कार्य करने लगा और उसके जरिये पत्र क्रमांक सैल्म/103 दिनांक 31-10-86 द्वारा परिवीक्षा काल की अवधि तीन माह के लिए बढ़ाई गई अर्थात 5-11-86 से तीन माह की अवधि बढ़ाई गई। प्रार्थी का यह भी कथन है कि विपक्षी ने दिनांक 4-4-87 को पुनः परिवीक्षा काल तीन माह के लिए बढ़ा दिया। प्रार्थी का यह भी कथन है कि उसको प्रशिक्षण काल पूरा करने के बाद जब परिवीक्षा काल में लगाया गया तो उसका कार्य पूरी तरह संतोषजनक रहा और अंतिम सेवा अवधि 5-2-87 को बढ़ाई गई जो परिवीक्षा काल 4-5-87 को पूरा हुआ किन्तु 5-5-87 अथवा इससे पूर्व या उसके बाद भी प्रार्थी की सेवा अवधि बढ़ाने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया और इससे नियमित कार्य लिया जाता रहा। प्रार्थी का यह भी कथन है कि 4-5-87 के पश्चात सेवा अवधि बढ़ाने का कोई आदेश जारी नहीं करने इस बात का प्रतीक है कि प्रार्थी परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद अपने पद पर स्वतः ही स्थाई हो गया है और उसे कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया और न ही कोई आरोप सिद्ध किया गया और न ही उसकी सेवा समाप्ति से पूर्व बचाव का कोई अवसर दिया गया। परन्तु विपक्षी द्वारा उसकी सेवाएं 14-9-87 को समाप्त की गई जो कि पूर्णतः अवैध व अनुचित है। प्रार्थी का यह भी कथन है कि अगर यह मान भी लिया जाये कि प्रार्थी की सेवा मुक्ति डिसमिसल अथवा डिसचार्ज नहीं है और दुराचरण के आधार पर ही है तो प्रार्थी की सेवा मुक्ति को छंटनी के रूप में देखा जाना चाहिये जो अनुचित व अवैध है क्योंकि प्रार्थी को प्रार्थी को सेवा मुक्ति से पहले एक माह का नोटिस, नोटिस पे अथवा छंटनी का मुआवजा नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिये था इसलिए प्रार्थी की सेवाएं धारा 25—एफ औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (जिसे तत्पश्चात् अधिनियम कहा जायेगा कि उल्लंघना में समाप्त की गई है जो कि अवैध है। प्रार्थी का यह भी कथन है कि कोई वरिष्ठता सूची नहीं बनाई गई और कनिष्ठ श्रमिकों को काम पर रखा गया और नई नियुक्तियां की गई जिसमें उसे प्राथमिकता देनी चाहिये थी जो नहीं दी गई इसलिए धारा 25—एच व नियम 77 एवं 78 की उल्लंघना की गई है इसलिए प्रार्थी की सेवा समाप्ति अवैध व अनुचित घोषित करते हुए उसे सवेतन निरन्तर सेवा में बहाल किया जाए।

3. विपक्षी ने जवाब पेश किया और उनका अभिकथन है कि प्रार्थी को परिवीक्षा काल पर नियुक्ति दी गई थी और उसका कार्य संतोषप्रद नहीं रहा जो कि परिवीक्षा काल की अवधि बढ़ाये जाने से भी स्पष्ट है इसलिए प्रार्थी को स्थाई करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता और जांच कराना या आरोप पत्र दिया जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए प्रार्थी को बिना नोटिस सेवा मुक्त किया जा सकता था। विपक्षी का यह भी अभिकथन है कि स्टाफ रैगूलेशन्स, 1960 के अनुसार परिवीक्षा के दौरान नियुक्त किये गये किसी भी कर्मचारी को बिना नोटिस हटाया जा सकता है। इसमें चार्जशीट देना या जांच कराना आवश्यक नहीं है इसलिए सेवा समाप्ति सही की गई है और क्लेम खारिज किये जाने योग्य है।

4. प्रार्थी ने अपने क्लेम को साबित करने के लिए स्वयं का शपथ पत्र पेश किया जिस पर विपक्षी द्वारा प्रति परीक्षण किया गया व डब्ल्यू—1 दस्तावेज प्रार्थी की ओर से पेश किया गया है। विपक्षी की ओर से श्री ए. के. नाटाणी

का शपथ पत्र पेश किया गया है जिस पर प्रार्थी ने प्रति परीक्षण किया वहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि श्री एम. एफ. बेग का तर्क है कि इस प्रकरण में प्रार्थी को प्रशिक्षण काल समाप्त होने के पश्चात् 29-10-85 को एक वर्ष की परिवीक्षा पर रखा गया जो समय बढ़ाया जाता रहा और अंतिम समय जो बढ़ाया गया उसकी अवधि 4-5-87 को पूरी हो गई परन्तु प्रार्थी को 14-9-87 के आदेश के जरिये सेवा मुक्त कर दिया गया और 5-5-87 से 14-9-87 तक जो प्रार्थी को सेवा में रखा गया वह अवधि परिवीक्षा काल पर नहीं थी क्योंकि समय नहीं बढ़ाया गया था और उसने 240 दिन से अधिक पूरे कर लिये थे इसलिए सेवा समाप्ति से पूर्व उसे कोई नोटिस, नोटिस पे अथवा छंटनी मुआवजा नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिये था इसलिए सेवा धारा 25-एफ औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (जिसे बाद में अधिनियम कहा जायेगा) के प्रावधान की उल्लंघना में समाप्ति की गई है जो अवैध है व प्रार्थी पुनः सेवा में बहाल किये जाने का अधिकारी है। यह भी तर्क है कि सेवा समाप्ति के समय कनिष्ठ कर्मचारी कार्यरत थे और बाद में भी अन्य कर्मचारियों को सेवा में लिया गया जबकि प्रार्थी को प्राथमिकता दी जानी चाहिये थी इसलिए सेवा समाप्ति धारा 25-एच व जी तथा नियम 77 व 78 की उल्लंघना में समाप्त की गई जो अवैध है अतः प्रार्थी पुनः सेवा में लिये जाने योग्य है। यह भी तर्क है कि प्रार्थी को पुनः सवैतन सेवा में लिया जाये।

6. विपक्षी के प्रतिनिधि श्री अनुराग अग्रवाल का जवाब में कहना है कि प्रार्थी को परिवीक्षा काल पर रखा गया था और स्टाफ रेगुलेशन्स 1960 के नियम 14 के अनुसार प्रार्थी का परिवीक्षा काल दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और 29-10-85 को उसकी परिवीक्षा अवधि शुरू हुई और उसकी सेवाएं 14-9-87 को अर्थात् दो वर्ष पहले परिवीक्षा काल में ही समाप्त कर दी गई इसलिए नोटिस देना या जांच करना आवश्यक नहीं था। इसलिए अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और ना ही वह प्रकरण छंटनी की परिभाषा में आता है इसलिए धारा 25-एच व नियम 77 एवं 78 की उल्लंघना साबित नहीं होती है। विपक्षी के विद्वान प्रतिनिधि ने इस तर्क के समर्थन में 1994(2) एस०एल०सी० पेज 323 एम० वेणुगोपाल बनाम डिवीजनल मैनेजर एल०आई०सी० ऑफ इंडिया मछलीपट्टम व अन्य को पेश किया है। मेरे विचार में प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि के तर्कों में कोई सार प्रतीत नहीं होता। हजारी लाल के शपथ पत्र के पैरा नं० 2 व 3 में कथन है कि :—

> पैरा नं० 2 : कि मुझे पुनः 29-10-85 को आदेश जारी कर एक वर्ष की परिवीक्षा काल पर रखा गया। उसके बाद ही मेरा परिवीक्षा काल 31-10-86 के आदेश द्वारा 5-11-86 से 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया।
>
> पैरा नं० 3 यह कि मेरी अंतिम रूप से सेवा अवधि बढ़ाने बाबत आदेश 5-2-87 को जारी किया गया था जो परिवीक्षा काल 4-5-87 को पूरा हो गया था।

प्रार्थी द्वारा प्रदर्श डब्ल्यू-1 दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार उसकी सेवाएं प्रोबेशन पीरियड के अनुसार 14-9-87 को समाप्त की गई। प्रार्थी का प्रति परीक्षण में कथन है कि प्रोबेशन पीरियड पर उसे रखा गया था, उसे कन्फर्म नहीं किया गया। इस प्रकार प्रार्थी के शपथ पत्र व प्रदर्श डब्ल्यू-1 दस्तावेज से यह साबित होता है कि प्रार्थी को विपक्षी के यहां 29-10-85 से परिवीक्षाकाल पर रखा गया था और उसके परिवीक्षाकाल को अवधि समय-समय पर बढ़ाई गई एवं दिनांक 14-9-87 को आदेश प्रदर्श डब्ल्यू-1 पत्र के जरिये उसकी सेवाएं समाप्त की गई। श्री ए०के० नाटाणी का शपथ पत्र के पैरा सं० 2 में कथन है कि :

> पैरा सं० 2: यह कि प्रार्थी की नियुक्ति केवल परिवीक्षा के रूप में की गई थी व उपरोक्त परिवीक्षा काल में प्रार्थी का कार्य संतोषजनक नहीं रहने के कारण समय-समय पर उसका परिवीक्षा काल बढ़ाया जाता रहा और फिर भी प्रार्थी का कार्य संतोषपूर्वक नहीं रहने के कारण उन विपक्षी निगम में आगे नियुक्ति नहीं दी गई। श्री ए०के० नाटाणी का शपथ पत्र के पैरा नं० 4 में कथन है कि :
>
> पैरा सं० 4: कि विपक्षी निगम के स्टाफ रेगुलेशन जो कि विधि के प्रावधानों का प्रभाव रखते है। परिवीक्षा काल में नियुक्त कर्मचारी को बिना कोई नोटिस दिये सेवा मुक्त किया जा सकता है व परिवीक्षा के दौरान उसका कार्य संतोषजनक नहीं हो तो उसको चार्जशीट देना अथवा जांच करना आवश्यक नहीं है।

इस प्रकार श्री ए०के० नाटाणी के शपथ पत्र से यह साबित होता है कि प्रार्थी को परिवीक्षा काल पर रखा गया, परिवीक्षा काल में उसकी सेवाएं संतोषप्रद नहीं होने से समाप्त की गई। अतः पक्षकारान के शपथपत्र व प्रदर्श डब्ल्यू-1 से यह साबित होता है कि प्रार्थी हजारी लाल को 29-10-85 को परिवीक्षा काल पर रखा गया था और उसकी सेवाएं 14-9-87 को समाप्त की गई हैं जबकि वह परिवीक्षा काल में ही था क्योंकि उसको स्थाई नहीं किया गया था।

7. प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि के तर्कों का विवेचन करने के लिए स्टाफ रेगुलेशन्स, 1960 के खण्ड 14 को प्रस्तुत करना आवश्यक है जो निम्न लिखित है :—

Probation :

14. (1) Persons appointed to posts belonging to classes I & II shall, on the first appointment in the Corporation's service, be required

to be on probation for the period of one year from the date of appointment.

(2) Persons appointed to the posts belonging to classes II & IV, shall on the first appointment in the Corporation's service, be required to be on probation for a months.

(3) Subject to the provisions of any law for the time being in force the appointing authority may, at its discretion, dispense with, reduce or extend the probationary period, but in no case shall the total period of probation exceed :—

(a) In case of employees to classes I & II.	Two years
(b) In other cases	One year

(4) During the period of probation an employees shall be liable to be discharged from service without any notice.

इस खण्ड के अनुसार अगर किसी क्लास 1 अथवा क्लास 2 अधिकारी को विपक्षी द्वारा नियुक्ति दी जाती है तो उसको एक वर्ष की परिवीक्षा के लिए रखा जायगा और उसकी यह परिवीक्षा अवधि विपक्षी द्वारा उसके विवेक के आधार पर बढ़ाई भी जा सकती है परन्तु यह परिवीक्षा काल दो वर्ष से अधिक नहीं होगा और इस परिवीक्षा काल में किसी भी कर्मचारी को बिना नोटिस दिये डिस्चार्ज किया जा सकता है। इस प्रकरण में भी प्रार्थी श्री हजारीलाल को 29-10-85 को परिवीक्षा काल पर रखा गया था और उसका परिवीक्षा काल समय-समय पर बढ़ाया गया है और उसकी सेवाएं 14-9-87 को परिवीक्षा काल में ही समाप्त कर दी गई है। इस प्रकार दो वर्ष के अन्दर परिवीक्षा काल के अन्दर ही उसकी सेवाएं समाप्त की गई हैं। इन परिस्थितियों में प्रार्थी को बिना नोटिस के कार्य संतोषजनक नहीं होने के कारण स्टाफ रेगुलेशन्स 1960 के खण्ड 14 के अनुसार हटाया जा सकता था जो कि विधि के अनुसार है क्योंकि स्टाफ रेगुलेशन्स 1960 विधि का प्रभाव रखते हैं। दूसर 4-5-87 के पश्चात् परिवीक्षा काल का नहीं बढ़ाना भी इस बात का द्योतक नहीं है कि उसका परिवीक्षा काल समाप्त कर दिया गया है परन्तु डब्ल्यू-1 पत्र कार्य संतोषजनक नहीं होने व दो वर्ष का परिवीक्षा काल समाप्त नहीं होने और प्रार्थी को स्थाई नहीं किये जाने से यही साबित होता है कि प्रार्थी का परिवीक्षा काल चल रहा था। इस प्रकार प्रार्थी को परिवीक्षाकाल 4-5-87 के बाद नहीं बढ़ाये जाने से यही माना जायेगा कि उसका परिवीक्षा काल चल रहा था। इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थी को परिवीक्षा काल 4-5-87 को समाप्त हो गया था परन्तु उसका परिवीक्षा काल चल रहा था। इन परिस्थितियों में दो वर्ष पूरे होने से पूर्व परिवीक्षा काल में प्रार्थी को सेवा से मुक्त करना खण्ड 14 स्टाफ रेगुलेशन्स 1960 के अन्तर्गत आता है जो कि विधि के अनुसार है और इसमें नोटिस दिये जाने की या जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसे प्रकरण में अधिनियम के प्रावधान भी लागू नहीं होते हैं। मेरे इस विचार का समर्थन 1994 (2) एस०सी०सी० पेज 323 एम० वेणुगोपालन बनाम डिवीजनल मेनेजर एल०आई०सी० ऑफ इंडिया 323 से ही होती है जिसमें माननीय न्यायाधीपतियों ने निम्नलिखित विनिश्चय किया है :

Service Law.—Life Insurance Corporation Act, 1956 Ss. 48(2)(cc)(2-A), (2-B) & (2-C) as introduced by LIC (Amendment) Act, 1981 (1 of 1981) and 49-Effect of the amendment introduced in S.48-Operation of ID Act excluded to the extent its provisions are in conflict with the rules framed under S-48 (2)(cc) Amendments not violative of Art. 14 on ground of depriving LIC Employees of benefit of the provisions of ID Act-Reg. 14 of LIC of India (Staff) Regulations 1960, originally framed under S-49 (regarding probation of employees belonging to classes I and II), deemed to be a statutory Rule under S.49(2)(cc) (relating to terms and conditions of service of the employees) and has overriding effect over Sc 2(oo) and 25-F of ID Act in view of the non-fulfilment of condition of achieving minimum business target stipulated in the order of appointment—termination effected under under the stipulation contained in terms of appointment read with Reg. 14(4) (providing for discharge during probation)-Held, operation of S. 2(oo) of ID Act excluded—Termination not being deemed to be retrenchment under S. 2(oo) S.25 not attracted—even if ID Act applicable, S.2(oo) thereof not attracted in view of the C1. (bb) thereof as introduced by ID (Amendment) Act, 1984 (49 of 1984) and hence S.25 F of that Act not invocable—Even under the general law termination of probationer on assessment of overall performance valid—termination of service—probationer—Labour Law—Industrial Disputes Act, 1947, Ss. 2(oo)(bb) & 25-F Constitution of India Art, 14.

8. तीसरे स्टाफ रैगूलेशन्स 1960 विधि का प्रभाव रखते हैं और खण्ड 14 सेवा की एक वैधानिक शर्त है। इस खण्ड 14 के अनुसार परिवीक्षा काल समाप्त होने से पूर्व बिना नोटिस दिये एवं जांच कराये प्रार्थी को हटाया जा सकता है। इस प्रकार परिवीक्षा काल को निश्चित अवधि के लिए प्रार्थी को रखा गया था और परिवीक्षक काल की अवधि, जो कि अधिकतम दो वर्ष है, से पूर्व ही प्रार्थी को हटा दिया गया, इसलिए प्रार्थी का प्रकरण धारा 2(00)(बीबी) अधिनियम के दायरे में भी आता है क्योंकि यह नियुक्ति परिवीक्षा काल के निश्चित समय के लिए थी। मेरे इस विचार का समर्थन उपरोक्त निर्णय से होता है। इस प्रकार जब निश्चित अवधि के लिए प्रार्थी की सेवा थी और प्रार्थी का प्रकरण धारा 2(00) (बीबी) अधिनियम के दायरे में आता है तो प्रार्थी कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है क्योंकि यह सेवा समाप्ति छंटनी की परिभाषा में नहीं आती है इसलिए प्रार्थी को जो सेवा समाप्त की गई है वह स्टाफ रैगूलेशन्स 1960 के खण्ड 14 के अनुसार व धारा 2(ओओ)(बीबी) अधिनियम के अनुसार की गई है जो कि उचित एवं वैध है। चूंकि प्रार्थी की छंटनी नहीं की गई परन्तु उसे विधि के अनुसार सेवा से डिस्चार्ज किया गया है इसलिए प्रार्थी का प्रकरण 25-एच व नियम 77 एवं 78 के दायरे में भी नहीं आता है क्योंकि इन नियमों के लिए छंटनी का होना आवश्यक है। न ही यह प्रकरण धारा 25-एफ अधिनियम के दायरे में आता है क्योंकि इसमें भी छंटनी का होना आवश्यक है जोकि नहीं है। अतः प्रार्थी धारा 25एफ, जी, एच एवं नियम 77 व 78 का कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

9. अतः प्रकरण में यह अवार्ड पारित किया जाता है कि सीनियर डिवीजनल मैनेजर, लाइफ इंश्योरेन्स कारपोरेशन आफ इंडिया जयपुर द्वारा श्रमिक श्री हजारी लाल को दिनांक 14-9-87 से सेवा समाप्त करने की कार्यवाही उचित एवं वैध है व प्रार्थी कोई दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

10 अवार्ड आज दिनांक 1-4-1997 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया जो केन्द्र सरकार को नियमानुसार प्रकाशनार्थ भेजा जाये।

एस.के. वर्मा, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1997

का. आ. 2118.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार उत्तर रेलवे, मुरादाबाद के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-7-97 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-41012/97/93-आई आर (डी.यू.)]

पी.जे. माईकल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1997

S.O. 2118.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, KANPUR as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Uttar Rly., Moradabad and their workmen, which was received by the Central Government on the 25th July, 1997.

[No. L-41012/97/93-IR(DU)]

P. J. MICHAEL, Desk Officer.

ANNEXURE

BEFORE SHRI B. K. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTIAL TRIBUNAL CUM LAPOUR COURT, DEOKI PALACE ROAD, PANDU NAGAR, KANPUR

Industrial Disput eNo. 97 of 1993

In the matter of Dispute

BETWEEN

B. D. Tiwari
Zonal President
Uttar Railway Karmchari Union
House No. 96/196, Roshan Bajaj Lane
Purana Ganeshganj, Lucknow-226001.

AND

Medical Suprintendent
Uttar Railway
Moradabad.

AWARD

1. Central Government Ministry of labour New Delhi vide its Notification No. L-41012/97/93-I.R. (D.U.) dated 20-11-93 has referred the following dispute for adjudication to this Tribunal :

> Whether the action of the management in declaring Shri Subhiivan Lal S/o Sri Kishori Lal, Fireman Grade B, as permanently unfit as Firemen but fit in a one and below with glasses on 12-6-1984, is legal and justified ? If not what relief the workman is entitled to ?

2. The concerned workman Subhjiwan Lal was initially appointed as cleaner in Loco Shed by the opposite party Northern Railway under D.R.M. Moradabad. In Feb., 1980 he was promoted as Fireman Grade 'B'. The case of the concerned workman is that on 8-3-84 he became sick and went under treatment of Asstt. Divisional Medical Officer Northern Railway Rosa, where he was directed to contact Divisional Medical Officer, Moradabad. There he was declared fit in category A-I but was advised not to do strenuous work. This certificate was given on 12-6-84. On the basis of this report the concerned workman was decategorised and was given a job of coaching clerk which was of lower grade. There after the concerned workman obtained fitness certificate from Safdar Jung Hospital and AIIMS. On the basis of this fitness certificate he made a request for fresh fitment. By letter dated 6-1-86 the concerned workman was directed for fresh medical examination before Medical Supdt. Moradabad, who in turn asked to meet Dr. R. N. Gupta, Central Hospital, New Delhi. After examination Dr. Gupta told him that there was disability with him and gave him a sealed envelop. The same was handed over at Moradabad. This time he was directed to meet Dr. Raj Kumar of Lucknow Hospital Dr. Raj Kumar also examined him and orally informed him that he was fit. He also gave him a sealed cover on 29-1-86 which was handed over to Medical Supdt. Moradabad. Since then no decision was taken in respect of his matter. As he has been declared medically fit by doctors at Delhi and Lucknow, his order of the opposite party in declaring the concerned workman as permanent unfit is bad in law.

3. The opposite party has filed reply in which it has been alleged that dispute has become stale. The concerned workman was actually found unfit for assistance to driver. Further the opinion of Doctor can not be questioned. It has not been disputed that the concerned workman was sent for fresh Medical Fitness but nothing has been said as to what happened subsequently.

4. In the rejoinder nothing new has been said.

5. In support of his case the concerned workman Subhjiwan Lal WW(1) examined himself. He has not been cross examined, although the Aup. Rep. of management was present. That shows that the averment of concerned workman that he was sent for fresh medical examination is correct. The opposite party has not adduced any evidence in rebuttal. The workman has also filed certificate of AIIMS dated 9-10-86 which show that the concerned workman did not suffer from any heart disease. There is also a letter dated 6-1-86 issued by the opposite party in which mention has been made about submission of medical certificate by Safdar Jung Hospital and AIIMS. Further Subhjiwan Lal has been directed for reexamination. The concerned workman has given onoath that thereafter he was examined at Moradabad, Delhi and Lucknow and doctor of Delhi and Lucknow had orally told him that he was medically fit. Further each of them had given an envelop which was handed over at Moradabad. There is no evidence in rebuttal. Further there is no explanation or evidence as to whether the concerned workman actually appeared for medical examination. If so what was the report. All these papers must with the opposite party. If they had failed to file them and furnish any explanation adverse inference will be drawn against them. According drawing such adverse inferhence and consequently relying upon the evidence of the concerned workman it is held that after reexamination the concerned workman was found medically fit. Hence he is entitled for post and pay and other emoluments of Fireman 'B'. Any how since the reference is belated the concerned workman will be entitled for this post and moluments from the date of reference.

6. Accordingly my award is that reversion of the concerned workman to the post of Coaching Clerk from the post of Fireman 'B' is not justified and the concerned workman will be entitled for the post of Fireman 'B' and its Pay and other allowances from the date of reference.

B. K. SRIVASTAVA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1997

का.आ. 2119 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सदर्न रेलवे के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, पालकाट के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-7-97 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-41012/4/95-आई आर (बी I)]

पी. जे. माईकल, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1997

S.O. 2119.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Palakkad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Southern Railway and their workman, which was received by the Central Government on the 25th July, 1997.

[No. L-41012/4/95-IR(B.I.)]

P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE COURT OF THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, PALAKKAD

(Tuesday the 24th June, 1997/3rd Ashadha 1919)

PRESENT :

Shri B. Ranjit Kumar

Industrial Tribunal

Industrial Dispute No. 17/96(C)

BETWEEN

(1) The Divisional Personnel Officer, Southern Railway, Palakkad. (2) The General Manager (Law), Southern Railway, Park Town, Madras-600001 and (3) The Ministry of Railways, Railway Board, Rail Bhavan, New Delhi-1.

(By Adv. T. R. Rajagopalan)

AND

The Dakshin Railway Casual Labour Union, Edappally North, Cochin-24.

(By Sri C. P. Menon)

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour as per order No. L-41012/4/95-IR (B.I) dated 27-2-96 and Corrigendum notification dated 8-4-96 referred to this Tribunal the following issues for adjudication :

"Whether the action of the Management of Divisional Personnel Officer, Southern Railway Palghat in terminating the services of Sri A. Venketachalam, Ty. Brick Layer Under IOW-E w.e.f. 21-9-1978 is legal & justified ? If not, to what relief the workman concerned is entitled to ?"

(2) The contention of the Union as stated in its claim statement dated 6-6-1996 is that the workman concerned had worked under the Inspector of Special Southern Railway, Salem Jn. from 21-6-77 to 20-9-78 and no work was given to him since 21-9-78. According to Union, he had worked 373 days and he was kept out of employment without giving him 14 days notice as provided under Rule 2302 (i) of Railway Establishment Manual, Chapter XXIII, or one months notice as provided under Section 25F of the I.D. Act. It is further contended by the Union that while the workman was denied employment, the Management retained 15 other Juniors in violation of Section 25-H of the I.D. Act.

(3) In opposition to the above averments, the Management has filed its written objection dated 22-7-96 contending inter alia that the Union of India, Ministry of Railway or the Departmental Officer of the workman concerned are not made parties to the dispute and hence the Industrial Dispute is not maintainable. It is also contended by the Management that the claim is hopelessly barred by limitation and the stale claim is liable to be dismissed in limine for delay and laches. On the merit of the dispute, it is submitted by the Management that the workman was engaged locally, purely on casual daily rates of wages for specific casual employment for very short duration against sanction obtained from time to time. There are two categories of workmen in Indian Railways, viz regular railway servants and casual labourers. Placing reliance on the judgement of the Kerala High Court in W.A. No. 344/80, it is further submitted by the Management that although the Labour Court, Kozhikode by Order in C.P.(C)/55/86 had granted benefits of temporary status to the workman in this dispute, he will remain as a casual labourer and will not become temporary railway servants. According to Management, attainment of temporary status is only betterment of the service condition of a daily rated casual labourer and attainment of such status alone will not automatically entitle him to notice or notice pay under Section 25-F and 25-FFF of the I.D. Act. In Chapter XXV, Rule 2514 Clause V and VI of Indian Railway Establishment Manual (1963) then prevalent, it is laid down the applicability of the said Section of the I.D. Act. According to Management, it is clearly mentioned therein that for a casual labourer with more than 240 days in the preceding twelve calendar months alone Sections 25-F and 25-FFF are applicable. The further contention of the Management is that the workman had worked only for 140 days in 1977 and 225 days in 1978 in broken spells and the above provisions are not applicable in this case as he had not worked for 240 days in a calendar year. It is further submitted by the Management that the awards in I.D. 140/89, O.A. 711/89 etc. cannot be made applicable in the case of the workman, as the workman concerned in the above proceedings were casual labourers with broken service of 8 to 12 years and they are not similarly placed.

(4) The Union has also filed a rejoinder dated 6-8-96 contradicting the above averments of the Management and reiterating the averments already stated in its claim statement. It is submitted in the rejoinder that a casual labourer who has attained temporary status on account of working 120 days (formerly 180 days) on continuous service is a temporary railway servant for all purposes. According to Union, termination of the workman in this dispute amounts to retrenchment which is

in violation of Section 25-F of the I.D. Act and hence he is entitled to reinstatement with full backwages.

(5) The first contention urged by the Management in its written objection is that the reference order is not maintainable as the Union of India, Ministry of Railways or the Departmental Officer of the workman concerned are not parties to this industrial dispute. However, this point was not canvassed at the time of hearing arguments by the learned counsel for the Management. Such a contention is also not raised in the argument notes submitted on behalf of the Management. It is seen from Ext. W5 award dated 19-1-91 of Industrial Tribunal, Alappuzha in I.D. No. 140/89 and Ext. W6 award dated 1-10-92 in I.D. No. 202/90 of the same Tribunal that the Union of India, Ministry of Railways was not a party to the above two disputes. It is submitted by the representative of the Union that Ext. W5 and W6 awards have become final. A perusal of the above two awards also shows that the contention as to the non-jointer of parties had not been taken in the above two matters. The present industrial dispute has been referred by the Government of India, Ministry of Labour. As far as this industrial dispute is concerned, as per the original reference order No. L-41012/4/95-IR (B.I), dated 27-2-96 and the Corrigendum Notification, dated 8-4-96 the Ministry of Railways, Railway Board, Rail Bhavan, New Delhi-1 and the General Manager (Law), Southern Railway, Park Town, Madras are also parties. It may be true that the concerned departmental officer of the workman is not a party to this dispute. I do not think that he is a necessary party for the effective adjudication of this dispute. Therefore, I find that there is no infirmity in the above reference order for non-jointer of parties.

(6) The Second contention raised by the Management is that the claim of the Union is barred by limitation as the alleged denial of employment or the retrenchment was on 21-9-78 and the dispute has been referred for adjudication only in 1996. According to Management, the claim is liable to be rejected for laches and delay on the part of the workman. In support of the above contention the learned counsel for the Management would rely on the two decisions of the Supreme Court in Bhoop Singh v. Union of India and Ors AIR 1992 SC 1414 and Ratan Chandra Sammanta & Ors v. Union of India and Ors AIR 1993 SC 2276. On the other hand, the representative of the Union would submit that the issue as to the claim for temporary status of the workman was pending before the Labour Court, Kozhikode in C.P.(C) 55/86 and by Ext. W2 order dated 18-5-87 the Labour Court allowed his claim holding that he was entitled to get the CPC scale of pay during the period 21-10-77 to 20-9-78. Thereafter, he submitted Ext. W3 representation dated 2-3-88 to the Management with a prayer to reinstate him in service with backwages. The Union had also approached the Assistant Labour Commissioner (C) Ernakulam by Ext. W4 Chapter of demands dated 1-11-88.

(7) The Management has not contradicted the above averments of the Union by adducing any rebuttal evidence. From Ext. W2 order of the Labour Court, it is clear that he had approached the Labour Court for CPC scale of pay in 1986. But he had not raised any dispute regarding the alleged denial of employment at that time. Thereafter, he had approached the Railway and the Union had also taken up the matter with the Labour Department. However, for some reason or other the matter was delayed and ultimately the reference order was issued only in 1996. Therefore, the workman alone cannot be blamed for the delay for the period from 1988 to 1996. However, neither the Union nor the workman has offered any explanation for the delay in not raising the dispute during the period 1978 to 1988. No limitation is prescribed for raising an industrial dispute under the Industrial Disputes Act, 1947 or the Rules made thereunder. Therefore, I do not think that merely because there is an unexplained delay of about 10 years in raising the dispute, on that ground alone the claim put forward by the Union should be rejected as a stale claim.

(8) The first decision relied on by the learned counsel for the Management in support of his contention that a stale claim should be rejected on the ground of delay is in Bhoop Singh v. Union of India and Ors—AIR 1992 SC 1414. This is not a case under the Industrial Disputes Act, 1947. In this case the petitioner approached the Court after a long lapse of 22 years without explaining the delay, solely based on the cases of other dismissed employees (Constables) who approached the Court earlier and got reinstatement. In this context, the Supreme Court held that grant of the relief to the petitioner would be inequitable instead of its refusal being discriminatory. I find that the facts of the case at hand is entirely different from that of the above Supreme Court case and hence the said decision cannot be made applicable in the present case.

(9) The facts of the second case viz. Ratan Chandra Sammanta & Ors v. Union of India—in AIR 1993 SC 2276 are also entirely different from that of the case at hand. In the above Supreme Court case, the Ministry of Railways issued a Circular pursuant to the directions given by the Supreme Court in an earlier order dated 23-2-87 in Writ Appeal No. 332/1986 inviting representations from casual labourers who were retrenched before 1981 alongwith documentary proof reaching

the office before 31-3-87 for employing them further. Certain casual employees did not respond to above circular but made vague representation only in 1990 to the authorities. The Supreme Court refused to entertain the above petition not only the ground of delay alone but also on the ground that the material particulars were not furnished in support of the representation made on behalf of the petitioners. This is clear from the following observation of the Supreme Court.

"We would have been persuaded to take a sympathetic view but in the absence of any positive material to establish that these petitioners were in fact appointed and working as alleged by them it would not be proper exercise of discrition to direct opposite parties to verify the correctness of the statement made by the petitioners that they were employed between 1964 to 1969 and retrenched between 1975 to 1979."

As far as the case at hand is concerned, the Union has furnished the required particulars|material in support of the claim put forwarded by it on behalf of the workman. In the circumstance, I am of the view that it will be improper not to answer the reference order on merit on the ground of delay.

(10) Ext. W1 is the casual labourers service card issued to the workman by the Management which shows that he had worked 373 days during the period 21st June, 1977 to 20th September, 1978. A perusal of Ext. W1 shows that he had worked continuously during this period, except the break during the periods 21st October, 1977 to 23rd October, 1977 and 21st January, 1978 to 4th February, 1978. During all the other months he had worked throughout without even rest days. By Ext. W2 order dated 18th May, 1987 the Labour Court, Kozhikode has already found that he had attained temporary status w.e.f. 21st October, 1977 and he is entitled to be CPC scale of pay during the period 21st October, 1977 to 20th September, 1978. The Ext. W1 order has become final and the Management has also implemented the said order. Therefore, the Management cannot now contended that the workman has not attained the temporary status. The relevant provisions of Railway Establishment Manual, Chapter XXIII governing such employees are the following :

"2301. Definition-A 'temporary railway servant' means, a railway servant without a lien on a permanent post on a Railway or any other administration or office under the Railway Board. The term does not include 'casual labour', or a 'contract' or 'part time' employee or an 'apprentice'."

"2302. Termination of service and periods of notice.—(1) Service of a temporary railway servant shall be liable to termination on 14 days notice on either side provided that such a railway servant shall not be entitled to any notice of termination of his service—

(i) if the termination is due to the expiry of the sanction to the post which he holds or the expiry of the officiating vacancy or to his compulsory retirement due to mental or physical incapacity or to his removal or dismissal from service as a disciplinary measure after compliance with the provisions of clause (2) of Article 311 of the Constitution of India;

(ii) . . . .
. . . ."

"2505. Notice of termination of service.—Except where notice is necessary under any statutory obligation, no notice is required for termination of service of the casual labour. Their services will be deemed to have terminated when they absent themselves or on the close of the day.

Note.—In the case of a casual labourer who is to be treated as temporary after completion of six months' continuous service, the period of notice will be determined by the rules applicable to temporary Railway servants".

(11) According to paragraphs 2302 and 2505 of the Railway Establishment Manual it is mandatory to give 14 days notice for termination of service of a temporary railway staff. The contention of the workman is that the Management had not served 14 days notice as provided in paragraph 2302 and 2505. The Kerala High Court has considered this point in the case of similarly placed workman in judgement dated 26th September, 1995 in O.P. No. 4393|93 against the Management. Admittedly, in the present case the Management had not served 14 days notice on the workmen concerned while terminating his services though he had already attained the temporary status. Therefore, it can be safely concluded that the Management had violated the provisions of paragraphs 2302 and 2505 of the Railway Establishment Manual.

(12) The further contention of the Union is that the workman was retrenched by the Management without complying with the mandatory provisions of Section 25F of the I.D. Act. According to Section 25F, a workman who had been in continuous

service for not less than one year under an employer cannot be retrenched without giving him one months notice in writing indicating the reasons for retrenchment or the workman has been paid in lieu of such notice the wages for the period of the notice. It is also necessary that he has been paid at the time of retrenchment, the compensation which shall be equivalent to 15 days average pay for every completed year of continuous service or any part thereof in excess of the service of 6 months. It is further provided under section 25F that notice in the prescribed manner should be served on the appropriate government or such authority as may be specified by the appropriate government by notification. It is not the case of the Managemtnt that it had retrenched the workman in accordance with Section 25F. According to Management, Section 25F is not applicable in the present case as the workman had not worked for 240 days in a calendar year. I do not find any substance in the above submission made on behalf of the Management. The expression "continuous service" has been defined in Section 25-B of the I.D. Act, according to which if the workman during a period of 12 calendar months preceding the date with reference to which calculation is to be made, had actually worked under the employer for not less than 240 days, he shall be deemed to be in continuous service. Nowhere in Section 25B of the I.D. Act it is mentioned that 240 days must be within a calendar year. In the present case the workman satisfies the definition of 'continuous service' under Section 25B and it follows that Section 25F was applicable in his case. Admittedly, the Management had not complied with the provisions of Section 25F. Management had neither issued notice to the workman nor paid him compensation as provided under Section 25-F.

(13) The further contention of the Management is that the workman was engaged as a casual labourer considering the availability of work against sanction obtained from time-to-time and his casual engagement was terminated on completion of the said work. The learned counsel for the Management had put a suggestive question in this regard to the workman while the workman (WW1) was cross examined and he had answered the above question in the negative. According to workmen, he was engaged as brick layer in connection with the repair work of the quarters and his termination was not on account of completion of the said repair works. In the present case, the Management has not adduced any evidence in support of its contention that the workman was engaged for a particular work against sanction order and on completion of the said work, his casual engagement was terminated. In the absence of any such evidence this Tribunal has no other alternative but to believe the testimony of the workman as WW1.

(14) In view of the definition of "retrenchment" as given in Section 2(oo) of th I.D. Act the termination of services for any reason whatsoever will amount to retrenchment. Therefore, the denial of employment to the workman concerned in this dispute would amount to retrenchment. Even assuming that the workman had been engaged for specific work or for specific period and the termination of his service w.e.f. 21st September, 1978 was on completion of such work or on efflux of time such termination will also come within the meaning of "retrenchment" as the amendment made to Section 2(oo) by inserting Sub Clause (bb) by Act 49/1984 which has come into force w.e.f. 18th August, 1994 is not applicable. As already observed hereinabove the retrenchment effected in this case is in violation of Section 25-F of the I.D. Act.

(15) The next question to be decided is as to the relief to which the workman is entitled. The prayer of the Union is for an award reinstating the workman with back wages which is the normal relief in case the retrenchment is found to be invalid and illegal. In this context the learned counsel for the Managtment would place strong reliance on the judgement dated 3rd January, 1986 of a Division Bench of the Kerala High Court in W.A. No. 344/80 and argue that a casual labourer who had attained the temporary status is not entitled to claim ptrmanent employment or any other benefits to which a temporary employee is entitled. It is observed from the above judgement that in that case the Division Bench was dealing with the claim for subsistence allowance based on a Government order put forward by casual labourers who had attained the temporary status whose services were terminated for having participated in tht strike and subsequently taken back in the same position which they had occupied before their services were terminated in the year 1974. In the above judgement, the Kerala High Court has observed that a casual labourer who had attained temporary status is not entitled to claim permanent employment as a matter of right. In the prtsent case, the question is whether the workman is entitled to be reinstated in the same position which he had ocoupied before his services were illegally terminated by the Railway Management. In other words, the issue referred for adiudication in the case at hand is not as to tht entitlement of the workman for permanent employment or regularisation. Therefore, I am of the view that the above judgement of the Kerala High Court has no relevance or application on the facts and circumstance of the case at hand. However, in the present case, in view of the long delay in raising the dispute, I am of the considered opinion that it will not be proper to grant the normal relief of reinstatement with full back wages. As already observed the workman had been retrenched from service on 21st September, 1978 and he had approached the Labour Court in 1986 and

that too only for wages applicable to the workman who had attained permanent status. Though the Labour Court allowed his claim by Ext. W2 order dated 18th May, 1987 the present dispute was raised only in 1988 by Ext. W3 representation dated 2nd March, 1988 addressed to the Management. Therefore, it is clear that he was idling over his right over several years. It is also pertinent to note that though the workman had taken up the matter in 1988, the Management was not amendable to settle the issue. In my view the Management being a public sector undertaking should have acted as a model employer. The Railway is running a big establishment which requires a large number of casual|temporary workers like the workman concerned in this dispute and the Management would have very well considered the request of the workman for re-employment. In Steel Authority of India Ltd. v. The Presiding Officer—1996 II LLJ 760 and Union of India v. Shri Chhida Singh Rawath 1991 AIR SCW 587 the Supreme Court has taken a view that if here is inordinate delay in taking action by a workman against illegal termination over a decade, the workman should not be entitled to full back wages. In Steel Authority case the Supreme Court set aside the order to give back wages and directed to pay only 25 per cent back wages. In Shri Chhida Singh Rawath's case the Suprtme Court denied the entire back wagts till the date the petitioner moved the High Court. Considering the facts and circumstances of the case at hand, I am of the view that for the ends of justice it would be only proper to direct the Management to engage the workman on the same service conditions as he had been engaged earlier but without back wages. However, on his re-employment he shall be paid wages applicable to the persons who had attained temporary status. The period from 1st November, 1988, i.e., the date of Ext. W4 representation and the date of re-employment of the workman shall be considered as service for the purpose of terminal benefits and not for any other purpose.

In the result an award is passed in the aforesaid terms and the reference order is answered accordingly.

Dated, this the 24th day of June, 1997.

B. RANJIT KUMAR, Industrial Tribunal

APPENDIX

Witness examined on the side of the Management—Nil.

Witness examined on the side of the Union :

WW1—Sri A. Venkitachalam.

Documents marked on the side of the Management—Nil.

Documents marked on the side of the Union :—

Ext. W1—Copy of Service Card issued by the Management to the workman.

Ext. W2—Copy of Judgment in CP(C) No. 55|86 issued by the Hon'ble Central Government Labour Court, Kozhikode.

Ext. W3—Copy of letter dated 2nd March, 1988 from the workman to the Divisional Officer, Southern Railway.

Ext. W3(a)—Postal receipt of Ext. W3.

Ext. W4—Copy of letter dated 1st November, 1988 from the Union to the Asstt. Labour Commissioner (C), Ernakulam.

Ext. W5—Copy of Award dated 19th January, 1991 in I.D. No. 140|89 of the Hon'ble Industrial Tribunal, Alappuzha.

Ext. W6—Copy of Award dated 1st October, 1992 in I.D. No. 202|90 of the Hon'ble Industrial Tribonal, Alappuzha.

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1997

का.आ. 2120:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार साउदर्न रेलवे पालघाट-2 के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, पालघाट के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 25-7-1997 को प्राप्त हुआ था।

[संख्या एल-41012/2/95-आई.आर. (बी.-I)]
पी.जे. माईकल, डैस्क अधिकारी

New Delhi, the 28th July, 1997

S.O. 2120.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, Palakkad as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Southern Rtilway, Palakkad-2 and their workman, which was received by the Central Government on the 25th July, 1997.

[No. L-41012|2|95-IR (B-I)]
P. J. MICHAEL, Desk Officer

ANNEXURE

IN THE COURT OF THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, PALAKKAD

Thursday, the 3rd July, 1997

PRESENT :

Shri B. Ranjit Kumar, Industrial Tribunal.
Industrial Dispute No. 21|96(C)

BETWEEN

(1) The Divisional Personnel Officer, Southern Railway, Palakkad-2.

(2) The Ministry of Railways, Railway Board, Rail Bhawan, New Delhi-1.
(By Adv. T. R. Rajagopalan)

AND

The General Secretary, D.R.C.L.U., Edappally North, Cochin-24.

(By Adv. Sri C. P. Menon)

AWARD

As per the Order No. L-41012|2|95-IR B-1), dt. 12th April, 1996 the Government of India, Ministry of Labour referred the following issues for adjudication :—

"Whether the action of the management of DPO Southern Railway, Palghat in not engaging the services of the workman Smt. Rajamma, LTI No. 573 w.e.f. 21st June, 1980 is justified ? If not, to what relief the concerned workman is entitled to ?"

(2) The Union would contend in its claim statement dated 16th June, 1996 that Rajamma (hereinafter referred to as the worker) had worked under the P.W. Inspector of Special Southern Railway, Palakkad from 21st November, 1976 to 21st June, 1980 and thereafter she was kept out of employment by the PW Inspector without notice. According to Union, the worker had attained temporary status as she had completed 120 days continuous service. Therefore, she was eligible for C.P.C. scale of pay and 14 days notice for terminating her services as per Rule 2302 of Railway Establishment Manual, Chapter XXIII. It is further contended by the Union that the worker had completed more than 240 days service and hence one month's notice indicating the reasons for retrenchment or notice pay was also necessary as provided under the provisions of Industrial Disputes Act. It is also contended by the Union that 15 other juniors were retained while terminating the services of the worker and hence the Management had violated the provisions of section 25-H of the I.D. Act (sic). Yet another contention of the Union is that the retrenchment was against the provisions of Chapters VA & VB of the I.D. Act. The prayer of the Union is to direct the Railway Administration to reinstate the worker with all attendant benefits.

(3) The Management would contend in its written objection dated 8th October, 1996 that the reference order itself is bad in law as the Union of India representing the Railways or the Ministry of Railways is not made as party under Section 2(b) and 2(k) of the I.D. Act. (sic.). It is further submitted by the Management that the worker was engaged as casual labourer on daily rate of wages with LTI No. 573 by the Permanent Way Inspector. According to Management, she was not a regular worker of the Railway Department, but one of the casual labourers engaged on day-to-day basis for seasonal work. The services of such casual labourers are liable to be terminated either on completion of work for which they were specifically engaged or on the expiry of the sanction under which they have been engaged. According to Management, the worker concerned was not on continuous work from 1976 to 1980 as alleged in the claim statement nor was she in continuous service for a period of more than 240 days. She had worked only for 12 days during 1977, 60 days in 1978 and 122 days in 1979. According to Management, even at the time of the alleged termination of the service, the worker had worked only for a total period of 65 days and hence she was not entitled to insist upon notice for terminating her services. It is further submitted by the Management that the Ministry of Labour, Government of India had turned down similar requests for reference for adjudication vide order No. L-41012|125|92-I.R. (D-4) dated 11th November, 1992 in the case of Smt. Revathi. The further contention of the Management is that though the alleged termination was during 1980, the dispute has been raised only in 1996 i.e. after 16 years and no reason for the delay has been indicated. Therefore, according to Management, the present claim is stale and not deserving any consideration.

(4) The Union has filed a rejoinder in reply to the written objection of the Management. According to Union, the Union of India is not a necessary or formal party to this Industrial dispute. The worker had been engaged by the Management intermittently during the period from 5th March, 1975 to 20th June, 1980 as evident from the casual labour card issued to her which was authenticated by the PWI|OJA bearing No. 573. According to Union, she was denied regular engagement and created artificial break so as to prevent her from attaining temporary status. This is against the provisions of paragraph 2501 of Railway Establishment Manual. It is further submitted by the Union that as per paragraph 2501(b) (i) the worker had attained the temporary status and therefore the termination without notice as provided under Para 2505 is vitiated. The further contention of the Union is that the termination is also in violation of the principles of natural justice. In the present case, the Management had also not complied with the provisions of section 25F of the I.D Act.

(5) When this dispute came up for hearing on 3rd December, 1996, the Union reptesentative reported that the worker concerned in this dispute

expired on 10th October, 1996. He has also filed M.P. No. 40|96 with a prayer to implead the following legal heirs of the deceased worker :

1. Murukan, S|o Velayudhan Poosari, Koziyiparambu, C|o GI. Secretary, Dakshina Railway Casual Labour Union, Edappally North, Cochin-24.
2. Rajesh, S|o Murukan (Minor), aged 6 years, (represented by father) C|o Dakshina Railway Casual Labour Union, Edappally North, Cochin-24.
3. Radika, D|o Murukan (Minor), aged 4 years, (represented by father) C|o Dhakshina Railway Casual Labour Union, Edappally North, Cochin-24.
4. Radha, D|o Murukan (Minor), aged 16 days (represented by father), C|o Dhakshina Railway Casual Labour Union, Edappally North, Cochin-24.

(6) I feel that in view of Sub-section (8) of Section 10 of the I.D. Act, it is not necessary to implead the legal heirs of the deceased worker as these adjudication proceedings will not lapse due to her death. Moreover this dispute has been raised by the Union and I am satisfied that the said Union will safeguard the interest of the legal heirs. If an award is passed in favour of the worker, the legal heirs will be entitled to receive the monetary benefits arising from the said award. Therefore, the M.P. No. 40|96 is hereby disposed of with the above observations.

(7) The first contention of the Management is that the reference order itself is bad in law for non-joinder of parties. I do not find any force in the above contention. A perusal of the reference order reveals that the Ministry of Railways is also a party to the reference. It is also pertinent to note that already there were other similar disputes like I.D. No. 140|89 on the file of Industrial Tribunal, Alappuzha (Ext. W4) in which the Union of India or the Ministry of Railways was not a party and the Management had not raised any contention therein regarding non-joinder of parties. According to me, even assuming that the Union of India or the Ministry of Railways was necessary party to this Industrial dispute the said issue should have been raised at the conciliation stage itself. The Management is not entitled to raise such a technical issue before this Tribunal at the adjudication stage. Any way, as far as this dispute is concerned I find that necessary parties are already on the party array and hence the reference order cannot be held as bad in law for non-joinder of parties.

(8) The next contention urged on behalf of the Management is that the claim put forward on behalf of the worker is belated and such a stale claim cannot be entertained. From Ext. W2 judgement dated 15th July, 1987 of the Kerala High Court in Writ Appeal No. 613|83, it is observed that the worker concerned in this dispute had approached the High Court in 1980 itself alongwith similar other workers immediately on denial of employment to them by filing O.P. No. 4178|1980. The said Original Petition was dismissed by a single judge holding that notwithstanding the material that had been placed before his Lordship it was not possible to record a finding in favour of the workers that they had qualified to claim the benefit of Section 25F. One of the workers who had filed the above original petition filed Writ Appeal No. 613|1983 and by Ext. W2 judgment the Division Bench of the Kerala High Court opined that the disputed question of fact in regard to the length of service rendered could be examined under the provisions of I.D. Act, 1947 and the writ appeal was dismissed without prejudice to the right of the appellant to invoke the remedies available under the I.D. Act. Thereafter, the Government of India referred the issue in relation to 16 workers which was adjudicated by Industrial Tribunal, Alappuzha and passed Ext. W4 award dated 19th January, 1991 in favour of those workers. Unfortunately the name of the worker concerned in this dispute was not included in the above reference. Thereafter, the worker concerned in this dispute submitted Ext. W5 representation dated 19th February, 1992 to the Management requesting to consider her case also in the light of the above award. She had also taken up the matter with the Central Administrative Tribunal, Ernakulam Bench along with other three workers by filing O.A. No. 1339|1993. Although both the Administrative Tribunal and Industrial Tribunal have concurrent jurisdiction to deal with the above issue, the learned Vice-Chairman of the Central Administrative Tribunal in Ext. W3 judgment dated 11th November, 1992 felt that the matter can be more appropriately dealt with by the Industrial Tribunal and rejected the application without prejudice to the rights, if any, of the workers to move Industrial Tribunal in accordance with law. Accordingly, the matter now stands referred to this Industrial Tribunal for adjudication.

(9) In the circumstance stated above, I find that this is not a case where the worker concerned was sleeping over her right without taking any action. She had approached the concerned authorities at appropriate time including the High Court of Kerala and the Central Administrative Tribunal, Ernakulam Bench for the redressal of her grievance. The High Court of Kerala and Administrative Tribunal felt that the issue could be more appropriately adjudicated by this Tribunal and ultimately the reference order was issued by the Government of India, Therefore, I find that there is no delay or laches either on the part of the worker or the union as alleged by the Management.

(10) The main contention of the representative of the worker is that her services were terminated in violation of the provisions of the Railway Establishment Manual. The relevant provisions of the Railway Establishment Manual applicable in this case are the following :

"2301. Definition—A 'temporary railway servant' means a railway servant without a lien on a permanent post on a Railway or any other administration or office under the Railway Board. The term does not include 'casual labour', a 'contract' or 'part time' employee or an 'apprentice' ".

"2302. Termination of service and periods of notice :—(1) Service of a temporary railway servant shall be liable to termination on 14 days' notice on either side provided that such a railway servant shall not be entitled to any notice of termination of his service—

(i) if the termination is due to the expiry of the sanction to the post which he holds or the expiry of the officiating vacancy or to is compulsory retirement due to mental or physical incapacity or to his removal or dismissal from service as a disciplinary measure after compliance with the provisions of clause (2) of Article 311 of the Constitution of India;

(ii) .....
....."

"2505. Notice of termination of service :— Except where notice is necessary under any statutory obligation, no notice is required for termination of service of the casual labour. Their services will be deemed to have terminated when they absent themselves or on the close of the day.

Note :—In the case of a casual labourer who is to be treated as temporary after completion of six months' continuous service, the period of notice will be determined by the rules applicable to temporary Railway servants".

(11) It is seen from Ext. W1 casual labourer service card that the worker had worked 120 days during all the calendar years from 1975 to 1980 except in the years 1977 and 1980. The Kerala High Court has observed in its judgment dated 26-9-95 in O.P. No. 4393|93 that a casual worker who had worked 120 days in a calendar year would attain temporary status. The worker concerned in this dispute had already attained the temporary status as early as in 1975, as she had worked for 126-1|2 days during the period from 5-3-75 to 20-12-75. Therefore, her services could be terminated only in accordance with the provisions of Para 2302 of the Railway Establishment Manual. Admittedly, no notice of 14 days had been served on the worker. Therefore, I find that the denial of employment to the worker w.e.f. 21-6-1980 is in violation of the Para 2302 and hence illegal.

(12) The worker had also a case that the termination of her services was in violation of Section 25-F of the I.D. Act. Section 25-F of the I.D. Act is appplicable to the workers who had one year continuous service as defined in Section 25-B of the I.D. Act. According to Section 25-B, if a worker had worked during a period of 12 calendar months preceding the date with reference to which calculation is to be made in actual work for not less than 240 days he|she shall be deemed to be in continuous service. This provision has been relaxed by Para 2514 of Railway Establishment Manual, according to which if a casual workman had worked 120 days instead of 240 days, it will be deemed that he was in continuous service. In the present case as per Ext. W1 casual service card the applicant had worked only 118 days during the 12 calendar months preceding 21-6-80. Therefore, it cannot be held that the termination of the worker in this case is in violation of Section 25F of the I.D. Act.

(13) The representative of the worker has a further case that the Management has violated the provisions of 25-G of the I.D. Act as 15 other juniors were retained in service while retrenching the worker concerned in this dispute. A casual or temporary labourer is also a 'workman' within the meaning of I.D. Act. In view of the decision of the Supreme Court in Central Bank of India V. S. Sathiam—1996 II LLJ 820 the termination of services of a workman who had not worked for 240 days will also amount to retrenchment within the meaning of Section 2(00) of the I.D. Act and provisions of Section 25-G and 25-H are applicable to such category of workmen. The Management has not disputed the averments of the Union with regard to applicability of Section 25-G and 25-H in its written statement. The contention of the Management in the written statements is that the Central Government had denied the reference in the case of another worker who had not worked for 240 days. It is now well settled that the Government is not competent to adjudicate such legal points. As far as the case at hand is concerned I have no hesitation in holding that the termination of services of the worker is in violation of the provisions of Section 25-G of the I.D. Act.

(14) It was further argued by the learned counsel for the Management that in view of the judgement dated 3-1-86 of a Division Bench of the Kerala High Court in W.A. No. 344|80 a casual labourer who had attained the temporary status is not entitled to claim permanent employment or any other benefits to which a temporary employee is entitled. It is observed from the above judgement that in that case the Division Bench was dealing with the claim for subsistence allowance based on a Government order put forward by casual labourers who had attained the temporary status and whose services were terminated for having participated in the strike and subsequently taken back in the same position which they had occupied before their services were terminated in the year 1974. In the above judgement, the Kerala High Court has observed that a casual labourer who had attained temporary status is not entitled to claim permanent employment as a matter of right. In the present case, the claim of the Union is not for regularisation or for permanent employment and hence the above decision of the Kerala High Court is not applicable.

(15) As already found hereinabove, the action of the Management in not engaging the worker w.e.f. 21-6-80 is unjustified and also illegal as the same is in violation of the mandatory provisions of Railway Establishment Manual as well as I.D. Act 1947. In the circumstance, the worker would have been entitled to the normal relief of reinstatement with all other consequential benefits. In the present case the worker expired on 10-10-96 and hence the question of giving the relief of reinstatement does not arise. However, her legal heirs shall be entitled to the monetory benefits. Since the worker was engaged on casual of temporary basis, there was no guarantee for every day work. Therefore, I feel that it will not be proper to award full backwages for more than 16 years i.e. from 21-6-80 to 10-10-96. As observed hereinabove, the worker had already attained temporary status as early as in 1975 and she was entitled to the CPC scale of pay. Considering all these aspects I direct the Management to pay a lumpsum amount of Rs. 30,000 (Rupees Thirty thousand only) to the legal heirs of the deceased worker in equal shares in lieu of reinstatement backwages and all other attendant benefits within thirty days from the date of production of heirship certificate by the legal heirs from a competent authority. The share of minor legal heirs shall be deposited with a nationalised bank or Unit Trust of India in a scheme which is more beneficial to them for periods not exceeding their respective dates of majority with instruction to pay the amounts to the concerned legal heirs directly on the maturity date of deposits. If the Management fails to disburse the amount as stipulated above, the legal heirs shall be entitle to recover the said amount of Rs. 30,000 together with interest @ 18 per cent per annum from the Management in accordance with law.

(16) In the result an award is passed in the aforesaid terms answering the reference order in favour of the worker.

Dated this the 3rd day of July, 1997.

B. RANJIT KUMAR, Industrial Tribunal

APPENDIX

Witness examined on the side of the Management :

Nil

Witness examined on theh side of the Union :

Nil

Documents marked on the side of the Management :

Nil

Documents marked on the side of the Union :

Ext. W1—Copy of Casual Labour Service Card issued by the Management to the worker.

Ext. W2—Copy of Judgement in W.A. No. 613|83 issued by the Hon'ble High Court of Kerala, Ernakulam.

Ext. W3—Copy of Judgement in O.A. No. 1339|92 dt. 11-11-92 of the Central Administrative Tribunal, Ernakulam.

Ext. W4—Copy of Award dated 19-1-91 in I.D. No. 140|89 of the Industrial Tribunal, Alappuzha.

Ext. W5—Copy of letter dated 19-2-92 from the Union to the Divisional Railway Manager, Southern Railway, Palakkad.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054; 1997